संपादकीय जागरण
सोमवार, 9 फरवरी, 2026 : फाल्गुन कृष्ण – 8 वि. 2082

ईमानदारी का भाव अपराधबोध से मुक्त करता है

बंगाल में एसआइआर

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआइआर की प्रक्रिया के तहत जारी मसौदा सूची से 58 लाख नाम कटने के बाद जिस तरह करीब पांच लाख लोग सुनवाई प्रक्रिया में नहीं पहुंचे, उससे यह लगता है कि नाम कटने वालों का आंकड़ा 63 लाख तक पहुंच सकता है। चूंकि एसआइआर से जुड़े दावों और आपत्तियों पर सुनवाई की समयसीमा बढ़ा दी गई है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह बंगाल में लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से कटे हैं, उसी तरह कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसा ही हुआ है। आम तौर पर ये वे लोग हैं, जो अन्यत्र चले गए अथवा अपने पते-ठिकाने पर नहीं रह रहे या फिर जिनका निधन हो गया है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बिहार में भी इसी कारण अच्छी खासी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर हुए थे। अब यदि बंगाल में भी ऐसा होने जा रहा है तो ऐसे किसी नतीजे पर पहुंचने का कोई मतलब नहीं कि जानबूझकर लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने इसी आरोप के साथ पहले तो धरने-प्रदर्शन की राजनीति की, फिर अपना पक्ष रखने वकील की हैसियत से स्वयं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। इसका उद्देश्य यह संदेश देना था कि चुनाव आयोग बंगाल के लोगों के साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन इसमें वे नाकाम रहीं। आखिर जब सुप्रीम कोर्ट एसआइआर से जुड़ी विसंगतियों पर निगाह रख रहा है और इस संदर्भ में आवश्यक आदेश-निर्देश भी दे रहा है, तब फिर मतदाता सूचियों को शुद्ध करने की इस प्रक्रिया के विरोध का कोई औचित्य नहीं।

यह विचित्र ही है कि ममता बनर्जी एसआइआर में विसंगतियों को इंगित करने की जगह यह चाह रही हैं कि यह प्रक्रिया हो ही न। चुनाव आयोग को समय-समय पर एसआइआर की प्रक्रिया करनी ही चाहिए, क्योंकि इसी से मतदाता सूचियां दुरुस्त होंगी और यह निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव की बुनियाद हैं। बंगाल में एसआइआर का विरोध इसलिए हो रहा है, क्योंकि इससे अवैध बांग्लादेशियों के नाम कट सकते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, लेकिन भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि एसआइआर के जरिये बांग्लादेशी घुसपैठिये चिह्नित हों तो उन्हें निष्कासित करने का काम हर हाल में किया जाए। यह ठीक नहीं कि भारत सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की बातें तो बार-बार करती है, लेकिन इसके लिए कोई प्रभावी अभियान नही चलाती। समझना कठिन है कि मतदाता सूचियों में संशोधन-परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर अर्थात एनआरसी को क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है?

स्वागतयोग्य कदम

दिल्ली में डीटीसी के बेड़े में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें जुड़ना स्वागतयोग्य है। इन बसों के शामिल हो जाने के बाद अब इलेक्ट्रिक बसों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर दिल्ली पहले नंबर पर आ गई है। वर्षभर वायु प्रदूषण से जूझने वाली राष्ट्रीय राजधानी के लिए इसे एक उपलब्धि कहना गलत नहीं होगा। रविवार को मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रामलीला मैदान में इन बसों को हरी झंडी दिखाई। साथ ही दिल्ली व पानीपत के बीच अंतरराज्यीय ई-बस सेवा की भी शुरुआत की। इस दौरान, मुख्यमंत्री ने वर्ष के अंत तक दिल्ली में ई-बसों की संख्या बढ़ाकर 7500 और वर्ष 2028 तक इसे 14 हजार करने की बात कही, जो सुखद भविष्य की उम्मीद जगाती है।

> दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए डीटीसी के बेड़े को स्वच्छ ईंधन वाली बसों से मजबूत बनाना आवश्यक है

वायु प्रदूषण और यातायात जाम दिल्ली की दो बड़ी समस्याएं हैं, जो यहां के निवासियों को रोज परेशान करती हैं। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ कर निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने से इन दोनों समस्याओं को काफी हद तक नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो के सतत विस्तार के साथ ही डीटीसी के बेड़े को स्वच्छ ईंधन वाली बसों से मजबूत करना दिल्ली की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ाती दिख रही है। इन प्रयासों से दिल्ली की सड़कों को जाम मुक्त और हवा को प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद मिलेगी और दिल्ली को रहने योग्य एक बेहतर शहर बनाया जा सकेगा।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या अमेरिका के साथ व्यापार समझौते संबंधी साझा बयान दोनों देशों के हितों के अनुरूप है?

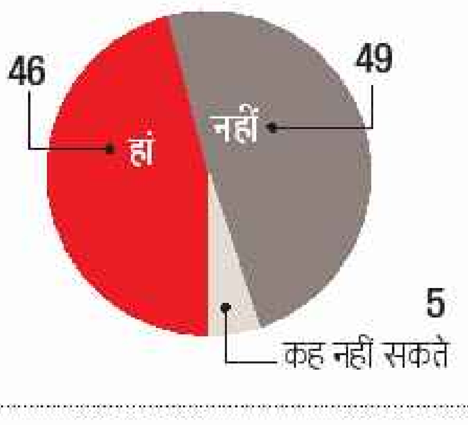

आज का सवाल

क्या अमेरिका से व्यापार समझौते पर कांग्रेस की आपत्ति सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

राजनीतिक कटुता की बंधक संसद

राज कुमार सिंह

राजनीति में हिसाब बराबर करने की प्रवृत्ति पुरानी है, पर उसके लिए संसदीय कार्यवाही को बाधित करना कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता

नेताओं का तो पता नहीं, मगर संसद के बजट सत्र में जारी हंगामा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नहीं बोल पाए तो विपक्ष के जवाबी हंगामे के चलते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी चर्चा का जवाब नहीं दे सके। हंगामे के दौरान आसन पर कागज फाड़ कर फेंकने के आरोप में विपक्षी दलों के आठ सांसदों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, जो संसद परिसर में धरने पर बैठ गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आंकड़े दिए हैं कि 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू संसद के बजट सत्र में अभी तक हंगामे के चलते 19 घंटे, 13 मिनट का समय बर्बाद हो चुका है। जाहिर है कि इस सबके लिए कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं स्वीकारेगा। किसी एक पक्ष को जिम्मेदार ठहराने से बात बनेगी भी नहीं। दरअसल इसके मूल में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच की राजनीतिक कटुता ही है। बढ़ती कटुता के लिए दोनों पक्षों के पास अपने-अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन संसद ही उसकी बंधक बनती नजर आए तो कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के जवाब के बिना ही ध्वनिमत से पारित होने की नौबत सामान्य घटना नहीं है। बेशक 2004 में भी ऐसा ही हुआ था, मगर गलतियां दोहराने के लिए नहीं, बल्कि सबक सीखने के लिए भी होती हैं। दोनों ही परिस्थितियां गलत हैं, जिनसे बचने का रास्ता निकालने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की भी बनती है। आखिर वे सदन के संरक्षक हैं।

इस टकराव की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक का संदर्भ प्रस्तुत करने से हुई। इसके जरिये राहुल गांधी ने यही दावा किया कि गलवन में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के समय सेनाध्यक्ष को यह कहकर कि 'जो उचित समझो, वह करो।' सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता ही नहीं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर भी आसीन हैं। एक बार नाकाम कोशिश से अपनी मंशा का संदेश देने के बाद वे अभिभाषण के अन्य बिंदुओं पर अपना भाषण केंद्रित करने की समझदारी दिखाते हुए जनरल नरवणे की पुस्तक से संबंधित विवाद से जुड़ी बात को सदन के बाहर भी कर सकते थे। यह सवाल भी अनुत्तरित है कि क्या ऐसा मध्यमार्ग निकालने की पहल लोकसभा अध्यक्ष या सत्तापक्ष की ओर से की गई? अतीत का अनुभव बताता है कि संवेदनशील और तल्ख मुद्दों पर दोनों पक्षों द्वारा लचीला रुख अपना कर ही सदन सुचारु रूप से चलाया जा सकता है। लोकसभा में राहुल गांधी को पुस्तक के अंश पढ़ने से रोकने के लिए तर्क दिया गया कि जो पुस्तक अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई, उसका हवाला संसदीय चर्चा में नहीं दिया जा सकता। अगले दिन धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का प्रधानमंत्री द्वारा शाम पांच बजे के लिए तय जवाब बिना ही हंगामे के बीच सदन स्थगित हो गया। इस दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कुछ पुस्तकों के हवाले से जिस तरह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चरित्र हनन करते हुए नेहरू परिवार पर प्रहार किए, उससे भी सत्तापक्ष और विपक्ष में तल्खी बढ़ी।

लोकसभा अध्यक्ष का यह रहस्योद्घाटन तो और भी गंभीर है कि उनकी सलाह पर ही प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए, क्योंकि उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती थी। यह सवाल भी अनुत्तरित है कि राज्यसभा के सभापति को आगाह करने समेत अनहोनी की साजिश रचने वाले सांसदों के विरुद्ध लोकसभा अध्यक्ष ने इस मामले में क्या कार्रवाई की? ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का अगले ही दिन जवाब दिया। ओम बिरला लोकसभा में जिस साजिश की बात कह रहे हैं, वह राज्यसभा में भी तो रची जा सकती थी? प्रधानमंत्री के जवाब का फोकस अभिभाषण के बिंदुओं तथा विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों से ज्यादा कांग्रेस और नेहरू परिवार की आलोचना पर केंद्रित रहना भी सवाल खड़े करता है। राजनीति में हिसाब बराबर करने की प्रवृत्ति पुरानी है, लेकिन आरोप-प्रत्यारोप का खेल संसद के बाहर खेला जाना चाहिए, उसके लिए संसदीय कार्यवाही को बाधित करना कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ती कटुता के मूल में भी एक-दूसरे के प्रति सम्मान और सहकार के बजाय अपमानजनक उपेक्षा भाव की मानसिकता ही जिम्मेदार है। सत्ता पर स्वयं की स्वाभाविक दावेदारी की मानसिकता से ग्रस्त कांग्रेस इस सच से मुंह मोड़े रहना चाहती है कि नरेन्द्र मोदी लगातार तीसरी बार बहुमत प्राप्त सरकार के प्रधानमंत्री हैं, जबकि उसे नेता-प्रतिपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए भी दस साल इंतजार करना पड़ा। बेशक भाजपा भी 'कांग्रेस मुक्त भारत' बनाने के अपने सोच से बाहर नहीं निकल पा रही, जबकि सच यह है कि 2014 में मात्र 44 लोकसभा सीटों पर सिमट गई कांग्रेस 2024 में 99 सीटों तक पहुंच चुकी है और तीन राज्यों में उसकी सरकार भी है।

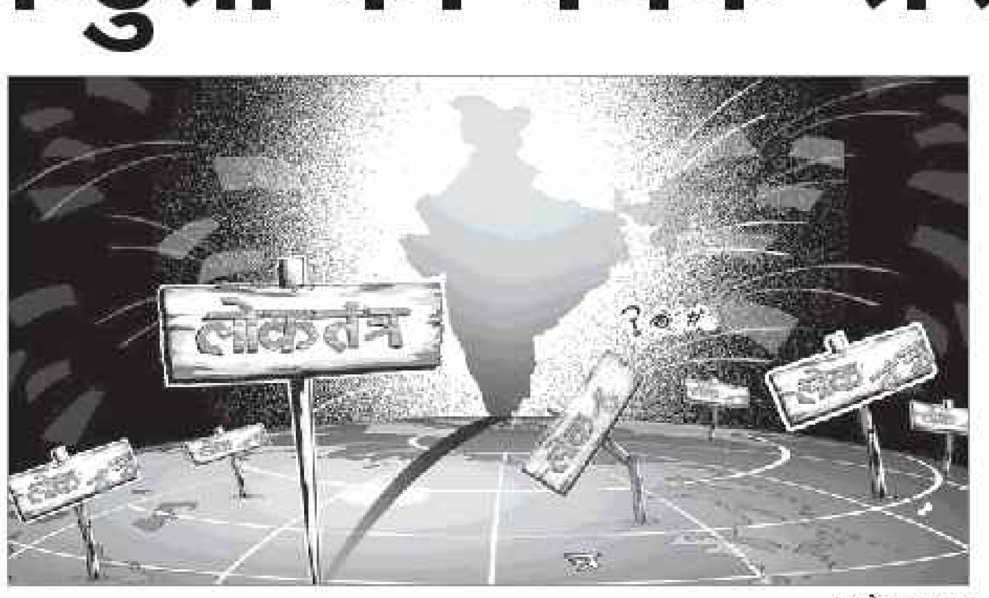

अवधेश राजपूत

राजग को शासक तो आइएनडीआइए को विपक्ष की भूमिका जनता ने ही सौंपी है, जिसे लोकतंत्र में जनार्दन कहा जाता है। बेशक ये भूमिकाएं स्थायी नहीं हैं। इसलिए जिस लोकतंत्र की दुहाई देते हुए दोनों पक्ष एक-दूसरे को कोसते हैं, उसका भी तकाजा है कि वे अपनी राजनीतिक कटुता में संसद को बंधक बनाने के बजाय परस्पर संवाद के जरिये देश हित में समन्वय से काम करने का सोच और कार्यशैली विकसित करें। दोनों ही पक्ष अगर राजनीतिक कटुता से मुक्त नहीं हो सकते, तो कम से कम उसे संसद के बाहर चुनावी मोर्चों पर ही जताने की परिपक्वता उन्हें दिखानी चाहिए। देश किसी भी दल या नेता से बड़ा है। तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था में तमाम चुनौतियों से देश को पार ले जाने की जिम्मेदारी सामूहिक है। इसलिए प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को सीधे संवाद और संपर्क से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति और समन्वय की राह निकालनी चाहिए, पर उसके लिए परस्पर सम्मान भाव पहली अनिवार्य शर्त है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

वैश्विक आकर्षण का केंद्र बनता भारत

डा. जयंतीलाल भंडारी

अमेरिका और ईयू से व्यापार समझौते का लाभ उठाने के लिए भारत को आर्थिक और ढांचागत सुधारों की गति बढ़ानी होगी

हाल में भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया। टैरिफ में यह बड़ी कमी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है। इस समझौते से जहां कई क्षेत्रों में भारत से अमेरिका को निर्यात बढ़ेगा, वहीं भारत में अमेरिकी निवेश में भी वृद्धि होगी। साथ ही दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई दिशा मिलेगी। वैश्विक कंपनियां चीन के विकल्प के रूप में भारत में निवेश बढ़ाएंगी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। इससे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनने की दिशा में और तेजी से बढ़ेगा। गत दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा भी कि अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ हुए व्यापार समझौते भारत की बढ़ती आर्थिक अहमियत के प्रतीक हैं। नई वैश्विक व्यवस्था भारत की ओर झुकती दिखाई दे रही है। पहले कहा जाता था कि भारत अवसर गंवा देता है, लेकिन अब दुनिया का मानना है कि यदि वे तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़े, तो महत्वपूर्ण अवसर खो देंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत का तेज आर्थिक विकास और महंगाई पर नियंत्रण एक दुर्लभ संयोजन है। मजबूत बुनियादी ढांचा, विशाल घरेलू बाजार, मध्यवर्ग की बढ़ती क्रयशक्ति, एमएसएमई की गति, ऊर्जा विकास, युवा शक्ति, डिजिटल प्रगति तथा मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र की ताकत ने भारत को दुनिया के लिए आकर्षक बना दिया है। इसी कारण विकसित देश भारत से द्विपक्षीय और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) कर रहे हैं।

भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क के अनुसार भारत मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, इथेनाल, तंबाकू, कुछ सब्जियों और मांस जैसे संवेदनशील कृषि एवं डेरी उत्पादों के मामले में पूरी तरह सुरक्षित है। यह समझौता भारत के टेक्सटाइल एवं परिधान, चमड़ा एवं फुटवियर, प्लास्टिक एवं रबर उत्पाद, आर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प और चुनिंदा मशीनरी जैसे क्षेत्रों को अमेरिकी बाजार में बड़े अवसर देगा। इसके अलावा जेनेरिक दवाओं, रत्न-हीरे और एयरक्राफ्ट पार्ट्स सहित कई उत्पादों के निर्यात को गति मिलेगी। विशेष रूप से एमएसएमई, किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डालर के अमेरिकी बाजार के द्वार खुलेंगे। निर्यात बढ़ने से महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार बढ़ेंगे। इस समझौते के तहत भारत अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों की बड़ी श्रृंखला पर टैरिफ घटाएगा या समाप्त करेगा तथा अगले पांच वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डालर के ऊर्जा उत्पाद, एयरक्राफ्ट एवं पार्ट्स, कीमती धातुएं, टेक्नोलाजी उत्पाद और कोकिंग कोल खरीदने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ता भरोसा ● प्रतीकात्मक

अमेरिका भारत के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बाजार है। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच 131.84 अरब डालर का व्यापार हुआ, जिसमें भारत का निर्यात 86.51 अरब डालर और आयात 45.33 अरब डालर रहा। वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत ने अमेरिका को 65.88 अरब डालर का निर्यात किया। 18 प्रतिशत टैरिफ भारत को चीन-प्लस-वन रणनीति के स्वाभाविक विकल्प के रूप में और मजबूत करता है। वर्तमान में अमेरिका ने ब्राजील पर 50 प्रतिशत, चीन पर 34 प्रतिशत, वियतनाम और बांग्लादेश पर 20 प्रतिशत तथा मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और थाइलैंड पर 19 प्रतिशत टैरिफ लगाया हुआ है। ऐसे में भारत-अमेरिका समझौता वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा।

पिछले दिनों हुआ भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इससे दो अरब लोगों का साझा बाजार बनेगा, जो वैश्विक जीडीपी के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करेगा। बीते वर्ष ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ हुए एफटीए का इस साल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होगा। साथ ही मारीशस, यूएई, आस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नार्वे और लिकटेंस्टाइन) के साथ लागू एफटीए के लाभ भी बढ़ेंगे। इस वर्ष पेरू, चिली, आसियान, मेक्सिको, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इजरायल और गल्फ कंट्रीज काउंसिल सहित अन्य देशों के साथ नए एफटीए हो सकते हैं। इन समझौतों का पूरा लाभ उठाने के लिए भारत को आर्थिक सुधारों और घरेलू ढांचागत बदलावों की गति बढ़ानी होगी। नियमों और नियामक संस्थाओं के कामकाज में सुधार, कर सुधारों को गहराई देना और जीएसटी को अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है। घरेलू कंपनियों को गुणवत्ता, तकनीक और कुशल मानव संसाधन पर ध्यान देना होगा। साथ ही प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, गैर-टैरिफ बाधाएं कम करने, सेवा क्षेत्र का लाभ उठाने, निर्यात विविधीकरण, कृषि सुरक्षा तथा पर्यावरण और श्रम मानकों के पालन पर विशेष ध्यान देना होगा।

उम्मीद है भारत-अमेरिका शीघ्र ही व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इससे 2030 तक दोनों के बीच 500 अरब डालर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। यह समझौता भारत के निर्यात और रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित हो सकता है तथा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

कर्म की कसौटी

महाभारत से एक बड़ी सीख मिलती है कि विजय केवल बाहुबल, अस्त्र-शस्त्र या सत्ता से नहीं होती, बल्कि सिद्धांत, धर्म और सत्य से होती है। सही और गलत का चुनाव ही मनुष्य का इतिहास में स्थान निर्धारित करता है। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे शक्तिशाली और आदरणीय योद्धाओं में से एक थे, किंतु इसके बावजूद वे गलत सिंहासन के साथ खड़े रहे। उन्होंने यह जानते हुए भी कि कौरव अधर्म के मार्ग पर हैं, हस्तिनापुर की सत्ता और अपनी प्रतिज्ञा को धर्म से ऊपर रख दिया। भीष्म का पतन इस बात का प्रतीक है कि जब शक्ति सिद्धांत से अलग हो जाती है, तो वह हार में बदल जाती है।

द्रोणाचार्य विद्या, ज्ञान और गुरु-परंपरा के प्रतीक थे, किंतु उनका ज्ञान भी उन्हें धर्म के मार्ग पर नहीं रख सका। पुत्र मोह और पक्षपात ने उनके विवेक को ढक लिया। उन्होंने यह जानते हुए भी कि दुर्योधन अन्याय कर रहा है, उसके पक्ष में युद्ध किया। द्रोणाचार्य का अंत यह दर्शाता है कि विद्वता तब तक अधूरी है, जब तक वह निष्पक्षता और सत्य से जुड़ी न हो। कर्ण के पास भी हर वह अवसर था कि वह सत्य का साथ चुने। परंतु उसने मित्रता और कृतज्ञता के नाम पर अधर्म का साथ दिया। उसने सत्य को पहचानने के बाद भी गलत का साथ नहीं छोड़ा।

महाभारत का संदेश यही है कि गलत के साथ खड़े रहकर कोई भी व्यक्ति सही नहीं बन सकता। चाहे वह कितना ही शक्तिशाली, ज्ञानी या वीर क्यों न हो। इतिहास कर्मों को देखता है। जो व्यक्ति अधर्म के पक्ष में खड़ा होता है, उसका नाम इतिहास में पराजितों की सूची में दर्ज होता है। इसलिए जीवन में तटस्थ रहना भी कई बार अधर्म का समर्थन बन जाता है। सही के साथ खड़े होने के लिए साहस चाहिए, त्याग चाहिए और कभी-कभी अपनों के विरुद्ध जाने का संकल्प भी चाहिए। अंततः विजय उसी की होती है, जो सिद्धांतों से समझौता नहीं करता।

समराज चौहान

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

उत्पादों की गुणवत्ता हो सुनिश्चित

'समझौते की रूपरेखा' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। इससे स्पष्ट होता है कि मार्च के मध्य तक भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भारतीय निर्यातकों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी भारत का अमेरिका को लगभग 86 अरब डालर का निर्यात और 40 अरब डालर का आयात होता है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार 44 अरब डालर मूल्य के भारतीय निर्यात पर अमेरिकी बाजार में शुल्क शून्य होगा, जबकि शेष 30 अरब डालर के निर्यात पर 18 प्रतिशत और 12 अरब डालर के निर्यात पर 50 प्रतिशत शुल्क लागू रहेगा, जो अन्य देशों पर भी समान रूप से लागू है। यूरोपीय बाजार भी भारतीय निर्यातकों के लिए खुल चुके हैं। हालांकि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किए बिना निर्यात में वृद्धि संभव नहीं होगी। समझौते का सकारात्मक पक्ष यह है कि कृषि और उससे जुड़े उत्पादों को इससे बाहर रखा गया है। फिर भी यह अस्पष्टता बनी हुई है कि भारत का रूस से कच्चे तेल का कारोबार बंद होगा या आंशिक रूप से जारी रहेगा, क्योंकि कठिन समय में रूस हमारा भरोसेमंद साझेदार रहा है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में द्विपक्षीय व्यापार समझौते से हमारे बहुपक्षीय संबंध प्रभावित नहीं होने चाहिए। यही कूटनीतिक सफलता और 'राष्ट्र प्रथम' का वास्तविक मानदंड है।

मुकेश कुमार मनन, पटना

विश्वविद्यालय समझें अपनी भूमिका

आज के दौर में विश्वविद्यालयों की भूमिका केवल डिग्री प्रदान करने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उन्हें समाज के बौद्धिक और नैतिक मार्गदर्शक के रूप में भी देखा जाता है। दुर्भाग्य से भारत के अधिकांश विश्वविद्यालय सामाजिक चुनौतियों से कटे हुए दिखाई देते हैं और अपनी सीमित शैक्षणिक दुनिया में सिमटते जा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालयों को शोध, नवाचार और सामाजिक जुड़ाव का केंद्र बनाने पर जोर देती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार 2024 तक देश में लगभग 1100 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, जिनमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 50 से अधिक है। इनमें से कई विश्वविद्यालय पिछड़े या दूरदराज जिलों में स्थापित किए गए ताकि क्षेत्रीय असमानता कम हो और स्थानीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, लेकिन बेहतर फैकल्टी और आधारभूत सुविधाओं की कमी इनके विकास में बड़ी बाधा बनी हुई है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 के आंकड़े बताते हैं कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात करीब 28.4 प्रतिशत है, जो विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। कई विश्वविद्यालयों में शिक्षक पद लंबे समय तक रिक्त रहते हैं, जिससे छात्र-शिक्षक अनुपात प्रभावित होता है और शिक्षा की गुणवत्ता गिरती है। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करने में कठोर नियम और प्रशासनिक बाधाएं बड़ी दिक्कत हैं। जब विश्वविद्यालय समाज से जुड़कर उसकी समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, तभी वे ज्ञान के वास्तविक केंद्र बन सकेंगे और भारत को वैश्विक शिक्षा मानचित्र पर सशक्त पहचान दिला पाएंगे।

–विभूति बुपक्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली

रसातल में जाती राजनीति

विपक्षी, विशेषकर कांग्रेस की राजनीति का स्तर बेहद गिर रहा है। लेकिन संसद के इस सत्र में तो गिरावट की हद पार हो चुकी है। मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन अब तो घोर नफरत, वैमनस्यता की राजनीति हो चुकी है। संविधान जेब में लेकर घूमने वाले राहुल गांधी बार-बार संवैधानिक तथा संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए लोकसभा स्पीकर के बार-बार टोकने के बाद भी एक अनछपी पुस्तक का हवाला देकर पीएम मोदी को निशाना बनाते रहे। उसके बाद तो दोनों सदनों में और संसदीय परिसर में जो हुआ, उसने लोकतांत्रिक और संसदीय मूल्यों को तार-तार कर दिया। इतना हंगामा किया कि पीएम को दो दिन लगातार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने नहीं दिया। दूसरे दिन तो पूरे देश ने टीवी पर देखा कि किस तरह कांग्रेस की महिला सांसद आक्रामक मुद्रा में प्रधानमंत्री की सीट के पास एकत्रित हो गईं। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि स्पीकर को यह कहना पड़ा कि किसी अनहोनी की संभावना देखते हुए उन्होंने ही प्रधानमंत्री को सदन में आने से मना किया। इससे अधिक दुखद कुछ नहीं हो सकता। गिरावट यही नहीं रुकी। स्पीकर ओम बिरला पर पक्षपात का न केवल आरोप लगाया, अपितु उनके चैंबर में जाकर कांग्रेस के सांसदों ने अभद्रता की। कांग्रेस और विपक्ष के ऐसे आचरण से अधिकांश देशवासी आहत हैं। सांसदों को अनुशासित करने के लिए, संसद को सख्त नीयम बनाने होंगे।

सीपी बंसल, दिल्ली

पोस्ट

ग्रीस के रक्षा मंत्री का यह बयान बहुत कुछ कहता है कि अतीत में भारत का साथ होना अच्छा तो माना जाता था, लेकिन आवश्यक नहीं था। जबकि अब भारत का साथ होना बहुत जरूरी हो गया है और उसके साथ मुक्त व्यापार समझौता बहुत कारगर रहेगा।

कादंबिनी शर्मा @SharmaKadambini

सूरजकुंड मेले में झूला टूटने की भयावह घटना से सबक सीखे जाने चाहिए। सरकार को ऐसे झूलों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए, जिनमें न तो सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम होते हैं और न ही वे नियमों का पालन करते हैं। सपन पांडेय @SapanPandey0

टी-20 विश्व कप की शुरुआत बहुत ही रोमांचक हुई है। अमेरिका पहले ही मैच में उलटफेर कर सकता था। पाकिस्तान भी नीदरलैंड से हारते-हारते बचा और इंग्लैंड नेपाल से। छोटे प्रारूप में सनसनी की बहुत गुंजाइश रहती है। अमेरिका के विरुद्ध भारत के नामी बल्लेबाज सस्ते में निपट गए और सूर्यकुमार यादव का कैच न छूटा होता तो लेने के देने भी पड़ सकते थे।

सुशील दोशी @RealSushilDoshi

जनपथ

मियां-असमिया में छिड़ी बड़ी भयंकर रार,
वचन हिमंता के सुने मचती चीख-पुकार।
मचती चीख-पुकार अश्रु पोछें ओवैसी,
डूबी बदरुद्दीन मियां की दिखती भैंसी।
करवाओ घुसपैठ न ढूंढो अपनी कमियां,
जब एक्शन हो जाय करो तब मियां-असमिया!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए, डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 206

हां 92% नहीं 8%
क्या जाम में फंसे रेंगते शहर तेज आर्थिक विकास के लिए चुनौती बन गए हैं?

हां 72% नहीं 28%
क्या सार्वजनिक परिवहन तंत्र की कमजोरी शहरों को बीमार बना रही है?

मुद्दा से संबंधित अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया mudda@jagran.com पर भेज सकते हैं।

आर्थिक विकास पर भारी रेंगते शहर

दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहर हों या लखनऊ जैसे टियर-2 शहर, घंटों जाम और सुस्त ट्रैफिक इन शहरों की साझा पहचान बन गया है। छोटे शहरों में भी हालात बहुत अलग नहीं हैं। लोग रुके हुए शहर में सुस्त गति से जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। हाल में जारी किए गए इकोनामिक सर्वे में कहा गया है कि परिवहन शहरों की रक्तधारा, रीढ़ और मांसपेशियां है, जो लोगों, वस्तुओं और विचारों के प्रवाह को आगे बढ़ाता है। अगर यह तंत्र कमजोर होता है तो ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और उत्पादकता में गिरावट शहरों की नियति बन जाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार, दिल्ली में एक अकुशल कामगार जाम की वजह से सालाना 19,600 रुपये का नुकसान उठाता है। कुशल कामगार के लिए यह नुकसान बढ़कर सालाना 26,000 रुपये हो जाता है। एक और अध्ययन बताता है कि देश के प्रमुख चार मेट्रो शहर जाम की वजह से सालाना अरबों डालर गंवा रहे हैं। अगर इस अनुमान को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए तो आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे देश की आर्थिक वृद्धि दर किस हद तक प्रभावित हो रही है। शहरों में गतिशीलता की समस्या और इससे देश को हो रहे नुकसान की पड़ताल कर रहे हैं **महेन्द्र सिंह**...

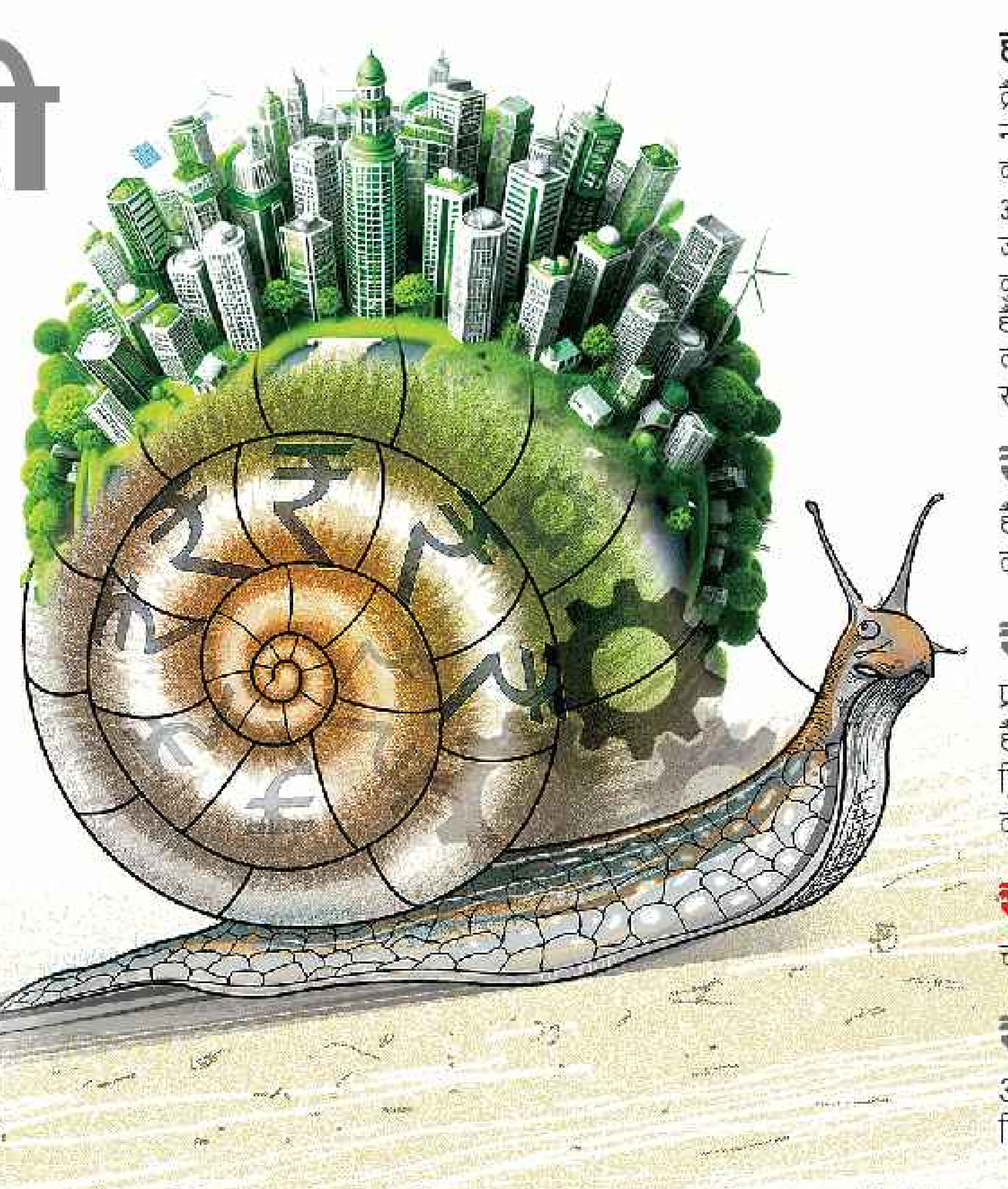

हजारों करोड़ की आर्थिक चपत

ट्रैफिक जाम का असर सिर्फ देर से आफिस पहुंचने तक सीमित नहीं है। इससे ईंधन की बर्बादी होती है, प्रदूषण बढ़ता है और लोगों की सेहत पर भी असर पड़ता है। इकोनामिक सर्वे में बताए गए अलग-अलग अध्ययनों के मुताबिक, एक अकुशल कामगार को जाम की वजह से हर साल हजारों रुपये का नुकसान होता है, वहीं कुशल और उच्च कुशल कामगार का नुकसान इससे भी ज्यादा है। बेंगलुरु में ही एक अध्ययन के अनुसार, ट्रैफिक जाम के कारण लाखों घंटे का उत्पादन खत्म हो जाता है, जिसकी कीमत अरबों रुपये में बैठती है।

₹19,600 का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है दिल्ली में अकुशल कामगार को ट्रैफिक जाम के कारण प्रतिवर्ष

₹23,800 प्रतिवर्ष नुकसान उठाता है कुशल कामगार दिल्ली में ट्रैफिक जाम की वजह से

7.07 लाख उत्पादक घंटों का नुकसान उठा रहा है बेंगलुरु शहर प्रतिवर्ष, जाम के कारण लोगों के देर से आफिस पहुंचने के चलते

₹1,00,000 करोड़ से अधिक की आर्थिक चपत झेल रहा है बेंगलुरु उत्पादक घंटों की बरबादी से

₹2,00,000 करोड़ से अधिक गंवा रहे हैं चार मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता

औसत यात्रा समय के लिहाज से 10 सबसे खराब शहर

शहर	रफ्तार भूले शहर: औसत यात्रा समय प्रति 10 किलोमीटर पर	यात्रा के दौरान समय का नुकसान: पीक आवर में समय का नुकसान, प्रति वर्ष
कोलकाता	34 मिनट, 33 सेकेंड	110 घंटे
बेंगलुरु	34 मिनट, 10 सेकेंड	117 घंटे
पुणे	33 मिनट, 22 सेकेंड	108 घंटे
हैदराबाद	31 मिनट, 30 सेकेंड	85 घंटे
चेन्नई	30 मिनट, 20 सेकेंड	94 घंटे
मुंबई	29 मिनट, 26 सेकेंड	103 घंटे
अहमदाबाद	29 मिनट, 3 सेकेंड	73 घंटे
एर्नाकुलम	28 मिनट, 30 सेकेंड	88 घंटे
जयपुर	28 मिनट, 28 सेकेंड	83 घंटे
नई दिल्ली	23 मिनट, 24 सेकेंड	76 घंटे

(स्रोत: टामटाम, आंकड़े वर्ष 2024 के हैं)

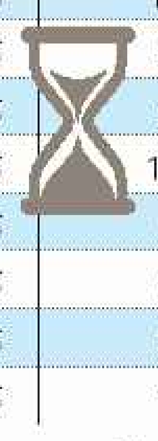

30% ट्रैफिक में गिरावट आई सिंगापुर में तीन दशक तक प्राइसिंग लागू रहने के बाद

40 कार है भारत में प्रति 1,000 लोगों पर

67% यात्री परिवहन के लिए निजी वाहनों पर है निर्भर टियर 2 शहरों में

1975 में सबसे पहले सिंगापुर ने लागू की कंजेशन प्राइसिंग

शहर तेज हुए या सुस्त

प्रति 10 किलोमीटर पर यात्रा के समय में बदलाव 2023 की तुलना में (स्रोत: टामटाम)

शहर	गिरावट / बढ़ोतरी
पुणे	-60 सेकेंड
अहमदाबाद	-30
मुंबई	-20
कोलकाता	10
चेन्नई	10
नई दिल्ली	10
जयपुर	20
बेंगलुरु	50
एर्नाकुलम	60 सेकेंड

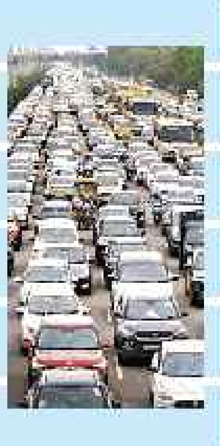

तो धीमी हो जाएगी ग्रोथ की रफ्तार

अगर ट्रैफिक जाम को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, तो आने वाले सालों में आर्थिक नुकसान और बढ़ेगा। सर्वे की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं, देश की आर्थिक रीढ़ हैं। अगर यही रीढ़ ट्रैफिक जाम में जकड़ी रही, तो भारत की ग्रोथ की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है।

निजी गाड़ियों पर बढ़ती निर्भरता

इस समस्या की जड़ में एक बड़ी वजह है निजी गाड़ियों पर बढ़ती निर्भरता। शहरों की सड़कें लोगों की आवाजाही के बजाय गाड़ियों की पार्किंग बनती जा रही हैं। एक कार में अक्सर एक या दो लोग ही होते हैं, लेकिन वह सड़क की उतनी ही जगह घेरती है जितनी एक बस या कई दोपहिया वाहन। नतीजा यह कि सड़क की क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता और जाम बढ़ता जाता है।

मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है समाधान

इकोनामिक सर्वे साफ कहता है कि समाधान सड़कों को चौड़ा करने में नहीं, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने में है। मेट्रो, बस, ई-बस, पैदल चलने और साइकिल जैसे विकल्प अगर सुरक्षित, सस्ते और भरोसेमंद हों, तो लोग खुद-ब-खुद निजी गाड़ियों से दूरी बनाएंगे। बेंगलुरु, दिल्ली जैसे शहरों में मेट्रो का विस्तार हुआ है, लेकिन बसों और आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी की अब भी भारी कमी है।

60 बसें होनी चाहिए प्रति एक लाख लोगों पर केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय के अनुसार

47,650 बसें ही सेवाएं दे रही हैं पूरे देश के शहरों में

60% बसें सिर्फ नौ बड़े शहरों में चल रहीं हैं देश में वर्तमान समय में

कंजेशन प्राइसिंग से मिलेगी मदद

शहरी भारतीय हर साल ट्रैफिक में बैठे-बैठे सैकड़ों घंटे बर्बाद कर देते हैं। यही समय वे काम, आराम या परिवार को दे सकते हैं। ट्रैफिक संकट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी है। जिन शहरों में कभी हवा साफ मानी जाती थी, वहां भी अब प्रदूषण से होने वाली मौतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कंजेशन प्राइसिंग जैसे बड़े सुधारों के बिना ये शहर पूरी तरह से ठप हो सकते हैं। हाल में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में भी जाम की समस्या से निपटने के लिए कंजेशन प्राइसिंग लागू करने का सुझाव दिया गया है।

क्या है कंजेशन प्राइसिंग

दरअसल कंजेशन प्राइसिंग जाम वाली सड़कों पर चलने का शुल्क है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इसका मूल विचार भीड़भाड़ से उत्पन्न बाहरी लागतों जैसे समय की हानि, प्रदूषण और ईंधन की बर्बादी को यूजर द्वारा ही वहन करना है ताकि सबसे अधिक भीड़भाड़ वाली सड़कों का उपयोग करने वाले यात्रा की वास्तविक कीमत चुकाएं।

बेहतर शहरी जीवन के लिए हो प्लानिंग

रितेश वैद्य, पूर्व निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स

सफल शहरों का अनुभव बताता है कि जब सड़कों को नागरिकों के लिए बनाया जाता है तो न सिर्फ जाम और प्रदूषण घटता है बल्कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं और जीवन बेहतर होता है। शहरी गतिशीलता का लक्ष्य गाड़ियों की रफ्तार नहीं, बेहतर जीवन होना चाहिए।

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगर हों या लखनऊ, नोएडा और जयपुर जैसे उभरते टियर-2 शहर, घंटों का ट्रैफिक जाम, बढ़ता प्रदूषण और सुस्त आवागमन अब शहरी भारत की साझा पहचान बनते जा रहे हैं। छोटे शहरों में भी तेजी से इसी राह पर बढ़ रहे हैं। यह सीधे तौर पर श्रम उत्पादकता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और भारत की पांच ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की गति को प्रभावित कर रहा है। रेंगते शहर अब केवल शहरी प्रबंधन की विफलता नहीं, बल्कि भारत की विकास महत्वाकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों के सामने खड़ी एक गंभीर संरचनात्मक चुनौती बन चुके हैं।

हालिया केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाकर इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास को आधार बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें सड़क, रेल, शहरी कनेक्टिविटी और लाजिस्टिक्स को शामिल किया गया है। इसके बावजूद जमीनी सच्चाई यह है कि यह निवेश अब भी अलग-अलग परियोजनाओं में बंटा हुआ दिखाई देता है, न कि एकीकृत गतिशीलता प्रणालियों में। मेट्रो को अक्सर अपने आप में समाधान मान लिया गया, जबकि उससे जुड़ी बस सेवाएं, पैदल मार्ग, साइकिल नेटवर्क और आखिरी गंतव्य तक कनेक्टिविटी पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जितना देना चाहिए।

शहरी परिवहन विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि शहर का परिवहन तंत्र मानव शरीर की तरह होता है। दिल के साथ धमनियों और कोशिकाओं का नेटवर्क भी उतना ही जरूरी है। भारत के कई शहरों में हमने मेट्रो के रूप में 'दिल' तो बना दिया, लेकिन उसे चलाने वाला सहायक नेटवर्क नहीं।

एक और आम भ्रम यह है कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) शहरी गतिशीलता की समस्या का समाधान हैं। निस्संदेह, ईवी वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन वे ट्रैफिक जाम की समस्या को अपने आप हल नहीं करते। सड़क पर खड़ी इलेक्ट्रिक कार भी उतनी ही जगह घेरती है, जितनी पेट्रोल या डीजल से चलने वाली कार। यदि शहरों की योजना, भूमि-उपयोग और यात्रा पैटर्न वही बना रहे, तो केवल ईंधन बदल देने से जाम, समय की बर्बादी और उत्पादकता का नुकसान कम नहीं होगा। शहरी गतिशीलता का वास्तविक समाधान ईंधन को 'स्वच्छ' बनाने में नहीं, बल्कि यात्रा की जरूरत को कम करने, साझा और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने और शहरों की योजना पर नए सिरे से सोचने में छिपा है।

इस संकट की जड़ शहरों के फैलाव और भूमि उपयोग के तरीके में भी छिपी है। जब आवास, रोजगार, शिक्षा और सेवाएं एक-दूसरे से दूर-दूर बसाई जाती हैं, तो लंबी यात्राएं अनिवार्य हो जाती हैं और निजी वाहनों पर निर्भरता बढ़ती है। इसके उलट, यदि शहरों की योजना 'ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट' (टीओडी) के सोच के साथ बनाई जाएं, जहां रोजमर्रा की जरूरतें सार्वजनिक परिवहन के आसपास केंद्रित हों, तो यात्रा की दूरी और जाम दोनों स्वाभाविक रूप से कम हो सकते हैं।

यह विडंबना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति लगभग दो दशक पहले ही कह चुकी थी कि शहरों को निजी वाहनों से हटाकर सार्वजनिक परिवहन और गैर-मोटर चालित साधनों की ओर बढ़ना होगा और परिवहन को भूमि उपयोग योजना के साथ जोड़ना होगा। लेकिन नीति और व्यवहार के बीच की खाई बनी रही। अधिकांश शहरों में परिवहन से जुड़े निर्णय कई एजेंसियों में बंटे हुए हैं, जिनके बीच समन्वय का अभाव है। भारत को ऐसे एकीकृत परिवहन तंत्र की जरूरत है जो पहुंच, समावेशन और कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दे। समावेशन का अर्थ है कि परिवहन व्यवस्था समाज के सबसे कमजोर वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए भी समान रूप से सुलभ हो। शहरी गतिशीलता की चर्चा में एक और अहम पहलू अक्सर हाशिये पर चला जाता है। इसमें गैर-मोटर चालित परिवहन, यानी पैदल चलना और साइकिल शामिल है। हकीकत यह है कि शहरों में अधिकांश यात्राएं पैदल चलने से ही शुरू और समाप्त होती हैं। यदि फुटपाथ टूटे हुए हों, सड़कों को पार करना असुरक्षित हो और सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच पैदल संभव न हो, तो कोई भी मेट्रो, बस या ई-वाहन प्रभावी नहीं हो सकता। यही हमारी व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी है।

आपकी आवाज

भारत के शहर पहले से लोगों को जीवन के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करने में संघर्ष कर रहे हैं। ऊपर से ट्रैफिक जाम की समस्या लोगों के जीवन की चुनौतियों को और गंभीर बना रही है। लोग न सिर्फ आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं बल्कि प्रदूषण की वजह से उनकी सेहत भी खतरे में हैं। **नीरज वर्मा**

नीतिगत स्तर पर बड़ी बातें भले होती हैं लेकिन देश के ज्यादातर शहरों में सार्वजनिक परिवहन का तंत्र बेहद कमजोर है। आप इसके भरोसे समय पर आफिस या अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे में लोग निजी वाहनों का सहारा ले रहे हैं और सड़कों पर निजी वाहनों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों को परिवहन पर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ रहा है। यह देश के संसाधनों की बरबादी है। बसों की संख्या बढ़ा कर उनका प्रभावी परिचालन सुनिश्चित करके जाम की समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन सरकार के दावों से इतर इस दिशा में खास प्रयास नहीं दिखता है। **पवन पासवान**

विकसित देशों के शहरों में अगर इस तरह की समस्या नहीं है तो इसके लिए उनका बेहतर सार्वजनिक परिवहन तंत्र जिम्मेदार है। इसके अलावा चीन जैसे देशों में प्रदूषण से निपटने के लिए निजी वाहनों पर भी अंकुश लगाया गया है। भारत में उद्योग जगत की लाबी इतनी प्रभावी है कि निजी वाहनों पर अंकुश लगाने की नीति बनाना बेहद मुश्किल है क्योंकि इससे वाहन निर्माता कंपनियों को नुकसान होगा। समाधान मुश्किल है। **ओम तिवारी**

रोड नेटवर्क समस्या का हल नहीं

अनुमिता चौधरी, कार्यकारी निदेशक, सेंटर फार साइंस एंड एनवायरनमेंट

नीति निर्माताओं का सोच है कि हम रोड नेटवर्क का विस्तार करके जाम की समस्या से निपट सकते हैं लेकिन यह सोच गलत साबित हो चुका है। जाम की समस्या का समाधान एक मजबूत सार्वजनिक परिवहन में ही है, जो आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करे।

पूरे शहरी जीवन पर ट्रैफिक जाम का जो प्रभाव है उसे समझना बहुत जरूरी है। इसका एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव यह है कि गाड़ियां बहुत धीमी गति से चलती हैं और लोगों को बार बार इंजन स्टार्ट और बंद करना पड़ता है, इससे गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है। अगर कोई जाम वाले रूट पर गाड़ी चलाता है तो उसका अपना जहरीले प्रदूषण से संपर्क कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा कई शोध यह बताते हैं कि गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण रास्ते से करीब 500 मीटर की रेंज में बहुत अधिक होता है।

जब इसके प्रभाव का आकलन दिल्ली में रहने वाले लोगों पर किया गया तो पता चला यहां की करीब 55 से 60 प्रतिशत आबादी इस खतरनाक जोन में रहती है। दूसरा नकारात्मक प्रभाव समय की बरबादी का है। अगर जाम की वजह से हमें अपने गंतव्य पर पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लग रहा तो इससे बड़े पैमाने पर उत्पादकता का नुकसान हो रहा है। तीसरा है ईंधन का नुकसान। जाम में धीरे-धीरे गाड़ियां चलने से ईंधन बहुत बरबाद होता है। यह हमारी ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करता है। सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसका मुख्य कारण है निजी गाड़ियों पर निर्भरता बढ़ना। अगर आप देखें कि हर शहर में बसें और पैदल चलने के साधनों की बहुत कमी है। लोगों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में आपकी निर्भरता निजी वाहन पर बढ़ेगी। इससे लोगों का ट्रांसपोर्ट पर खर्चा भी लगातार बढ़ रहा है। अगर गाड़ी एक व्यक्ति को लेकर जा रही है तो सड़कों का प्रभावी इस्तेमाल नहीं हो पता है। अगर इसकी जगह लोग बसों से सफर करें तो एक बस में 60 लोग आ सकते हैं। इस तरह से एक बस 60 गाड़ियां सड़कों से कम कर सकती है। इस तरीके से सड़कों का प्रभावी इस्तेमाल हो सकता है। अगर दिल्ली की बात करें तो परिवहन को लेकर नीतियां बनाने वाले समझते हैं कि सड़कों पर गाड़ियां तो बढ़ेंगी। ऐसे में और सड़कें बनानी पड़ेंगी, सड़कों को चौड़ा करना पड़ेगा और फ्लाईओवर बनाएंगे तो जाम कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिल्ली के पूरे भौगोलिक क्षेत्र को देखें तो यहां कुल 1400 वर्ग किलोमीटर जमीन और यहां पहले से करीब 23 प्रतिशत जमीन पर सड़कें और फ्लाईओवर बन चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा फ्लाईओवर दिल्ली में हैं। इसके बावजूद दिल्ली में गाड़ियों की भीड़ के साथ जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। इसका मतलब हुआ कि आप रोड नेटवर्क को बढ़ा कर और सड़कों को चौड़ा करके जाम की समस्या को खत्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि गाड़ियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। आपको कहीं न कहीं निजी गाड़ियों की संख्या पर अंकुश लगाना ही पड़ेगा और मजबूत सार्वजनिक परिवहन तंत्र के जरिये ही ऐसा किया जा सकता है। लोग अगर अपने घर से निकल कर कार्यालय जाते हैं तो उनको उनके घर के पास से ही आफिस तक बस या मेट्रो की सुविधा मिलनी चाहिए।

'मलेशिया के साथ रणनीतिक विश्वास से आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेंगे'

मोदी बोले- दोनों पक्ष हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति व स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध, मलेशिया में महावाणिज्य दूतावास खोलने का किया एलान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: मलेशिया दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने समकक्ष अनवर इब्राहिम के साथ मीडिया संबोधन में कहा कि हम रणनीतिक विश्वास के माध्यम से आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। भारत-मलेशिया समुद्री पड़ोसी हैं और सदियों से हमारे गहरे सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, डिजिटल इकोनमी, बायोटेक व आइटी में निवेश बढ़ा है। सुरक्षा क्षेत्र में हम आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई, खुफिया जानकारी साझा करने और समुद्री सुरक्षा के साथ रक्षा सहयोग को भी व्यापक बनाएंगे।

एआइ और डिजिटल टेक्नोलाजी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा साझेदारी को भी आगे बढ़ाएंगे। यहां हुई सीईओ फोरम ने व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोले हैं। मोदी ने मलाया विश्वविद्यालय में थिरुवल्लुवर चेयर स्थापित करने और मलेशिया में भारत का एक महावाणिज्य दूतावास स्थापित करने की घोषणा कर कहा कि मलेशिया में भारत के कामगारों के संरक्षण के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौता, पर्यटन के लिए मुफ्त ई-वीजा और यूपीआइ का मलेशिया में लागू होना दोनों देशों के लोगों के जीवन को सरल करेंगे। हिंद-प्रशांत क्षेत्र को विश्व का उभरता हुआ ग्रोथ इंजन बताते हुए मोदी ने कहा कि हम आसियान के साथ पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। मलेशिया जैसे मित्र देशों के सहयोग से भारत आसियान से अपने संबंधों को और व्यापक बनाएगा। भारत-मलेशिया रिश्तों के लिए इब्राहिम की प्रतिबद्धता की प्रशंसा कर मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हमने चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में आपसी मुद्राओं (रुपये और रिंगिट) के उपयोग को बढ़ावा देने की कोशिशों की सराहना की। इब्राहिम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए मलेशिया के समर्थन की बात दोहराई।

मोदी ने बताया, पीएम इब्राहिम एमजीआर के बड़े प्रशंसक: मोदी ने रविवार को मलेशिया के चार प्रमुख उद्योगपतियों से बातचीत की। उन्होंने मलेशिया के भारतीय मूल के मंत्रियों, सांसदों और सीनेटरों से भी मुलाकात की। मोदी ने बताया कि प्रधानमंत्री इब्राहिम एमजीआर के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उनके सम्मान में आयोजित भोज में भी एमजीआर की फिल्म का एक गीत प्रस्तुत किया गया।

जातीय भेदभाव के खात्मे तक लागू रहे आरक्षण व्यवस्था : भागवत

राज्य ब्यूरो, मुंबई: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सेवानिवृत्ति की आयु को भी स्पष्ट करते हुए कहा कि वैसे तो 75 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को बिना कोई दायित्व लिए काम करना चाहिए। 75 वर्ष का होने के बाद मैंने भी पद छोड़ने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन आरएसएस ने यह कहकर सेवानिवृत्त नहीं किया कि अभी तो आप स्वस्थ हैं। घूम रहे हैं। फिर पद छोड़ने की जरूरत क्या है। संगठन का निर्देश मिलते ही मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। आरक्षण पर संघ की स्थिति स्पष्ट करते हुए भागवत ने कहा कि जब तक जातीय भेदभाव की भावना जाती नहीं, तब तक आरक्षण व्यवस्था चालू रहनी चाहिए।

देश में आबादी के बढ़ते असंतुलन पर भागवत ने हर परिवार में तीन बच्चों का समर्थन करते हुए कहा कि देश में हो रही घुसपैठ एवं मतांतरण भी जनसंख्या असंतुलन का बड़ा कारण बन रहे हैं।

संघ प्रमुख ने मेरी गलतफहमियों और भ्रम को दूर किया : अदनान सामी

मुंबई, आइएएनएस : प्रसिद्ध गायक अदनान सामी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह के दौरान भागवत से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि संघ प्रमुख ने उनके कई भ्रम और गलतफहमियों को दूर किया। रविवार को उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर भागवत के साथ तस्वीरों का एक कोलाज साझा किया। संघ की व्याख्यानमाला में शामिल होने के बाद फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर ने मोहन भागवत के भाषण को प्रेरणादायक बताया।

यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद संघ के अच्छे दिन आ गए हैं, भागवत ने कहा कि इसका उल्टा हुआ है। राम जन्मभूमि आंदोलन संघ ने शुरू किया, जिसने उसमें साथ दिया वह फायदे में रहा।

केंद्र व राज्य सरकारों को बढ़ते वन अग्निकांडों पर एनजीटी का नोटिस

नई दिल्ली, आइएएनएस : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बढ़ते वन अग्निकांडों के समाधान के लिए व्यापक दिशा-निर्देशों की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र, राज्य सरकारों और कई वैधानिक प्राधिकरणों को नोटिस जारी किए हैं। पीठ ने हिमालय और पश्चिमी घाट जैसे पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में 'तेजी से और चिंताजनक' वृद्धि को उजागर करने वाली मूल याचिका की सुनवाई की। याचिकाकर्ता को याचिका की प्रतियां देने व अगली सुनवाई की तारीख से एक सप्ताह पहले हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।

विशेषज्ञ सदस्य डा. ए. सेंथिल वेल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को समयबद्ध स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए निर्देश देने की मांग की है।

उत्तराखंड में 2022 के बाद दिखा हिम तेंदुआ, स्नो काक भी मौजूद

पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में कैमरे में कैद स्नो काक • सौ. जयेंद्र सिंह फिरमाल

संसू, जागरण • धारचूला (पिथौरागढ़) : चीन व नेपाल से लगी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की उच्च हिमालयी दारमा घाटी में चार साल बाद फिर हिम तेंदुआ (स्नो लैपर्ड) नजर आया है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में वन्यजीव व पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही दारमा घाटी के स्थानीय युवाओं की टीम हिडेन हिमालयाज आफ उत्तराखंड ने गत 28 जनवरी को हिम तेंदुए को अपने कैमरे में कैद किया है। साथ ही दुर्लभ स्नो काक की फोटो लेने में भी टीम को सफलता मिली है।

टीम हिडेन हिमालयाज आफ उत्तराखंड पिछले सात वर्षों से प्रकृति व वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है। दारमा-व्यास घाटी क्षेत्र में विषम भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए टीम हिम तेंदुआ समेत अन्य दुर्लभ वन्यजीवों के संरक्षण का प्रयास कर रही है। टीम के जयेंद्र सिंह फिरमाल ने बताया कि इससे पहले दो जनवरी 2022 को हिम तेंदुए को कैमरे में कैद किया गया था।

कल्पमेधा

सृजनशीलता इस्तेमाल करने से कम नहीं होती। इसका जितना इस्तेमाल किया जाएगा, उतना ही यह बढ़ती जाती है।

– माया एंजेलो

सहयोग के मोर्चे

पिछले करीब एक वर्ष से गहन विचार-विमर्श के बाद भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर आखिरकार द्विपक्षीय सहमति बन गई है। दोनों देशों की ओर से शनिवार को इसका एलान किया गया। समझौते के नियम-शर्तों के तहत अमेरिका, भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को घटाकर अठारह फीसद करेगा। वहीं, भारत की ओर से अमेरिका की सभी औद्योगिक वस्तुओं और खाद्य एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला पर आयात शुल्क समाप्त या कम किया जाएगा। निश्चित रूप से यह समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन नफा-नुकसान का पलड़ा किस ओर भारी रहेगा, इसको लेकर अलग-अलग विश्लेषण सामने आए हैं। ऐसे में कुछ आशंकाएं और सवाल भी उठ रहे हैं कि इस समझौते को आकार देने में अड़चन कहां थी और अब ऐसा क्या हुआ कि दोनों पक्ष इसके लिए राजी हो गए। हालांकि, इस मामले में भारतीय सत्तापक्ष की ओर से स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन विपक्ष इससे सहमत नहीं है।

भारत और अमेरिका ने पिछले वर्ष फरवरी में प्रस्तावित व्यापार समझौते पर पहले चरण की बातचीत शुरू की थी। कई दौर की वार्ता के बाद भी दोनों पक्षों के बीच कुछ मसलों पर आम सहमति नहीं बन पाई, जिनमें भारतीय कृषि और डेयरी बाजार में अमेरिका की पहुंच को विस्तार देने का मुद्दा भी शामिल था। दरअसल, अमेरिका शुरू से यह मांग करता रहा है कि भारतीय कृषि एवं डेयरी बाजार को उसके लिए पूरी तरह खोल दिया जाए। जबकि भारत इस मांग को खारिज करता रहा है। अब इस समझौते की जिस रूपरेखा पर सहमति बनी है, उसके मुताबिक अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर भारत आयात शुल्क समाप्त या कम करेगा। इससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि भारत ने इस मसले पर उदार रुख अपनाकर अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। माना जा रहा है कि समझौते के लागू होने से भारतीय बाजार में अमेरिका के कृषि उत्पादों की आवक बढ़ेगी, जिसका असर देश के किसानों पर पड़ सकता है। हालांकि, सरकार का दावा है कि देश के किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं और इस समझौते से उन्हें भी लाभ होगा।

व्यापार समझौते की शर्तों में यह बात भी शामिल है कि भारत अगले पांच वर्ष में 500 अरब डालर के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान एवं उसके कलपुर्जे, कीमती धातु, प्रौद्योगिकी उत्पाद और कोयला खरीदेगा। साथ ही रूस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल खरीद बंद करनी होगी। यानी समझौते का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत इन शर्तों को पूरा कर पाता है या नहीं। इसमें दोराय नहीं कि भारतीय वस्तुओं का निर्यात, जो अमेरिकी शुल्क की वजह से प्रभावित हुआ था, वह फिर से पटरी लौट आएगा। सरकार का कहना है कि इससे तीस हजार अरब अमेरिकी डालर का बाजार खुलेगा, जो भारतीय निर्यात को नई दिशा देगा। सवाल है कि क्या अमेरिका से आयात और निर्यात के बीच संतुलन का ध्यान रखा गया है? विपक्ष का आरोप है कि इस समझौते से भारत के मुकाबले अमेरिका को ज्यादा फायदा होगा। वहीं सत्तापक्ष की दलील है कि अमेरिका के कुछ कृषि उत्पादों को कोटा-आधारित शुल्क रियायत दी जाएगी, जिसका भारतीय किसानों की आजीविका पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल, समझौते के नफा-नुकसान का वास्तविक आकलन तभी हो पाएगा, जब कुछ दिनों में द्विपक्षीय कारोबार के आंकड़े सामने आएंगे।

जानलेवा लापरवाही

दिल्ली के जनकपुरी इलाके में खुले गड्ढे में गिर कर एक मोटरसाइकिल सवार की मौत की घटना ने फिर यही साबित किया है कि सरकार के संबंधित महकमे किस कदर संवेदनहीन और गैरजिम्मेदार हैं। इस बात की कोई फिक्र नहीं दिखती कि अधिकारियों की लापरवाही से किसी की जान तक चली जा रही है। गौरतलब है कि जनकपुरी इलाके में डिस्ट्रिक सेंटर के नजदीक सीवर पाइपलाइन परियोजना के लिए करीब पंद्रह फुट गहरा गड्ढा खोदा गया था, जो खुला था। गुरुवार रात काम के बाद घर लौटते हुए एक पच्चीस वर्षीय युवक उसी गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई। उसके परिजन रात भर उसे खोजते रहे, लेकिन उन्हें सुबह घटना की जानकारी मिली। जबकि खबरों के मुताबिक, घटना की जानकारी एक उप-ठेकेदार को रात में मिल गई थी, मगर उसने न तो पुलिस को बताना जरूरी समझा, न ही समय पर आपातकालीन सेवा को सूचित किया। घटना के तूल पकड़ लेने के बाद दिल्ली जल बोर्ड के तीन इंजीनियरों को निलंबित करने और उप-ठेकेदार को गिरफ्तार करने के अलावा गैरइरादतन हत्या की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मगर अधिकारियों की जिस जानलेवा लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई, वह कब तक एक रिवायत की तरह बनी रहेगी।

सड़कों के किनारे खुले गड्ढे या मैनहोल में किसी के गिर जाने से बुरी तरह घायल होने या फिर मौत की यह कोई पहली घटना नहीं है। विचित्र यह है कि जो मामले सुर्खियों में आ जाते हैं, उन पर सरकार कार्रवाई करती दिखती है, मगर थोड़े ही दिनों बाद फिर हर तरफ लापरवाही का आलम छाया दिखता है। सीवर के लिए पाइप लाइन या फिर किसी अन्य कार्य की वजह से बड़े-बड़े गड्ढे खोद तो दिए जाते हैं, लेकिन वहां कोई भी सुरक्षा घेरा और खतरे का संकेतक लगाने की जरूरत नहीं समझी जाती। सिर्फ इसी लापरवाही की वजह से अक्सर सड़क किनारे खुले नाले, गड्ढे या मैनहोल में गिर कर किसी की मौत हो जाती है। सवाल है कि इस तरह की बदस्तूर लापरवाहियों की वजह से होने वाली मौत को हत्या की श्रेणी में क्यों नहीं माना जा सकता। अफसोसनाक यह है कि ऐसी घटनाओं के बावजूद संबंधित महकमे और उनके अधिकारी कोई सबक लेने को तैयार नहीं दिखते।

विकेंद्रित विकास की समावेशी राह

हम 'नारंगी अर्थव्यवस्था' से देश के विकास की बात करते हैं, तो हम एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे होते हैं जो दुनिया का कारखाना बनने की बजाय विश्व का 'विचार-कक्ष' बनने की ओर अग्रसर है। यह बदलाव भारत की आर्थिक तकदीर बदलने की क्षमता रखता है।

रंजना मिश्रा

इस बार के केंद्रीय बजट ने देश को एक नया आर्थिक मंत्र दिया है। इसे 'नारंगी अर्थव्यवस्था' (आरेंज इकोनोमी) का नाम दिया गया है। यह भारत के विकास की उस नई अवधारणा का प्रतीक है जो ईंट-गारे या भारी मशीनों पर नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क की असीम रचनात्मकता पर टिकी है। दरअसल, जब हम इस अर्थव्यवस्था से देश के विकास की बात करते हैं, तो हम एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे होते हैं जो दुनिया का कारखाना बनने की बजाय विश्व का 'विचार-कक्ष' बनने की ओर अग्रसर है। यह बदलाव भारत की आर्थिक तकदीर बदलने की क्षमता रखता है, क्योंकि यह हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी युवा आबादी और समृद्ध संस्कृति का सीधा उपयोग करता है। वैश्विक स्तर पर देखें, तो आज दुनिया के विकसित देश अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का बड़ा हिस्सा बौद्धिक संपदा और रचनात्मक उद्योगों से प्राप्त करते हैं। भारत का यह कदम उसे वैश्विक महाशक्तियों की कतार में खड़ा करने की एक सुविचारित रणनीति है।

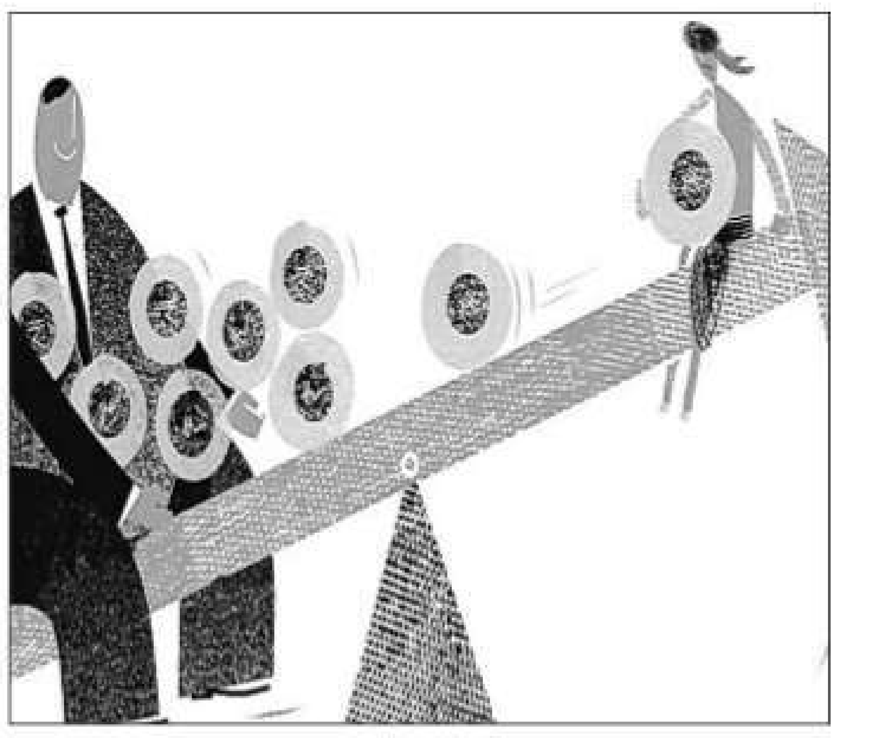

'नारंगी अर्थव्यवस्था' का मूल सिद्धांत यह है कि एक विचार, एक डिजाइन या एक कहानी, तेल के कुएं या सोने की खदान से भी अधिक मूल्यवान हो सकती है। परंपरागत अर्थव्यवस्था में संसाधनों की एक सीमा होती है, लेकिन रचनात्मकता का स्रोत अनंत है। वर्ष 2026-27 के बजट में सरकार ने एनिमेशन, गेमिंग और अन्य डिजिटल सामग्री निर्माण को जिस तरह प्राथमिकता दी है, वह इस बात का संकेत है कि भारत अब अपनी बौद्धिक संपदा से धन कमाना चाहता है। अब तक हम दुनिया के लिए 'कोडिंग' करते थे, विदेशी कंपनियों के लिए डेटा पर काम करते थे, लेकिन उत्पाद उनका होता था और असली मुनाफा भी उन्हीं का होता था। मगर 'नारंगी अर्थव्यवस्था' इस समीकरण को बदल देती है। जब भारत में बना कोई वीडियो गेम, कोई फिल्म या कोई फैशन डिजाइन दुनिया भर में बिकता है, तो उसका मालिकाना हक भारत के पास रहता है। यह 'सेवा प्रदाता' से 'मालिक' बनने की यात्रा है, जो देश के आर्थिक स्वाभिमान को नई ऊंचाई देगी। जब हम किसी विदेशी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो हमें एक बार भुगतान मिलता है, लेकिन जब हम किसी रचनात्मक उत्पाद के मालिक होते हैं, तो वह उत्पाद हमें वर्षों तक और कभी-कभी पीढ़ियों तक कमाई करके देता है। यही वह तरीका है जिसने अमेरिका और जापान की अर्थव्यवस्थाओं को इतना मजबूत बनाया है। अब भारत उसी राह पर चल पड़ा है।

देश के विकास में इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा योगदान रोजगार के स्वरूप को बदलने में होगा। भारत के पास दुनिया में सबसे अधिक युवा है, लेकिन हर युवा इंजीनियर या डाक्टर नहीं बन सकता। लाखों युवाओं के पास कलात्मक प्रतिभा है। कोई अच्छा चित्रकार है, कोई संगीतकार है, तो कोई कहानियां लिख सकता है। अब तक इस प्रतिभा को केवल शौक माना जाता था, जिससे आजीविका नहीं चलती थी। मगर 'नारंगी अर्थव्यवस्था' ने इन हुनर को उच्च भुगतान वाले करिअर में बदल दिया है। सरकार द्वारा स्कूलों और कालेजों में पंद्रह हजार 'कंटेंट क्रिएटर लैब' खोलने की घोषणा ने इस बदलाव को संस्थागत रूप दे दिया है। जब एक साधारण परिवार का बच्चा स्कूल में ही डिजिटल कला और डिजाइन की बारीकियां सीखेगा, तो वह भविष्य में नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि अपनी कला के दम पर दुनिया से काम लेने वाला बनेगा।

'नारंगी अर्थव्यवस्था' विकास को बड़े शहरों से निकाल कर छोटे शहरों और गांवों तक ले जाती है। एक बड़ी फैक्टरी लगाने के लिए जमीन, बिजली

> 'नारंगी अर्थव्यवस्था' विकास को बड़े शहरों से निकाल कर छोटे शहरों और गांवों तक ले जाती है। एक बड़ी फैक्टरी लगाने के लिए जमीन, बिजली और परिवहन की जरूरत होती है, जो अक्सर विशेष औद्योगिक क्षेत्रों में ही संभव है। मगर रचनात्मकता के लिए केवल एक कंप्यूटर, इंटरनेट और एक कुशल दिमाग की जरूरत होती है। आज भारत के एक छोटे शहर या कस्बे का कोई भी ग्राफिक डिजाइनर घर बैठे अमेरिका या यूरोप के ग्राहकों के लिए काम कर सकता है। यह भौगोलिक बाधाओं को पार कर आर्थिक अवसरों का विकेंद्रीकरण करता है। जब छोटे शहरों में पैसा आता है, तो वहां के स्थानीय बाजार फलते-फूलते हैं और पलायन की मजबूरी कम होती है।

और परिवहन की जरूरत होती है, जो विशेष औद्योगिक क्षेत्रों में ही संभव है। मगर रचनात्मकता के लिए केवल एक कंप्यूटर, इंटरनेट और एक कुशल दिमाग की जरूरत होती है। आज भारत के एक छोटे शहर या कस्बे का कोई भी ग्राफिक डिजाइनर घर बैठे अमेरिका या यूरोप के ग्राहकों के लिए काम कर सकता है। यह भौगोलिक बाधाओं को पार कर आर्थिक अवसरों का विकेंद्रीकरण है। जब छोटे शहरों में पैसा आता है, तो वहां के स्थानीय बाजार फलते-फूलते हैं और पलायन की मजबूरी कम होती है। इस तरह, 'नारंगी अर्थव्यवस्था' केवल जीडीपी के आंकड़े नहीं बढ़ाती, बल्कि यह समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी वैश्विक बाजार से जोड़ती है। इस विकेंद्रीकरण का एक और लाभ महिला सशक्तीकरण के रूप में सामने आ रहा है। हमारे देश में कई प्रतिभाशाली महिलाएं पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण घर से बाहर जाकर सुबह नौ से शाम पांच बजे की नौकरी नहीं कर पाती थीं। अब उनके लिए भी राहें खुलेंगी।

'नारंगी अर्थव्यवस्था' केवल डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की हजारों साल पुरानी हस्तशिल्प और कारीगरी की परंपरा को भी पुनर्जीवित कर रही है। भारत के कोने-कोने में बांस की कलाकारी, मधुबनी पेंटिंग और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लाखों कारीगर हैं। यह अर्थव्यवस्था इन पारंपरिक कौशलों को आधुनिक डिजाइन और ई-कामर्स के साथ जोड़ती है। जब एक आदिवासी कलाकार की बनाई पेंटिंग को डिजिटल रूप में बेचा जाता है या जब खादी के कपड़ों को एक फैशन ब्रांड के रूप में दुनिया के सामने रखा जाता है, तो यह परंपरा और तकनीक का एक अनूठा संगम होता है। यह 'वोकल फार लोकल' अभियान को 'लोकल फार ग्लोबल' में बदलने की शक्ति रखता है। इससे न केवल हमारी विरासत सुरक्षित रहती है, बल्कि उन कारीगरों को भी उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलता है जो अब तक बिचौलियों के कारण शोषण का शिकार थे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में, 'नारंगी अर्थव्यवस्था' भारत के लिए एक सुरक्षा कवच है। जैसे-जैसे मशीनें इंसानों के नियमित काम छीन रही हैं, यह सवाल उठता है कि भविष्य में इंसान क्या करेगा? इसका उत्तर रचनात्मकता में छिपा है। मशीनें गणना कर सकती हैं, लेकिन वे मानवीय संवेदनाओं के साथ मौलिक सृजन नहीं कर सकतीं। इसलिए, रचनात्मक क्षेत्र में निवेश करना देश के भविष्य को सुरक्षित करना है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां तकनीकी रूप से सक्षम होने के साथ-साथ मानवीय रूप से भी प्रासंगिक बनी रहें। जब मानव मस्तिष्क की कल्पनाशीलता कृत्रिम मेधा की गति के साथ मिलती है, तो परिणामों की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। भारत का युवा वर्ग, जो तकनीक को बहुत जल्दी अपनाता है, इस सह-अस्तित्व का सबसे अच्छा उदाहरण बन कर उभर सकता है। जब रचनात्मक उद्योग बढ़ता है, तो इसका फायदा सिर्फ कलाकारों को नहीं मिलता। इससे हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों की बिक्री बढ़ती है, इंटरनेट डेटा की खपत बढ़ती है और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इससे स्थानीय टैक्सी वालों, होटल वालों और दुकानदारों की भी आय बढ़ती है। यानी एक रचनात्मक विचार पूरी अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बढ़ा देता है।

वास्तव में, 'नारंगी अर्थव्यवस्था' भारत के आत्मविश्वास की एक नई कहानी है। यह इस विश्वास की बहाली है कि भारतीय दिमाग केवल नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि नए आविष्कार और नई दुनिया रचने के लिए बना है। जब देश का युवा अपनी शर्तों पर, अपनी भाषा में और अपनी संस्कृति के रंगों में दुनिया को कुछ नया देगा, तो उसी से विकास की सार्थकता परिभाषित होगी।

उम्र की सिलवटें

दुनिया मेरे आगे

चैतन्य नागर

धीरे-धीरे देह की सीढ़ियां चढ़ती है उम्र। आहिस्ता-आहिस्ता दीमक समय कुतरता है हड्डियों को। त्वचा सिकुड़ती है बगैर किसी शोर-शराबे के। आंखों की रोशनी बुझने लगती है। ऐसा नहीं होता कि अचानक कोई सुबह उठे और देखे कि वह बूढ़ा हो गया है। ऐसी ही है जीवन की सांझ। इसकी आहट किसी कैलेंडर की तारीख से नहीं, बल्कि आईने से झांकते उस खामोश सच से आती है, जिसमें हमें अक्सर 'जेरंटाफोबिया' या बुढ़ापे का डर दिखाई देता है। यह डर वक्त के बीतने का नहीं, जितना कि अपने वजूद के धीरे-धीरे सिकुड़ने का है। हम घबराते हैं कि व्यक्तिगत पहचान की जिस इमारत को हमने ताकत, सौंदर्य और उपयोगिता की 'मजबूत' चट्टान पर बनाया था, वह कहीं भविष्य की धुंधली अनिश्चितता में ढह न जाए।

इस डर की गहराई को समझने के लिए उस ढांचे को देखना चाहिए, जो हमने अपने 'अहंकार' के इर्द-गिर्द बनाया है। दुनिया हमें सिखाती है कि हमारे होने का अर्थ है लगातार कुछ करते रहना और बराबर लोगों को आकर्षित करना। जब देह के पहिये घिसने लगते हैं, तो मन में एक अजीब शोक उतरने लगता है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक, बुढ़ापे की चिंता अक्सर अपनी स्वायत्तता को खोने से जुड़ी होती है। बचपन में होने वाले भय का एक दिलचस्प और दर्दनाक विलोम है यह। एक बच्चा अंधेरे में खो जाने से डरता है। बुजुर्ग समाज की भीड़ में ओझल हो जाने से और अपनों पर ही 'बोझ' बन जाने से डरता है। जिस दुनिया में सिर्फ नवीन, शक्तिशाली और गतिमान को पूजा जाता है, वहां 'पुराना' अक्सर हाशिये पर धकेल दिया जाता है। उम्र का लिहाज पहले हमारी संस्कृति का हिस्सा था, वृद्ध लोगों की इज्जत करना बचपन से ही सिखाया जाता था। पश्चिम की संस्कृतियां यौवन की तारीफ करते नहीं थकतीं। वृद्ध वहां अनुपयोगी हो जाता है। अर्थव्यवस्था पर एक बोझ और किसी काम के लिए अनुपयुक्त। अक्सर हम झुर्रियों से सिर्फ इसलिए नहीं डरते कि वे खराब दिखती हैं, बल्कि इसलिए कि वे समाज के लिए हमारी 'अनुपयोगिता' का प्रतीक बन जाती हैं।

> आज का मनोविज्ञान बुढ़ापे के बारे में एक सकारात्मक कहानी भी सुनाता है। जिसे हम 'कमी' समझते हैं, वह अक्सर बड़ी उपलब्धि होती है। जैसे-जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, वे उन रिश्तों को छोड़ देते हैं, जो औपचारिक या दिखावे मात्र के होते हैं। वे अपना समय और ऊर्जा केवल उन लोगों पर खर्च करते हैं, जिनसे उन्हें सच्चा प्रेम मिलता है।

साहित्य ने हमारे इस डर बखूबी बयान किया है। आस्कर वाइल्ड के कालजयी उपन्यास 'द पिक्चर आफ डोरियन ग्रे' में डोरियन का डर मौत से ज्यादा 'बदलाव' को लेकर है। वह जानता है कि उसकी शक्ति उसकी शीशे जैसी चिकनी त्वचा में है। उसका चित्र, जो लगातार बूढ़ा और बदसूरत होता जाता है, इसी बात का प्रतीक है कि हम अपने भीतर के डर को चाहे कितना भी छिपा लें, समय की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकतीं। शेक्सपियर के 'किंग लियर' की त्रासदी सिर्फ सत्ता को नहीं, बल्कि उस गरिमा को खोने में है, जो उसे समाज में 'प्रासंगिक' बनाए रखती थी। उसकी चीख दरअसल संज्ञानात्मक पतन और स्मृति के धुंधलाने का वह डर है, जो हर इंसान को सताता है। मुक्तिबोध की कविताओं में बुढ़ापा एक 'अंधेरे' की तरह आता है और यह 'समझौते' का पर्याय है, जिससे वे सबसे ज्यादा डरते हैं।

जहां साहित्य हमारे जख्मों को दिखाता है, वहीं धर्मग्रंथ उन पर मरहम लगाते हैं। कई बार वे ढलते शरीर को एक 'टूटते हुए मकान' के रूप में नहीं, बल्कि एक परिपक्व होते आत्म के रूप में देखते हैं। बाइबिल के 'एक्लेसिएस्टेस' में बुढ़ापे का वर्णन बहुत ही बेबाक और सच्चा है। वहां शरीर को एक ऐसे घर की तरह बताया गया है, जिसकी खिड़कियां (आंखें) धुंधली हो गई हैं और पहरेदार (हाथ) कांप रहे हैं। मगर इसे दुख की तरह नहीं, बल्कि एक 'पवित्र उल्टी गिनती' की तरह पेश किया गया है। वृद्ध का दिखना राजकुमार सिद्धार्थ के लिए वैराग्य और नवीन अंतर्दृष्टि का कारण बना। बुढ़ापा उनके लिए 'अनित्यता' या अनिक्क का संदेश लेकर आता है।

आज का मनोविज्ञान बुढ़ापे के बारे में एक सकारात्मक कहानी भी सुनाता है। जिसे हम 'कमी' समझते हैं, वह अक्सर एक बहुत बड़ी 'उपलब्धि' होती है। जैसे-जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, लोग उन रिश्तों को छोड़ देते हैं, जो केवल औपचारिक या दिखावे मात्र के होते हैं। वे अपना समय और ऊर्जा केवल उन लोगों पर खर्च करते हैं, जिनसे उन्हें सच्चा प्रेम मिलता है। बुढ़ापे में भले ही सीखने की गति कम हो जाए, लेकिन जीवन भर का संचित अनुभव एक ऐसी बुद्धिमत्ता को जन्म देता है, जो युवाओं के पास नहीं होती। यह समस्याओं को सुलझाने की वह जादुई क्षमता है, जो केवल वक्त के साथ आती है। समाजशास्त्री लार्स टार्नस्टैम के अनुसार, बुढ़ापे में व्यक्ति भौतिकवादी दुनिया से ऊपर उठकर एक 'ब्रह्मांडीय' नजरिया अपना लेता है। वह अब खुद को केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि इस अनंत ब्रह्मांड का एक हिस्सा मानने लगता है।

देखा जाए तो, बुढ़ापा सिर्फ बंद होते दरवाजों और खिड़कियों का नाम नहीं, बल्कि एक नए नजरिए के खुलने का भी संकेत है। यह वह समय है, जब हम 'नायक' बनने की होड़ को एक तरफ सरका कर जीवन के द्रष्टा बन जाते हैं। अथर्ववेद की प्रार्थना 'पश्येम शरदः शतम्' (हम सौ शरद ऋतुएं देखें) हमें सिखाती है कि लंबी उम्र एक सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है। अगर जीवन एक उपन्यास जैसा है, तो बुढ़ापा उसका अंतिम अध्याय नहीं, बल्कि उसका सार है- वह क्षण, जहां कहानी के सभी बिखरे हुए तार एक सुंदर स्वरूप में जुड़ जाते हैं। बालों का सफेद होना सिर्फ रोशनी का कम होना नहीं, बल्कि आत्मा का स्वच्छ होना भी है।

बुढ़ापा नए डर लाता है और नए अवसर भी। यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है कि हम चुनते क्या हैं। बुढ़ापा इस बात का सबूत है कि हमने दिन की तपिश को झेला है, ताकि सांझ की शीतलता तक पहुंच सकें। भागदौड़ से निकलकर अब हम लहरों की उस लय में भी शामिल हो जाते हैं, जहां शांति ही संगीत है। झुर्रियों से भरी देह और क्लांत मन के पास भी शायद इस चयन की ऊर्जा तो बचती ही है।

कसौटी पर तकनीक

'कृत्रिम मेधा और संसाधनों की सीमा' (लेख, 4 फरवरी) में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समांतर स्थितियों का यथोचित विश्लेषण है। सवाल यह नहीं है कि एआइ कितनी तेज या कितनी समझदार है, बल्कि यह है कि हम उसे किस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। तकनीक अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य उसका उपयोग किस सोच और उद्देश्य से करता है। अगर एआइ का विकास केवल मुनाफा कमाने और प्रतिस्पर्धा जीतने के लिए किया जाएगा, तो उसका बोझ प्रकृति को उठाना पड़ेगा। आज एआइ जिन बड़े-बड़े डेटा केंद्रों पर निर्भर है, वे अत्यधिक बिजली खर्च करते हैं। इससे साफ है कि अगर अभी सावधानी नहीं बरती गई, तो तकनीक की यह प्रगति पर्यावरण के लिए नई परेशानी बन सकती है। इसलिए एआइ का भविष्य तभी उपयोगी और सार्थक होगा, जब उसे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के साथ विकसित किया जाए। डेटा केंद्रों को सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोतों से जोड़ना जरूरी है, ताकि कार्बन प्रदूषण कम हो सके। साथ ही ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम और एल्गोरिद्म विकसित करने होंगे, जो कम बिजली में अधिक काम कर सकें।

– मो अजहर आलम अंसारी, पूर्णिया

आभासी जंजीरें

हाल ही में गाजियाबाद में घटी घटना बताती है कि कम उम्र के बच्चों में अकेलापन और अवसाद बढ़ रहा है। वे एक खतरनाक मोड़ पर हैं। मोबाइल उन्हें एक ऐसी आभासी दुनिया में ले जा रहा है, जहां से वे गुम हो रहे हैं। ऐसी घटनाओं के लिए जितना जिम्मेदार मोबाइल फोन और ऐप हैं, उतने ही परिजन भी जिम्मेदार हैं जो समय रहते बच्चों के बदलते व्यवहार को समझ नहीं पाते। आज के समय में इंसान इतना व्यस्त है कि अपने आप से भी मिल नहीं पाता। इसी वजह से आज मानसिक अलगाव की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि माता-पिता अपने बच्चे से संवाद तक नहीं कर पाते और वे अपनी एक अलग काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं। ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना चाहिए। उनके लिए समय निकालना चाहिए। उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनके लिए हमेशा उपलब्ध हैं और उन्हें इस तरह की घटनाओं से भी अवगत कराएं जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

– अभिषेक जैसवाल, मैहर, मप्र

सतर्कता का समय

बीते कुछ दिनों से दिल्ली से लोगों के लापता होने की खबरें आ रही हैं। गुम हुए कुल लोगों में बच्चों और महिलाओं का अनुपात अधिक है। खबरों के अनुसार, जनवरी के पहले पखवाड़े में करीब आठ सौ लोग लापता हो गए। सवाल उठता है कि जब देश की राजधानी ही लोगों की सुरक्षा करने में असमर्थ है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि दूसरे राज्यों में नागरिकों को क्या सुरक्षा मिल रही होगी। लोगों का लापता होना एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। लोगों के गायब होने के पीछे किसकी साजिश हो सकती है? क्या देश में कुछ गिरोह किसी के इशारे पर ये काम कर रहे हैं? अगर ऐसा है, तो सुरक्षा एजंसियों को उचित कदम उठा कर इस साजिश की सच्चाई को उजागर करना चाहिए। साथ ही सभी नागरिकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। घर से स्कूल या बाजार जाने वाले बच्चों और लड़कियों को सचेत करना होगा कि वे किसी अजनबी से बात करते समय सजग रहें।

– शाहिद हाशमी, दिल्ली

पलायन का चक्र

निमाड़ अंचल से हजारों आदिवासी परिवार गुजरात और महाराष्ट्र की ओर पलायन करते हैं। कारण स्पष्ट है- स्थानीय स्तर पर रोजगार का अभाव और सिंचाई के सीमित साधन। योजनाएं कागजों पर तो दौड़ रही हैं, लेकिन धरातल पर इतनी सक्षम नहीं हैं कि एक परिवार का साल भर भरण-पोषण कर सकें। माता-पिता के साथ पलायन करने के कारण कई बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। इसके अलावा, दूसरे राज्यों में अमानवीय परिस्थितियों में काम करने से मजदूरों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। प्रशासन को चाहिए कि वह केवल आंकड़ों में पलायन को न देखे, बल्कि स्थानीय स्तर पर कुटीर उद्योगों, कृषि आधारित रोजगार और सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा दे। जब तक इस अंचल के युवाओं को अपने ही गांव में रोजी-रोटी नहीं मिलेगी, तब तक पलायन का यह चक्र नहीं थमेगा।

– रोहित सेनानी, बड़वानी

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

कारोबाजार
जनसत्ता | 9 फरवरी, 2026

जोखिम उठाने की क्षमता के अनुरूप हो रणनीति

जनसत्ता कारोबाजार

जब शेयर बाजार में निवेश कर रहे हों तो सीधे शेयर में कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड्स में करें, निवेश की रणनीति सुरक्षित होनी चाहिए। पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट में जरूरत और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुरूप सामंजस्य होना चाहिए। 80:20 (80 अनुपात 20) के अनुपात में इक्विटी और डेट में निवेश करना अच्छी रणनीति है। अधिक उम्र होने पर 60:40 के अनुपात में भी इक्विटी और डेट का पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। डेट का कुछ हिस्सा जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आकस्मिक स्थिति में डेट फंड से तुरंत पैसा मिल सकता है।

जोखिम का गणित

यह बात अक्सर सुनते होंगे कि इस ब्लूचिप शेयर को खरीद लीजिए इसमें कोई जोखिम नहीं है। बांड और बैंक जमा में जो लोग धन लगाते हैं, उनका विचार यही रहता है कि कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए। धन सुरक्षित चाहिए। क्या यह सही बात है? नहीं। जब भी कोई निवेश करेंगे, उसके साथ जोखिम जरूर है। विभिन्न संपत्तियों में निवेश के विश्लेषण से पता चलता है कि इक्विटी शेयरों में लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न मिलता है।

ऋण पत्र और बांड में जोखिम कैसे है? तो समझिए कि किसी कंपनी का ऋणपत्र या बांड खरीद रखा है और यदि उस कंपनी की वित्तीय स्थिति लड़खड़ा जाती है, तो वह ब्याज भुगतान रोक सकती है और धन लौटाने से पीछे हट सकती हैं। सरकारी बांड में भी कुछ जोखिम है। कंपनियों की तरह ही सरकार की हालत भी लड़खड़ा सकती है। कंपनी और सरकार दोनों पैसा लौटाने में डिफाल्टर हो सकते हैं, हालांकि सरकार के पास ज्यादा मुद्रा छापने का विकल्प है, लेकिन ज्यादा मुद्रा छापने का अर्थ है कि निवेश का मूल्य घटना, यानी रिटर्न कम मिलना। यह भी एक जोखिम है। बेहतर यही है कि जोखिम का सही आकलन करके निवेश करें।

शेयरों में धन लगाने के चार नियम

शेयर दलाल शेयरों की खरीद-बिक्री पर धन कमाता है। इसलिए ज्यादातर 'ब्रोकरेज हाउस' मुफ्त में सलाह देते हैं और अधिक से अधिक शेयरों की खरीद-बिक्री पर जोर देते हैं। अगर आप अपने धन से हाथ नहीं धोना चाहते तो इन चार नियमों का पालन करें।

शेयर सूत्र

नियम एक : निवेश से पहले सलाह का अध्ययन करें। 'लिटमस टेस्ट' करें। निवेश करने के पहले, किसी भी विश्लेषक की सलाह का कुछ समय तक परीक्षण करें। उसके बाद ही फैसला करें। कई 'ब्रोकरेज हाउस' अपने 'शोध दलों' के जरिए दावा करते हैं। उनकी रोजाना रपट आती हैं। इनमें से कितनी सही रहती होंगी। यह पता लगाएं।

नियम दो : निवेश के पहले शेयर के बारे में ठीक से शोध करें। उस पर दलाल से विस्तार से रपट मांगें। लंबी अवधि की संभावनाएं अच्छी हों, तभी निवेश करें। ट्रिगर प्राइस और टार्गेट प्राइस वाली सलाह पर समय बर्बाद नहीं करें।

नियम तीन : जो तेज चढ़ता है, तेज गिरता है। जब भी ऊंचाई पर कोई आंकड़ा देखा जाता है, उसमें प्रगति की बड़ी संभावना दिखाई देती है, लेकिन जब कोई शेयर काफी बढ़ चुका हो या किसी सेक्टर में काफी तेजी आ चुकी हो, सतर्क रहना चाहिए। ज्यादा पीई अनुपात का मतलब है कि भविष्य में प्रगति दर घटने वाली है।

नियम चार : समय नहीं है तो म्यूचुअल फंड में धन लगाएं। पोर्टफोलियो में नए शेयर चुनने का समय नहीं है, तो शेयर बाजार में सीधे धन नहीं लगाएं। सिप में निवेश से भी काफी मूल्य निर्मित किया जा सकता है।

सेवानिवृत्ति के लिए कोष बनाना आसान, युवा रहते शुरू करें तैयारी

जनसत्ता कारोबाजार

बचत की बात

भारत में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए हर किसी को अपनी सेवानिवृत्ति की योजना समय रहते बना लेनी चाहिए। चाहे आप अपना काम कर रहे हों या नौकरीपेशा हों, अपनी वृद्धावस्था के लिए पर्याप्त कोष होना चाहिए। जब आप कमाई शुरू करें तो उसके कुछ समय बाद ही अपनी सेवानिवृत्ति के लिए कोष बनाना शुरू कर दें। अपनी मासिक आय की 20 फीसद तक बचत करें, इक्विटी में निवेश करें और एसआइपी को समय-समय पर बढ़ाएं। महंगाई और स्वास्थ्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए नियमित समीक्षा करें ताकि लंबी अवधि में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। असली कामयाबी संतुलन बनाने में है, क्योंकि आर्थिक रूप से कठिन समय में भी सेवानिवृत्ति कोष में छोटा-छोटा निवेश जारी रखना चाहिए। ऐसे में हर किसी के पास 20 से 30 वर्ष के खर्च के लिए कोष होना चाहिए। इसके लिए कुछ तैयारी की जरूरत होती है।

चरण 1 : समय का गणित

सेवानिवृत्ति योजना बनाने में समय सबसे कीमती साथी है। चूंकि युवाओं के पास अभी कई दशक बाकी हैं, इसलिए निवेश को बढ़ने और 'कंपाउंड' होने का पूरा मौका मिलता है। छोटी रकम से शुरुआत करना आसान है, बजाय इसके कि भविष्य में बड़ी पूंजी जुटाने के लिए आर्थिक दबाव डालें। अगर निवेश शुरू करने में सिर्फ पांच साल की देरी होती है, तो समान लक्ष्य पाने के लिए हर महीने 30 से 40 फीसद ज्यादा पैसा बचाना होगा। 10 साल की देरी इस बोझ को तीन गुना तक बढ़ा सकती है। यह 'कंपाउंडिंग' का सीधा गणित है। वक्त हाथ से गया, तो पैसा जेब से ज्यादा जाएगा।

चरण 2 : कैसी जिंदगी चाहते हैं

इस बात को समझना जरूरी है कि सेवानिवृत्ति हर किसी के लिए अलग होती है। हर किसी की जरूरत भी अलग होती है। हर व्यक्ति का निवास स्थान भी अलग-अलग होता है, जहां जीवन स्तर पर खर्च में अंतर होता है। कुछ लोग सादगी से, कम खर्च में जीवन बिताना चाहते हैं।

कुछ लोग चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वे वही जीवन जिएं जो उसे पहले से जी रहे हैं।

चरण 3 : महंगाई के असर का भी रखें ध्यान

अगर कोई यह सोच कर योजना बनाते हैं कि उनके जीवन के अंतिम 25झ30 साल के दौरान भी खर्च आज जैसा ही रहेगा, तो यह भूल होगी। समय के साथ महंगाई बढती जाती है। किसी चीज का दाम आज जो है..25-30 साल के बाद उसी का दाम अधिक होगा। महंगाई धीरे-धीरे, चुपचाप खर्च बढ़ाती रहती है। आज जो खर्च किफायती लगते हैं जैसे राशन, बिजली-पानी के बिल, दवाएं, घरेलू मदद और रोजमर्रा की जरूरतें- समय के साथ काफ़ी बढ़ जाते है। इसलिए अपनी सेवानिवृत्ति योजना में बढती महंगाई का भी ध्यान रखें।

चरण 4 : कुल कोष कैसे तय करें

जब यह अंदाजा हो जाए कि सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने लगभग कितना खर्च होगा, तब अगला आसान कदम है। इस चरण में उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि जीवन की गुणवत्ता उस समय भी बनी रहे, जब नियमित आमदनी बंद हो जाए। इसलिए बचत इतनी होनी चाहिए कि रोजमर्रा के खर्च, अचानक आने वाले खर्च और बढ़ती स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा किया जा सके।

चरण 5 : बड़े लक्ष्य को छोटे टुकड़ों में बांटें

सेवानिवृत्ति के लिए बड़ी रकम सुनकर घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन पहाड़ जैसा दिखने वाला यह लक्ष्य असल में बहुत आसान हो सकता है, अगर नजरिया बदला जाए तो। एक बड़ी कुल राशि को देखने के बजाय सिर्फ आज पर ध्यान दें, महीने का बजट तय करें। खुद से पूछें कि हर महीने कितनी रकम बिना किसी तनाव के बचाई जा सकती है? अगर उम्र के 30 वर्ष के आस-पास छोटे-छोटे निवेश शुरू हो जाते हैं, तो 'कंपाउंडिंग' (ब्याज पर ब्याज) की ताकत उसे समय के साथ एक विशाल कोष बना देती है। इसलिए छोटे पर नियमित निवेश करते रहें ।

चरण 6 : बीस फीसद का नियम

सेवानिवृत्ति की योजना को पेचीदा बनाने के बजाय, इसे कमाई के फीसद (%) से जोड़ दिया जाए। यह एक ऐसा आसान तरीका है जिससे बार-बार पैसों का हिसाब-किताब नहीं करना पड़ेगा। जब यह तय हो जाता है कि अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा (जैसे 20%) निवेश करना है, तो हर महीने यह नहीं सोचना पड़ता कि कितनी रकम बचाई जाए।

चरण 7 : तीस की उम्र में 'इक्विटी' जरूरी है

कोष बनाने के लिए सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, यह भी जरूरी है कि उसे कहां निवेश करना है। निवेश के लिए पोर्टफोलियो बनाएं। उसमें शेयर, म्यूच्यूअल, सोना-चांदी के साथ बांड, एफडी, जायदाद भी शामिल हो और एनपीएस, पीपीएफ जैसे कोई न कोई पेंशन कोष भी हो। वृद्धि-आधारित निवेश रणनीति अपनाने से सेवानिवृत्ति कोष उस रफ्तार से बढ़ता है जो न केवल महंगाई का मुकाबला करता है, बल्कि भविष्य में खरीदारी की ताकत को भी बढ़ाता है। बचत के शुरुआती वर्ष में इक्विटी में अधिक निवेश करना बेहतर है।

चरण 8 : एसआइपी का तरीका अपनाएं

सेवानिवृत्ति कोष बनाने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि जैसे-जैसे आमदनी बढ़े, वैसे-वैसे निवेश की राशि भी बढ़े। इसमें एसआइपी कारगर तरीका है। छोटे पर नियमित निवेश बड़ा कोष बना सकते हैं ।

नए साल में क्या रणनीति अपनाएं सोने-चांदी में निवेश करने वाले

जनसत्ता कारोबाजार

नव वर्ष में अमेरिका-वेनेजुएला के बीच बढ़ता तनाव और ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिया गया बयान, कच्चे तेल बाजार की अनिश्चतता आदि ने वैश्विक भू-राजनीति को अस्थिर कर दिया है। इन सबसे वैश्विक अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। इसके कारण सोने-चांदी की मांग बढ़ रही है। नए साल में सोनेझचांदी में निवेश का बेहतर तरीका क्या हो सकता है और पोर्टफोलियो में कितना सोना-चांदी रखना चाहिए? क्या सोने-चांदी के अलावा भी धातु में कोई विकल्प है?

सोने की कीमतें मुख्य रूप से केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियां, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और महंगाई के रुझान पर निर्भर करेंगी। चांदी की कीमतें औद्योगिक मांग पर निर्भर करेगी। वर्ष 2025 में सोना 73 फीसद तो चांदी करीब 160 फीसद मजबूत हो चुकी है। गत वर्ष चांदी ने करीब 138 फीसद और सोने ने 74.5 फीसद लाभ दिया। यह दशकों में सबसे अच्छा रिटर्न है। सवाल है कि अब नया साल इनके लिए कैसा रहेगा। भू राजनीतिक तनाव के कारण देशों के केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं।

वर्ष 2026 में सोने- चांदी का भविष्य अच्छा दिख रहा है। अगर महंगाई उम्मीद से ज्यादा बढ़ती है, तो सोने की मांग बनी रहेगी। यदि बैंक ब्याज दरों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करते हैं, तो थोड़े समय के लिए सोने की कीमतों पर दबाव आ सकता है। अमेरिकी डालर मजबूत होने या ब्याज दरों में बदलाव से सोने-चांदी कीमती में क्षणिक अस्थिरता आ सकती है। फिर भी, लंबे समय के निवेश के नजरिए से सोना-चांदी एक सुरक्षित विकल्प बना रहेगा। इस वर्ष निवेशक अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15 फीसद तक सोनेझचांदी रख सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ निवेश के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। जिन निवेशकों के पास पहले से काफी अधिक सोना है, वे गोल्ड फंड या गोल्ड ईटीएफ के जरिए निवेश को और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अनुमान के मुताबिक, भारतीय परिवारों के पास कुल मिलाकर करीब 25,000 से 30,000 टन सोना मौजूद है, जो दुनिया में निजी तौर पर रखे गए सोने के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। इसलिए परिदृश्य मजबूत है।

निवेश निश्चय

नव वर्ष में अब तक सोने करीब छह फीसद और चांदी करीब 17 फीसद मजबूत हुई है। दिसंबर में गोल्ड ईटीएफ में रिकार्ड 11,646 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो सालाना आधार पर 1719 फीसद बढ़ा। 2025 में गोल्ड ईटीएफ ने औसतन 71.55 फीसद का लाभ दिया। इसलिए नव वर्ष में गोल्ड ईटीएफ आकर्षक बना रहेगा। चांदी ईटीएफ भी बेहतर विकल्प बन कर उभरा है। आजकल इलेक्ट्रिक कार, सौर ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, टेलिकाम और कृत्रिम मेधा जैसी नई तकनीकों में चांदी की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि नव वर्ष में चांदी की कीमतें स्थायी तौर पर ऊपर जा सकती हैं।

तांबा नया खिलाड़ी

तांबा आज की दुनिया की रीढ़ है। चाहे वह नवीनीकरण ऊर्जा हो, बिजली चालित वाहन (ईवी) हो या फिर एआइ के लिए बनने वाले विशाल डेटा केंद्र, बिना तांबे के कुछ भी मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि इसे अब एक केवल धातु के बजाय औद्योगिक मांग वाली धातु मानी जा रही है। दुनिया में तांबे का सबसे बड़ा खरीदार चीन है, उसके बाद अमेरिका है। भारत तेजी से तांबे के बड़े औद्योगिक उपयोगकर्ता देशों में शामिल हो रहा है। मांग जरूर बढ़ रही है , लेकिन आपूर्ति बढ़ाना आसान नहीं है। मोतीलाल ओसवाल की रपट कहती है कि एक नई तांबे खदान को शुरू करने में कम से कम एक दशक का समय लगता है। भारतीय शेयर बाजार में तांबे की इस कहानी का सबसे बड़ा नायक हिंदुस्तान कापर बनकर उभरा है। कंपनी के शेयर तेजी से ऊपर भाग रहे हैं। तांबा अब सिर्फ बिजली के तारों तक सीमित नहीं है। यह 2026 का वह 'गुपचुप खिलाड़ी' है जो आने वाले समय में सोने और चांदी को लाभ के मामले में कड़ी टक्कर दे सकता है। निवेशकों के लिए यह एक नया मंच है। वायदा बाजार में इसकी धमक देखी जा रही है।

संवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मलेशिया के कुआलालंपुर में फिसन इलेक्ट्रानिक्स के संस्थापक पुआ खिन सेंग केएस पुआ ने मुलाकात की।

आय के स्रोत पर कर क्या है

आय के स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस) भारत की कराधान प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा है। चाहे वेतनभोगी कर्मचारी हों, कारोबार के मालिक हों या निवेशक हों, टीडीएस के दायरे में हैं। कर कानूनों का पालन करने और अनावश्यक दंड से बचने के लिए टीडीएस को समझना आवश्यक है। टीडीएस आयकर कानून, 1961 के तहत एक तंत्र है, जहां भुगतानकर्ता (कटौतीकर्ता) वेतन, ब्याज, किराया, पेशेवर शुल्क, कमीशन आदि जैसे विशिष्ट भुगतान करते समय कर की कटौती करता है। बाद में कटौती की गई राशि आयकर विभाग में जमा की जाती है। कर योग्य सीमा से अधिक वेतन का भुगतान करने वाले नियोक्ता, एक निश्चित सीमा से अधिक अर्जित ब्याज पर बैंक और वित्तीय संस्थान, ई-कामर्स मंच विक्रेता की आय, प्रति माह 50,000 रुपए से अधिक किराए का भुगतान करने वाले, डिविडेंड भुगतान करने वाली सूचीबद्ध कंपनियां, रेसकोर्स घोड़े की दौड़ से जीतने पर, गेमिंग मंच और लाटरी संचालक, गेम, बेटिंग और लाटरी जीतने आदि टीडीएस के दायरे में हैं। कटौतीकर्ता सरकार के साथ टीडीएस राशि जमा करने और टीडीएस प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार है।

शेयर और आभासी मुद्रा में कौन सा विकल्प चुनें

आज निवेशकों के सामने बड़ा सवाल है कि वे शेयर बाजार में निवेश करे या क्रिप्टो में। दोनों में निवेश के अपने फायदे और जोखिम हैं। तुलनात्मक रूप से शेयर बाजार में क्रिप्टो से कम जोखिम है। तो कमाई भी कम है । अगर सुरक्षित और लंबी अवधि के लिए फंड ग्रोथ की चाहत है, तो शेयर बाजार बेहतर है। अगर ज्यादा जोखिम लेकर बहुत कम समय में भारी मुनाफा चाहते हैं, तो क्रिप्टो बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन इसमें पैसा डूबने का खतरा भी ज्यादा है।

शेयर बाजार अधिक स्थिर है। भारत में विनियमित है। लंबी अवधि के लिए सुरक्षित है। इसके उलट क्रिप्टो बाजार अत्यधिक अस्थिर है।, 24/7 ट्रेडिंग चलती रहती है। उच्च जोखिम है पर उच्च कमाई भी है। नई तकनीक पर आधारित है और क्रिप्टो की संख्या निश्चित है। बिटकाइन की कुल अधिकतम संख्या 21 मिलियन (2.1 करोड़) निर्धारित है, जो इसके साफ्टवेयर कोड में अंतर्निहित है। ऐसे ही दूसरे क्रिप्टो की भी संख्या सीमित है। इसलिए सुरक्षित निवेशकों के लिए शेयर बाजार अच्छा है जबकि उच्च जोखिम लेने वाले के लिए क्रिप्टो बेहतर है । लेकिन क्रिप्टो में केवल उतना ही पैसा लगाएं, जितना डूबने पर आप सहन कर सकें। क्रिप्टो में निवेश करने से पहले अच्छी तरह शोध करें और केवल वित्तीय खुफिया इकाई (एफ आइ यू)- पंजीकृत एक्सचेंज का ही उपयोग करें। अपने पोर्टफोलियो को संतुलित रखने के लिए शेयर व क्रिप्टो दोनों में थोड़ा-थोड़ा निवेश करना सबसे अच्छी रणनीति हो सकती है। भारत में एफआइयू के साथ पंजीकृत क्रिप्टो एक्सचेंज कानूनी रूप से सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि वे धनशोधन विरोधी कानूनों और सख्त केवाईसी नियमों का पालन करते हैं। देश में करीब 49 एक्सचेंज पंजीकृत हैं।

क्रिप्टो करामात

अब बड़े फंड मैनेजर और कंपनियां शेयर और क्रिप्टो दोनों में निवेश करती हैं, जिससे दोनों का रुझान एक जैसा हो जाता है। शेयर बाजार में भारी गिरावट आने पर, व्यापारी नुकसान की भरपाई के लिए क्रिप्टो संपत्ति बेचते हैं। इससे क्रिप्टो बाजार भी दबाव में आ जाता है। मुद्रास्फीति या ब्याज दरों में बदलाव का असर दोनों परिसंपत्ति वर्गों पर पड़ता है। हालांकि दोनों पूरी तरह एक नहीं हैं, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में वे एक-दूसरे से काफी प्रभावित हो रहे हैं। भारत में क्रिप्टो बहुत जोखिम भरी बनी हुई है, भले ही इसके निवेशक बढ़ रहे हों । उपयोगकर्ता संख्या के मामले में भारत विश्व के शीर्ष देशों में शुमार है। क्रिप्टो की कीमतें बहुत तेजी से बदलती हैं। कीमत में उतार-चढ़ाव तेज होता है। क्रिप्टो में नुकसान होने पर उसे दूसरे इनकम या भविष्य के क्रिप्टो लाभ से 'एडजस्ट' नहीं कर सकते। क्रिप्टो ट्रेड में अभी भी नियामकीय अनिश्चितता हैं और अधिकारियों की सतर्कता है। भारत सरकार और रिजर्व बैंक क्रिप्टो को संदेह की नजर से देखते हैं। अभी तक कोई पूरा कानून नहीं बना है। घोटाला, सेंधमारी और सुरक्षा जोखिम बहुत ज्यादा है। भारत में रग पुल, फिशिंग, फर्जी एप, पंप-एंड-डंप ग्रुप्स (टेलीग्राम/वाट्सएप पर) और इंपर्सोनेशन स्कैम आम हैं। निवेशक सुरक्षा और तरलता की कमी है। क्रिप्टो नुकसान होने पर शेयर या बैंक जमा की तरह कोई बीमा या मुआवजा नहीं मिलता। भारत में अन्य चिंताएं भी हैं। अवैध गतिविधियों (क्रिप्टो हवाला, टेरर फंडिंग) से जुड़े होने के कारण जांच बढ़ती है। वैश्विक प्रभाव (जैसे यूएस नज बदलाव, इंटरनेशनल क्रैकडाउन) भारतीय खुदरा सेंटिमेंट पर सीधा असर डालते हैं। साफ लाइसेंसिंग और उपभोक्ता संरक्षण ढांचे की कमी से सुरक्षित, संस्थागत स्तर की भागीदारी सीमित है। इसलिए सोच समझकर फैसला लें।

गलत जानकारी देने पर लगेगा जुर्माना

बजट आया। इसमें क्रिप्टो को लेकर नई घोषणा हुई है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। अब कोई भी क्रिप्टो निवेशक अपने निवेश की जानकारी अगर सरकार से छुपाएगा, तो उसे जुर्माना देना होगा। आयकर कानून की नई धारा 509 के तहत अब गलत/अपूर्ण जानकारी देने या सूचना में चूक पर 50,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और चुकाने में देरी पर प्रतिदिन 200 रुपए का दंड लगेगा।

-दिव्या तंवर शिक्षाविद व साइबर विशेषज्ञ

अधिवक्ताओं की फीस में केंद्र ने 11 साल बाद की बढ़ोतरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 फरवरी।

केंद्र सरकार की ओर से अदालतों में प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की फीस लगभग 11 साल बाद बढ़ा दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने पांच फरवरी को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि अब नियमित अपील और अंतिम सुनवाई पर बचाव के लिए पेश होने वाले वाले 'ए' समूह के वकीलों को हर मामले पर प्रति दिन 21,600 रुपए मिलेंगे, जबकि 'बी' और 'सी' समूह के वकीलों को 14,400 रुपए मिलेंगे।

पहले, 'ए' समूह के वकीलों को 13,500 और 'बी' तथा 'सी' समूह के वकीलों को 9,000 रुपए मिलते थे।

पहले, 'ए' समूह के वकीलों को 13,500 रुपए और 'बी' तथा 'सी' समूह के वकीलों को 9,000 रुपए मिलते थे। सरकार के वकीलों के की फीस आखिरी बार अक्तूबर 2015 में संशोधित की गई थी। इसके अलावा, अन्य प्रकार के मामलों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के साथ सम्मेलन आयोजित करने के लिए फीस को भी संशोधित किया गया है। साथ ही दिल्ली या राज्य की राजधानी में पेश होने वाले वकीलों की फीस में भी वृद्धि की गई है। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि महंगाई और पेशेवरों को नियुक्त करने से जुड़े खर्चों में बढ़ोतरी को देखते हुए यह वृद्धि की गई है।

एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि महंगाई और पेशेवरों को काम पर रखने की बढ़ती लागत को देखते हुए यह बढ़ोतरी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। यह फैसला काफी समय से अटका हुआ था। पूर्व केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा ने 'एक्स' पर लिखा कि केंद्र सरकार के वकीलों के लिए फीस संशोधन अधिसूचना अब लागू हो गई है। कानून सचिव के रूप में कार्यकाल के दौरान इस संबंध में फैसला लिया गया था। सभी वकीलों को बधाई। यह एक दशक से अधिक समय से लंबित था। मुझे खुशी है कि यह प्रयास अपने सही निष्कर्ष पर पहुंचा। विधि आयोग की सदस्य सचिव राणा ने कहा कि यह वृद्धि अदालतों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभाशाली वकीलों को बनाए रखने के लिए आवश्यक थी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा

संघ कहेगा तो पद छोड़ने के लिए तैयार हूं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 फरवरी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि अगर संघ उन्हें पद से हटने के लिए कहेगा तो वे इस्तीफा दे देंगे और इस संगठन ने ही उनसे उनकी उम्र के बावजूद काम जारी रखने के लिए कहा है। भागवत ने यह भी कहा कि संघ का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हमेशा एक हिंदू ही होगा, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो और शीर्ष पद सबसे योग्य उम्मीदवार को ही दिया जाएगा। संघ प्रमुख के पद के लिए कोई चुनाव नहीं होता। क्षेत्रीय और मंडल प्रमुख ही संघ प्रमुख की नियुक्ति करते हैं। आम तौर पर कहा जाता है कि 75 वर्ष की आयु के बाद किसी को कोई पद धारण किए बिना काम करना चाहिए।

वे संघ शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के साथ एक संवादात्मक सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने 75 वर्ष पूरे कर लिए और मैंने संघ को इसकी सूचना भी दे दी थी, लेकिन संगठन ने मुझसे काम जारी रखने को कहा। जब भी संघ मुझसे पद छोड़ने को कहेगा, मैं पद छोड़ दूंगा लेकिन काम से सेवानिवृत्ति कभी नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का निर्माण सभी को विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए और इससे मतभेद नहीं पैदा होने चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए अंतरिम व्यापार समझौते के बारे में भागवत ने कहा कि उन्हें इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। यह सच है कि हम अलग-थलग नहीं रह सकते।

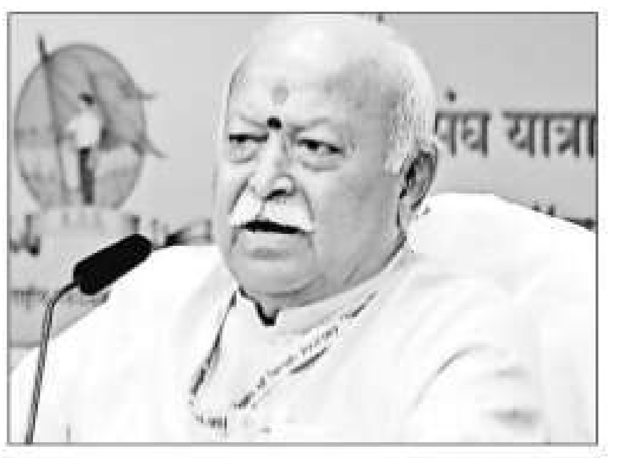

उन्होंने कहा कि संघ में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व नहीं है और स्वयंसेवक अपने काम के आधार पर पदोन्नति पाते हैं। संघ प्रमुख को हिंदू होना चाहिए चाहे उसकी जाति कोई भी हो। जब संघ की स्थापना हुई थी, तब इसका काम ब्राह्मण-बहुल समुदाय में शुरू हुआ था और इसलिए इसके अधिकांश संस्थापक ब्राह्मण थे, जिसके कारण उस समय संगठन को ब्राह्मण संगठन के रूप में जाना जाता था। लोग हमेशा ऐसे संगठन की तलाश करते हैं जिसमें उनके समुदाय के प्रतिनिधि हों।

भागवत ने कहा कि वे इस बारे में कोई निश्चित जवाब नहीं दे सकते कि संघ प्रमुख अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि से होगा या नहीं क्योंकि यह निर्णय संघ प्रमुख की नियुक्ति करने वालों पर निर्भर करता है। अगर मुझे किसी प्रमुख का चयन करना होता, तो मैं 'सबसे योग्य उम्मीदवार' के मानदंड को अपनाता। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का निर्माण सभी को विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए और इससे मतभेद नहीं पैदा होने चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए अंतरिम व्यापार समझौते के बारे में भागवत ने कहा कि उन्हें इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। यह सच है कि हम अलग-थलग नहीं रह सकते। सौदों में लेन-देन होता है। यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होना चाहिए, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें नुकसान न हो।

उन्होंने कहा कि संगठन 'अपने स्वयंसेवकों से खून के आखिरी कतरे तक काम निकलवाता है' और उन्होंने दावा किया कि संघ के इतिहास में अब तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है जब किसी को सेवानिवृत्त करना पड़ा हो। संघ का काम संस्कारों को बढ़ावा देना है, न कि चुनाव प्रचार करना। अत्यधिक प्रचार से प्रसिद्धि तो मिलती है, लेकिन फिर अहंकार भी आ जाता है। इससे बचना जरूरी है। संघ के कामकाज में अंग्रेजी कभी भी संचार का माध्यम नहीं होगी क्योंकि यह भारतीय भाषा नहीं है।

फिल्म निर्देशक अनुराज मनोहर को नोटिस जारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 फरवरी।

वन विभाग ने केरल के पंपा में सबरीमला मकरविलक्कू उत्सव की कथित रूप से वीडियो बनाने के आरोप में मलयालम फिल्म निर्देशक अनुराज मनोहर को नोटिस जारी कर तलब किया। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

केरल के पंपा में वीडियो बनाने पर वन विभाग की कार्रवाई।

अधिकारी ने बताया कि विभाग ने सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना वन क्षेत्र के अंदर वीडियो रिकार्ड करने के आरोप में मामला दर्ज किया। गुडारिकल वन रेंज कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, मनोहर को 11 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस दिया गया है। जांच के तहत उन्हें पलापल्ली वन स्टेशन पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। मनोहर पिछले महीने मकरविलक्कू उत्सव के दिन पंपा वन क्षेत्र में की गई वीडियोग्राफी के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने सबरीमला सन्निधानम में वीडियोग्राफी की अनुमति के लिए त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) से संपर्क किया था लेकिन उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था। बिना अनुमति के वीडियोग्राफी की सूचना मिलने पर बोर्ड की सतर्कता एवं सुरक्षा शाखा ने प्रारंभिक जांच की और मनोहर से पूछताछ की। एक अधिकारी ने बताया कि जांच में पाया गया कि निदेशक ने पंपा में बिना किसी अनुमति के वीडियो बनाए गए थे। बोर्ड की टीम द्वारा जांच किये जाने के बाद वन विभाग ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मनोहर ने 'नारिवेटा' और 'इश्क' जैसी कई सफल फिल्मों का निर्देशन किया है।

सतर्कता श्रीनगर के बाहरी इलाके में रविवार को राष्ट्रीय जांच एजंसी की छापेमारी के दौरान निगरानी करते सुरक्षाकर्मी।

मणिपुर : जनजातीय समूहों के बीच झड़प में गोलीबारी

हिंसा भड़कने के बाद इलाके में तनाव, एहतियातन भारी सुरक्षाबल तैनात

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 फरवरी।

मणिपुर के उखरुल जिले में रविवार शाम दो जनजातीय समूहों के बीच जोरदार पत्थरबाजी हुई, जिसके कारण प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। अधिकारियों ने बताया कि जिले के लिटन गांव में झड़प करने वाले समूहों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। क्षेत्र में कई गोलियां भी चलाए जाने की जानकारी मिली है, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया।

अधिकारियों ने बताया कि जिले के लिटन गांव में झड़प करने वाले समूहों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे।

उखरुल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि लिटन गांव में तांगखुल और कुकी समुदाय के सदस्यों के बीच शांति और सार्वजनिक सुव्यवस्था भंग होने की आशंका है। ऐसी घटनाओं से शांति भंग होने और सार्वजनिक व्यवस्था के खतरे में पड़ने के साथ मानव जीवन और संपत्ति के लिए जोखिम उत्पन्न हो सकता हैं। वर्तमान परिस्थितियां तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता दर्शाती हैं।

आदेश में कहा गया कि आठ फरवरी को शाम सात बजे से अगला आदेश जारी होने तक अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का बाहर निकलना और कोई भी अन्य कार्य या गतिविधि जो कानून-व्यवस्था को बाधित कर सकती है, पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रावधान सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में तनाव शनिवार रात से बढ़ रहा था, जब कथित रूप से तांगखुल समुदाय के एक सदस्य पर लिटन गांव में सात से आठ लोगों ने हमला किया था।

अधिकारियों ने बताया कि इस मामले को पीड़ित पक्ष व लिटन सारैखोंग के प्रमुख ने आपसी सहमति से परंपरागत तरीकों से सुलझाने का निर्णय लिया था और रविवार को बैठक निर्धारित की गई थी। हालांकि, तय बैठक नहीं हुई क्योंकि पीड़ित का परिवार नहीं आया। इसके बाद हिंसा भड़क उठी।

गोली मारते दिखाने वाले वीडियो के मामले में कांग्रेस ने की मांग

न्यायपालिका भाजपा के वीडियो पर कड़ी कार्रवाई करे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 फरवरी।

कांग्रेस ने रविवार को भाजपा पर उसकी असम इकाई के 'एक्स' पर पोस्ट किए गए एक कथित वीडियो को लेकर तीखा हमला बोला व दावा किया कि इसमें 'अल्पसंख्यकों की लक्षित और बिल्कुल करीब से हत्या' दिखाई गई है जो बेहद गंभीर है तथा न्यायपालिका को इसमें किसी भी तरह की नरमी बरते बिना कार्रवाई करनी चाहिए।

अब हटाए जा चुके इस वीडियो में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा कथित तौर पर राइफल से दो लोगों पर निशाना साधकर गोली चलाते दिखाए गए थे जिनमें से एक व्यक्ति ने टोपी पहन रखी है जबकि दूसरे की दाढ़ी है। वीडियो के कैप्शन में 'पाइंट ब्लैंक शाट' लिखा गया था। कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने इस मुद्दे पर भाजपा की कड़ी आलोचना की करते हुए कहा कि भाजपा के एक आधिकारिक खाते से अल्पसंख्यकों की लक्षित और बहुत करीब से (पाइंट ब्लैंक) हत्या दिखाने वाला वीडियो पोस्ट किया गया। यह नरसंहार का खुला आह्वान है-एक ऐसा सपना जिसे यह फासीवादी शासन दशकों से देखता रहा है। वेणुगोपाल ने कहा कि इसे सामान्य ट्रोल सामग्री मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि यह शीर्ष स्तर से फैलाया गया जहर है और इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि (प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी की ओर से इसकी निंदा किए जाने या कोई कार्रवाई की उम्मीद नहीं है, लेकिन न्यायपालिका को जरूर कदम उठाना चाहिए।

कांग्रेस के मुताबिक, अब हटाए जा चुके इस वीडियो में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा कथित तौर पर राइफल से दो लोगों पर निशाना साधकर गोली चलाते दिखाए गए थे जिनमें से एक व्यक्ति ने टोपी पहन रखी है जबकि दूसरे की दाढ़ी है।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि वीडियो को हटाना काफी नहीं है। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि यही असली भाजपा है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भी 'एक्स' पर कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप 'सबका साथ, सबका विकास' की बात करते हैं, लेकिन सरमा का मुसलमानों को गोली मारते दिखाने वाला वीडियो भाजपा की असम इकाई के आधिकारिक खाते से पोस्ट किया गया।

मध्य प्रदेश : गेहूं चोरी के 45 साल पुराने मामले में आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 फरवरी।

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक बुजुर्ग व्यक्ति को 45 साल पहले दर्ज गेहूं चोरी के एक मामले गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। मंडलेश्वर की अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) श्वेता शुक्ला ने रविवार को बताया कि सलीम और छह अन्य ने 1980 में बालसमुंद के काकड़ इलाके में खेतों से गेहूं चुराया था।

उन्होंने कहा कि उस समय सलीम 20 साल का था। चोरी किए गए गेहूं की कीमत 100 रुपए थी और उस समय एक कुंतल (100 किलोग्राम) अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं की कीमत 1.15 रुपए प्रति किलोग्राम थी। बलकवाड़ा थाना क्षेत्र के बलखड गांव का रहने वाला सलीम चोरी के बाद भाग गया और पड़ोसी धार जिले के बाग कस्बे में अपने बेटे के साथ किराने की दुकान चलाने लगा। यह मामला अदालतों में लंबित रहा जबकि सलीम के खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था।

खलटका थाने के प्रभारी मिथुन चौहान ने बताया कि एक अन्य आरोपी की तलाशी के दौरान पुलिस को पता चला कि सलीम किराने की दुकान के जरिए जीवन यापन चला रहा है। पहचान की पुष्टि होने के बाद उसे शनिवार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका मानना था कि इतने सालों के बाद मामले को भुला दिया गया होगा और वह कानूनी कार्रवाई से बच गया है। सलीम को खरगोन की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

पेज 1 का बाकी

उत्तर भारत में बदलेगा मौसम, पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना

के बीच कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि, किसी मजबूत मौसमी गतिविधि की चेतावनी नहीं है। बहरहाल, बिहार और मध्य प्रदेश समेत सभी राज्यों में पछुआ हवाओं के असर से सर्दी महसूस होगी, लेकिन तापमान बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि सोमवार से नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई से लेकर मैदानी भागों तक बारिश से मौसम खराब होगा।

11 फरवरी तक पहाड़ों पर लगातार बारिश और बर्फबारी के संकेत हैं। उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बागेश्वर में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं, हिमाचल प्रदेश के चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुकुमसेरी, ताबो समेत कई इलाकों में बर्फबारी की गति बढ़ सकती है और बारिश से मौसम पूरी तरह खराब हो जाएगा। मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान कुछ इलाकों में तापमान माइनस और अधिकांश हिस्सों पर 5 डिग्री सेल्सियस से कम रहने का अनुमान है। वहीं, जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले स्थानों से लेकर घाटी में बर्फबारी के बीच गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। आइएमडी ने बताया घाटी समेत कोकरनाग, कुपवाड़ा, गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, पहलगाम और अमरनाथ इत्यादि इलाकों में तापमान माइनस में रहेगा।

गोगोई का मामला गृह मंत्रालय को सौंपेगी असम सरकार : हिमंत

पाकिस्तान की एक 'अत्यंत गोपनीय' यात्रा की थी और माना जाता है कि वहां उन्होंने 'किसी प्रकार का प्रशिक्षण' लिया। उन्होंने कांग्रेस नेता को इस यात्रा को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की चुनौती दी, अन्यथा उन पर 'राष्ट्रद्रोह' के आरोप लगेंगे। इस बीच, प्रदेश कांग्रेस प्रमुख गोगोई ने सरमा के संवाददाता सम्मेलन को एक 'सी-ग्रेड सिनेमा से भी बदतर' और 'सुपर फ्लाप' करार दिया। उन्होंने दावा किया कि इन लोगों ने भारत सरकार को दरकिनार करते हुए स्थानीय निकाय एजंसियों के साथ काम किया और इसकी जांच असम पुलिस नहीं कर सकती। इसलिए हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जांच कराए जाने की सिफारिश की है।

उन्होंने कहा कि एलिजाबेथ ने पाकिस्तान में शेख के संगठन 'लीड पाकिस्तान' के साथ काम किया। फिर उनका तबादला भारत में हो गया और उन्होंने उसी संगठन में काम किया। लेकिन उनका वेतन अली तौकीर शेख द्वारा ही दिया जाता रहा।मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि लीड पाकिस्तान ने 'लीड इंडिया' को पैसे भेजे और लीड इंडिया ने एफसीआरए नियमों को दरकिनार करते हुए एलिजाबेथ को भुगतान किया। पाकिस्तानी एजंसियां किसी भारतीय संस्था को दान नहीं दे सकतीं, क्योंकि वह एक शत्रु राष्ट्र है। संभवतः यूपीए की तत्कालीन सरकार के समय में एलिजाबेथ को भुगतान करने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त की गई थी। उन्होंने दावा किया कि भारत में काम करने के बाद एलिजाबेथ ने भारत से संबंधित जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की और वह शेख को रपट दिया करती थीं। एलिजाबेथ को नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद जलवायु संबंधी कार्रवाई के बारे में आईबी सूत्रों से जानकारी मिली। उन्होंने शेख को 45 पन्नों की रपट भेजी।

लीड इंडिया के साथ काम करते समय एलिजाबेथ ने छह बार इस्लामाबाद की यात्रा की, जबकि एक अन्य एनजीओ में शामिल होने के बाद उन्होंने तीन बार पाकिस्तान की यात्रा की। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि एफसीआरए नियमों का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान से सीधे धन प्राप्त करना आसान नहीं था।

ठेकेदार तो पकड़े गए, पर 'दोषी' अधिकारियों का नंबर कब आएगा

को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। उन्होंने प्रसाद को शहीद का दर्जा देते हुए दूसरों की जान बचाने के प्रयास में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अधिकारी की सराहना की। रविवार को डीजीपी सिंघल और फरीदाबाद के आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने प्रसाद के परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। वे घायलों के बारे में जानकारी लेने के लिए अस्पताल भी गए।पर्यटन निदेशक पार्थ गुप्ता और फरीदाबाद के उपायुक्त आयुष सिन्हा ने रविवार को सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मेला मैदान का निरीक्षण किया।

अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना मेला मैदान में एक गेट गिरने के ठीक एक घंटे बाद हुई, जिसमें एक बच्चे समेत दो लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने बताया कि एसआइटी का नेतृत्व पुलिस उपायुक्त (अपराध) मुकेश कुमार कर रहे हैं, जबकि सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) वरुण दहिया और सूरजकुंड थाने के उपनिरीक्षक संजय कुमार इसके सदस्य हैं।

सहायक उपनिरीक्षक सन्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, वह घटना के समय निरीक्षक प्रसाद के साथ मेला परिसर में मौजूद थे। इसमें कहा गया कि प्रसाद फंसे लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे थे कि तभी झूला एक ओर से पूरी तरह टूटकर प्रसाद के ऊपर गिर गया। निरीक्षक की मौत झूले के मालिक मोहम्मद शाकिर और उसके कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन न किए जाने व लोगों की जान को जानबूझकर खतरे में डालने के कारण हुई।जिला प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त-सह-मेला प्रशासक सतबीर सिंह कर रहे हैं।

इस समिति के सदस्यों में डीसीपी मकसूद अहमद, वाईएमसीए यूनिवर्सिटी के यांत्रिक विभाग के विभागाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, कार्यकारी अभियंता (यांत्रिक) हितेश कुमार और कार्यकारी अभियंता (विद्युत) अश्विनी गौर शामिल हैं। हादसे के मद्देनजर, एहतियात के तौर पर आगे की जांच होने तक झूले वाले क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सुरक्षा मानकों की गहन समीक्षा की जा रही है। प्रसाद के अचानक निधन से मथुरा जिले के उनके पैतृक गांव डेंगरा में लोगों को गहरा सदमा लगा। प्रसाद के एक भाई प्रदीप शिक्षक हैं और अपने पिता सूरजमल और माता शांति देवी के साथ गांव में रहते हैं। उनके दूसरे भाई सतीश चंद्र बल्लभगढ़ की एक रसायन कारखाने में काम करते हैं जबकि चंद्रभान सिंह फरीदाबाद की एक मोटर कंपनी में कार्यरत हैं।

प्रदीप ने बताया कि हमें शनिवार रात आठ बजे यह खबर मिली। उनकी (प्रसाद की) पत्नी सुधा अपनी दो बेटियों निधि व दीप्ति और बेटे गौरव के साथ सोनीपत पुलिस लाइंस के सरकारी आवास में रहती हैं। मेरे भाई को 2019-20 में राज्यपाल द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था।

आतंकवाद पर दोहरा मापदंड और कोई समझौता मंजूर नहीं

और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। मोदी शनिवार को कुआलालंपुर पहुंचे। मोदी और इब्राहिम दोनों ने व्यापार निस्तारण के लिए स्थानीय मुद्राओं - भारतीय रुपया और मलेशियाई रिंगिट के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। मोदी ने भारत-मलेशिया संबंधों को विशेष बताते हुए कहा, 'हम रणनीतिक विश्वास के माध्यम से आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेंगे।' उन्होंने मीडिया में जारी अपने बयान में कहा, 'हम समुद्री पड़ोसी हैं। सदियों से दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे और स्नेहपूर्ण संबंध रहे हैं।'

मोदी ने मलेशिया में भारतीय वाणिज्य दूतावास स्थापित करने के भारत के निर्णय की भी घोषणा की। अपने संबोधन में इब्राहिम ने भारत की आर्थिक वृद्धि का उल्लेख किया और कहा कि अगर उनका देश भारत के साथ सहयोग के और अधिक तरीके एवं अवसर तलाश सके तो उसे बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा, 'यह (भारत की आर्थिक वृद्धि) अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार के क्षेत्र में एक शानदार उन्नति है।' उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करने के निर्णय को उल्लेखनीय बताया। वार्ता के दौरान मलेशिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बाद भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।

सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग के बारे में विस्तार से बताते हुए मोदी ने कहा कि आतंकवाद विरोधी अभियान, खुफिया जानकारी साझा करने और समुद्री सुरक्षा में सहयोग को मजबूत किया जाएगा, साथ ही दोनों पक्ष रक्षा संबंधों को और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा, 'कृत्रिम मेधा (एआइ) और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ हम सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे।' उन्होंने यह भी कहा कि सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) फोरम में हुई चर्चाओं ने व्यापार और निवेश के नए अवसर खोले हैं। प्रधानमंत्री ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर भारत के रुख और इस क्षेत्र में 10 देशों के समूह वाले आसियान (दक्षिणपूर्व एशियाई देशों का संघ) की केंद्रीय भूमिका पर भारत के दृढ़ विचारों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र विश्व के विकास के इंजन के रूप में उभर रहा है। भारत आसियान के साथ मिलकर पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है।' उन्होंने कहा, 'मलेशिया जैसे मित्र देशों के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को और अधिक विस्तारित करेगा। हम इस बात से सहमत हैं कि आसियान-भारत व्यापार समझौते की समीक्षा शीघ्रता से पूरी की जानी चाहिए।'

मोदी ने कहा कि उन्होंने और इब्राहिम ने क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा, 'वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया के बीच बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।' उन्होंने कहा, 'हम इस बात से सहमत हैं कि आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार आवश्यक है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट हैः कोई दोहरा मापदंड नहीं कोई समझौता नहीं।' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'भारत-मलेशिया संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की हम सराहना करते हैं। आइए, हम मिलकर एक समृद्ध मलेशिया के आपके सपने और विकसित भारत के हमारे संकल्प को साकार करें।' संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट और कड़ी निंदा की और आतंकवाद के प्रति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति का आ''ान किया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद से व्यापक और सतत तरीके से निपटने के लिए समन्वित वैश्विक प्रयासों का आ''ान किया तथा कट्टरता और हिंसक चरमपंथ का मुकाबला करने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की।

उन्होंने आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने और आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नयी और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग को रोकने की दिशा में काम करने का भी संकल्प लिया। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और एफएटीएफ (वित्तीय कार्रवाई कार्य बल) सहित आतंकवाद का मुकाबला करने में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मोदी और इब्राहिम ने संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों में सहयोग को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के सुधारों का समर्थन करने पर भी सहमति व्यक्त की।

राजनीति में भाग लेने से इन्कार करने का दंड यह है कि आप अंततः अपने से बुरे लोगों द्वारा शासित होते हैं। -प्लेटो

यूरोपीय संघ से समझौते के बाद दबाव में आए अमेरिका की अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति नई दिल्ली के साथ उसके संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। विपक्ष के दावों व अमल की चुनौतियों के बावजूद इससे आत्मविश्वासी भारत और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इसके बढ़ते कद की झलक मिलती है।

ऐतिहासिक समझौते की ओर

भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनना दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी की दिशा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है, जो भारत को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी बाजारों तक उसकी पहुंच को बढ़ाता है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष फरवरी के मध्य में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर वार्ता शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन पिछले ही वर्ष अप्रैल में अमेरिका की तरफ से 25 फीसदी के पारस्परिक टैरिफ और फिर अगस्त में रूस से तेल खरीदने के दंडस्वरूप भारत पर और 25 फीसदी टैरिफ से अमेरिकी बाजारों में भारतीय निर्यात संकट में आ गया था। इसने भारत को वैकल्पिक निर्यात गंतव्यों की तलाश के लिए प्रेरित किया। तथ्य यह भी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा जैसे कुछ उत्पादों को अमेरिका द्वारा 50 फीसदी के टैरिफ से मुक्त रखने की वजह से वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल-दिसंबर में गत वर्ष की समान अवधि की अपेक्षया आठ फीसदी बढ़ोतरी ही हुई है। इस दौरान, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ओमान और यूरोपीय संघ के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते अगले वर्ष तक पूरी तरह संचालित होने लगेंगे, लिहाजा अगले वित्तीय वर्ष में भारतीय निर्यात में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। खासकर यूरोपीय संघ के भारत के साथ हुए समझौते के बाद से ही दबाव में आए अमेरिका की भारत के साथ समझौते पर सहमति नई दिल्ली के साथ उसके संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ तो है ही, इससे एक आत्मविश्वासी भारत की झलक भी मिलती है। भारत के लिए यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस और चीन को मिलाकर होने वाले निर्यात का तकरीबन चार गुना निर्यात वह अमेरिका को करता है। चूंकि अमेरिका ने चीन पर 37 फीसदी टैरिफ लगाया हुआ है, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजारों में चीनी कंपनियों के मुकाबले बढ़त हासिल हो सकती है। जहां तक सवाल विपक्ष के दावों का है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का यह आश्वासन अहम है कि डेयरी उत्पादों के मामले में किसी भी शर्त के साथ बाजार नहीं खोला गया है। सरकार यह तो कह रही है कि बाजार को उन्हीं कृषि उत्पादों के लिए सीमित तौर पर खोला गया है, जहां भारत आयात पर निर्भर है या जहां घरेलू उत्पादन कम है, पर उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि यह आंशिक खुलापन लंबे समय में घरेलू किसानों पर दबाव न डाले। समझौते की जटिलताओं के मद्देनजर इसका कार्यान्वयन नई चुनौतियां पैदा कर सकता है, लेकिन इससे भारत को जो हासिल हुआ है, उसे बदलती वैश्विक भू-राजनीति और आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर ही समझा जा सकता है।

सत्ता में कोई आए, चुनौती तो रहेगी

बांग्लादेश में होने वाले चुनाव के स्पष्ट संकेत हैं कि बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन देखना होगा कि क्या वह सुधार व स्थिरता और जनादेश व वास्तविकताओं के बीच संतुलन बना पाएगी, या फिर यह चुनाव देश के अस्थिर इतिहास का एक और विवादित अध्याय बनकर रह जाएगा?

बांग्लादेश इस समय अपने इतिहास के सबसे निर्णायक चुनावों में से एक की ओर बढ़ रहा है। यह चुनाव केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन-सी पार्टियां मैदान में हैं, बल्कि इस कारण भी कि देश की सबसे पुरानी और लंबे समय तक सत्ता में रही पार्टी अवामी लीग इसमें शामिल नहीं है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार द्वारा आयोजित 12 फरवरी, 2026 को होने वाला आम चुनाव तकनीकी रूप से पिछले कई चुनावों की तुलना में अधिक स्वतंत्र व निष्पक्ष माना जा रहा है। इसके बावजूद, अवामी लीग की अनुपस्थिति चुनाव की राजनीतिक समावेशिता तथा नैतिक वैधता पर प्रश्नचिह्न खड़े करती है। यदि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सत्ता में लौटती भी है, जैसा कि अधिकांश आकलन संकेत देते हैं, तो उसकी जीत अधूरी और कई लोगों के लिए खोखली प्रतीत हो सकती है।

आनंद कुमार
एसोसिएट फेलो
एमपीआईडीएसए

इस चुनाव की पृष्ठभूमि असाधारण परिस्थितियों से बनी है। अगस्त 2024 में हुए छात्र-नेतृत्व वाले जनविद्रोह ने शेख हसीना के 15 वर्षों के शासन का अंत कर दिया और उन्हें भारत में शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद एक अंतरिम प्रशासन की स्थापना हुई, जिसने जवाबदेही व सुधार का वादा किया।

हिंसक दमन में भूमिका के आरोपों के चलते अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। हालांकि शेख हसीना के पतन का देश के बड़े हिस्से ने स्वागत किया, पर अवामी लीग को चुनाव से बाहर कर देना इस आशंका को जन्म देता है कि लोकतांत्रिक पुनर्निर्माण राजनीतिक सुधार के बजाय राजनीतिक बहिष्कार के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इस बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य का सबसे बड़ा लाभ बीएनपी को मिला है। लगभग 17–18 वर्षों तक सत्ता से बाहर रहने, दमन, जेल और निर्वासन झेलने के बाद पार्टी एक बार फिर सत्ता के करीब दिखाई दे रही है। दिसंबर, 2025 में लंदन से तारिक रहमान की वापसी ने इस पुनरुत्थान को प्रतीकात्मक रूप से मजबूत किया। चुनाव से ठीक पहले जारी बीएनपी का घोषणापत्र गंभीरता, संतुलन और शासन क्षमता दिखाने का प्रयास करता है। इसमें चुनावी सुधार, जवाबदेही, मतदाता की गरिमा और नागरिकों के प्रति उत्तरदायी सरकार की बात की गई है। इसकी भाषा अपेक्षाकृत संयमित है, जो दर्शाती है कि मुल्क का मतदाता टकराव व अस्थिरता से थक चुका है।

घोषणापत्र में भारत का नाम सीधे लिए बिना बीएनपी ने सीमा हत्याओं, जबरन धकेलने, तस्करी और नदी जल-बंटवारे जैसे मुद्दों को उठाया है, जो लंबे समय से बांग्लादेश–भारत संबंधों में संवेदनशील रहे हैं। तीस्ता और पद्मा जैसी नदियों में 'उचित हिस्सेदारी' की मांग, संयुक्त नदी आयोग को सशक्त बनाने की बात और 'बांग्लादेश पहले' का सिद्धांत दर्शाता है कि बीएनपी नई दिल्ली के साथ रिश्तों को बगैर शत्रुता के पुनर्संतुलित करना चाहती है। वहीं, चीन का कोई स्पष्ट उल्लेख न होना इस ओर संकेत करता है कि बीएनपी किसी एक महाशक्ति के साथ खुला झुकाव दिखाने के बजाय रणनीतिक लचीलापन बनाए रखना चाहती है। हालांकि बीएनपी की राजनीतिक स्थिति निर्विवाद नहीं है।

जमात-ए-इस्लामी के साथ एकता सरकार से इन्कार कर पार्टी ने इस्लामी राजनीति से दूरी बनाने और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भरोसा कायम करने की कोशिश की है। यह 2001–06 के दौर से अलग है। तारिक रहमान का आकलन है कि जमात से खुला गठबंधन शहरी मतदाताओं, अल्पसंख्यकों और विदेशी साझेदारों के बीच पार्टी की स्वीकार्यता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बावजूद, बीएनपी को हेफाजत-ए-इस्लाम के जमात-विरोधी रुख से अप्रत्यक्ष लाभ मिला है, लेकिन इससे वैचारिक जटिलताएं भी बढ़ी हैं। मुख्य चुनौती जमात-नेतृत्व वाले गठबंधन से है, जिसमें छात्र आंदोलन से निकली नेशनल सिटिजन पार्टी भी शामिल है। जमात ने खुद को नए सिरे से पेश करने की कोशिश की है, और एक हिंदू उम्मीदवार को भी मैदान में उतारा है। फिर भी महिलाओं के अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं। नेशनल सिटिजन पार्टी का जमात के साथ जाना उसकी स्वतंत्र सुधारवादी छवि को नुकसान पहुंचाता है और इससे आंतरिक असंतोष तथा सार्वजनिक संदेह, दोनों बढ़े हैं। राजनीतिक दलों से परे, स्थिरता के असली निर्णायक अन्य संस्थानों में निहित हैं। मुख्य सलाहकार के रूप में मोहम्मद यूनुस एक कठिन संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं—विश्वसनीय चुनाव कराना, सुरक्षा संभालना और जुलाई राष्ट्रीय चार्टर पर जनमत संग्रह कराना। आलोचकों का मानना है कि आम चुनाव के साथ जनमत संग्रह कराना भ्रम और राजनीतिकरण को बढ़ा सकता है, खासकर तब, जब ऊपरी सदन जैसी प्रमुख सिफारिशें पहले ही बीएनपी जैसे दलों के घोषणापत्र से गायब हैं। बांग्लादेश के इतिहास में सैन्य तख्तापलटों की स्मृति अब भी ताजा है, पर 2024 के विद्रोह के दौरान सेना का संयम एक बड़ा बदलाव था। फिर भी कानून-व्यवस्था की कमजोर स्थिति में सेना की तैनाती और चुनाव के दौरान उसकी भूमिका अनिवार्य है। शेख हसीना के शासनकाल में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए सेवारत अधिकारियों पर मुकदमे सैन्य संस्थान के भीतर असहजता पैदा कर सकते हैं। भावी सरकार को नागरिक-सैन्य संबंधों को सावधानी से संतुलित करना होगा।

मानवाधिकारों का मुद्दा भी चुनावी माहौल को जटिल बना रहा है। अवामी लीग के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की हिरासत में मौत ने राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों को हवा दी है। ऐसी घटनाएं अल्पसंख्यकों के बीच भय और असुरक्षा की भावना को मजबूत करती हैं। सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान को लेकर प्रदर्शन, चुनाव बहिष्कार की धमकियां और प्रशासनिक पक्षपात के आरोप बताते हैं कि असंतोष गहरा है। जब लगभग हर प्रमुख पक्ष चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हो, तो परिणाम चाहे जो भी हों, उनकी वैधता कमजोर हो जाती है। संकेत स्पष्ट हैं कि बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन जीत अपने-आप में शासन की गारंटी नहीं है।

नई सरकार विरासत में एक खंडित समाज पाएगी। ऐसे में बांग्लादेश के लोकतांत्रिक घावों को पूरी तरह भर पाना कठिन रहेगा। असली परीक्षा सत्ता में आने के बाद होगी—क्या बीएनपी न्याय और संयम, सुधार और स्थिरता तथा जनादेश और संस्थागत वास्तविकताओं के बीच संतुलन बना पाएगी, या फिर यह चुनाव देश के अस्थिर राजनीतिक इतिहास का एक और विवादित अध्याय बनकर रह जाएगा।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

नॉर्मन कजिंस

मृत्यु तो निश्चित है। वह प्रकृति का नियम है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। प्रश्न यह नहीं है कि मृत्यु कब आएगी, बल्कि यह है कि उसके आने तक हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं।

हमने अपने भीतर क्या जीवित रखा

हम अक्सर मृत्यु को जीवन की सबसे बड़ी क्षति मानते हैं। हमें लगता है कि किसी व्यक्ति का चले जाना, उसकी सांसों का थम जाना ही अंतिम और सबसे गहरा दुख है। हम मृत्यु का नाम सुनते ही सिहर उठते हैं। लेकिन इस सोच में हम एक बहुत बड़ी सच्चाई को भूल जाते हैं। मृत्यु तो निश्चित है। वह प्रकृति का नियम है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। प्रश्न यह नहीं है कि मृत्यु कब आएगी, बल्कि यह है कि उसके आने तक हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी हानि नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी हानि वह है, जो हमारे भीतर जीवित रहते हुए मर जाता है। जब हम जीना भूल जाते हैं, तभी हमारे भीतर मृत्यु शुरू होती है। जीने का अर्थ केवल जिम्मेदारियां निभाना नहीं है। जीना है महसूस करना, सवाल करना, गलतियों से सीखना और अपने मन की आवाज को सुनना। लेकिन जीवन की दौड़ में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि संवेदनाएं बोझ लगने लगती हैं। हम सपनों को अव्यावहारिक कहकर त्याग देते हैं, इच्छाओं को डर के नाम पर दबा देते हैं और धीरे-धीरे एक ऐसा जीवन जीने लगते हैं, जो सुरक्षित तो होता है, पर जीवंत नहीं होता।

जब प्रयास करने की इच्छा खत्म हो जाती है, जब कुछ नया शुरू करने का साहस नहीं बचता, जब असफलता का डर हमें जकड़ लेता है, तब हम जीवित रहकर भी जीवन से दूर हो जाते हैं। यह एक शांत मृत्यु होती है, जिसमें कोई शोर नहीं होता, कोई आंसू नहीं बहते, पर भीतर कुछ हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय हमें जीवन से जोड़ने के बजाय उससे काट देता है। हम सोचते हैं कि समय कम है, इसलिए जोखिम नहीं ले सकते। हम कहते हैं कि हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए इंतजार करना बेहतर है। लेकिन यह इंतजार ही वह जगह है, जहां जीवन फिसलता चला जाता है। समय गुजरता रहता है और हम बस देखते रहते हैं। इसी बीच हमारे भीतर की जिज्ञासा, उत्साह और रचनात्मकता दम तोड़ देती है। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है, जब हम स्वयं से समझौता कर लेते हैं। जब हम वह बन जाते हैं, जो हम नहीं हैं, केवल इसलिए कि समाज को यही स्वीकार्य है। जब हम अपने विचारों को छोटा कर लेते हैं, ताकि टकराव न हो। जब हम सच बोलने से बचते हैं, क्योंकि चुप रहना आसान लगता है। हर ऐसा समझौता हमारे भीतर के किसी हिस्से को कमजोर करता है। जीवन का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं, उसकी गहराई में होता है। कोई व्यक्ति सौ वर्ष जी सकता है, फिर भी भीतर से खाली रह सकता है, जबकि कोई कम समय में भी जीवन को पूरी तरह महसूस कर सकता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने अपने भीतर क्या जीवित रखा। क्या हमने प्रेम को जीवित रखा, करुणा, सच्चाई को, या केवल डर और आदतों के सहारे समय काटा। मृत्यु अपरिहार्य है, लेकिन भीतर का मर जाना हमारी अपनी लापरवाही का परिणाम होता है। हम चाहें तो अपने भीतर की संवेदनाओं को बचा सकते हैं।

प्रेम व करुणा को बचाएं

सूत्र

मृत्यु वह नहीं जो जीवन के अंत में होता है, बल्कि वह है जो जीते-जी हमारे भीतर मर जाता है। जब हम डर के कारण सपने देखना छोड़ देते हैं, सवाल करना बंद कर देते हैं और सच से समझौता कर लेते हैं, तब हम जीवित रहकर भी जीवन खो देते हैं। प्रेम, करुणा और सच्चाई को अपने भीतर बचाकर रखें।

दूसरा पहलू

आगरा के सिकंदरा में मौजूद अकबर के मकबरे की बनावट मुगल वास्तुकला से अलग है, जो इतिहासकारों के बीच कौतुहल का विषय है।

अकबर के मकबरे की चौथी मंजिल पर कब्र का राज

कभी-कभी सच तक पहुंचने का रास्ता इतना धुंधला होता है कि पता ही नहीं चलता कि मंजिल कहां है। कई इतिहासकारों ने आगरा के सिकंदरा में मौजूद अकबर के मकबरे के बारे में लिखा है कि इसमें इस्लामी, बौद्ध, हिंदू व ईसाई धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया, या इसमें सुलहकुल का सिद्धांत दिखता है। मकबरे की खासियत यह है कि अकबर ने इसे बनाने का विचार अपने जीवनकाल में ही कर लिया था।

भूपेंद्र कुमार

वर्षों तक किसी की भी नजर चौथी मंजिल पर मौजूद कब्र पर नहीं पड़ी। लेकिन एक शोधार्थी ने इसे खोज निकाला।

इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शायद हमले की संभावनाओं से आशंकित होकर अकबर ने वह गोपनीय कक्ष बनवाया था, जहां उसे दफन किया जाए। लेकिन इसका राज उसकी मौत के साथ ही दफन हो गया।

इसे बहिश्ताबाद का नाम दिया गया, यानी स्वर्ग सरीखा स्थान। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन यह इमारत आज भी दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचती है। आगरा के जिस इलाके (सिकंदरा) में यह बना है, उसे नाम ही सल्तनत काल के शासक सिकंदर लोदी से मिला है। अकबर के शासनकाल में 1602 ईस्वी में निर्माण शुरू हुआ और करीब 15 लाख रुपये लागत आई। 1605 में अकबर का निधन हो गया। फिर उसके उत्तराधिकारी जहांगीर ने इसे 1613 में पूरा करा दिया। पर एक बात है, जो इतिहासकारों को उलझन में डाल देती है। दरअसल, मुगल वास्तुकला में तहखाने में असली कब्र, उसके ऊपर कब्र की प्रतिकृति और फिर गुंबद होता है। मगर इस मकबरे के तहखाने में कब्र तो है, पर उसके ऊपर कब्र की प्रतिकृति और गुंबद नहीं है। तहखाने में संगमरमर से बनी अकबर की मुख्य कब्र बहुत सादी है और इस पर कुछ नहीं लिखा है। हैरानी की बात यह है कि पांचवीं मंजिल पर असली कब्र की प्रतिकृति है, जो अलंकृत है और बेहतरीन कारीगरी की मिसाल है। इस पर अरबी व फारसी में अल्लाह के 99 नाम लिखे गए हैं। इसे ही अकबर की कब्र की प्रतिकृति माना जाता है।

पर असली राज चौथी मंजिल का है। वरिष्ठ पत्रकार थॉमस स्मिथ ने अपने लेख में लिखा था कि वर्षों तक किसी की भी नजर चौथी मंजिल पर मौजूद कब्र पर नहीं पड़ी। लेकिन एक शोधार्थी ने इसे खोज निकाला। यहां पहुंचना आसान नहीं था। यहां तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनाई गई। फर्श से छह फीट की ऊंचाई पर एक खिड़की है, जिससे एक बड़े गुप्त कक्ष में पहुंचा जा सकता है। पर इसके लिए पहले सीढ़ी लगानी होगी। कक्ष के मध्य में प्लास्टर और ईंटों से बनी साधारण कब्र है। यह किसकी है, कहीं भी इसका कोई ब्योरा उपलब्ध नहीं है। इतालवी यात्री मनुची ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि 1688 में औरंगजेब के शासनकाल में भरतपुर के राजाराम के नेतृत्व में जाटों ने मकबरे पर हमला किया और अकबर की कब्र को नुकसान पहुंचाया। इतिहासकार मानते हैं कि इस तरह की संभावनाओं से आशंकित होकर ही तो कहीं अकबर ने वह गोपनीय कक्ष नहीं बनवाया था, जहां उसे दफन किया जाए। यह ऐसा सवाल है, जिसका जवाब शायद इसे जानने वाले के साथ ही दफन हो गया।

आंकड़े

तनावग्रस्त देश

पिछले कुछ वर्षों में, चिंता एवं मानसिक तनाव एक वैश्विक महामारी की तरह उभरे हैं। आजकल लोगों के जीवन में तनाव का स्तर काफी बढ़ गया है।

अर्जेंटीना	49
फिनलैंड	45
कनाडा	42
अमेरिका	39
इंडोनेशिया	19

आंकड़े रोजमर्रा के जीवन में तनाव महसूस करने वाले देशों के प्रतिशत में। | स्रोत : स्टेटिस्टा कंज्यूमर इनसाइट्स

माता अनसूया को ज्ञात हुआ कि माता सीता को दीर्घकाल तक वनवास का कठोर जीवन व्यतीत करना होगा, तो उन्होंने माता सीता को एक दिव्य साड़ी भेंट की।

जानकी जयंती

अंतर्यात्रा
संकलित

आज जानकी जयंती का पावन पर्व है। माता सीता से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं हमारे शास्त्रों और परंपराओं में वर्णित हैं। उन्हीं में से एक अत्यंत भावपूर्ण और प्रेरक कथा यह भी है।

जब श्रीराम, लक्ष्मण और माता सीता चौदह वर्षों के वनवास के लिए अयोध्या से प्रस्थान कर रहे थे, तब उनके पथ में महर्षि अत्रि का पवित्र आश्रम आया। प्रभु श्रीराम ने वहां कुछ समय विश्राम करने का निश्चय किया।

आश्रम में महर्षि अत्रि की धर्मपत्नी, पतिव्रता माता अनसूया ने उनका अत्यंत श्रद्धा और स्नेह से आदर-सत्कार किया। माता अनसूया स्वयं तप, त्याग और शील की मूर्ति थीं। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि माता सीता को दीर्घकाल तक वनवास का कठोर जीवन व्यतीत करना होगा, तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने माता सीता को स्नेहपूर्वक एक दिव्य साड़ी भेंट की। यह कोई साधारण वस्त्र नहीं था। अग्निदेव ने तपोबल से प्रसन्न होकर माता अनसूया को यह साड़ी दी थी।

उस दिव्य साड़ी की विशेषता यह थी कि वह कभी मैली नहीं होती थी, न फटती थी और न ही अपनी आभा खोती थी। वह सदैव नवीन और उज्ज्वल बनी रहती थी। माता सीता ने वनवास के चौदह वर्षों तक उसी साड़ी को धारण किया। घोर वन जीवन, कष्ट और कठिनाइयों के बावजूद वह साड़ी चौदह वर्षों बाद भी वैसी ही नई रही।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 9 फरवरी, 1953

अमेरिका का साम्राज्य विस्तार रक्तपात के बिना संभव नहीं

का साम्राज्य
विस्तार एशियनों का खून
बहा कर किया जायगा

जम्मू सचिवालय के प्रचार मन्त्री गिरफ्तार

न्यूयॉर्क टाइम्स का कथन है कि राष्ट्रपति आइजनहावर एशिया के देशों में विशाल सेना खड़ी करने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका का साम्राज्य विस्तार रक्तपात के बिना संभव नहीं होगा। राष्ट्रपति अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कुछ भी कर सकते हैं।

वन नेशन और वन परीक्षा व आवेदन शुल्क

वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर चर्चा के साथ उच्चतर शिक्षा संस्थान जिस तरह से मनमानी फीस वसूल रहे हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए।

डॉ. विवेक एस अग्रवाल

मुद्दा

देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर व्यापक चर्चा की जा रही है। इसके पीछे मूल रूप से जनता को होने वाली असुविधा तथा निरंतर चुनाव संचालन में होने वाले व्यय को आधार माना गया है। इसी संदर्भ में एक विषय देश में निरंतर होने वाली परीक्षाएं भी है। विद्यालयी स्तर पर, निजी हो या सरकारी, दोनों प्रकार की संस्थाओं का नियंत्रण राज्य या केंद्रीय बोर्ड के माध्यम से किया जाता रहा है, लेकिन तदुपरांत संपूर्ण शिक्षा एवं प्रतियोगिताएं लगभग अनियंत्रित हो जाती हैं।

स्वायत्तता एवं निजीकरण के नाम पर उच्चतर शिक्षा संस्थानों को नीति के साथ विभिन्न मदों हेतु अपने शुल्क तय करने की भी छूट प्राप्त होती है। विभिन्न संस्थानों के प्रवेश शुल्क से लेकर शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क में अत्यधिक भिन्नता देखने को मिलती है। इन भिन्नताओं की शुरुआत प्रवेश चाहने वाले भावी विद्यार्थियों को बेचे जाने वाले आवेदन पत्रों से ही हो जाती है। यदि आवेदन पत्र का विश्लेषण करें, तो उसमें मूलभूत जानकारी के साथ-साथ संस्थान संबंधी जानकारी होती है। प्रशासनिक शुल्क भी जोड़ लिया जाए, तो उसकी लागत कुछ सौ रुपये तक ही सीमित रह जाएगी। लेकिन संस्थानों द्वारा छात्रों से अधिकतम राशि वसूली जाती है। यह व्यवस्था न सिर्फ औपचारिक, अपितु अनौपचारिक एवं ट्यूशन तथा प्रशिक्षण संस्थानों में भी विद्यमान है।

पूरे देश में स्थित विद्यालयों में 25 करोड़ तथा महाविद्यालयों में पांच करोड़ के करीब छात्र अध्ययनरत हैं। यदि इनमें से आधे सरकारी, तो शेष छात्र निजी क्षेत्र में ही पढ़ रहे हैं। यह भी तथ्य है कि एक विद्यार्थी औसतन दो बार प्रवेश हेतु आवेदन प्रपत्र खरीदता है। यदि निजी क्षेत्र में एक आवेदन पत्र की न्यूनतम कीमत 1,000 रुपये मानी जाए, तो देशभर में लगभग 25,000 करोड़ रुपये का व्यवहार मात्र प्रवेश हेतु आवेदन पत्रों की बिक्री से ही होता है। उच्चतर शिक्षा के निजी संस्थानों में तो आवेदन पत्र की राशि पूरी तरह बेलगाम दिखाई देती है। इसके विपरीत, केंद्रीय विद्यालयों समेत सरकारी शिक्षण संस्थानों में यह प्रायः शून्य ही होता है। उच्चतर शिक्षा के निजी संस्थानों में तो आवेदन पत्र की राशि बेलगाम होती है। आवेदन के डिजिटल विकल्प के लिए भी शुल्क वसूला जाता है। सरकारी विद्यालयों से बेरुखी का एक कारण यह भी हो सकता है कि वहां किसी भी प्रकार के शुल्क की वसूली नहीं की जा सकती, क्योंकि आमजन के मन में बिना शुल्क की किसी भी वस्तु या सेवा को गुणात्मक दृष्टि से हेय समझ लिया जाता है।

शिक्षण संस्थानों में आवेदन, प्रार्थना पत्र और परीक्षा जैसे हर अवसर को राजस्व वसूली का माध्यम बना लिया गया है। हाल ही एक निजी मेडिकल विश्वविद्यालय में पीजी की परीक्षा हेतु आवेदन शुल्क की राशि आठ लाख रुपये वसूली गई। छात्रों के लिए मजबूरी होती है कि आवेदन के बिना परीक्षा कैसे दें? यह प्रत्यक्ष रूप से न सिर्फ ब्लैकमेलिंग, बल्कि शोषण के समकक्ष अपराध भी है। छात्र एवं अभिभावक आवाज नहीं उठा पाते, क्योंकि संपूर्ण कॅरिअर दांव पर लगा होता है। सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि स्वायत्तता के नाते संपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार निजी प्रबंध मंडल को ही है। लेकिन तथ्य यह भी है कि समस्त निजी विश्वविद्यालय राज्यों की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के जरिये स्थापित हैं और उनके प्रबंध मंडल में सरकारी प्रतिनिधि भी होते हैं, किंतु अपनी अक्षमता को ढकने के लिए ऐसे बहाने गढ़ दिए जाते हैं। वर्तमान युग में जब सब कुछ डिजिटल हो गया है, संस्थानों द्वारा डिजिलॉकर, लिंक, ई-मेल या किसी साझा प्रवेश संबंधी आवेदन के जरिये भावी छात्र का डाटा उपयोग कर धन के साथ कागज के जरिये हो रहे पर्यावरणीय नुकसान को भी रोका जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटेन के महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों ने लगभग 20 वर्ष पहले यूकास पोर्टल के जरिये साझा आवेदन लेने की शुरुआत कर दी थी, जिसके जरिये छात्र को एकबारगी देय शुल्क के साथ अनेक संस्थानों में आवेदन का विकल्प प्राप्त होता था। कालांतर में तकनीकी दक्षता में उन्नयन के साथ प्रवेश प्रक्रिया को सहज बनाया जा सकता है।

निजी संस्थान यदि इसी प्रकार निरंकुश तरीके से वसूली करके अपनी आय वृद्धि करते रहे, तो शिक्षा प्राप्त करना जटिल होता जाएगा। नीतिगत स्तर पर शिक्षण शुल्क के साथ अप्रत्यक्ष माध्यमों से हो रही वसूली पर निगरानी रखने के लिए कठोर नियमावली के साथ नियामक संस्था का गठन होना चाहिए। वैसे, पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न वर्गों द्वारा सरकारी विद्यालयों के आधारभूत ढांचे में अभिवृद्धि की पहल की गई है, लेकिन निजी क्षेत्र की मार्केटिंग के आगे अब भी सरकारी संस्थानों में शिक्षण के प्रयास धूमिल हो जाते है। सामाजिक मान्यताओं के चलते निजी क्षेत्र पहली पसंद बने हुए हैं और हर कोई उस चक्रव्यूह में प्रवेश के लिए यत्नशील रहता है। प्रारंभिक तौर पर विभिन्न आवेदन पत्रों एवं परीक्षा शुल्क में निःशुल्क या एकरूपता के साथ डिजिटलाइजेशन लागू करने संबंधी कदम उठाए जा सकते हैं। इस नियामक कदम से करोड़ों छात्रों को राहत मिलेगी और अनावश्यक खर्चों से मुक्ति मिलेगी। यह तो मात्र एक बानगी है शिक्षा के व्यावसायीकरण की।

अमर उजाला
नई दिल्ली | सोमवार | 9 फरवरी 2026
amarujala.com

एजुकेशन & कॅरिअर

मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, सही समय पर रंग लाती है।

अमर उजाला Job Alert

Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग

ग्रुप-सी पदों पर रिक्तियां

4227 पद

परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि : 23 फरवरी, 2026
योग्यताएं : बारहवीं, ग्रेजुएशन व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : hssc.gov.in

ईसीएचएस में नौकरी के अवसर ■ 175 पद

मेडिकल ऑफिसर, क्लर्क आदि पद रिक्त
आवेदन की अंतिम तिथि
28 फरवरी, 2026
योग्यताएं
बीएससी, एमबीबीएस व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
echs.gov.in

झारखंड लोक सेवा आयोग ■ 103 पद

उप-समाहर्त्ता, पुलिस उपाधीक्षक आदि के पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि
14 फरवरी, 2026
आयु-सीमा
न्यूनतम उम्र 21 वर्ष व अधिकतम उम्र 35 वर्ष
यहां आवेदन करें
jpsc.gov.in

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ■ 637 पद

अप्रेंटिसशिप के लिए करें आवेदन
आवेदन की अंतिम तिथि : 20 फरवरी, 2026
योग्यताएं : आईटीआई, बीए, बीएससी व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : iocl.com

एआईआईए में आवेदन आमंत्रित ■ 33 पद

कंप्यूटर प्रोग्रामर, अकाउंट ऑफिसर आदि के पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि
02 मार्च, 2026
योग्यताएं
एमकॉम, एमबीए व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
aiia.gov.in

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ■ 16 पद

वैज्ञानिक अधिकारी व अन्य पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि
14 मार्च, 2026
वेतनमान
रुपये 56,100 से लेकर रुपये 2,09,200 प्रतिमाह
यहां आवेदन करें
api.amu.ac.in

यहां भी नौकरी के मौके...

- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया : काउंसलर के पदों पर आवेदन आमंत्रित।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 21 फरवरी, 2026
- centralbankofindia.co.in
- नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली : डिप्टी जनरल मैनेजर व कंपनी सेक्रेटरी के पद खाली।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 17 फरवरी, 2026
- indiaseeds.com

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

एआई फॉर ऑल : हर युवा के लिए अवसर

इस कोर्स से युवा एआई की बुनियादी समझ हासिल करेंगे, जिससे उनका रिज्यूमे मजबूत होगा और वे भविष्य के लिए तैयार हो सकेंगे

यामिनी गौड़
एआई ट्रेनर, टेक इन्फ्लुएंसर

आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। स्मार्टफोन, इंटरनेट सर्च, मनोरंजन, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर खेती और ट्रैफिक व्यवस्था हर क्षेत्र में इसका तेजी से उपयोग हो रहा है। जिस तरह पहले कंप्यूटर सीखना आवश्यक हो गया था, उसी तरह आज एआई स्किल्स भी कॅरिअर के लिए अनिवार्य होती जा रही हैं, क्योंकि इससे नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। पहले एआई सीखना महंगा और कठिन माना जाता था, खासकर छोटे शहरों और गांवों के युवाओं के लिए, लेकिन अब भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडियाएआई मिशन के तहत 'युवा एआई फॉर ऑल' कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स के माध्यम से हर युवा को आसान और सुलभ तरीके से एआई शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है, जिससे वे भविष्य के लिए खुद को बेहतर रूप से तैयार कर सकें।

■ कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध

इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह निःशुल्क है और फ्यूचरस्किल्स प्राइम आईजीओटी कर्मयोगी तथा अन्य लोकप्रिय एडटेक पोर्टल्स जैसे प्रमुख लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। यह कार्यक्रम कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इसके अलावा, एआई फॉर ऑल के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, न्यूरल नेटवर्क व डीप लर्निंग की मूल से उन्नत समझ के साथ वास्तविक जीवन आधारित केस स्टडी और प्रोजेक्ट्स सिखाए जाते हैं, जो रिज्यूमे को मजबूत बनाते हैं।

■ बिना कोडिंग ज्ञान के भी सीखें

इस कोर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बिना किसी कोडिंग की पूर्व जानकारी वाला व्यक्ति भी इसे आसानी से समझ और सीख सके। सभी अवधारणाओं को सरल भाषा में, रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ समझाया गया है, ताकि विषय जटिल न लगे। यह कोर्स पूरी तरह ऑनलाइन और स्व-नियंत्रित (सेल्फ-पेस्ड) है, जिससे आप अपनी सुविधा और उपलब्ध समय के अनुसार कभी भी और कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। चाहे आप छात्र हों या नौकरीपेशा, आप अपने समय के हिसाब से सीख सकते हैं, बिना किसी दबाव के। कोर्स

पूरा करने पर आपको एक प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाता है, जो आपके कॅरिअर में कौशल को दर्शाने और नए अवसर पाने में सहायक साबित होता है।

■ रजिस्ट्रेशन कैसे करें

एआई फॉर ऑल प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले ai-for-all.in वेबसाइट पर जाएं। वहां रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा, जहां आपको अपना नाम, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी सामान्य जानकारी भरनी होगी। इसके बाद ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आप अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं और तुरंत सीखना शुरू कर सकते हैं।

ब्लूमबर्ग फेलोशिप प्रोग्राम-2026

आवेदन आमंत्रित

ब्लूमबर्ग फेलोशिप-2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह एक पूर्णतः वित्तपोषित फेलोशिप है, जो अंतरराष्ट्रीय छात्रों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययनरत छात्रों के लिए उपलब्ध है। यह फेलोशिप 18 से 22 मई, 2026 तक आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम पत्रकारिता में गहरी रुचि रखने वाले विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, खासकर उन छात्रों के लिए जो वर्तमान में व्यावसायिक पत्रकारिता का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। यह फेलोशिप तीसरे या चौथे वर्ष में अध्ययनरत छात्रों (जूनियर और सीनियर) के लिए खुली है। साथ ही, विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न पृष्ठभूमि, दृष्टिकोण और जीवन अनुभवों वाले छात्रों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है। योग्य आवेदक आधिकारिक लिंक tinyurl.com/5xykzbjs पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

विकी लव्स फोकलोर फोटोग्राफी-2026

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता

विकिमीडिया कॉमन्स पर आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता विकी लव्स फोकलोर-2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को अपने अनूठे दृष्टिकोण से आकर्षक फोटोग्राफ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

■ विविधता का उत्सव

यह प्रतियोगिता दुनिया भर की लोक संस्कृतियों को दर्शाने पर केंद्रित है, जहां परंपराएं, उत्सव, कला, भोजन, वेशभूषा और लोककथाओं जैसी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां तस्वीरों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं।

■ प्राइज

इस प्रतियोगिता में फोटोग्राफी, मल्टीमीडिया तथा सामुदायिक और स्वयंसेवी श्रेणियों में 100 से 500 अमेरिकी डॉलर तक के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। साथ ही शीर्ष 100 अपलोडरों को विकी लव्स फोकलोर पोस्टकार्ड भी प्रदान किए जाएंगे।

■ आवेदन प्रक्रिया

प्रतिभागी आधिकारिक लिंक tinyurl.com/4s7ct5nh पर जाकर 31 मार्च, 2026 तक शामिल हो सकते हैं।

अभिजीत सेन ग्रामीण इंटर्नशिप-2026

इंटर्नशिप अलर्ट

अभिजीत सेन ग्रामीण इंटर्नशिप प्रोग्राम-2026 नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया द्वारा संचालित एक प्रतिष्ठित फील्ड-आधारित अनुसंधान इंटर्नशिप है। यह कार्यक्रम छात्रों को ग्रामीण भारत का अन्वेषण करने और विभिन्न समुदायों द्वारा सामना की जा रही सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को समझने का अवसर प्रदान करता है। इस इंटर्नशिप के लिए भारत के किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज या तकनीकी शिक्षण संस्थान में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को इंटर्नशिप पूर्ण करने पर 20,000 रुपये का वजीफा दिया जाएगा, साथ ही यात्रा, भोजन और आवास से संबंधित सभी खर्च भी वहन किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है। योग्य आवेदक अपनी अर्हता की जांच करते हुए आधिकारिक लिंक nfi.org.in/internship पर जाकर इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

खुद को परखें

1. नलसरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?
   (a) गुजरात
   (b) कर्नाटक
   (c) केरल
   (d) मध्य प्रदेश
2. हक्की पिक्की जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है?
   (a) कर्नाटक (b) केरल
   (c) तमिलनाडु (d) महाराष्ट्र
3. एशियाई राइफल एवं पिस्टल चैंपियनशिप-2027 की मेजबानी कौन-सा देश कर रहा है?
   (a) मलयेशिया
   (b) इंडोनेशिया
   (c) जापान
   (d) भारत

उत्तर-1.a, 2.a, 3.d

मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल

सामान्य ज्ञान

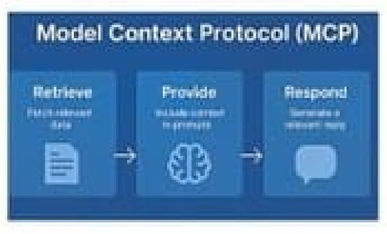

■ क्या है

यह एक ऐसी तकनीक है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने स्वयं के एआई टूल्स और एप्लिकेशनों के माध्यम से डाटासेट से सीधे जुड़ने की अनुमति देती है।

■ चर्चा में क्यों

हाल ही में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ई-सांख्यिकी पोर्टल के लिए मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (एमसीपी) सर्वर का बीटा संस्करण लॉन्च किया है।

■ जानकारी उपलब्ध कराने के लिए खास

यह बड़े भाषा मॉडलों (एलएलएम) को जानकारी उपलब्ध कराने का एक मानक तरीका है।

■ इसकी भूमिका

एमसीपी की मदद से एआई एप्लिकेशन अलग-अलग डाटा स्रोतों, टूल्स और वर्कफ्लो से जुड़ सकते हैं, जिससे वे जरूरी जानकारी हासिल कर पाते हैं और काम कर सकते हैं।

रोशनी यहां है

इस बार : राजा नायक
क्यों : फुटपाथ से उठकर बना बिजनेस का शहंशाह

राजा नायक ने गरीबी और अधूरी शिक्षा के बावजूद हार नहीं मानी। एक साधारण-सी तीन घंटे की फिल्म उनके लिए सोच बदलने वाला अनुभव साबित हुई, जिसने उनकी जिंदगी को नई दिशा दी। आज वे लगभग 100 करोड़ रुपये का कारोबार खड़ा कर कई कंपनियों के मालिक हैं।

उधार की पूंजी, फुटपाथ पर बेची शर्ट, फिल्म से ली प्रेरणा, फिर बनाया करोड़ों का कारोबार

कर्नाटक के एक छोटे से गांव से आए दलित प्रवासी माता-पिता के बेटे राजा नायक ने वह सफर तय किया है, जो अक्सर सपनों तक ही सीमित रह जाता है। बचपन भूख, अभाव और गरीबी में बीता, लेकिन आज वही राजा नायक लगभग करोड़ों रुपये के कारोबार के मालिक हैं। संभव है कि वह भी बंगलूरू की किसी झुग्गी में गुमनामी भरा जीवन जी रहे होते, अगर बचपन में एक दोस्त के कहने पर उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म *त्रिशूल* न देखी होती। इस फिल्म ने उनके भीतर कुछ कर गुजरने की ऐसी चिंगारी जलाई कि कम उम्र में उन्होंने व्यापार की राह पकड़ ली। शुरुआत फुटपाथ पर कमीज बेचने से हुई। वर्षों की अडिग जिद, असफलताओं से बार-बार गिरकर फिर उठने का हौसला और गरीबी से बाहर निकलने के सपने ने आज उन्हें कई कंपनियों का मालिक बना दिया। राजा नायक की कहानी बताती है कि आत्मविश्वास के सहारे दुनिया जीती जा सकती है, और किसी एक सपने के टूटने का मतलब सब कुछ खत्म होना नहीं होता। साथ ही यह भी कि फिल्में केवल बिगाड़ती नहीं, संवारती भी हैं। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनसे कौन-सी राह चुनते हैं।

बेहद साधारण परिवार में जन्म

विरासत में मिली दौलत की कहानियों से बिल्कुल अलग, राजा नायक का संघर्ष भरा सफर बंगलूरू की गरीबी से शुरू हुआ। उनका जन्म शहर के एक बेहद साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ, जहां हालात इतने कठिन थे कि दो वक्त की रोटी जुटाना भी रोज की चुनौती थी। आर्थिक तंगी के चलते उन्हें मात्र 15 वर्ष की उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कुछ कर दिखाने के जुनून के साथ 17 साल की उम्र में वे मुंबई पहुंचे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिल सकी और अंततः उन्हें बंगलूरू लौटना पड़ा। वह समय उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। एक ओर भविष्य अनिश्चित था, तो दूसरी ओर समाज की नजरों में वे एक 'ड्रॉपआउट' और असफल युवक माने जाने लगे थे।

मां का भरोसा बना सफलता की पहली पूंजी

जब दुनिया ने राजा नायक से उम्मीदें छोड़ दी थीं, तब उनकी मां ने उन पर भरोसा किया। बंगलूरू लौटने पर मां ने अपनी छोटी-सी बचत में से कुछ रुपये उन्हें उधार दिए। राजा ने उन पैसों से सस्ती टी-शर्ट खरीदीं और फुटपाथ पर 50 रुपये में बेचने लगे। शुरुआत में बिक्री धीमी रही, लेकिन फैक्टरी वर्कर्स को देखकर उन्होंने केवल नीले और सफेद रंग की टी-शर्ट पर ध्यान दिया। इसका असर तुरंत दिखा कि पहले ही दिन सारी टी-शर्ट बिक गईं और करीब 5,000 रुपये का मुनाफा हुआ। इसके बाद उन्होंने शर्ट, जूते और घरेलू सामान बेचना शुरू किया, प्रदर्शनी स्टॉल लगाए और अपनी बिक्री व्यवस्था खड़ी की। आगे चलकर कोल्हापुरी चप्पलों के कारोबार में भी उतरे। लोगों ने उनकी जाति पूछी, लेकिन राजा ने कभी इसे अपनी सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया।

फिल्म ने दिए पंख

फुटपाथ पर सामान बेचते हुए भी राजा नायक के मन में आगे बढ़ने की चाह बनी रही। मुंबई यात्रा के दौरान एक दोस्त के आग्रह पर उन्होंने अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म 'त्रिशूल' देखी। फिल्म में अभिनेता को शून्य से शुरू कर एक विशाल व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा करते हुए दिखाया गया था। यह फिल्म राजा के लिए सिर्फ सिनेमा नहीं रही, बल्कि एक स्पष्ट विजन बन गई। फुटपाथ पर बैठकर वह अक्सर सोचते थे कि जब पर्दे पर एक आम आदमी संघर्षों से लड़कर बड़ा बन सकता है, तो वह वास्तविक जीवन में क्यों नहीं। फिल्म ने उनके भीतर एक स्पष्ट विजन जगाया और वही प्रेरणा उन्हें फुटपाथ से आगे बढ़कर बड़ा करने का साहस दे गई।

पैकेजिंग क्षेत्र में रखा कदम

राजा नायक ने अपने कारोबारी सफर की शुरुआत 'अक्षय एंटरप्राइजेज' के साथ की और पैकेजिंग व्यवस्था के क्षेत्र में कदम रखा। इसके बाद 1998 में उन्होंने लॉजिस्टिक्स सेक्टर में प्रवेश करते हुए 'एमसीएस लॉजिस्टिक्स' की नींव रखी, जो आज एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल कंपनी बन चुकी है। उनका विस्तार यहीं नहीं रुका। उन्होंने 'जाला बेवरेजेज' के नाम से पेयजल कंपनी शुरू की, बंगलूरू में 'पर्पल हेज' नाम से तीन ब्यूटी सैलून और स्पा की श्रृंखला स्थापित की, और बाद में 'न्यूट्री प्लैनेट' की शुरुआत की। आज वे कई कंपनियों के संस्थापक हैं और उनकी सफलता की कहानी एक फिल्म से मिली प्रेरणा का परिणाम है।

युवाओं को सीख

- हालात नहीं, हौसला भविष्य तय करता है।
- छोटा काम भी बड़े सपनों की शुरुआत हो सकता है।
- असफलता अंत नहीं, दिशा बदलने का संकेत है।
- मौके अपने आप दिखाई नहीं देते, उन्हें समझदारी और सजग नजर से तलाशना पड़ता है।

आज का दिन

9 फरवरी, 1996

जर्मन भौतिक विज्ञानी पीटर आर्मब्रस्टर और उनकी टीम ने एक भारी रासायनिक तत्व ट्रांसयूरेनियम 112 को संश्लेषित किया था। बाद में इसे कोपरनिसियम नाम दिया गया था।

- 1796 : चीन के चौथे सम्राट कियानलांग ने पद को त्याग दिया था।
- 1940 : दक्षिण अफ्रीकी उपन्यासकार जेएम कोएट्जी का जन्म हुआ था।
- 1943 : गुआडलकैनाल की लड़ाई जापान पर मित्र राष्ट्रों की जीत के साथ समाप्त हुई थी।
- 2002 : राजकुमारी मार्गरेट का निधन हुआ था।

व्रत त्योहार

आज : फाल्गुन कृष्ण पक्ष अष्टमी।
कल : शिशिर ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, दक्षिण गोले।
राहुकाल : दिन में 15.00 से 16.30 तक।

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2082, 21 माघ मास शक 1947, माघ मास 28 प्रविष्टे, 21 सावान हिजरी 1447, फाल्गुन कृष्ण पक्ष अष्टमी 07.27 तक उपरांत नवमी, विशाखा नक्षत्र 07.54 तक उपरांत अनुराधा नक्षत्र, ध्रुव योग 25.41 तक उपरांत व्याघात योग, कौलव करण 07.27 तक उपरांत तैतिल करण, चंद्रमा वृश्चिक राशि में दिन-रात।

■ सूर्योदय : 07.08
■ सूर्यास्त : 18.03
(भारतीय मानक समयानुसार)

amarujala.com/astrology

राशिफल

■ पं. विनोद त्यागी

मेष : आत्मबल बनाए रखें। अटके कार्य में सफलता मिल सकती है। नौकरी में श्रम की अधिकता रहेगी।

वृष : व्यक्तिगत संबंध सहायक रहेंगे। नौकरी में स्थिति अनुकूल रहेगी। व्यवसाय में लाभ होगा।

मिथुन : राजनीतिक संबंध सहायक रहेंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी बढ़ सकती है। व्यवसाय में यथेष्ट लाभ होगा।

कर्क : चले आ रहे पुराने विवाद से मुक्ति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में दौड़ भाग रहेगी। नौकरी में मन नहीं लगेगा।

सिंह : लोकप्रियता में वृद्धि होगी। नौकरी में कार्य कुशलता का लाभ मिलेगा। नए कार्य में पूंजी निवेश होगा।

कन्या : मानसिक तनाव बना रहेगा। योजनाओं में अवरोध आएंगे। नौकरी में सावधानी बरतें। व्यवसाय में लाभ होगा।

तुला : दिनमान अनुकूल रहेगा। स्व विवेक से अटका कार्य बन सकता है। नौकरी में स्थिति यथावत रहेगी।

वृश्चिक : मानसिक उलझन बनी रहेगी। नौकरी में तबादला हो सकता है। व्यवसाय में आय व्यय सम रहेंगे।

धनु : शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा। संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। घर में मेहमान का आगमन हो सकता है।

मकर : कार्यक्षेत्र में श्रम की अधिकता रहेगी। व्यवसाय में लाभ के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ : मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा।

मीन : किसी नए कार्य में व्यस्त रहेंगे। प्रभावी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। संतान से सुख मिल सकता है।

जन्मदिन

राहुल रॉय, अभिनेता

इस जन्में जातक साहसी, स्पष्टवक्ता एवं न्यायप्रिय होते हैं। इस वर्ष स्वश्रम से अटकी योजनाएं साकार होंगी। आय का स्थाई स्त्रोत बन सकता है। आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। रोजगारपरक परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। अविवाहितों के विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा।

सुडोकू

6				8				
		9		5	1		4	
		4			2			
8	6						1	2
	4						7	
5	2						9	3
			5			3		
	1		6	3		5		
				4				7

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

6	7	2	4	8	3	1	5	9
3	8	9	7	5	1	2	4	6
1	5	4	9	6	2	7	3	8
8	6	7	3	9	5	4	1	2
9	4	3	2	1	6	8	7	5
5	2	1	8	7	4	6	9	3
4	9	6	5	2	7	3	8	1
7	1	8	6	3	9	5	2	4
2	3	5	1	4	8	9	6	7

डेली हेल्थ कैप्सूल

खट्टे-मीठे बेर स्वादिष्ट ही नहीं सेहतमंद भी

औषधीय गुणों से भरपूर बेर खाने से सेहत को कई लाभ मिलते हैं। इससे कई बीमारियों का खतरा भी कम होता है।

बेर एक तरह की बेरीज की प्रजाति का फल है, जो स्वाद में ही नहीं बल्कि कई पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। आयुर्वेद में बेर के पत्ते, फल और बीज का उपयोग दवाओं में किया जाता है। बेर में मौजूद फाइबर और कम कैलोरी पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं। इस फल में विटामिन ए, सी, बी12 और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में

पाया जाता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करता है। बेर में मौजूद फाइबर मीठे की क्रेविंग को नियंत्रित करने में मदद करता है। साथ ही इसके सेवन से मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ता है, जिससे वजन कम होता है। बेर में मौजूद गुण त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। बेर और इसके बीज में सेपोनीन और पॉलिसैक्राइड्स प्रचुर मात्रा में होता है, जो अच्छी और गहरी नींद लाने में सहायता करते हैं। ये दोनों नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करते हैं, जिससे गहरी नींद आसानी से आ जाती है। बेर में आयरन और फास्फोरस अधिक होता है, जो रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद करता है। इस फल में कैल्शियम और फास्फोरस भी होता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करता है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

डायबिटीज, लो फाइबर डाइट का पालन करने वाले लोगों, लेटेक्स से एलर्जी होने पर या गैस और सूजन से पीड़ित लोगों को बेर नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा तनाव या अनिद्रा की दवा लेने वाले भी इससे परहेज करें।

-नेहा पठानिया, आहार विशेषज्ञ

ताकि सनद रहे

उधार लेकर निवेश अब पड़ेगा महंगा

अगर आप पराई पूंजी (Loan) से मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं, तो अब टैक्स का भारी बोझ उठाने के लिए तैयार रहिए। बजट 2026 में उधार लेकर निवेश करने वालों (Leveraged Investors) के लिए एक बड़ा झटका दिया गया है।

अब उधार के पैसे से शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करके टैक्स बचाने का खेल खत्म होने वाला है।

ब्याज कटौती का रास्ता बंद

बजट डॉक्यूमेंट्स में प्रस्ताव है कि डिविडेंड इनकम या म्यूचुअल फंड की यूनिट से होने वाली इनकम के संबंध में किए गए किसी भी ब्याज खर्च पर कोई डिडक्शन नहीं दिया जाएगा और एक तय लिमिट के तहत ऐसे डिडक्शन की अनुमति देने वाले मौजूदा प्रावधान को हटा दिया जाएगा।

कौन होगा सबसे ज्यादा प्रभावित?

इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 93 के मौजूदा प्रावधानों के तहत, निवेशकों को ब्याज पर खर्च की गई रकम को डिडक्शन के तौर पर क्लेम करने की अनुमति है, लेकिन ये सिर्फ कुल डिविडेंड या म्यूचुअल फंड इनकम के 20% तक ही हो सकता है। अब बजट ने उधार लिए गए फंड पर ब्याज खर्च को डिविडेंड या म्यूचुअल फंड आय के खिलाफ घटाने की सुविधा को हटा दिया है, जो अन्य स्रोतों से आय (Income from other sources) के तहत टैक्स के दायरे में आती है। यह प्रस्ताव नियमित लंबी अवधि के म्यूचुअल फंड धारकों के बजाय उन निवेशकों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, जो उधार लेकर निवेश करते हैं।

अब नेट नहीं फुल इनकम पर टैक्स

पहले: अगर आपको 100 रुपये डिविडेंड मिला और 20 रुपये ब्याज भरा, तो टैक्स सिर्फ 80 रुपये पर लगता था।

अब: आपको पूरे 100 रुपये पर टैक्स देना होगा, भले ही आपने उसके लिए कितना भी ब्याज भरा हो। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ब्याज खर्च को घटाने की कोई जगह नहीं बची है।

नए नियम से क्या बदलेगा?

संशोधन लागू होने के बाद, डिविडेंड इनकम और म्यूचुअल फंड यूनिट्स से होने वाली इनकम की गणना ब्याज खर्च के लिए कोई कटौती दिए बिना की जाएगी। अगर आपने डिविडेंड देने वाले शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए ऋण या मार्जिन के माध्यम से पैसा उधार लिया है, तो अब आप ब्याज लागत के जरिये अपनी कर योग्य आय को कम नहीं कर सकते। अब पूरा डिविडेंड या म्यूचुअल फंड आय बिना किसी कटौती के कर योग्य हो जाएगी।

किसे होगा सबसे ज्यादा नुकसान?

HNI और कॉरपोरेट ट्रेजरी: बड़े निवेशक और कंपनियां जो भारी कर्ज लेकर पैसिव पोर्टफोलियो बनाते हैं, उनका टैक्स खर्च अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।

रिटेल निवेशक: उतार-चढ़ाव वाले बाजार में कर्ज लेकर निवेश करने वाले रिटेल निवेशकों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा।

तारीख पता है?

आईपीओ लिस्टिंग

- 16 फरवरी: Aye Finance Ltd (1010 करोड़ रुपये) Fractal Analytics Ltd (2833 करोड़ रुपये)

कंपनियों के तिमाही नतीजे

- 9 फरवरी : BSE, Zydus Lifescience, KPR Mills ■10 फरवरी: Titan company, Grasim Ind, Oil India ■12 फरवरी: SPML Infra ■13 फरवरी: Torrent Pharma, Kfin Technologies ■14 फरवरी: NBCC ■16 फरवरी: NLC India, Rajesh Exports

■ डिस्क्लेमर : अपना पैसा में छपे विचार, राय और निवेश संबंधी सुझाव अलग-अलग विशेषज्ञों, ब्रोकर फर्मों या रिसर्च संस्थानों के हैं। इनसे अखबार या उसके प्रबंधन की सहमति जरूरी नहीं है। कृपया किसी भी तरह का निवेश फैसला लेने से पहले अपने पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इस जानकारी के आधार पर होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी अखबार या उसके प्रबंधन की नहीं होगी।

बदलते आर्थिक माहौल, स्थिर आय की जरूरत और बेहतर रिटर्न के विकल्प तलाशते निवेशकों के लिए बॉन्ड अब एक जरूरी एसेट क्लास बनते जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि भारतीय निवेशक सिर्फ बैंक FD या शेयर बाजार पर निर्भर न रहें। कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में सुधार से निवेशकों को फिक्स्ड इनकम के नए और बेहतर विकल्प मिलेंगे।

बॉन्ड है सुरक्षित और मजबूत

BUDGET 2026

बॉन्ड न सिर्फ पोर्टफोलियो में स्थिरता लाते हैं, बल्कि कई मामलों में बैंक एफडी और छोटी बचत योजनाओं से बेहतर रिटर्न भी देते हैं

क्या आप भी अधिक जोखिम उठाए बिना अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो बॉन्ड्स आपके लिए ही हैं। जल्द ही भारत का बॉन्ड बाजार अब शेयर बाजार की तरह गहरा, सक्रिय और मजबूत बनने जा रहा है।

238 लाख करोड़ रुपये (31 मार्च, 2025 तक) के बॉन्ड बाजार में कॉरपोरेट हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में पेश बजट 2026 में मार्केट-मेकिंग फ्रेमवर्क और टोटल रिटर्न स्वैप जैसे प्रस्तावों की घोषणा की है।

मार्केट-मेकिंग फ्रेमवर्क से चुनिंदा संस्थान हर समय बॉन्ड खरीदने और बेचने के लिए तैयार रहेंगे। इससे बाजार में तरलता बढ़ेगी।

अब आपको अपने बॉन्ड बेचने के लिए किसी भारी डिस्काउंट का इंतजार नहीं करना होगा।

कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर टोटल रिटर्न स्वैप (TRS) जैसे नए डेरिवेटिव्स पेश किए जाएंगे।

इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि निवेशक या विदेशी संस्थान बिना बॉन्ड को सीधे अपने पास रखे, उसकी आय और कीमत के उतार-चढ़ाव का लाभ उठा सकेंगे। इससे बाजार की गहराई बढ़ेगी।

बॉन्ड्स उन निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प हैं, जो अपनी पूंजी को सुरक्षित रखते हुए नियमित आय अर्जित करने के साथ ही अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहते हैं।

■ **भारत में दो प्रकार के बॉन्ड प्रचलित हैं, सरकारी बॉन्ड और कॉरपोरेट बॉन्ड।**

■ **सरकारी बॉन्ड:** ट्रेजरी बिल्स (T-Bills) और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज (G-Secs) सरकारी बॉन्ड होते हैं। इन्हें केंद्र सरकार जारी करती है। इन्हें सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता है। सरकार समर्थित होने से डिफॉल्ट का जोखिम बहुत कम होता है। इनमें सालाना 5 से 7.5% तक रिटर्न मिलता है।

■ **कॉरपोरेट बॉन्ड:** निजी कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। सरकारी बॉन्ड की तुलना में अधिक जोखिम वाले होते हैं। इनमें रिटर्न अधिक मिलता है, आमतौर पर 8-14 फीसदी तक।

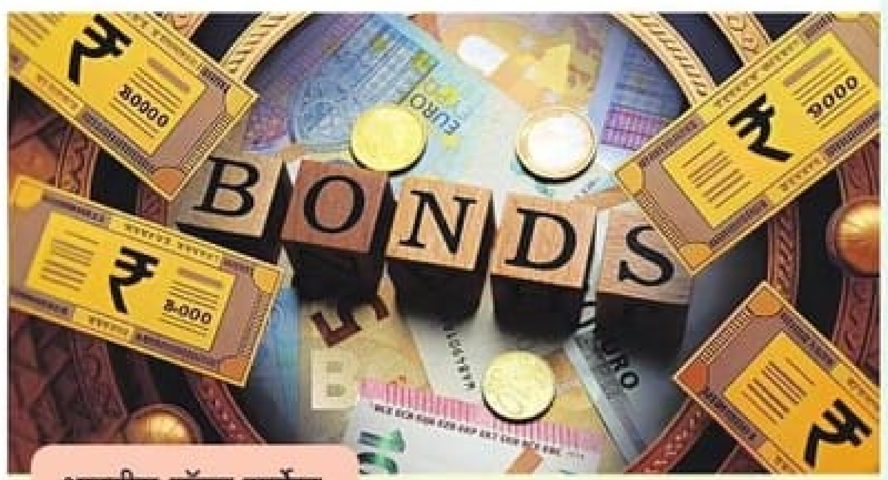

भारतीय बॉन्ड मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स के प्रकार

नाम	हिस्सेदारी
G-sec (सरकारी प्रतिभूतियां)	45%
SDL (राज्य विकास ऋण)	25%
Corporate Bond	22%
T-bill (ट्रेजरी बिल)	4%
CP (कमर्शियल पेपर)	2%
CD (जमा पत्र)	2%

मार्च 2024 तक, स्रोत: SEBI

नए निर्गम से 9.9 लाख करोड़ रुपये जुटाए

सेबी के मुताबिक भारत के कुल बॉन्ड बाजार में कॉरपोरेट बॉन्ड्स की हिस्सेदारी करीब 22 फीसदी (मार्च, 2024 तक) है। कॉरपोरेट बॉन्ड के तहत शुद्ध बकाया राशि वित्त वर्ष 2014-15 के 17.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 53.6 लाख करोड़ रुपये (RBI, 2025 रिपोर्ट के मुताबिक) हो गई है।

- **इसमें करीब 12% CAGR दर से वृद्धि हुई है।** इस दौरान 2024-25 में अब तक के सर्वाधिक नए निर्गम से 9.9 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए।

रिटेल निवेशकों के लिए निवेश के कई तरीके मौजूद

- **RBI रिटेल डायरेक्ट:** आप इस पोर्टल पर अपना अकाउंट खोलकर सीधे G-Secs (केंद्र सरकार के बॉन्ड), T-Bills और SDL (राज्य सरकारों के बॉन्ड) खरीद सकते हैं। इसमें कोई कमीशन नहीं देना होता।
- **स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर:** अगर आपके पास पहले से ही एक डिमैट अकाउंट है, तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर (जैसे Zerodha, Groww) के जरिए बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। यहां आप लिस्टेड बॉन्ड्स को शेयरों की तरह खरीद-बेच सकते हैं।
- **ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स:** नए जमाने के प्लेटफॉर्म (GoldenPi, IndiaBonds) आ गए हैं, जो खास तौर पर रिटेल निवेशकों के लिए बने हैं। यहां आप अलग-अलग कंपनियों के बॉन्ड्स की तुलना कर सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग देख सकते हैं और 10,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं।
- **डेट म्यूचुअल फंड्स:** अगर आप खुद रिसर्च नहीं करना चाहते, तो डेट म्यूचुअल फंड्स सबसे अच्छा तरीका है। आप SIP से भी बॉन्ड खरीद सकते हैं।

निवेश से पहले करें जोखिम का आकलन

मनिकरण सिंघल
डायरेक्टर, Good Moneying Wealth Planners

बॉन्ड एक आकर्षक विकल्प के रूप में उभरे हैं। हालांकि, बॉन्ड में निवेश करने से पहले जोखिमों और लाभों को समझना महत्वपूर्ण है। अपनी वित्तीय स्थिति, जोखिम क्षमता और निवेश लक्ष्यों के आधार पर अच्छी रेटिंग और गारंटी वाले बॉन्ड्स में निवेश का निर्णय लें। छोटे निवेशकों को म्यूचुअल फंड के जरिये निवेश करना चाहिए।

बॉन्ड्स में निवेश किसके लिए बेहतर?

- **रिटायरमेंट और नियमित आय चाहने वालों के लिए:** अगर आप रिटायर हो चुके हैं या आपको हर महीने एक निश्चित कमाई चाहिए, तो बॉन्ड से बेहतर कुछ नहीं। बॉन्ड्स (विशेषकर कॉरपोरेट) FD के मुकाबले अक्सर 1-2% ज्यादा रिटर्न देते हैं।
- **कम जोखिम वाले निवेशकों के लिए:** शेयर बाजार का लाल-हरा निशान आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, तो आप बॉन्ड इन्वेस्टर हैं। सरकारी बॉन्ड्स में रिस्क लगभग 0 होता है।
- **पोर्टफोलियो में बैलेंस :** जब शेयर बाजार गिरता है, तब बॉन्ड्स पोर्टफोलियो को सहारा देते हैं। एक आदर्श पोर्टफोलियो में आपकी उम्र के हिसाब से 20-40% हिस्सा बॉन्ड्स का होना चाहिए।
- **लंबी अवधि के लक्ष्य :** अगर आप अपनी पूंजी को सुरक्षित रखते हुए धीरे-धीरे बढ़ाना चाहते हैं, तो बॉन्ड बेहतर विकल्प है।

समझ बूझ

फॉर्म-15एच बार-बार जमा नहीं करना होगा

अगर किसी ने 5 अलग-अलग कंपनियों के बॉन्ड या डिबेंचर लिए हैं, तो उन्हें TDS बचाने के लिए उन पांचों जगहों पर अलग-अलग Form 15H जमा करना पड़ता था। बजट 2026 ने इस सिरदर्द को खत्म कर दिया है।

डिपॉजिटरी निभाएगी जिम्मेदारी

- अब आपको अपना Form 15H सिर्फ एक बार अपनी डिपॉजिटरी (NSDL या CDSL) के पास जमा करना होगा।
- इसके बाद डिपॉजिटरी की जिम्मेदारी होगी कि वह खुद उन सभी कंपनियों और बॉन्ड जारी करने वालों को जानकारी दे कि आपने निवेश किया है।

डिमैट होल्डिंग्स के लिए बड़ी सुविधा

उन निवेशकों को ज्यादा फायदा होगा जिनके पोर्टफोलियो में कई सिक्योरिटीज (बॉन्ड, डिबेंचर आदि) डिमैट फॉर्म में शामिल हैं।

क्या है Form 15H?

यह फॉर्म 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए होता है। अगर कुल टैक्स योग्य आय बेसिक छूट सीमा से कम है, तो आप यह फॉर्म जमा करके अनुरोध करते हैं कि आपकी ब्याज आय पर TDS न काटा जाए।

खबरों के आर पार

आधार एप से डिजिटल सत्यापन होगा आसान

UIDAI ने एक नया आधार एप लॉन्च किया है। इसकी मदद से लोग और कंपनियां किसी व्यक्ति की डिजिटल रूप से पहचान सत्यापित कर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

- आधार एप के जरिये उम्र की जांच आसानी से कर सकते हैं
- इसके लिए किसी अतिरिक्त जानकारी को साझा करने की जरूरत नहीं होगी
- उम्र की पुष्टि सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम और ई-कॉमर्स कंपनियों को यूजर्स की उम्र जांचने में मदद करेगी।
- इससे बच्चों को अनुपयुक्त सामग्री या उत्पादों तक पहुंच से बचाया जा सकेगा।

पूछताछ

माता-पिता को बड़ी रकम गिफ्ट करके, उनके नाम पर FD करा ब्याज इस्तेमाल कर सकता हूं?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56(2)(x) के तहत, किसी रिश्तेदार से बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त कोई भी राशि टैक्स से मुक्त है। चूंकि माता-पिता रिश्तेदारों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आप उन्हें जो राशि उपहार में देंगे, वह कर योग्य नहीं होगी। FD पर अर्जित ब्याज आपके माता-पिता के नाम पर उनके लागू स्लैब दरों के आधार पर अन्य स्रोतों से आय के रूप में कर योग्य होगा।

■ आप अपने माता-पिता के साथ एक संयुक्त खाता खोल सकते हैं, आमतौर पर, पहले धारक को प्राथमिक खाताधारक माना जाता है, और ब्याज आय पर उसी के अनुसार टैक्स लगाया जाता है।

■ यदि आपके माता-पिता ब्याज आय को वापस आपको हस्तांतरित करते हैं, तो यह धारा 56(2)(x) के तहत फिर से टैक्स-मुक्त होगा, और आप अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

फंड की फिटनेस

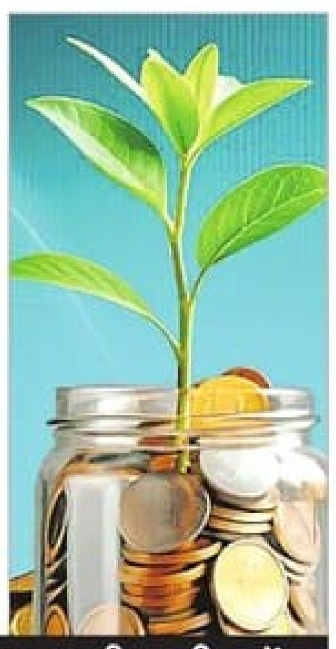

NFO की जरूरी बातें

- आप इसे 16 फरवरी तक सब्सक्राइब कर सकते हैं।
- 99 रुपये की SIP से शुरुआत
- लंपसम : कम से कम 5,000
- यूनिट्स अलॉटमेंट 23 फरवरी तक
- 15 दिन के भीतर रिडीम करने पर 0.5% एग्जिट लोड

डिफेंस सेक्टर पर दांव लगाने का मौका

रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों में निवेश से बनाएं पोर्टफोलियो को मजबूत

Mirae Asset BSE India Defence ETF FoF

भारत सरकार पिछले कुछ सालों से Make in India, आत्मनिर्भर भारत और घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसका फायदा डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को मिल रहा है। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, हथियार, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों को लगातार नए ऑर्डर मिल रहे हैं। डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ में हिस्सेदारी लेने का एक तरीका है Mirae Asset BSE India Defence ETF FoF।

■ **क्या है यह फंड?**

यह एक Fund of Funds (FoF) है, जो सीधे BSE में लिस्टेड उन कंपनियों में निवेश करता है, जो देश के लिए लड़ाकू विमान, युद्धपोत और आधुनिक हथियार बनाती हैं। सरकार का पूरा जोर अब Make in India पर है, जिसका सीधा फायदा इन कंपनियों को मिल रहा है।

■ **किसे निवेश करना चाहिए?**

यह एक सेक्टोरल फंड है। इसमें हाई रिस्क-हाई रिवॉर्ड का खेल है। यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म में हाई ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं और सेक्टोरल फंड में निवेश का जोखिम समझते हैं। आपका सारा पैसा सिर्फ एक ही सेक्टर (डिफेंस) पर टिका है। अगर सेक्टर में मंदी आई, तो उतार-चढ़ाव तगड़ा होगा। यह उनके लिए है, जिनका पोर्टफोलियो पहले से संतुलित है और जो अतिरिक्त ग्रोथ के लिए थोड़ा जोखिम ले सकते हैं।

■ **क्या कहते हैं एक्सपर्ट?**

MapMyGoals के फाउंडर विपिन पालीवाल का मानना है कि बजट 2026 में रक्षा बजट का बढ़ना इस फंड के लिए सबसे बड़ा बूस्टर है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। लेकिन याद रखिए, इसमें कम से कम 5 साल का विजन लेकर ही उतरना समझदारी है।

अब मिलेगा गलतियां सुधारने का भरपूर मौका

जल्दबाजी में रिटर्न भरते समय कुछ न कुछ छूट ही जाता है, लेकिन अब वित्त वर्ष के अंत तक सुधार करने का समय होगा

श्रीपति झा
सीए और टैक्स एक्सपर्ट

अमर उजाला अपना पैसा
इनकम टैक्स नोटिस आया? डरें नहीं, सुधारें

10 नवंबर, 2025 के अंक में इनकम टैक्स नोटिस पर अमर उजाला बोनस ने अपने पाठकों को दी थी जानकारी।

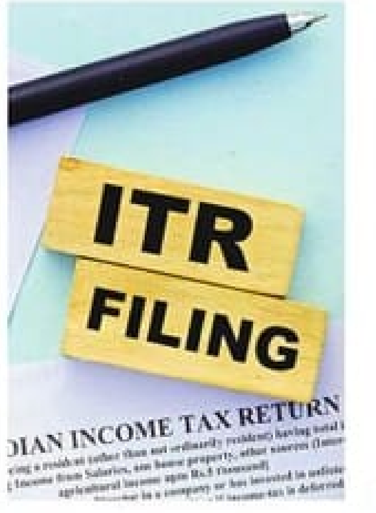

वर्ष 2025 में वेतनभोगी लोगों के पास ऑटोमेटेड नोटिसों की झड़ी लग गई थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी विभाग के हाई-टेक एल्गोरिदम और AIS का कड़ा पहरा। बचत खाते का ब्याज, शेयरों का डिविडेंड या म्यूचुअल फंड की छोटी सी कमाई भी अगर आपके रिटर्न से मैच नहीं हुई, तो सिस्टम ने तुरंत धारा 143(1)(a) के तहत नोटिस भेज दिया। ऐसे करीब 15 लाख से ज्यादा नोटिस भेजे गए।

अब सरकार ने माना है कि डाटा मिसमैच की वजह से करदाता परेशान हो रहे हैं।

इसलिए सरकार ने बजट 2026 में करदाताओं को 31 दिसंबर के बाद भी अपना संशोधित ITR दाखिल करने की सुविधा देने का ऐलान किया है।

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263(5) के तहत, करदाता मूल ITR में हुई चूक या गलतियों को सुधारने के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

पहले यह समयसीमा संबंधित निर्धारण वर्ष (Assessment Year) की 31 दिसंबर तक सीमित थी। 1 अप्रैल से, करदाता 31 मार्च तक अपना संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। हालांकि, यदि वे 31 दिसंबर की समयसीमा चूक जाते हैं, तो उन्हें इसके लिए एक मामूली शुल्क देना होगा। सरकार का यह कदम करदाताओं को वास्तविक गलतियों को सुधारने और अपडेटेड जानकारी शामिल करने के लिए अधिक समय देता है। इससे भरोसे पर आधारित टैक्स व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

नया नियम 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा, जिससे यह निर्धारण वर्ष 2026-27 से लागू होगा, यानी वित्त वर्ष 2025-26 से संबंधित रिटर्न पर नया नियम प्रभावी होगा।

■ **ध्यान रखें, देना होगा शुल्क**

यदि कोई करदाता 31 दिसंबर के बाद लेकिन 31 मार्च से पहले संशोधित रिटर्न दाखिल करता है, तो उसे शुल्क देना होगा। यदि आय 5 लाख रुपये तक है, तो शुल्क 1,000 रुपये होगा। यदि यह 5 लाख रुपये से अधिक है, तो यह 5,000 रुपये होगा।

■ **समय-सीमा बढ़ने से किसे लाभ?**

■ करदाताओं को अक्सर मूल रिटर्न की समयसीमा समाप्त होने के बाद संशोधित फॉर्म 16, टीडीएस प्रमाणपत्र या विदेशी आय का प्रमाण जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त होते हैं। एक लंबी समयसीमा उन्हें इन दस्तावेजों की जानकारी को अपने संशोधित रिटर्न में शामिल करने के लिए पर्याप्त समय देगी।

■ अंतरराष्ट्रीय टैक्स संबंधों वाले लोगों को भी लाभ होगा। मार्च के अंत की समयसीमा कई वैश्विक टैक्स कैलेंडरों के साथ बेहतर तालमेल बिठाती है और डाटा मिसमैच के जोखिम को कम करेगी।

■ उनको भी रिटर्न संशोधित करने के लिए समय देगा, जो विलंबित रिटर्न (Belated Return) दाखिल करते हैं (जिसकी समयसीमा भी 31 दिसंबर है)।

■ **क्या होगा फायदा?**

■ करदाताओं को बिना किसी नोटिस या विवाद के डर के वास्तविक गलतियों को सुधारने की अनुमति देने से स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा।

■ टैक्स विभाग का प्रशासनिक बोझ कम होगा।

■ अनजाने में हुई गलतियों के कारण होने वाले निर्धारण, दंड और मुकदमेबाजी को कम करने में मदद करेगा।

■ कर वर्ष के सुचारू अनुपालन, समापन को सक्षम बनाएगा ।

कौन फाइल कर सकता है संशोधित रिटर्न?

- यदि आय की गलत रिपोर्ट करते हैं
- किसी आय या आय के स्रोत को भूल जाते हैं
- छूट का दावा करने में विफल रहते हैं
- गलत कटौती या छूट का दावा करते हैं
- टैक्स की गलत गणना करते हैं
- गलतियां या गलत बैंक विवरण देते हैं
- विदेशी संपत्ति या आय की रिपोर्ट नहीं की
- रिपोर्ट की गई आय वार्षिक सूचना विवरण (AIS) से मेल नहीं खाती

जानना जरूरी है

संशोधित रिटर्न क्या है?

- एक करदाता मूल रिटर्न में गलतियों, चूक या गलत बयानों को सुधारने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत संशोधित रिटर्न दाखिल करता है।
- एक बार स्वीकार होने के बाद, यह निर्धारण उद्देश्यों के लिए मूल रिटर्न को पूरी तरह से बदल देता है।

तारीख बढ़ने के बड़े फायदे

- **गलतियां सुधारने का भरपूर मौका:** अब तक 31 दिसंबर की डेडलाइन के बाद गलती सुधारना नामुमकिन जैसा था। अब 31 मार्च तक का समय मिलने से आप तसल्ली से अपने कागजात चेक करके सुधार कर सकते हैं।
- **भारी जुर्माने और नोटिस से बचाव:** अब आपके पास वित्त वर्ष खत्म होने तक का समय है। आप खुद ही संशोधित रिटर्न भर देंगे, तो विभाग की नजरों में आप एक ईमानदार करदाता बने रहेंगे और भारी पेनल्टी से बच जाएंगे।
- **टैक्स प्लानिंग और निवेश का तालमेल:** संशोधित रिटर्न की तारीख 31 मार्च होने से आप अपने टैक्स और निवेश का बेहतर मिलान कर पाएंगे। मामूली शुल्क देकर अपनी टैक्स देनदारी को सही ढंग से एडजस्ट करने की सुविधा एक बड़ा वित्तीय लचीलापन है।
- **नए कानून के साथ तालमेल:** 1 अप्रैल, 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू हो रहा है, बढ़ी हुई समयसीमा करदाताओं को पुराने और नए नियमों के बीच सुचारु रूप से तालमेल बिठाने में मदद करेगी।

इन्फोग्राफिक्स

भारतीय परिवारों की 'बचत की आदत' अब 'निवेश की संस्कृति' में बदल गई है। लोग अब सिर्फ बैंकों में पैसा जमा नहीं कर रहे, बल्कि SIP और शेयरों के जरिये देश की तरक्की में सीधे साझेदार बन रहे हैं। छोटे निवेशक अब बाजार के असली खिलाड़ी बन चुके हैं।

घरेलू बचत व निवेश का बदलता स्वरूप

विवरण / मानक	आधार वर्ष (2013-14)	वर्तमान स्थिति (2025-26)
कुल इक्विटी स्वामित्व में व्यक्तिगत निवेशकों की हिस्सेदारी	11% (FY 2014)	18.8% (सितंबर 2025)
व्यक्तिगत निवेशकों की इक्विटी होल्डिंग्स (मूल्य)	8 लाख करोड़ (FY 2014)	84 लाख करोड़ (सितंबर 2025)
इक्विटी में अप्रत्यक्ष भागीदारी	3.1% (अनुमानित)	9.2% (सितंबर 2025)
वार्षिक बचत में इक्विटी और म्यूचुअल फंड का हिस्सा	2% (FY 2012)	15.2% (FY 2025)
औसत मासिक SIP	4,000 करोड़ (FY 2017)	28,000 करोड़ (FY 2026)
कुल वित्तीय संपत्तियों में जमा का हिस्सा	58% (FY 2012)	35% (FY 2025)
कुल घरेलू संपत्तियों में इक्विटी और निवेश फंड का हिस्सा	15.7% (मार्च 2019)	23% (मार्च 2025)
GDP के मुकाबले म्यूचुअल फंड परिसंपत्तियां (AUM)	10% (2010 का दशक)	23% (80 लाख करोड़)...2026

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26

कंटेंट : अमर उजाला बोनस टीम

हिन्दुस्तान
1936
सत्य ★ सार्थक ★ सदैव

अच्छे समझौते की ओर

एक लंबी और तल्ख कवायद के बाद भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते का खाका आधिकारिक रूप से संयुक्त बयान में पेश कर दिया है। यह एक उम्मीद भरी पहल है, जिसे अंतिम मुकाम पर पहुंचाने के लिए भारत को बहुत सतर्कता के साथ कदम बढ़ाने होंगे। फिलहाल समझौते का जो प्रारूप सामने आया है, वह तलवार की धार की तरह है, जिस पर अगर संतुलन साधकर न चला गया, तो नुकसान हो सकता है। व्यावहारिक रूप से देखें, तो अनेक उद्योग क्षेत्रों में खुशी है, मगर कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों में चिंता का आलम है। बहरहाल, यह स्पष्ट है कि भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क 50 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। साझा बयान के मुताबिक, दोनों देश चुनिंदा उत्पादों पर शून्य शुल्क, बाजार खोलने के उपाय और समग्र रूप से गहरे आर्थिक संबंधों के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत ने अगले पांच वर्षों में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है, तो यह खरीद इस तरह होनी चाहिए कि भारत को भी लाभ हो। अंतरिम समझौते को अंतिम न माना जाए और भारतीय वार्ताकार आगे की व्यापार वार्ता में बहुत सतर्कता से भारतीय हितों का संरक्षण कर सकें, ऐसी उम्मीद हर भारतीय को होगी।

कोई दोराय नहीं कि इस समझौते से भारत के भविष्य पर असर पड़ेगा। इतिहास में लिखा जाएगा कि जो समझौता भारत ने किया, उससे देश के किसानों, दुग्ध उत्पादकों को क्या लाभ हुआ? यह भूलना नहीं चाहिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा व्यावसायिक ढांचा अमेरिका जैसा नहीं है। हमारी एक बड़ी आबादी गांवों में रहती है, जो अपनी जीविका के लिए कृषि और डेयरी पर निर्भर है। भारत सरकार के लिए असली चुनौती इन्हीं दो क्षेत्रों में होगी और सरकार के आलोचकों की निगाह भी इन्हीं दो क्षेत्रों पर टिकी रहेगी। यही वे दो क्षेत्र हैं, जिनकी वजह से भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो नहीं पा रहा था और अमेरिका ने भारी टैरिफ भारत पर लाद रखा था। खैर, अन्य अनेक उद्योग हैं, जहां उद्यमी-निर्यातक राहत की सांस ले रहे हैं। श्रम-प्रधान कई क्षेत्रों- वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर पर लगने वाले कुल 50 प्रतिशत टैरिफ में 32 प्रतिशत अंकों की कमी आई है। मतलब, भारतीय निर्यातक फिर अन्य देशों से प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति में आ गए हैं, इससे भारतीय निर्यात में निश्चित ही बढ़त दर्ज की जाएगी।

अंतरिम समझौते को अंतिम न माना जाए और भारतीय वार्ताकार बहुत सतर्कता से भारतीय हितों का संरक्षण करें, ऐसी उम्मीद हर भारतीय को होगी।

चिंताओं से परे अगर देखें, तो अनुमान है कि भारत के लगभग 44 अरब डॉलर के उत्पाद निर्यात को अमेरिकी बाजार में शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। आश्चर्य नहीं, भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इसे एक ऐतिहासिक व्यापार ढांचा और बेहद निष्पक्ष, न्यायसंगत व संतुलित समझौता बता रहे हैं। हालांकि, यह आश्वस्त भाव से नहीं कहा जा सकता कि भारत को इस समझौते से केवल लाभ ही होगा। यदि हम सावधान नहीं रहे, तो अमेरिकी निर्यातक हमें सिर्फ बाजार बना देंगे। भारत के लिए आगे की राह आसान नहीं है, क्योंकि यह समझौता करते हुए शायद हम रूस से कुछ दूर जाते लग रहे हैं। रूस के साथ हमारा संतुलन बना रहे, यह बहुत जरूरी है, हालांकि इसके लिए रूस को भी हमारे प्रति ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। उसे ध्यान रखना होगा कि रूसी तेल की आयात की वजह से हमने 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ का जुर्माना भी झेला है। हमारी कूटनीतिक और रणनीतिक मजबूती ही संतुलित व न्यायसंगत व्यापार समझौतों को साकार करेगी।

हिन्दुस्तान Hindustan | **75 साल पहले** 09 फरवरी, 1951

सावधानी की जरूरत

हाल में दो-तीन ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं, जिनसे सरकार की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार का तंत्र विशाल होने के साथ-साथ पेचीदा है और उसके द्वारा करोड़ों रुपये खर्च होता रहता है। सरकारी खजाने में जितना भी पैसा जाता है, वह जनता का है। उस पैसे का सदुपयोग करने का दायित्व जनता ने सरकार को सौंपा है। सरकार इस धन की संरक्षक है और जनता को यह हक हासिल है कि वह सरकारी कोष से होने वाले व्यय के संबंध में सरकार से कैफियत तलब करे। जनता ने संसद में अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजे हैं और वह उनके जरिये अपने इस अधिकार का उपयोग करती है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है और उसे जनता के प्रतिनिधियों को पूरी तरह अपने विश्वास में लेना चाहिए। यदि कहीं कोई गोलमाल हुआ है, तो उस पर पर्दा डालने से कोई लाभ नहीं हो सकता। प्रकाश में आ जाने पर न केवल उसकी पुनरावृत्ति की संभावना कम हो जायेगी, बल्कि सरकारी अफसर आम तौर पर सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता अनुभव करेंगे। भारतीय संसद में प्रश्नोत्तर के समय रासायनिक खाद की खरीदी में हुआ एक गंभीर गोलमाल प्रकाश में आया है। इस गोलमाल के लिए उत्तरदायी एक उच्च सरकारी अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और दूसरे बड़े अफसर के प्रति सरकार ने अपनी नाराजगी प्रदर्शित की है।

मामला यों है कि रासायनिक खाद जितनी मात्रा में खरीदने की अनुमति दी गयी थी, उससे अधिक मात्रा में वह खरीदा गया। अनुमति केवल 4 लाख टन रासायनिक खाद खरीदने की दी गई थी, जबकि 5 लाख 48 हजार टन खरीद लिया गया। इसमें से 1 लाख 50 हजार टन राज्य सरकारों के पास और 20 हजार टन केन्द्रीय सरकार के पास अब भी बचा हुआ पड़ा है। यह रासायनिक खाद ऐसे समय खरीदा गया, जब उसकी कीमतें बहुत ऊंची थीं। इसलिए उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य चुकाना पड़ा। नियमानुसार उसे खरीदने के पहले राजस्व मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी, किन्तु वह नहीं प्राप्त की गयी। संसद के किसी सदस्य ने प्रश्न उठाया था कि जिस वस्तु को खरीदने के लिए राजस्व मंत्रालय ने अनुमति नहीं दी, उसकी अदायगी उसने कैसे होने दी, किन्तु खाद्य और कृषि मंत्री इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाये।

खेतिहर मजदूरों की संख्या क्यों बढ़ी

कृषि को फिर से जिंदा करने की जरूरत सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसमें श्रमबल का आधा हिस्सा लगा है, बल्कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक सुधार करने में मदद मिलेगी।

यहां स्कैन करें

हिमांशु | एसोशिएट प्रोफेसर, जेएनयू

राष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक, देश में अगर कोई एक क्षेत्र ऐसा है, जिसने हालिया वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो वह कृषि है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात की पुष्टि की गई है। पिछले पांच वर्षों में पूरे कृषि क्षेत्र में सालाना 4.4 प्रतिशत और बीते 10 सालों में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ये आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले कृषि क्षेत्र के लिए काफी प्रभावशाली हैं। कृषि क्षेत्र का यह प्रदर्शन पहले के प्रदर्शन से बेहतर हैं।

दूसरी तरफ, जमीनी स्तर से प्राप्त आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि कमाई के मामले में कृषि क्षेत्र अपने सबसे लंबे और गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। खेती-किसानी के क्षेत्र में यह विरोधाभास इसलिए है कि आकलन का एक हिस्सा डाटा इकट्ठा करने और उसे उपलब्ध कराने के तरीके पर आधारित होता है, जबकि विकास दर आमतौर पर कृषि और उससे जुड़े सभी क्षेत्रों को मिलाकर तय की जाती है। इसीलिए कृषि-आय और उससे जुड़े रोजगार में विकास दर जैसी तेजी नहीं दिखाई देती है।

कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में फसल उत्पादन, पशुपालन, वानिकी, लकड़ी काटना, मछली पालन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इनमें से फसल उत्पादन का हिस्सा 54 प्रतिशत, पशुपालन का 30 प्रतिशत, वानिकी का आठ प्रतिशत और बाकी मछली पालन का है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में जो विकास हुआ है, उसका एक बड़ा हिस्सा पशुपालन की वजह से आया है, जो सालाना सात प्रतिशत से भी ज्यादा की दर से बढ़ा है। पिछले दशक में मछली पालन आठ प्रतिशत से ज्यादा की दर से बढ़ा।

दूसरी ओर, कृषि-कर्म के सबसे बड़े उप-क्षेत्र में सालाना दो प्रतिशत की वृद्धि ही देखी गई है। इनमें अनाज, तिलहन, दलहन, कपास और गन्ना जैसी मुख्य फसलों के साथ ही फल, सब्जियां व बागवानी शामिल हैं। पशुपालन के साथ यह खेतिहर मजदूरों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र भी रहा है। विडंबना यह है कि फसल उगाने वाले कृषि क्षेत्र में साल 2004 से 2014 के बीच सालाना 3.3 प्रतिशत की दर से विकास हुआ था, लेकिन इसके आगे के दशक में उसकी विकास दर वानिकी और पशुपालन से बहुत पीछे रह गई है।

हालांकि, पशुपालन, मछली पालन और वानिकी के बारे में जो बुनियादी आंकड़े फसलों की तुलना में कमजोर रहे हैं, मगर पिछले दशक में इन क्षेत्रों में सात प्रतिशत से ज्यादा की सालाना विकास दर बताई जा रही है, जो कुछ संदिग्ध लगता है। पिछले रुझानों से पता चलता है कि पशुपालन में विकास फसली खेती के बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा हुआ था। इसका मूल कारण यह है कि हमारे देश में ज्यादातर किसान खेती के साथ-साथ मवेशी भी पालते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर जारी आंकड़े बताते हैं कि पशुपालन में फसली खेती से कहीं तेज विकास हो रहा है, लेकिन स्थिति आकलन सर्वेक्षण, यानी एसएएस के आंकड़ों को देखें, तो उसमें पशुपालन में वृद्धि की रफ्तार कम दिखाई देती है। यही नहीं, ज्यादातर किसानों के मुख्य पेशे में शामिल फसली खेती में राष्ट्रीय स्तर पर अन्य क्षेत्रों की तुलना में विकास दर सुस्त है। भारतीय परिवार सर्वेक्षण के अप्रत्यक्ष आकलनों में भी इसी तरह की कमजोर विकास दर दिखती है।

खेती-किसानी से होने वाली आमदनी में कमी का ही परिणाम है कि किसान परिवारों के सदस्यों को मजदूरी करनी पड़ती है, लेकिन पिछले दशक में मजदूरी दर के लगभग स्थिर रहने के कारण मजदूरी भी उनकी आय बढ़ाने में अपर्याप्त साबित हुई है। नीति आयोग द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय स्तर के अप्रत्यक्ष आय आकलन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच किसानों की आय में सालाना 0.62 प्रतिशत की गिरावट आई है।

ये आंकड़े न केवल किसानों की आय दोगुनी करने के दावों के विपरीत हैं, बल्कि इससे कमाई और मुनाफे की दर में गिरावट का भी सहज अंदाजा हो जाता है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि साल 2004-05 से 2011-12 के बीच किसानों की आय में प्रतिवर्ष 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2014-15 के पूरे दशक के आधार पर गणना करने पर किसानों की आय में वृद्धि छह प्रतिशत ही रही। मतलब साफ है कि बाद के तीन वर्षों में कृषि आय में भारी गिरावट आई।

खेती-किसानी से होने वाली कमाई में गिरावट ऐसे समय में हो रही है, जब इस पर आश्रितों की संख्या बढ़ रही है। गौर कीजिए, पिछले छह सालों में लगभग 6.6 करोड़ खेतिहर मजदूर बढ़े हैं। साल 2004-05 से 2017-18 के बीच उनकी संख्या में जो गिरावट आई थी, वह फिर से बराबर हो गई है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ है कि खेती में बेहतर मजदूरी मिल रही है, बल्कि गैर-कृषि क्षेत्र के संकट में होने के कारण मजदूर वहां से पलायन करके फिर खेती की ओर भाग रहे हैं। गैर-कृषि क्षेत्र के उद्योग-कारोबार रोजगार देने में नाकाम रहे हैं। मजदूरों का वापस खेती की ओर लौटना इस बात का सुबूत है कि हम जिस संकट का सामना कर रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वह बहुत गंभीर है। यह सब तब हो रहा है, जब हमारे किसान पैदावार बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए इस गिरावट के लिए कृषि संबंधी नीतिगत उदासीनता को जिम्मेदार माना जा सकता है।

देखा जाए, हाल के वर्षों में खेती में सरकारी निवेश कम हुआ है। सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने की व्यवस्था भी फसलों की कीमतों को थामे रखने में मददगार नहीं साबित हो पा रही है। इस साल तो ज्यादातर फसलों की कीमतों में गिरावट खेत से उठाव के स्तर पर ही आई है। खाने-पीने की चीजों में महंगाई कम हुई है, तो किसानों को मिलने वाली कीमतें भी कम हो गई हैं।

साफ है, कृषि को फिर से जिंदा करने की जरूरत सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसमें देश के श्रमबल का आधा हिस्सा लगा हुआ है, बल्कि खेती में सुधार से ही हमारी अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक सुधार लाने में मदद मिलेगी। निजी निवेश में तेजी नहीं आ रही, इसलिए अर्थव्यवस्था में विकास की गति को बनाए रखने के लिए हमें घरेलू मांग बढ़ाने की जरूरत है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जानलेवा डिजिटल खेलों से बच्चों को बचाना जरूरी

यहां स्कैन करें

क्षमा शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार

पिछले दिनों गाजियाबाद की तीन बहनों ने जिस तरह अपने फ्लैट से कूदकर आत्महत्या कर ली, वह दिल दहलाने वाला वाकया है। बताया जा रहा है कि ये बच्चियां ऑनलाइन कोरियन गेम्स खेलती थीं और उनमें दिए गए तरह-तरह के टास्क पूरे करती थीं। सिर्फ खेल ही नहीं, हर वह चीज उन्हें पसंद थी, जो कोरिया से जुड़ी हैं। अपने घर वालों से वे यही कहा करती थीं कि तुम लोग भारतीय हो और हम कोरियाई। वे तीनों शादी भी कोरिया के लड़कों से ही करेंगी।

जैसी कि खबरें आई हैं, उनसे पता चलता है कि पिता ने इन लड़कियों के मोबाइल फोन छीन लिए थे, जिससे वे नाराज थीं। उन्होंने इसे लिखा भी और डायरी पढ़ने को कहा। न वे स्कूल जाती थीं, न उनके घर में बिजली थी। इसके अलावा उनके पिता ने तीन शादियां की थीं। पहली पत्नी से बच्चे न हुए, तो दूसरी शादी उसकी बहन से ही कर ली। इसके बाद तीसरी बहन को भी घर ले आया। यह बिडंबना ही है कि इन लड़कियों को तीन माओं को सहना पड़ा। आखिर किस कानून के तहत ऐसा हुआ और कोई कार्रवाई नहीं की गई? क्यों उनके घर में बिजली नहीं थी। वे नौवीं मंजिल पर रहती थीं। बिजली के बिना उनके फोन कैसे चार्ज होते थे। यदि यह मान भी लें कि मोबाइल की लत में उन्होंने खुद ही स्कूल जाना छोड़ दिया था, तो घर वालों ने उन्हें क्यों नहीं समझाया, उनके इस निर्णय को स्वीकार कैसे कर लिया गया? ऐसे बहुत से सवाल अनुत्तरित हैं, जो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन कुछ भी जांच कर लें, तो वे लड़कियां, जिनकी उम्र सोलह वर्ष से बारह वर्ष के बीच थी, जा चुकी हैं। अरसे से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोरिया के संगीत, कोरियाई सौंदर्य उत्पाद, वहां का खाना किशोरों व युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। इस मामले में कोरिया ने अमेरिका व यूरोप तक को पछाड़ दिया है।

आखिर उद्योग की बढ़त के नाम पर बच्चों की जान से खेलने वाली गेम कंपनियों पर दुनिया भर में कोई रोक क्यों नहीं लगाई जाती?

साल 2015 में रूसी गेम 'ब्लू व्हेल' खेलते हुए एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। अर्जेंटीना की एक लड़की ने भी ऐसा किया था। भारत से भी ऐसी खबरें आई थीं। एक लड़के को तो ऐन टाइम पर पुलिस ने आत्महत्या करने से बचा लिया था। पबजी भी ऐसा ही एक खेल था। भारत में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। राजस्थान में एक लड़के को जब माता-पिता ने पबजी खेलने से मना किया, तो उसने तवा मारकर उनकी हत्या कर दी। इन दिनों विशेषज्ञ कहते हैं कि ऑनलाइन खेल खेलने से बेशक बच्चे औरों से जुड़े रहते हों, पर मूलतः वे लगातार अकेले होते जाते हैं। अनेक मामलों में अवसाद से घिर जाते हैं। क्या पता ये तीनों लड़कियां भी अवसादग्रसित हों, क्योंकि ये किसी से मिलती-जुलती भी नहीं थीं।

कुछ खबरों में बताया गया है कि ऑनलाइन गेम खेलने की लत के कारण ही वे फेल हो गई थीं, इसलिए स्कूल छूट गया था। अनुत्तीर्ण होना इतनी बड़ी बात तो नहीं कि बच्चों का स्कूल ही छूट जाए और उन्हें दोबारा स्कूल ही न भेजा जाए? जिस घर में एक पिता और तीन माएं हों, वहां लड़कियां किस मुसीबत में हैं, इसकी भनक तक नहीं लगी। लगी भी हो, तो उसका निदान कैसे किया गया, यह मालूम नहीं। आज की दुनिया में हमारे बच्चे इतने अकेले हैं कि उनके सवालों से बचने के लिए माता-पिता उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं। यदि माता-पिता अपने बच्चों के सवालों से बचते हैं, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान नहीं करते, तो बच्चे बाहर की दुनिया की ही राह पकड़ेंगे। आजकल बहुत से माता-पिता यही दलील देते हैं कि वे बच्चों को मोबाइल कैसे न दें, स्कूल के असाइनमेंट मोबाइल पर आते हैं? इसलिए बच्चों को मोबाइल देना उनकी मजबूरी है। मोबाइल पर वे क्या कुछ देख रहे हैं, इसका पता नहीं चलता। इसलिए स्कूलों को मोबाइल पर असाइनमेंट भेजने बंद करने चाहिए।

इसके अलावा वे गेम कंपनियां भी कोई कम दोषी नहीं, जो ऐसे खेल बनाती हैं, जिनमें बच्चे इतने उलझ जाते हैं कि वे उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। मोबाइल छीनने पर वे इतने हिंसक भी हो जाते हैं कि या तो किसी परिजन पर हमलावर हो जाते हैं, या अपनी जान दे देते हैं। आखिर उद्योग की बढ़त के नाम पर बच्चों की जान से खेलने वाली ऐसी गेम कंपनियों पर दुनिया भर में कोई रोक क्यों नहीं लगाई जाती, यह भी सोचने की बात है। कृपया बच्चों की जिंदगी से मत खेलिए।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

प्रेम सफल क्यों नहीं होता

प्यार का मौसम आ रहा है। 'आई लव यू' के संदेशे हवाओं में उछाले जाएंगे। प्रेम के बारे में इतना लिखा जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद कोई प्रेम कहानी सफल होती नहीं दिखती। लोग प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, क्योंकि प्यार रोमांस में ही उलझकर रह जाता है। प्रेम के बारे में गलतफहमियां बहुत हैं। ओशो ने एक अद्भुत बात कही है : 'आई लव यू' के जुमले से सावधान! यह एक आक्रामक वक्तव्य है। इसके बदले में दूसरे को फौरन कहना पड़ता है- 'आई लव यू टू।' यह एक शिष्टाचार बन गया है। इसका निहित अर्थ है कि मैं तुमसे सिर्फ इसलिए प्यार करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार करो। इसमें एक शर्त है कि तुम्हें किसी और से प्यार नहीं करना चाहिए। हर कोई चाहता है कि मेरे प्यार में कोई हिस्सेदार न हो। यह बहुत बड़ी भ्रांति है।

रोमांस सिर्फ ख्यालों में जी सकता है। जब लोग साथ रहने लगते हैं, तो रोमांस यथार्थ की आग में जल जाता है। एक दूसरे की छोटी-छोटी बातें चुभने लगती हैं, अखरने लगती हैं। प्यार करने वाले एक-दूसरे की जासूसी कर रहे होते हैं। जब प्रेम का रंग उड़ जाता है, तब प्रेमी एक-दूसरे को दोष देते हैं, फिर प्यार एक लगातार संघर्ष बन जाता है। समस्या यह है कि प्रेमी एक-दूसरे को बांधकर रखना चाहते हैं। प्रेम कोई एक वस्तु नहीं है, वह सीमित नहीं होता कि एक को मिले, तो दूसरे को नहीं मिल सकता। इंसान का संकीर्ण मन सोचता है कि प्यार को एक व्यक्ति के साथ बांधकर रखना है। ऐसा बंधा हुआ प्रेम सड़ जाता है। जिनसे प्रेम हो, उनका भरोसा करना सीखें।

प्रेम की बुनियाद है भरोसा। खासकर स्त्री के लिए भरोसा बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वह इतनी असुरक्षा में जीती आई है कि उसका किसी पर भरोसा नहीं रहा। हर कोई उसका शोषण करता है। स्त्री या पुरुष का दिल जीतना है, तो पहले उनका भरोसा जीतें। 'आई लव यू' की जगह कहें, 'आई ट्रस्ट यू'। अगर भरोसा है, तो प्रेम उसके पीछे छाया की तरह चला आता है। प्यार खूबसूरत होगा, अगर वह भरोसे का हिस्सा बनकर आए। भरोसे के बिना प्यार विफल होता है, क्योंकि अंदर ही अंदर उसमें जलन, शक, अविश्वास, बंधन वगैरह छिपे हुए दुश्मन सक्रिय होते हैं।

प्रेम की बुनियाद है भरोसा। स्त्री के लिए भरोसा बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वह इतनी असुरक्षा में जीती आई है कि उसका किसी पर भरोसा नहीं रहा। इसलिए दिल जीतना है, तो पहले भरोसा जीतें।

भरोसे का फूल हृदय में खिलता है। भरोसे में आपको हमेशा खुद में कमियां ही मिलेंगी; सतही प्यार में आपको हमेशा उस इंसान में कमियां मिलेंगी, जिससे आप प्यार करते हैं। भरोसे में आपका ध्यान दूसरे पर नहीं होता, खुद पर होता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैं कैसे अपने आपको निखारूं। भरोसा हृदय में पलता है, पनपता है। भरोसेमंद बनना बहुत बड़ा वरदान है।

अमृत साधना

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

दो देश का समाधान ही स्थायी शांति का एकमात्र न्यायपूर्ण रास्ता है। इजरायली और फलस्तीनी शांति व सुरक्षा के साथ अपने-अपने देश में रहें। इजरायली कब्जा खत्म होना चाहिए। फलस्तीनी लोगों को जरूरी अधिकार मिलने चाहिए।

यातना के केंद्र बन रहे निजी अस्पताल

आज देश की निजी अस्पताल व्यवस्था जिस हालत में पहुंच चुकी है, वह एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों आम नागरिकों का साझा अनुभव बनती जा रही है। जो कभी सेवा और संवेदना का क्षेत्र माना जाता था, अब मुनाफा कूटने का ऐसा संगठित उद्योग बन चुका है, जहां इंसान की बीमारी से ज्यादा उसकी जेब देखी जाती है, उसका बीमा और सामाजिक दर्जा देखा जाता है। निजी अस्पतालों की चमक-दमक, वातानुकूलित गलियारे और आधुनिक मशीनें बाहर से भले तरक्की का भ्रम पैदा करती हों, लेकिन भीतर एक ऐसी व्यवस्था काम कर रही है, जो आम आदमी के लिए किसी यातना सेल से कम नहीं है।

आज अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े अस्पताल में इलाज कराने जाता है, तो सबसे पहला सवाल बीमारी को लेकर नहीं, बल्कि उसकी भुगतान क्षमता को लेकर होता है। रिसेप्शन पर, एडमिशन काउंटर पर या डॉक्टर से मिलने से पहले ही यह पूछा जाता है कि आपके पास स्वास्थ्य बीमा है या नहीं, आप सरकारी नौकरी में हैं या निजी क्षेत्र में, कैश में भुगतान करेंगे या कैशलेस। इनके जवाब से मरीज का पूरा इलाज तय होता है। जैसे ही यह स्पष्ट होता है कि मरीज 'इंश्योरेंस कवर' में है या किसी सरकारी/कॉरपोरेट स्कीम के तहत आता है, अस्पताल का रवैया बदल जाता है। इलाज की जगह एक योजनाबद्ध कमाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

स्वास्थ्य बीमा का अर्थ होना चाहिए सुरक्षा, लेकिन आज कई निजी अस्पतालों के लिए यह लूट का लाइसेंस बन चुका है। जरूरत से ज्यादा महंगी दवाइयां लिख दी जाती हैं, जबकि उनके सस्ते और समान प्रभाव वाले विकल्प आसानी से उपलब्ध होते हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति तो तब बनती है, जब मरीज की हालत में सुधार के बावजूद उसे अस्पताल में रखा जाता है। जो मरीज सामान्य स्थिति में चार-पांच दिन में घर जा सकता है, उसे जान-बूझकर दस-पंद्रह दिन तक भर्ती रखा जाता है।

सरकारी अस्पतालों की स्थिति भी खास संतोषजनक नहीं है। वहां इलाज सस्ता या मुफ्त तो है, पर भीड़, संसाधनों की कमी और अव्यवस्था के कारण मरीजों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है। बेड की कमी, स्टाफ की कमी और दवाइयों की अनुपलब्धता के चलते कई लोग मजबूरी में निजी अस्पतालों की ओर रुख करते हैं। इसी मजबूरी का फायदा निजी अस्पताल उठाते हैं। तो क्या हम इलाज को सिर्फ मुनाफे का साधन मानने को तैयार हैं, या फिर उसे इंसानियत और सेवा से जोड़कर देखना चाहते हैं? अगर समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो वह दिन दूर नहीं, जब बीमारी से ज्यादा डर इलाज के बिल से लगने लगेगा।

प्रियंका सौरभ, सामाजिक कार्यकर्ता

अनुलोम-विलोम

महंगा इलाज

इन अस्पतालों से लाखों जानें बच रहीं

हमारे देश में निजी अस्पतालों के खिलाफ अक्सर यह शिकायत की जाती है कि वे अनाप-शनाप बिल बनाते हैं और बिना मतलब मरीजों को आईसीयू में रख देते हैं। इस तर्क की सबसे पहली काट तो यही है कि निजी अस्पतालों में भी ओपीडी (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) होता है और सामान्य मरीज वहीं अपने रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर से दिखाते हैं, दवा लिखवाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अस्पताल में सिर्फ वही मरीज भर्ती किए जाते हैं, जिनकी हालत गंभीर होती है या गंभीर बनने का अंदेशा होता है। कई बार लोगों को लगता है कि बेकार ही भर्ती कर लिया, जरूरत नहीं थी, मगर अगर किसी मरीज ने अस्पताल के रास्ते में दम तोड़ दिया, तो परिजनों को जिंदगी भर का अफसोस रह जाता है कि काश! समय रहते भर्ती करा दिए होते, तो शायद उनका मरीज बच जाता। मैं यह नहीं कहता कि निजी अस्पतालों के प्रबंधन में कमियां नहीं हैं या फिर वे दूध के धुले हैं, मगर किसी भी समस्या का सरलीकरण उसके निदान की राह में सबसे बड़ी बाधा है।

हमारे देश में लगभग 43 हजार निजी अस्पाल हैं, जो दिन-रात लाखों मरीजों की सेवा कर रहे हैं। फर्ज कीजिए, अगर ये न होते, तब क्या होता? सरकारी अस्पतालों की तब क्या स्थिति होती? महामारी के समय हमने देखा कि कितनी शिद्दत से निजी अस्पतालों और उनके डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी लोगों की सेवा की थी, इसलिए एक-दो मामलों के आधार पर आम राय बनाना ठीक नहीं है। हां! अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ गलत हो रहा है, तो उसे उजागर करना और दुरुस्त कराना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। निजी अस्पतालों में अमूमन समर्थ लोग जाते हैं और वे चिकित्सा के साथ उसकी सुविधाओं की कीमत जानते हैं। सरकारी अस्पतालों की कम संख्या और उन पर मरीजों के भारी दबाव को देखते हुए ही सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत 15,733 निजी अस्पतालों को पंजीकृत किया है, ताकि आपात स्थिति में लोग वहां इलाज करा सकें। इसलिए निजी अस्पतालों को लूट का अड्डा बताकर उनमें सेवा दे रहे डॉक्टरों व नर्सों के साथ अन्याय मत कीजिए। अगर आर्थिक रूप से असमर्थ हैं, तो सरकारी अस्पतालों की कतार में आपको लगना चाहिए। हमारे मध्यवर्ग दोमुंहापन यही है कि उसे सुविधाएं तो उच्च वर्ग वाली चाहिए, मगर वे उसे निम्न मध्यवर्ग वाली रियायती दर पर चाहिए। इसी दोहरेपन ने उसे निजी अस्पतालों के खिलाफ कर रखा है। उसे हकीकत स्वीकारते हुए स्वास्थ्य बीमा लेने की आदत डालनी चाहिए।

अधीर शर्मा, टिप्पणीकार

मन की जाग से बदलेगी जिंदगी

रोज की भागदौड़ में यह नहीं दिखता कि हम सजग होकर नहीं, अपनी आदतों के भरोसे जी रहे हैं। हमारी इच्छाएं जब अधूरी रह जाती हैं, तो हम उन्हें किस्मत या संयोग मानकर बैठ जाते हैं। वहीं, सजग मन से किए कामों के साथ पूरे ब्रह्मांड की शक्ति जुड़ी होती है। सही लोग, सही संसाधन खुद-ब-खुद आपके पास खिंचे चले आते हैं।

एकहार्ट टॉल्ल
आध्यात्मिक शिक्षक और लेखक। 'द पावर ऑफ नाउ' आपकी चर्चित किताब है।

कभी गौर किया है कि हम हर दिन अपनी आदतों को ही दोहराते हुए बिताते हैं। हम इच्छाएं करते हैं, प्रयास करते हैं और जो परिणाम मिलता है, उसे भाग्य या संयोग मान लेते हैं, लेकिन क्या सच में जीवन इतना अनिश्चित है? क्या हर इच्छा का परिणाम केवल किस्मत पर निर्भर करता है या इसमें हमारी अपनी भी कोई भूमिका होती है?

जीवन में जाग्रति की प्रक्रिया दो तरह से आगे बढ़ती है। पहले हम अपने भीतर उस 'परम स्रोत' को खोजें, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। उसके बाद उस बोध को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करें, इस तरह धीरे-धीरे हमारा जीवन उस शाश्वत स्थिरता से सराबोर होने लगेगा।

अपने वर्तमान से जुड़ें

जैसे-जैसे जीवन में सजगता का ठहराव आता है, अहंकार धुंधला होने लगता है। हम एक अलग ऊर्जा से संपन्न होने लगते हैं, मानो किसी दूसरे आयाम की शक्ति आपके माध्यम से इस संसार में प्रकट हो रही हो। असल में, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, जो निरंतर कुछ न कुछ 'कर' रहे हैं, लेकिन वे ये सब अपनी चेतना के साथ नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही कर्म अक्सर अशांति पैदा करते हैं और अंततः असंतोष पैदा होने लगता है, इसलिए हमारा पहला काम अपने परम स्वरूप से जुड़ना है।

आप अपने वर्तमान से जुड़ें। अपनी व्यस्त दिनचर्या पर गौर करें कि क्या आपकी सजगता छोटी-छोटी चीजों में भी दिखाई पड़ती है? किसी को सुनते हुए या रास्ते पर चलते हुए, क्या आपका ध्यान पूरी तरह उसी काम पर होता है। सजगता का अर्थ है- वर्तमान क्षण जैसा भी है, उसे बिना किसी विरोध के स्वीकार करना। आप वर्तमान के साथ जितना तालमेल बिठाते हैं, चेतना की शक्ति उतनी ही प्रबल होती जाती है।

अहंकार से मुक्त कर्म

जब आप वर्तमान को स्वीकार लेते हैं, तो कर्म का एक नया स्वरूप उभरता है, जिसे 'जाग्रत कर्म' कहते हैं। यह कर्म किसी दबाव से नहीं, बल्कि आंतरिक प्रेरणा से जन्म लेता है। यह कर्म अहंकार से मुक्त होता है। आप कुछ पाने के लिए ही कर्म नहीं करते, बल्कि उस कर्म को करने में ही आपको एक असीम आनंद की अनुभूति होने लगती है। जब आप कोई काम पूरे आनंद से करते हैं, तो उसके नतीजों की चिंता ही खत्म हो जाती है। परिणाम आपकी उम्मीद से कहीं बेहतर मिलते हैं।

जागे हुए मन के साथ किए जाने वाले कर्म किसी अभाव को भरने के लिए नहीं होते। यह 'पूर्णता' के भाव से जुड़े होते हैं। जब आप भीतर से स्वयं को पूर्ण महसूस करते हैं, तो आपके काम संसार में कुछ जोड़ने या खुद को महान साबित करने के लिए नहीं होते, बल्कि वे आंतरिक आनंद का विस्तार बन जाते हैं।

इस मार्ग में चुनौतियां और बाधाएं भी आती हैं, खासकर तब जब आप दुनिया की स्थापित मान्यताओं से हटकर कुछ करते हैं, लेकिन याद रखें, जब आप पूरी तरह सजग होते हैं, तो एक विराट ब्रह्मांडीय शक्ति आपकी ढाल बन जाती है। सही समय पर सही व्यक्ति और सही साधन खुद-ब-खुद आपके पास खिंचे चले आते हैं। एक जागरूक व्यक्ति बाधाओं को 'शत्रु' नहीं मानता।

इच्छाओं की पूर्ति के चार चरण

अपनी चेतना के माध्यम से किसी भी लक्ष्य को पाने के चार चरण हैं- स्वयं को पहचानें। अपनी इच्छा को स्पष्ट रखें। इच्छा पूरी होने की प्रक्रिया पर विश्वास रखें और नतीजों के लिए सजग रहें।

इस सप्ताह करें यह अभ्यास

1. **अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ना :** जब आप शांत, स्पष्ट और एकाग्र होते हैं, तब आप अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़े होते हैं। तनाव, बिखराव, अत्यधिक सोच या अहंकार के हावी होने पर यह जुड़ाव टूट जाता है।
2. **मन में स्पष्ट इच्छा रखना :** जिन इच्छाओं के पीछे मंशा अच्छी होती है, वे सहज और स्वाभाविक लगती हैं। वे बिना जोर डाले अपने आप मन में आती हैं। स्वार्थ से भरी इच्छाएं मन पर दबाव बनाती हैं।
3. **प्रक्रिया पर भरोसा रखना :** अब इच्छा को पकड़े न रहें। मन को खुला छोड़ें। परिणाम की चिंता करना केवल प्रक्रिया को रोकता है और तनाव बढ़ाता है।
4. **नतीजों के प्रति सजगता :** जागरूक अवस्था में इच्छाएं भीतर और बाहर के बीच निरंतर संवाद से सही नतीजों तक पहुंचती हैं। प्रकृति को आपकी शुरुआती इच्छा के अलावा किसी हस्तक्षेप की जरूर होती। अब जब प्रकृति अपको उस अनुरूप मौके दे, तो उसे स्वीकारें।

चेतना और इच्छाएं

आज हम चेतना को अपनी निजी चीज मानते हैं- मेरे विचार, मेरी इच्छा, लेकिन अकेला अहंकार कभी भी जागरूकता की गहरी सच्चाई को नहीं समझ पाता। असल में हमारा मन जिस स्रोत से आता है, वही शुद्ध जागरूकता है, जो सभी में समान रूप से मौजूद है। वहीं हमारा सच्चा स्वरूप है। जब हम इसे समझ लेते हैं, तब इच्छाओं के सकारात्मक परिणाम अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं।

जब आप बिना किसी झिझक, अपने सजग मन से उपजी इच्छाओं को शब्दों का रूप देना छोड़ देते हैं, तो आपका शरीर स्वयं वो इच्छाएं पूरी करने लगता है। इस विचार को पूरी तरह से त्याग दें कि एक अलग इकाई के रूप में आपको कुछ 'करना' है। इस बात के लिए तैयार रहें कि यह संसार आपसे क्या करवाना चाहता है, तब आपके माध्यम से 'सजग कर्म' घटित होने लगते हैं। आप जितना अधिक अपने 'अहंकार' को रास्ते से हटाएंगे, अपने जीवन को सजगता से जोड़ेंगे, उतना ही इस प्रश्न का उत्तर मिलने लगेगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, क्या किया जाना चाहिए। धीरे-धीरे आप उस दिशा में बढ़ने लगेंगे। इसके साथ तालमेल बिठाना एक अद्भुत साहसिक यात्रा है।

-eckharttolle.com

काम की बात

दूसरों को खुशी देने के लिए चढ़ें यह सीढ़ी

हम सभी को ऐसे लोगों का साथ अच्छा लगता है, जो हमें हमारे बारे में अच्छा महसूस कराएं। यहां दी गई 'वेलिडेशन लेडर' में सुझाए कौशल के जरिये आप बिना किसी दिखावे, दूसरों को सम्मानित महसूस करा सकते हैं। जितना ऊंचा आप इस सीढ़ी पर चढ़ेंगे, उतने ही दूसरों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे।

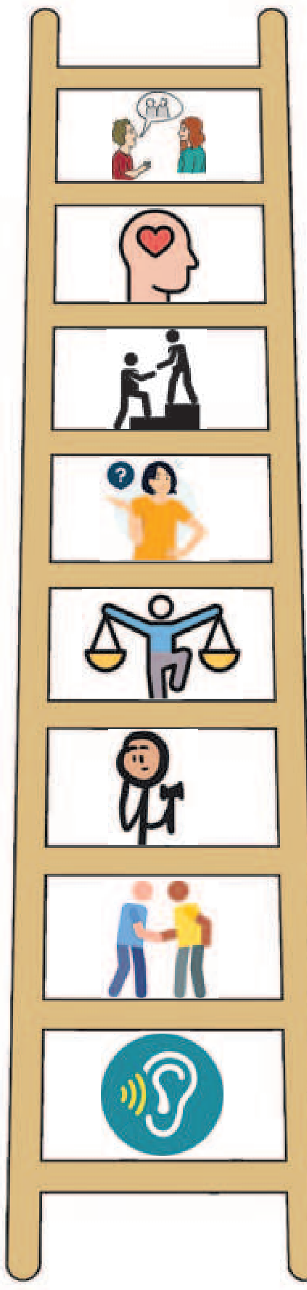

- **समानता :** कोई खुद को हीन या अयोग्य मान रहा है, तो उन्हें एहसास कराएं कि ऐसा सबके साथ हो सकता है। इससे उनका बोझ कम होगा।
- **भावनाओं को शब्द दें :** अगर वे अपनी स्थिति बयां नहीं कर पा रहे, तो उनके हाव-भाव और मंशा को समझते हुए उनकी भावनाओं को सही शब्दों में विस्तार दें।
- **कदम उठाएं :** सिर्फ शब्दों तक सीमित न रहें। उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें और उनके लिए कुछ खास करने की कोशिश करें।
- **संवेदना :** अपनी सच्ची प्रतिक्रिया जाहिर करें। बिना किसी दिखावे के दूसरों का दुख समझते हुए उन्हें साथ होने का एहसास कराएं।
- **साझा करें :** दूसरों से अपने निजी अनुभव भी साझा करें। उनकी स्थिति से मिलती-जुलती अपनी बातें उन्हें बताएं। इससे आपसी भरोसा और अपनत्व बढ़ता है।
- **प्रतिबिंब :** उनके शब्दों और भावनाओं को दोहराएं। जब आप उनकी बात को उनके ही अंदाज में कहते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्हें वाकई सुना गया है।
- **संदर्भ समझें :** दूसरों की बात को पूरी तरह समझने के लिए उनके हालात को समझें। इससे आप बेहतर प्रतिक्रिया दे पाएंगे।
- **उपस्थिति :** बिना राय बनाए सिर्फ उनकी बात सुनें। अपने हाव-भाव से यह दिखाएं कि आपका पूरा ध्यान उन पर है।

याद रखें : एक साथ सभी पायदान चढ़ना जरूरी नहीं है। आप धीरे-धीरे अपने सफर को आगे ले जा सकते हैं।

दिन की शुरुआत ही नहीं समापन भी हो सार्थक

रात में सोने से पहले आप क्या करते हैं? यह सवाल इसलिए कि अक्सर हम सुबह की दिनचर्या को अच्छा बनाने पर ही जोर देते हैं। अगर आप देर रात तक सोशल मीडिया देखते रहते हैं, तो आपकी सुबह कब तक अच्छी रहेगी?

विविध

आप किसी से मिलने गए। उन्होंने गर्मजोशी से आपका स्वागत किया। लेकिन अगली बार आप उनसे किस ढंग से मिलेंगे, यह निर्भर करेगा कि उन्होंने जाते समय आपको कैसा एहसास कराया था? इसी तरह, हम सुबह की शुरुआत कितने ही अनुशासन से करें, अगर हमारी रात की दिनचर्या सही नहीं है, तो हम अगले दिन खुद को जूझता हुआ ही पाएंगे।

अगर आप देर रात तक यूं ही फोन चलाते रहते हैं या चार-पांच घंटे भी ढंग से नहीं सो पाते, तो मानकर चलें कि आपने अपना अगला दिन बर्बाद कर दिया है। नोबेल विजेता जेफरी हॉल व माइकल रोसबैश के अनुसार, हमारा शरीर पृथ्वी के 24 घंटे घूमने की गति के अनुसार बना है। यदि रात का रूटीन गड़बड़ है, तो हमारी जैविक घड़ी का तालमेल बिगड़ जाता है। 'सोशल जेट लेग' के कारण अगले दिन थकान होती है। काम पर बुरा असर पड़ता है। रात का रूटीन महज सोना नहीं है, यह अपनी जैविक घड़ी को ब्रह्मांड से जोड़ना है।

नींद का दिमाग पर असर

नींद की कमी होने पर सबसे पहले मस्तिष्क का 'प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स' (निर्णय लेने वाला हिस्सा) काम करना बंद कर देता है। शोध बताते हैं कि 7 घंटे से कम की नींद लेने पर मानसिक प्रदर्शन में 10% तक की कमी आ सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, रात की सही दिनचर्या दिमाग के 'ग्लिम्फैटिक सिस्टम' को सक्रिय करती है। यह दिमाग की साफ-सफाई की प्रणाली है, जो दिनभर में जमा टॉक्सिक प्रोटीन को साफ करती है। इससे दिमाग के बूढ़े होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। कुलमिलाकर, हमारी हर सुबह, ताजगी से भरी हो, इसके लिए हमें रात में अच्छी नींद चाहिए। यह तब होगा, जब हम सोने से पहले दिनभर की थकान और अच्छे-बुरे अनुभवों को एक सुखद विदाई देना सीख जाते हैं।

पूनम जैन

सोने से पहले के दो घंटे खास

आपका दिमाग कोई स्विच नहीं है कि आप बटन दबाएं और वह तुरंत सो जाएं। वह धीरे-धीरे सोने के मोड में जाता है। सोने से पहले के दो घंटों में स्क्रीन देखना, संदेशों का जवाब देना या काम की चिंता करना नींद को कोसों दूर कर देता है। कुल मिलाकर, शाम के बाद से अपनी रफ्तार धीमी कर दें। तेज रोशनी के बजाए हल्की रोशनी रखें।

10-3-2-1-0 का नियम

- **10 घंटे पहले :** कैफीन बंद कर दें।
- **3 घंटे पहले :** खाना बंद। धूम्रपान, शराब या नशीली दवा गहरी नींद में बाधक होती हैं।
- **2 घंटे पहले :** सारा काम बंद। परिवार से बात करें। अगले दिन की थोड़ी तैयारी करें।
- **1 घंटा पहले :** स्क्रीन (मोबाइल/टीवी) बंद। शोधों के अनुसार स्क्रीन की नीली रोशनी दिमाग को देर तक जगाए रखती है। दिमाग शांत करने वाले काम करें–
  - किताब पढ़ें, संगीत सुनें। गहरे सांस लें।
  - अपना बिस्तर सही करें।
  - दिनभर में जो अच्छा हुआ, जिन्होंने आपका साथ दिया, उनका आभार व्यक्त करें। किसी ने दुख दिया है तो उन्हें माफ करें।
  - अगर कोई जाप करते हैं, तो उसे दोहराएं।
  - ब्रह्मांड से अपने और सबके भले की कामना कर सकते हैं।
- **0 :** सुबह अलार्म बजते ही उठें।

एकदा

जगह

एक रात बहुत जोर की वर्षा हो रही थी। एक साधु और उनकी पत्नी अपनी छोटी-सी झोपड़ी में सोए हुए थे। आधी रात किसी ने दरवाजा खटखटाया।

साधु उठने लगे, तो पत्नी ने मना किया। पत्नी ने कहा कि कोई शरण मांगने आया होगा और आप मना कर नहीं सकोगे। इस घर में जगह भी कहां है? इस पर साधु ने कहा, 'जगह दो के सोने के लायक है, तो तीन के बैठने के लायक काफी होगी। द्वार आए आदमी को वापिस तो नहीं लौटाना है।'

दरवाजा खोला, तो कोई शरण ही मांग रहा था। अब तीनों बैठकर गपशप करने लगे। थोड़ी देर बाद किसी और आदमी ने दस्तक दी, तो फिर पत्नी ने कहा कि अब किसी ने शरण मांगी तो? इस पर साधु ने कहा कि अभी बैठने लायक जगह है, पर चार लोग आराम से खड़े हो जाएंगे। दरवाजा खोला गया और इस तरह अब वे चारों खड़े होकर समय बिताने लगे।

थोड़ी देर बाद झोपड़ी के बाहर एक गधा जोर से दरवाजा हिलाने लगा। इस बार पत्नी ने थोड़ा जोर देकर कहा, 'यह गधा है, आदमी नहीं। अब यहां बिल्कुल जगह नहीं है।' इस पर साधु ने कहा कि हमने आदमियों के कारण दरवाजा नहीं खोला था, हमने अपनी करुणा के कारण दरवाजा खोला था। हमारे लिए गधे और आदमी में क्या फर्क? दूसरे मेहमानों की तरह गधे ने अपना काम कर दिया है। अब हमें अपना काम करना है। मैं दरवाजा खोलता हूं।'

पत्नी ने कहा, 'अब खड़े होने की भी जगह नहीं है।' साधु ने कहा, 'अभी हम जरा आराम से खड़े हैं, फिर सटकर खड़े हो जाएंगे। यह किसी अमीर का महल नहीं है, यह गरीब का झोपड़ा है। इसमें खूब जगह है। बात अमीर या गरीब की नहीं, हृदय की है। पर एक सच यह है कि जैसे-जैसे हम अमीर होते हैं, पकड़ने के लिए चीजें मिलती हैं, तो हम कंजूस होने लगते हैं। पकड़ने का मोह बढ़ता है।' साधु उठे और फिर से दरवाजा खोल दिया।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में तरक्की के मौके मिलेंगे। शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी, परंतु स्थान परिवर्तन भी हो सकता है।

वृष : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान हो सकता है। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। सेहत का ध्यान रखें।

मिथुन : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे।

कर्क : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान हो सकता है। नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा, परंतु कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

सिंह : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है। परिवार से दूर रहना पड़ सकता है।

कन्या : वाणी में मधुरता रहेगी, परंतु संयत भी रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी।

तुला : मन में शांति व प्रसन्नता रहेगी। आत्मविश्वास से भी भरपूर रहेंगे। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। मित्रों का सहयोग भी मिलेगा।

वृश्चिक : आत्मविश्वास भरपूर तो रहेगा, लेकिन मन परेशान हो सकता है। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। वाहन सुख में बढ़ोतरी होगी।

धनु : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। संयत रहें। क्रोध से बचें। बातचीत में संतुलित बने रहें। कारोबार में वृद्धि होगी।

मकर : आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

कुंभ : मन परेशान हो सकता है। पिता व जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। माता का साथ मिलेगा। भागदौड़ अधिक रहेगी। खर्चों में बढ़ोतरी होगी।

मीन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु आत्मसंयत भी रहें। बेकार के क्रोध से बचें। संतान की सेहत का ध्यान रखें। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

9 फरवरी, सोमवार, **शक संवत् :** 20 माघ (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग :** 27 माघ मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम :** 20 शब्बान, 1447, **विक्रमी संवत् :** फाल्गुन कृष्ण अष्टमी तिथि (दिन-रात), विशाखा नक्षत्र, वृद्धि योग रात्रि 12.52 मिनट तक पश्चात ध्रुव योग, बालव करण, चंद्रमा तुला राशि में रात्रि 01.11 बजे तक उपरांत वृश्चिक राशि में।

सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। प्रातः 07.30 मिनट से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। जानकी व्रत।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

हमारे घर में बच्चों की शादी नहीं हो पा रही। हमारे रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों से संबंध भी ठीक नहीं है। क्या करें?
-आशुतोष ढींगरा, नोएडा

- आपने अपने घर में लगभग बीच में बोरिंग करवा रखी है। यह एकदम गलत है, इसको तुरंत बंद करवाएं।
- आपने घर का मंदिर भी छत पर बना रखा है, जो कि ठीक नहीं है। ऊपर एकदम अकेले में मंदिर बनाना उचित नहीं है। आप इसे अपने लिविंग फ्लोर पर लेकर आएं।
- अग्निकोण के शौचालय खराब परिणाम देते हैं। इन्हें बंद करें या फिर इनका प्रयोग न करें। सबसे ऊपर पानी की टंकी को ईशान कोण से हटाकर पश्चिम दिशा में बनाएं।

वर्ग पहेली : 8235

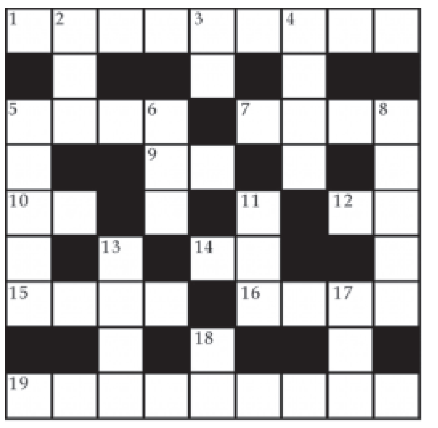

बाएं से दाएं

1. ध्वस्त करना; नष्ट-भ्रष्ट करना; तोड़ना-फोड़ना; पूरी तरह से बरबाद करना (3,3,3)
5. मध्यमा के साथ वाली अंगुली (4)
7. उतावली; तेजी; चंचलता; धृष्टता (4)
9. पर्वत; नगीना; मणि; रत्न; अदद (2)
10. काजल के रंग वाला; कलुषित; बुरा; स्याह; कृष्ण; श्याम (2)
12. कर्ण; श्रवणेंद्री; नाव की पतवार (2)
14. रस्सी; कंठहार; माला; कीमत; मूल्य (2)
15. जो कमल में उत्पन्न हुआ हो; कमल में जन्मा; ब्रह्मा (4)
16. पूरी तरह से; प्रत्यक्ष; बिल्कुल; साक्षात (4)
19. अराजकता फैलाना; उलट-पुलट करना; क्रमभंग करना; सनसनी पैदा करना (3,3,3)

ऊपर से नीचे

2. सरकना; टलना; दूर होना; भागना (3)
3. हरे रंग का; हरित; ताजा; प्रसन्न; प्रफुल्लित (2)
4. कुछ; कई एक; कितने ही (4)
5. जिसके कई अर्थ हों; अनेकार्थी; (5)
6. जंगल; गृह; घर (3)
8. उद्धार करने वाला; तारने वाला; नाविक; भगवान; संकटमोचक (5)
11. वर्षा ऋतु में हवा बंद होने पर लगने वाली गरमी (3)
13. समाचार; दशा; स्थिति की सूचना (4)
17. अखंड; अभंजित; अविभक्त; पूरा; समग्र; संपूर्ण (3)
18. मार्ग; रास्ता; राह (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8234

■	1अं	2ग	अं	ग	3ढी	ला	4हो	ना
5अ	■	र्व	■	■	ल	■	न	■
6वि	वे	क	शी	7ल	■	8प	हा	ड़ी
ना	■	र	■	ट	■	■	र	■
शी	■	9ना	म	क	मा	10ना	■	11अ
■	12प	■	■	जा	■	ट	■	प
13म	थ	ना	■	14ना	गा	क	र	ना
■	रा	■	15गी	■	■	का	■	ना
16अ	व	हे	ल	ना	क	र	ना	■

सुडोकू : 8217

* कठिन

	4		1			3		9
	8		9	2		1		
				1	7	6		
9			6		2			7
		6	5	9				
		3		8	6		5	
4		2			1		7	

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8216

7	8	5	1	3	2	4	9	6
9	3	4	7	8	6	2	5	1
6	2	1	9	4	5	8	3	7
1	7	3	8	2	4	5	6	9
8	6	2	5	7	9	1	4	3
4	5	9	3	6	1	7	2	8
5	9	7	4	1	3	6	8	2
2	4	8	6	9	7	3	1	5
3	1	6	2	5	8	9	7	4

सुरक्षित बैंकों को कम प्रीमियम देना होगा, जोखिम वाले बैंकों पर अधिक बोझ पड़ेगा

बैंकों का जमा बीमा नियम बदलेगा

सुविधा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक अप्रैल 2026 से खाता जमा बीमा के लिए एक बड़ा बदलाव लागू करने जा रहा है। अब तक सभी बैंकों से एक समान दर पर वसूला जाने वाला बीमा प्रीमियम समाप्त होगा और उसकी जगह जोखिम आधारित प्रीमियम मॉडल लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था में मजबूत और सुरक्षित बैंकों को कम प्रीमियम देना होगा, जबकि जोखिम वाले बैंकों पर अधिक बोझ पड़ेगा।

अब तक भारत में जमा बीमा के लिए समान दर प्रणाली लागू थी, जो 1962 से चला आ रहा थी। इसके तहत सभी बैंक अपने जमा पर प्रति 100 रुपये पर 12 पैसे का प्रीमियम जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम को देते थे। बैंक कितना सुरक्षित है या उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, इसका इस दर पर कोई असर नहीं पड़ता था। आरबीआई का मानना है कि यह व्यवस्था में बैंकों को बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित नहीं करती थी।

क्या है नया जोखिम आधारित प्रीमियम मॉडल: नए मॉडल के तहत बैंकों को उनकी वित्तीय सेहत और जोखिम प्रोफाइल के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाएगा। इसके लिए पूंजी पर्याप्तता, एनपीए, लाभप्रदता, तरलता और पर्यवेक्षण रेटिंग जैसे मानकों को आधार बनाया जाएगा। अप्रैल 2026 से बैंकों को ए, बी, सी और डी-चार जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा।

कितनी होगी प्रीमियम दर: सबसे सुरक्षित बैंकों को अब प्रति 100 रुपये जमा पर सिर्फ आठ पैसे का प्रीमियम देना पड़ सकता है, जो मौजूदा दर से करीब 33 फीसदी कम है। श्रेणी बी के बैंक 10 पैसे, श्रेणी सी के बैंक 11 पैसे और श्रेणी डी के बैंक 12 पैसे प्रीमियम का भुगतान करेंगे। इसका सीधा फायदा मजबूत बैलेंस शीट वाले बैंकों को मिलेगा, जबकि कमजोर बैंकों पर दबाव बढ़ेगा।

जोखिम का आकलन कैसे होगा

जोखिम आकलन के लिए दो मॉडल अपनाए जाएंगे। टियर-1 मॉडल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होगा, जिसमें पर्यवेक्षी रेटिंग, कैमल्स मानक और जमा बीमा कोष पर संभावित नुकसान को आधार बनाया जाएगा। टियर-2 मॉडल क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंकों के लिए होगा, जिसमें मात्रात्मक संकेतकों और संभावित नुकसान पर ध्यान दिया जाएगा।

पुराने बैंकों को राहत

आरबीआई ने इस व्यवस्था में एक 'विंटेज इंसेंटिव' भी जोड़ा है। जिन बैंकों का रिकॉर्ड लंबे समय तक स्थिर रहा है और जिन पर कोई बड़ा नियामकीय प्रतिबंध या पुनर्गठन नहीं हुआ है, उन्हें अतिरिक्त छूट मिलेगी।

जो इस ढांचे से बाहर रहेंगे

लोकल एरिया बैंक और पेमेंट्स बैंक जोखिम-आधारित प्रीमियम व्यवस्था से बाहर रहेंगे और पहले की तरह ₹100 जमा पर 12 पैसे की समान दर चुकाते रहेंगे। डेटा सीमाओं के कारण इनके लिए सटीक जोखिम मॉडलिंग संभव नहीं है।

आम आदमी को सीधे नहीं अप्रत्यक्ष फायदे

1. आपकी जमा पहले की तरह सुरक्षित रहेगी, जमा बीमा कवर में कोई बदलाव नहीं।
2. ग्राहकों में मजबूत बैंकों को लेकर भरोसा और बढ़ेगा।
3. बैंक लागत घटने से बढ़ा सकते हैं ब्याज दर, यानी बेहतर एफडी दर और लोन पर कम ब्याज दर।
4. कमजोर बैंकों पर अपना प्रदर्शन सुधारने का बढ़ेगा दबाव।
5. बैंक चुनते समय ग्राहक ज्यादा सतर्कता बरतेंगे।
6. बैंकिंग सिस्टम और ज्यादा सुरक्षित एवं मजबूत होगा।

जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम क्या है

जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है। यह भारत में बैंक जमाकर्ताओं को जमा बीमा सुरक्षा प्रदान करता है, जो वर्तमान में प्रति जमाकर्ता पांच लाख तक है। जमा बीमा योजना आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त सभी बैंकों (वाणिज्यिक और सहकारी) के लिए अनिवार्य है।

म्यूचुअल फंड निवेशकों को बड़ी राहत

प्रस्ताव

नई दिल्ली, एजेंसी। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सेबी ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है, जिससे डीमैट खाते में म्यूचुअल फंड यूनिट रखने वाले निवेशकों की परेशानी कम हो जाएगी।

अब तक जो निवेशक म्यूचुअल फंड डीमैट खाते में रखते हैं, उन्हें हर बार सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान या सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के लिए अलग-अलग निर्देश देने पड़ते थे। यह काम समय लेने वाला और झंझट भरा होता था। सेबी के नए प्रस्ताव से यह दिक्कत खत्म हो सकती है।

अब डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर भी स्थाई निर्देश की सुविधा दी जाएगी यानी निवेशक एक बार निर्देश देंगे और फिर तय तारीख पर अपने आप पैसा निकलेगा या दूसरे फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। यह सुविधा अभी तक सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मोड में निवेश करने वालों को ही मिलती थी।

इस बदलाव से खासतौर पर रिटायर हो चुके लोगों, नियमित आमदनी के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान पर निर्भर निवेशकों और लंबे समय के निवेशकों को फायदा होगा। अब उन्हें हर महीने या तय समय पर पैसे निकालने के लिए बार-बार फॉर्म भरने या अनुरोध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

दो चरणों में लागू होगा

यह दो हिस्सों में लागू होगा। पहले चरण में निवेशक डिपॉजिटरी या स्टॉक एक्सचेंज के जरिए यूनिट और तारीख के हिसाब से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान सेट कर सकेंगे। इस लेन-देन को स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण में इसमें रकम के हिसाब से निकासी, मुनाफे के आधार पर ट्रांसफर और स्विंग एसटीपी जैसे विकल्प शामिल होंगे।

निवेश करना होगा सहज

बाजार नियामक सेबी का कहना है कि इस प्रस्तावित बदलाव से म्यूचुअल फंड में निवेश करना लोगों के लिए और भी आसान होगा। साथ ही निवेशकों का अपने पैसों पर नियंत्रण बढ़ेगा और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसी जटिलताओं पर निर्भरता कम होगी। सेबी ने इस प्रस्ताव पर 26 फरवरी तक सुझाव मांगे हैं। इसके बाद अंतिम फैसला लेकर इसे लागू करने की तारीख घोषित की जाएगी।

समझौते का असर दिखेगा

मुंबई, एजेंसी। पिछले सप्ताह रही तेजी के बाद आने वाले सप्ताह में अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते का असर घरेलू शेयर बाजारों में देखा जाएगा। अमेरिका और भारत के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर दोनों देशों ने शनिवार को एक साझा बयान जारी किया था।

आने वाले सप्ताह में गुरुवार को आधार वर्ष 2024 की सीरीज पर पहली बार खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी होंगे। निवेशकों की नजर इस पर भी होगी। वाहनों की खुदरा बिक्री के आंकड़े भी इसी सप्ताह आने हैं।

बाजार 30s

बढ़ती लागत से आने वाले हफ्तों में दाम बढ़ाएगी टाटा मोटर्स

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ शैलेश चंद्रा के अनुसार, जिंसों की बढ़ती लागत के दबाव के कारण कंपनी आगामी हफ्तों में अपने वाहनों की कीमतें बढ़ाएगी। दूसरी ओर मारुति सुजुकी इंडिया मूल्य वृद्धि के लिए स्थिति की समीक्षा कर रही है, वहीं हुंदै मोटर इंडिया ने जनवरी में मुख्य रूप से अपने वेन्यू मॉडल पर कीमतें पहले ही बढ़ा दी हैं।

नए आयकर कानून पर सुझाव मांगे

नई दिल्ली, एजेंसी। आयकर विभाग ने रविवार को कहा कि उसने एक अप्रैल से प्रभावी होने वाले नए आयकर कानून, 2025 के तहत कर नियमों और प्रपत्रों के मसौदे पर हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। विभाग ने कहा कि 'प्रस्तावित आयकर नियम, 2026' और संबंधित फॉर्म को अंतिम अधिसूचना से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने परामर्श प्रक्रिया के तहत हितधारकों से चार श्रेणियों में सुझाव मांगे हैं। इनमें भाषा का सरलीकरण, मुकदमों में कमी, अनुपालन बोझ को कम करना और अप्रासंगिक या पुराने हो चुके नियमों व प्रपत्रों की पहचान करना शामिल है।

'ई-फाइलिंग' पोर्टल पर लिंक जारी

सुझाव देने की सुविधा के लिए www.incometax.gov.in एक लिंक जारी किया गया है, जो चार फरवरी, 2026 से सक्रिय है। हितधारक अपने नाम और मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी आधारित सत्यापन के बाद अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सुझाव देते समय संबंधित नियम, उप-नियम या प्रपत्र संख्या का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर अब नया आयकर अधिनियम, 2025 आगामी एक अप्रैल से लागू होगा। वर्तमान आयकर नियम, 1962 में 511 नियम और 399 फॉर्म हैं, जबकि प्रस्तावित नए नियमों में इनकी संख्या घटाकर क्रमश: 333 नियम और 190 फॉर्म कर दी गई है।

विभाग ने कहा, हितधारकों को इन मसौदों का अध्ययन कर सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अंतिम अधिसूचना से पूर्व इन सभी सुझावों को संकलित कर उन पर समीक्षा के लिए विचार किया जाएगा।

विदेशी निवेशकों ने पिछले हफ्ते भारतीय बाजारों में निवेश बढ़ाया

नई दिल्ली, एजेंसी। लगातार तीन महीनों की भारी बिकवाली के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) फरवरी के पहले सप्ताह में शुद्ध खरीदार बन गए हैं। बेहतर जोखिम धारणा और अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते के कारण उन्होंने भारतीय इक्विटी में 8,100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।

डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार यह निवेश हाल के महीनों में हुई लगातार निकासी के बाद आया है। एफपीआई ने जनवरी में 35,962 करोड़ रुपये, दिसंबर में 22,611 करोड़ रुपये और नवंबर में 3,765 करोड़ रुपये निकाले थे। एफपीआई ने कुल मिलाकर 2025 में भारतीय इक्विटी से शुद्ध 1.66 लाख करोड़ रुपये निकाले थे। यह निकासी मुद्रा में उतार-चढ़ाव, व्यापार तनाव, अमेरिकी शुल्क की चिंता और इक्विटी के ऊंचे मूल्यांकन के कारण हुई थी।

आंकड़ों के मुताबिक एफपीआई ने इस महीने (छह फरवरी तक) 8,129 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के प्रधान प्रबंधक (शोध) हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि हालिया खरीदारी जोखिम लेने की बढ़ती क्षमता और भारत के वृद्धि परिदृश्य में नए भरोसे को दर्शाती है।

कब कितनी निकासी

जनवरी, 2026	**35,962** करोड़
दिसंबर, 2025	**22,611** करोड़
नवंबर, 2025	**3,765** करोड़

कारोबारी चर्चा

कंज्यूमर कनेक्ट इनिशिएटिव

शारदा विश्वविद्यालय ने ट्रांसफॉर्मेशनल टीचर अवार्ड 2026 के 7वें संस्करण का आयोजन किया

ग्रेनो के नॉलेज पार्क स्थित शारदा विश्वविद्यालय ने सातवें ट्रांस्फॉर्मेशनल टीचर अवार्ड समारोह में देश भर से लगभग 150 शिक्षकों को उनके शैक्षणिक योगदान के लिए सम्मानित किया।
शिक्षकों को भारत भर के छात्रों द्वारा उनके शैक्षणिक या व्यक्तिगत जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए नामित किया गया ।
अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले चुनिंदा प्रिंसिपलों को भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इंडिया हैबिटैट सेंटर के डायरेक्टर डॉ. के. जी. सुरेश का विश्वविद्यालय के चांसलर पीके गुप्ता व एडमिशन डायरेक्टर डॉ राजीव गुप्ता ने मोमेंटो देकर स्वागत किया।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के चांसलर पीके गुप्ता , इंडिया हैबिटैट सेंटर के डायरेक्टर डॉ. के. जी. सुरेश, विश्वविद्यालय के एडमिशन डायरेक्टर डॉ राजीव गुप्ता , वाइस चांसलर डॉ. सिबाराम खारा, डायरेक्टर पीआर डॉ अजीत कुमार, डॉ हरिशंकर श्याम, रीमा, अलोक अहतेश्याम समेत डीन और एचओडी मौजूद रहे।

रोजगार विद अंकित(RWA) में चुनिंदा अभ्यर्थियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन

रोजगार विद अंकित(RWA), देश का अग्रणी ऑनलाइन शिक्षण संस्थान, ने SSC GD अर्ध सैनिक (BSF, CISF, CRPF, ITBP, असम राइफ, SSB,आदि) में चुने हुए अभ्यर्थियों के सम्मान में सम्मान समारोह का सफल आयोजन किया। "रोजगार विद अंकित" एक online education platform है जो YouTube और RWA के official application पर सभी Govt. Jobs के लिए Online Classes द्वारा स्टूडेंट्स को competitive exams और academic (उप्र बोर्ड, बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड) की तैयारी कराई जाती है। संस्थान के YouTube चैनल पर सभी स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त में क्लास उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे लगभग 2.75 करोड़ बच्चा मुफ्त में घर बैठ कर

उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इस सम्मान समारोह में देश के लगभग सभी राज्यों से लगभग 2000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, इस समारोह में सबसे ज्यादा बच्चे UP, बिहार, राजस्थान, MP, Haryana, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आसाम और जम्मू कश्मीर से बच्चे शामिल हुए।

फायर सेफ्टी पर उद्योग की साझा पहल: एल्यूडेकोर ने ACP सेक्टर के लिए उठाया अभूतपूर्व कदम

फसाड और बिल्डिंग मैटेरियल सेक्टर में फायर सेफ्टी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, देश की अग्रणी फसाड प्रोडक्ट निर्माता कंपनी Aludecor ने एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल (ACP) उद्योग के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। कंपनी ने सभी ACP ब्रांड्स के लिए निःशुल्क, स्वैच्छिक और ओपन-टू-ऑल मैटेरियल टेस्टिंग पहल की शुरुआत की है, जो B2B क्षेत्र में अपनी तरह की सबसे बड़ी पहल मानी जा रही है। यह पहल ऐसे समय में शुरू की गई है, जब देशभर में इमारतों में आग की घटनाओं के बाद ACP की गुणवत्ता, फायर रेजिस्टेंस और ट्रेसबिलिटी को लेकर सवाल तेज हुए हैं। ACP का उपयोग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अस्पतालों, होटलों और आवासीय इमारतों में बड़े पैमाने पर होता है, ऐसे में किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता सीधे जन-सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन जाता है। लखनऊ, जो उत्तर भारत के तेजी से उभरते ACP बाजारों में शामिल है, इस पहल का अहम केंद्र है। एल्यूडेकोर का यहां फैब्रिकेटर्स, आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स के साथ लंबे समय से सक्रिय जुड़ाव रहा है।

ललित बेरीवाला ने केंद्रीय बजट 2026-27 को सराहा

श्याम स्टील ग्रुप के प्रबंध निदेशक ललित बेरीवाला, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी, 2026 को लगातार 9वें साल पेश किए गए 2026-27 के केंद्रीय बजट का हृदय से स्वागत करते हैं, जो एक अत्यधिक तर्कसंगत, प्रौद्योगिकी से लैस और समावेशी भारत के लिए एक मजबूत नींव रखता है और जिसका लक्ष्य 2047 तक प्रधानमंत्री मोदीजी के विकसित भारत के सपने को साकार करना है। कुल मिलाकर, बजट अवसंरचना की गति को मजबूत करता है, तकनीकी लक्ष्य को तेज करता है, और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है जो भारत के औद्योगिक और सामाजिक प्रगति के अगले चरण के लिए एक मजबूत नींव रखता है। पिछले बजट की तरह, यह बजट भी विकासोन्मुखी, प्रगतिशील, व्यवसाय-अनुकूल और जमीनी बजट है।

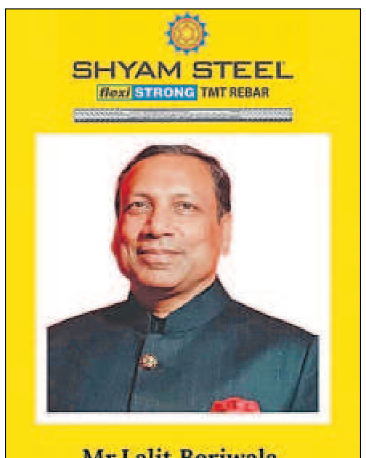

Mr.Lalit Beriwala
Director, Shyam Steel Group

KIIT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ने 2025 बैच के लिए शानदार प्लेसमेंट परफॉर्मेंस जारी रखा

KIIT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी (KIIT-DU) ने 2025 बैच के लिए शानदार ऑन-कैंपस प्लेसमेंट परफॉर्मेंस के साथ एक बार फिर भारत की प्रमुख यूनिवर्सिटीज में अपनी मजबूत स्थिति साबित की है। दुनिया भर में चुनौतीपूर्ण जॉब मार्केट के बावजूद, KIIT ने लगभग 92.5 प्रतिशत का कुल प्लेसमेंट कन्वर्जन दर्ज किया, जो इस बात की पुष्टि करता है कि इसे देश में कैंपस प्लेसमेंट के लिए लगातार सबसे अच्छे संस्थानों में से एक क्यों माना जाता है। 2025 प्लेसमेंट सीजन के दौरान, 757 से ज्यादा कंपनियों ने लगभग 5,000 योग्य छात्रों को भर्ती करने के लिए KIIT कैंपस का दौरा किया, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्कूल और विषयों में लगभग 4,621 जॉब ऑफर मिले। NVIDIA, Microsoft टॉप रिक्रूटर्स में शामिल रहे।

अपना देश

मेरठ में पबजी खेल रहे युवक के दिमाग की नस फटी, मौत

मेरठ, संवाददाता। गाजियाबाद में कोरियन गेम की लत में तीन बहनों द्वारा नौवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने की दिल दहला देने वाली घटना के बाद अब मेरठ में पबजी गेम की लत ने एक युवक की जान ले ली। देर रात तक मोबाइल पर गेम खेल रहे युवक के दिमाग की नस फट गई। परिजन जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो तब युवक का ब्लड प्रेशर 300 के पार पहुंच गया था। दो दिन दिल्ली के अस्पताल में चले उपचार के बाद रविवार सुबह युवक की मौत हो गई।

देहलीगेट थाना क्षेत्र के खैरनगर गूलर वाली गली निवासी प्रॉपर्टी डीलर फारुक का 22 वर्षीय बेटा मोहम्मद कैफ शुक्रवार रात हेडफोन लगाकर मोबाइल पर पबजी गेम खेल रहा था। परिजनों ने बताया कि देर रात करीब तीन बजे गेम खेलते खेलते कैफ बेड से नीचे गिर गया। परिजनों को इसका पता लगा तो वह उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच की तब उसका ब्लड प्रेशर 300 के पार पहुंच गया था।

मोबाइल से दूरी, मैदान है जरूरी : बढ़ते स्क्रीन टाइम ने बच्चों के खेलने और समझने की शक्ति को प्रभावित किया है। चिकित्सकों का मानना है कि स्क्रीन टाइम घटाने का सबसे बेहतर माध्यम स्पोर्ट्स है।

रिश्ता देख रहा था परिवार

कैफ के जीजा शाहिद ने बताया कि कैफ की मौत के बाद बहन और मां का रो रोकर बुरा हाल है। पूरा परिवार सदमे में है। कुछ दिन पहले कैफ की शादी को लेकर बात हुई थी। परिवार उसके लिए रिश्ता देख रहा था। वहीं, इस घटना को लेकर आस पड़ोस में तमाम चर्चाएं बनी हुई हैं।

चार महीने से खेल रहा था गेम

कैफ के पिता ने बताया कि कैफ चार माह से गेम खेल रहा था। उसे सोशल मीडिया पर रील बनाने का भी शौक था। वह देर रात तक हेडफोन लगाकर मोबाइल चलाता था। परिजनों ने बताया कि कैफ को कुछ साल पहले ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत हुई थी।

> परिजनों की तरफ से थाने में कोई सूचना नहीं दी गई है। परिवार के लोग तहरीर देते हैं तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
>
> –**आयुष विक्रम सिंह**, एसपी सिटी

नाबालिगों को मतदान केंद्र के अंदर आने देने पर तीन निलंबित

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव के दौरान नाबालिगों को मतदान केंद्र के अंदर ले जाने से जुड़े दो मामले सामने आए हैं। पहला केस सोलापुर और दूसरा छत्रपति संभाजीनगर जिले से जुड़ा है। दूसरे मामले में रविवार को तीन मतदान कर्मियों को निलंबित कर दिया गया।

शनिवार को हुए जिला पंचायत चुनाव में छत्रपति संभाजीनगर जिले में शिवसेना विधायक विलास भूमरे नाबालिग बेटे को मतदान केंद्र के अंदर ले गए। विधायक ने अपने और बेटे दोनों की उंगली पर स्याही लगवाई। वहीं, सोलापुर के अकलुज स्थित यशवंत नगर मतदान केंद्र पर उम्मीदवार अर्जुन सिंह मोहिते पाटिल अपने 14 साल के बेटे के साथ पोलिंग बूथ के अंदर गए।

मेरा मामला कोर्ट में, किसी और लड़की से संबंध नहीं: तेज प्रताप

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरा तलाक का मामला कोर्ट में है। ऐसे में मैं दूसरी शादी की बात सोच भी नहीं सकता। मेरा किसी और लड़की से कोई संबंध नहीं है।

रविवार की रात पत्रकारों से बातचीत में तेज प्रताप ने कहा कि राजद के जयचंद मेरी छवि खराब करना चाह रहे हैं। पांच लोगों के नाम गिनाते हुए कहा कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे पिता लालू प्रसाद दही-चूड़ा' के दिन आशीर्वाद देने आए, तो नेताओं में डर समा गया। ये लोग मुझे डिप्रेशन में पहुंचा रहे हैं। सवाल किया कि क्या करूं मैं फांसी लगा लूं? तेज प्रताप ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई है।

'रक्षा स्टार्टअप को बढ़ावा देने आगे आएं'

नागपुर, एजेंसी। नीति आयोग के सदस्य और डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक वीके सारस्वत का कहना है कि रक्षा स्टार्टअप बेहतर काम कर रहे हैं। उन्हें वित्तीय मदद करने को उद्यमियों को आगे आना चाहिए।

सारस्वत 'एडवांटेज विदर्भ -2026 बिजनेस कॉन्क्लेव और इन्वेस्टमेंट समिट' में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए तय आवंटन बताता है कि देश का फोकस अब भविष्य के युद्धों में जरूरी हथियारों और उपकरणों के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर होगा। यह ऑपरेशन सिंदूर में हथियारों के चुनाव और उनके उत्पादन की प्राथमिकता के बारे में सीखे गए सबक के अनुरूप हैं।

पप्पू यादव अस्पताल से बेऊर जेल भेजे गए

बिहार

पटना, प्रधान संवाददाता। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को रविवार की दोपहर तीन बजे पीएमसीएच अस्पताल के कैदी वार्ड से केंद्रीय कारागार बेऊर भेज दिया गया। इससे पहले डॉक्टरों की टीम ने उनका चिकित्सकीय परीक्षण करने के बाद भर्ती योग्य नहीं पाया।

बेऊर जेल भेजे जाने से पहले दोपहर में मेडिसिन विभाग, न्यूरोलॉजी विभाग, गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी विभाग के डॉक्टरों की टीम ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। डॉक्टरों ने परीक्षण में पाया कि उनकी सेहत सामान्य है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन बीपी की नियमित दवा ले रहे हैं। इसीलिए कोई खतरे की बात नहीं है। सीने और पीठ में दर्द की शिकायत पर उनका उपचार किया गया और जरूरी दवाएं दे दी गई हैं। बेऊर जेल में भी उनकी सेहत पर डॉक्टर ख्याल रखेंगे। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने बताया कि डॉक्टरों की टीम के परीक्षण के बाद उन्हें डिस्चार्ज करने की सलाह दी थी। पप्पू यादव को पुलिस ने शुक्रवार की रात गिरफ्तार किया था।

कानून तोड़ा तो गिरफ्तारी हुई : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई कानून तोड़ेगा, किसी का मकान हड़पेगा, तो एफआईआर होगी ही। पुलिस पकड़ेगी ही।

सरकार निर्दोष को फंसाती नहीं, दोषी को छोड़ती नहीं : चिराग

खगड़िया। केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में नीट छात्रा की हुई मौत के मामले में कहा कि दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार न निर्दोष को फंसाती है और न ही दोषी को छोड़ती है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के मामले में विपक्ष राजनीति कर रहा है। चिराग पासवान रविवार को खगड़िया पहुंचे थे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के शासन में भारत आज जितना सुरक्षित है, उतना कभी नहीं था।

पूर्व सीएफओ को छोड़ विमान रवाना हुआ

चेन्नई, एजेंसी। एयरएशिया के पूर्व सीएफओ विजय गोपालन ने आरोप लगाया है कि हवाई अड्डे के डिस्प्ले बोर्ड पर विमान में देरी दिखाए जाने के बावजूद इंडिगो की उड़ान उनके बिना ही रवाना हो गई।

गोपालन ने अपनी पूरी शिकायत इंस्टाग्राम पर साझा की और यह भी आरोप लगाया कि एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ ने उनसे झूठ बोला, उन्हें ही दोषी ठहराया और उनका व्यवहार बेहद असभ्य और अहंकारी था। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में गोपालन ने बताया कि उनकी तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से चेन्नई के लिए दोपहर 2:55 बजे की उड़ान निर्धारित थी।

फ्रांस से स्कैल्प मिसाइल खरीद पर फैसला जल्द होगा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और फ्रांस के बीच स्कैल्प क्रूज मिसाइलों की खरीद को लेकर लगभग 300 करोड़ यूरो के बड़े रक्षा सौदे पर बातचीत चल रही है। रक्षा सूत्रों के अनुसार, भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी संख्या में इन मिसाइलों की खरीद पर चर्चा अंतिम चरण में है और जल्द फैसला होने की उम्मीद है।

सूत्रों ने बताया, इन मिसाइलों का उपयोग पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था। स्कैल्प और ब्रह्मोस मिसाइलों के संयुक्त इस्तेमाल से लक्ष्यों को पूरी तरह ध्वस्त किया गया था। भारतीय वायुसेना अपने राफेल बेड़े के साथ इन क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल जारी रखेगी। इसके साथ ही हवा से हवा में मार करने वाली मेटेओर मिसाइलों की खरीद की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। ये मिसाइलें नौसेना के लिए ऑर्डर किए गए 26 राफेल लड़ाकू विमानों में भी लगाई जाएंगी, जिनकी आपूर्ति अगले 3 से 4 वर्षों में होने की उम्मीद है।

300 करोड़ यूरो की डील पर बातचीत जारी

खासियत
- हवा से दागी जाने वाली लंबी दूरी की मिसाइल
- बंकर और मजबूत ठिकानों को भेदने में सक्षम
- कम ऊंचाई पर उड़ान भरने से रडार की पकड़ से दूर

रिटायर्ड इंजीनियर से 3.95 करोड़ की ठगी

ठाणे, एजेंसी। ठाणे में महाराष्ट्र सरकार के 62 साल के एक रिटायर्ड इंजीनियर के साथ 3.95 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

17 जुलाई, 2025 को पीड़ित को एक अंजान नंबर से व्हाटसअप कॉल आई। कॉल करने वाली महिला ने पीड़ित से जान-पहचान बढ़ाई और कई हफ्तों तक बातचीत करती रही।

चिंतन

ट्रेड डील में किसानों और घरेलू उद्योगों के हित सुरक्षित

भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते (ट्रेड डील) ने देश में कृषि और घरेलू उद्योग के लिए राहत दी है। इस ऐतिहासिक समझौते में भारतीय किसानों की प्रमुख फसलें, डेयरी उत्पाद और पोल्ट्री पूरी तरह सुरक्षित रहे। गेहूं, चावल, तिलहन, आलू, मसाले, मक्का, सोयाबीन, आटा और एथनॉल जैसे महत्वपूर्ण उत्पाद समझौते के दायरे से बाहर रखे गए हैं। इसके साथ ही पोल्ट्री और चिकन का आयात भी प्रतिबंधित किया है, जिससे घरेलू पोल्ट्री उद्योग को कोई नुकसान नहीं होगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह समझौता एक प्रकार का 'लेबर ऑफ लव' है यानि एक ऐसा प्रयास, जो रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ दिल से और पूरी मेहनत से किया गया है। इसमें किसी तरह की मजबूरी नहीं थी। इस दृष्टिकोण ने यह सुनिश्चित किया कि भारत ने अपने किसानों और घरेलू उद्योगों के हितों से कोई समझौता नहीं किया। सबसे बड़ी सफलता यह है कि समझौते में भारतीय किसानों की मुख्य फसलें और डेयरी उद्योग पूरी तरह सुरक्षित रहे। अमेरिका की ओर से एथनॉल और पोल्ट्री को शामिल करने का दबाव था, लेकिन भारत ने अपने किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इनका समावेश नहीं किया। यह ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका से आने वाली मक्का और सोयाबीन जेनेटिकली मोडिफाइड हैं, जिन्हें भारत में अनुमति नहीं है। यदि पोल्ट्री और चिकन को भारत में आयात करने की अनुमति मिलती, तो घरेलू उद्योगों और किसानों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता था। साथ ही, चाय, नारियल (खोपरा) और दक्षिण भारत के अन्य किसानों से जुड़े उत्पादों को भी समझौते से बाहर रखा गया। तंबाकू को भी शामिल नहीं किया गया। यह दर्शाता है कि भारत ने अपनी कृषि और घरेलू उद्योग की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस ट्रेड डील का महत्व केवल किसानों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। यह भारत की दीर्घकालिक रणनीति और ऊर्जा सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बावजूद भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक खरीद नीति पर कोई समझौता नहीं करेगा। गोयल ने कहा कि अमेरिका से अब 500 अरब डॉलर से अधिक मूल्य का सामान खरीदना आसान होगा, जिससे भारत वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त कर सकेगा। इस ट्रेड डील की तुलना पहले हुए ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और यूरोपीय यूनियन के व्यापार समझौतों से की जा सकती है। इनमें भी किसी देश को भारतीय कृषि और डेयरी से जुड़े उत्पाद निर्यात करने की अनुमति नहीं दी गई। अमेरिका को केवल पिस्ता, काजू, बादाम और कुछ फलों का निर्यात करने की अनुमति मिली है, जिसका आम किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका कृषि और पोल्ट्री में दुनिया का बड़ा उत्पादक है। यदि इनका आयात भारत में खुल जाता, तो घरेलू उद्योग और किसानों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता था। इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने स्पष्ट रूप से सीमा तय की और किसानों और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। मार्च तक समझौते पर अंतिम हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता संतुलित, रणनीतिक और किसानों के हित में किया गया एक कदम है। यह समझौता न केवल व्यापार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि किसानों और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

भारत से कारोबार के लिए बेताब दुनिया

आर्थिकी
डॉ. जयंतीलाल भंडारी

भारत का तेजी से बढ़ता मजबूत बुनियादी ढांचा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) की रफ्तार, ऊर्जा विकास ,नई पीढ़ी की शक्ति, डिजिटल विकास व मैन्युफैक्चरिंग सहित सर्विस सेक्टर की ताकत की वजह से दुनिया के लिए भारत उद्योग-कारोबार और चमकीले बाजार के दृष्टिकोण से आकर्षक देश बन गया है। हाल ही में भारत के अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ हुए व्यापार समझौते भारत के युवाओं और एमएसएमई के लिए अपार अवसरों के द्वार खोलेंगे। गौरतलब है कि 2 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते ने आकार लिया है।

यकीनन इस समय दुनिया के कई विकसित और विकासशील देश भारत से व्यापार समझौते के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि इस समय दुनिया में आकार ले रही नई विश्व व्यवस्था भारत की ओर झुकी हुई है। पहले अधिकांश अंतरराष्ट्रीय आर्थिक-व्यापारिक टिप्पणियों में कहा जाता था कि भारत ने मौका गंवा दिया, लेकिन अब दुनिया भर के देशों का मानना है कि अगर वे आर्थिक रूप से तेजी से बढ़ते हुए भारत के साथ नहीं जुड़ पाए तो वे महत्वपूर्ण मौका गंवा देंगे।

भारत का तेजी से बढ़ता मजबूत बुनियादी ढांचा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) की रफ्तार, ऊर्जा विकास ,नई पीढ़ी की शक्ति, डिजिटल विकास व मैन्युफैक्चरिंग सहित सर्विस सेक्टर की ताकत की वजह से दुनिया के लिए भारत उद्योग- कारोबार और चमकीले बाजार के दृष्टिकोण से आकर्षक देश बन गया है। हाल ही में भारत के अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ हुए व्यापार समझौते सहित अन्य व्यापार समझौते भारत के युवाओं और एमएसएमई के लिए अपार अवसरों के द्वार खोलेंगे। गौरतलब है कि 2 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते ने आकार लिया है। इस समझौते से जहां कई क्षेत्रों में भारत से अमेरिका को निर्यात बढ़ेंगे, वहीं भारत में निवेश भी बढ़ेंगे। इस समझौते से दुनिया के लिए मेक इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया और इनोवेट इन इंडिया का अभियान तेजी से आगे बढ़ेगा। इस अंतरिम व्यापार समझौते के तहत अमेरिका के द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 25 प्रतिशत जवाबी टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी किया गया है और रूस से तेल खरीदी के मद्देनजर दंडात्मक रूप में भारत पर लगाए गए 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ को हटा दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले माह 27 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित भारत ईयू के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ऊर्सला वान डेर लायन की उपस्थिति में भारत-ईयू के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का ऐलान किया गया। इस एफटीए पर आधिकारिक हस्ताक्षर लगभग छह महीने बाद होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह एफटीए दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का शानदार उदाहरण है और भारत के लिए अत्यधिक लाभप्रद है। ऊर्सला ने इस समझौते को सभी व्यापार समझौतों की जननी (मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स) कहते हुए यह रेखांकित किया कि दुनिया के वर्तमान 'ग्रोथ सेंटर' और इस सदी के आर्थिक पावर हाउस भारत के साथ यह एफटीए यूरोप को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते आर्थिक क्षेत्रों में पहली बढ़त दिलाएगा। साथ ही यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम-चेंजर साबित होने वाला एफटीए होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस एफटीए से दो अरब लोगों का एक साझा बाजार तैयार होगा और यह संयुक्त बाजार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करेगा। निश्चित रूप से इस एफटीए ने अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ के बीच भारत और

ईयू को नई रणनीतिक गोलबंदी के साथ व्यापारिक संबंधों को नई दिशा दी है। गौरतलब है कि भारत-ईयू एफटीए के लिए बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन 2013 में यह वार्ता रुक गई। जून 2022 में वार्ता फिर से शुरू की गई थी, जो अब अंजाम तक पहुंची है। यह बात महत्वपूर्ण है कि यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत और यूरोपीय संघ एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार हैं, क्योंकि दोनों मूल्य श्रृंखला के अलग-अलग स्तरों पर काम करते हैं। भारत प्रमुखतया श्रम-प्रधान और प्रसंस्करण आधारित वस्तुओं का निर्यात करता है, जबकि यूरोपीय संघ प्रमुखतया पूंजीगत वस्तुओं, उन्नत प्रौद्योगिकी और औद्योगिक उत्पादों की आपूर्ति करता है। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और 27 देशों के संगठन ईयू के बीच वस्तुओं और सेवाओं में कुल व्यापार 190 अरब डॉलर से अधिक का रहा है। पिछले वित्त वर्ष में दोनों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 136.53 अरब डॉलर रहा। इसमें भारत का निर्यात 75.85 अरब डॉलर और आयात 60.68 अरब डॉलर था। इसके अलावा, यूरोपीय संघ भारत में एक बड़ा निवेशक भी है, जिसका अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) करीब 117.4 अरब डॉलर रहा है। यदि हम भारत-ईयू एफटीए को देखें तो पाते हैं कि इससे भारत और यूरोपीय संघ के छात्रों, मौसमी कामगारों, शोधकर्ताओं और उच्च कुशल पेशेवरों की आवाजाही को सुगम बनाने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक गतिशील ढांचे को आकार मिला है। यह एफटीए भारत-ईयू व्यापार के लिए महज एक व्यापार का रणनीतिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि आर्थिक पुनर्व्यवस्था के रूप में भारत और ईयू दोनों के लिए व्यापारिक जोखिम को पुनर्संतुलित करने और बदलते वैश्विक व्यापार वातावरण में आगे बढ़ने का अवसर देने वाला चमकीला दस्तावेज है। इस एफटीए के तहत दोनों पक्ष आपसी व्यापार वाली 90 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं पर आयात शुल्क शुरुआत से ही कम या समाप्त कर देंगे, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं पर इसे आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।

यह एफटीए व्यापार, निवेश, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और रक्षा, डिजिटल पहलों, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और कृषि के क्षेत्रों में आपसी प्रतिबद्धता को दिखाता है। यह वस्तुओं, सेवाओं के व्यापार और नियमों पर केंद्रित है,लेकिन निवेश संरक्षण और जीआई जैसे मुद्दे अलग से सुलझाए जाएंगे। निसंदेह विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग भारत-ईयू एफटीए का एक मुख्य स्तंभ है और इससे सहयोगी अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्मार्ट ग्रिड, जल, टीके, आईसीटी, ध्रुवीय विज्ञान और यूरोपीय अनुसंधान परिषद के साथ काम करने वाले युवा वैज्ञानिकों की गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में नया सहयोग मिलेगा। अंतरिक्ष सहयोग भारत-ईयू एफटीए का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जो दशकों के तकनीकी सहयोग और बढ़ते संस्थागत जुड़ाव पर आधारित है। ईयू के अलावा अन्य देशों के साथ भारत के एफटीए भारत की आर्थिक तस्वीर को नया रूप देंगे। अब भारत के द्वारा विभिन्न देशों के साथ एफटीए के अधिकतम लाभ उठाने के लिए घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, एफटीए के लिए जागरूकता बढ़ाने, गैर-टैरिफ बाधाएं दूर करने, सेवा क्षेत्र का लाभ उठाने, निर्यात में विविधता लाने, कृषि और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करने, व्यापार संतुलन को भारत के पक्ष में लाना होगा। उम्मीद करें कि अमेरिका, ईयू और अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार समझौते भारतीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार देंगे और भारत विकसित देश बनने की डगर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा।

(लेखक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **haribhoomi@gmail.com** पर दे सकते हैं।

जानकी जयंती
श्वेता गोयल

आधुनिक युग में माता सीता की प्रासंगिकता और नारी सम्मान

भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की समृद्ध आध्यात्मिक चेतना में माता सीता केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं बल्कि त्याग, समर्पण, धैर्य, करुणा, असीम पवित्रता और नारी मर्यादा की ऐसी जीवंत प्रतिमूर्ति हैं, जो युगों-युगों से नारी शक्ति को परिभाषित करती आई हैं। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियां चाहे कितनी ही कठोर क्यों न हों, यदि मन में धर्म, संयम और आत्मविश्वास अडिग हो तो जीवन की हर अग्निपरीक्षा सार्थक बन जाती है। प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाने वाली जानकी जयंती, जिसे सीता अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, इसी आदर्श जीवन दर्शन का उत्सव है। यह पर्व माता सीता के पृथ्वी पर प्राकट्य का स्मरण कराता है और नारी शक्ति के उस स्वरूप को प्रणाम करता है, जिसने प्रेम, सहनशीलता और मर्यादा को जीवन का आधार बनाया। इस वर्ष जानकी जयंती 9 फरवरी को मनाई जा रही है। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, 9 फरवरी को ही व्रत, पूजन और साधना करना शास्त्र सम्मत और श्रेष्ठ माना गया है। माता सीता के प्राकट्य की कथा भारतीय परंपरा की सबसे दिव्य और अर्थपूर्ण कथाओं में से एक है। रामायण के अनुसार मिथिला में एक समय भयंकर अकाल पड़ा था। ऋषियों के परामर्श पर मिथिला के राजा जनक ने स्वयं हल चलाने का संकल्प लिया, जिससे धरती माता प्रसन्न हों और वर्षा हो। जब राजा जनक खेत जोत रहे थे, तब हल का अग्र भाग, जिसे 'सीत' कहा जाता है, धरती में गड़े एक स्वर्ण कलश से टकराया। उस कलश से एक दिव्य, तेजस्वी और अनुपम सौंदर्य से युक्त कन्या प्रकट हुई। निःसंतान राजा जनक ने उस कन्या को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार किया। हल के अग्र भाग से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम सीता पड़ा, राजा जनक की पुत्री होने के कारण वे जानकी कहलाई और धरती से जन्म लेने के कारण उन्हें भूमिजा कहा गया। इस प्रकार माता सीता का जन्म स्वयं प्रकृति और धर्म के मिलन का प्रतीक बन गया। माता सीता का संपूर्ण जीवन त्याग और धैर्य की जीवंत मिसाल है। राजमहल की सुख-सुविधाओं को त्यागकर उन्होंने वनवास स्वीकार किया; अपहरण, अकेलापन, लोकापवाद और कठिन परीक्षाओं को सहन किया, फिर भी अपने चरित्र, आत्मसम्मान और धर्म से कभी विचलित नहीं हुई। वे केवल भगवान राम की अर्धांगिनी नहीं बल्कि उनके धर्मपथ की सहचरी और नैतिक भी शक्ति थी। जानकी जयंती का पर्व इसी स्त्री शक्ति, आत्मबल और मर्यादा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है।

धार्मिक दृष्टि से जानकी जयंती का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन माता सीता और भगवान राम की संयुक्त पूजा करने से दांपत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सामंजस्य बढ़ता है। विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए यह पर्व विशेष रूप से फलदायी माना गया है क्योंकि माता सीता को आदर्श पत्नी और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और नियमपूर्वक किए गए व्रत से योग्य और मनचाहा वर प्राप्त होता है। माता सीता को लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। उनके पूजन से घर में सुख-समृद्धि, धन-धान्य और स्थायित्व का वास होता है। यह पर्व समाज को संदेश देता है कि स्त्री केवल सहनशील नहीं बल्कि सृजन, संतुलन और शक्ति का मूल आधार है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी जानकी जयंती का विशेष महत्व माना गया है। माघ-फाल्गुन संधिकाल में आने वाली इस अष्टमी तिथि पर चंद्रमा और शुक्र ग्रह का प्रभाव प्रेम, सौंदर्य और वैवाहिक सुख को प्रबल करता है। कुछ मान्यताओं में माता सीता को शनि तत्व से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि उनका जीवन तपस्या, धैर्य और कर्म का प्रतीक है। इस दिन व्रत और साधना करने से शनि दोष की शांति और मानसिक दृढ़ता प्राप्त होने की आस्था है। जानकी जयंती केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि नारी सम्मान, आत्मबल और धर्मनिष्ठ जीवन का उत्सव है, जो हमें स्मरण कराता है कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि आंतरिक धैर्य और सत्य के पालन में निहित है। यदि हम माता सीता के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं तो जीवन की कठिन से कठिन राह भी सहज और अर्थपूर्ण बन सकती है। जिस प्रकार सीता ने राजसी सुखों का त्याग कर वनवास स्वीकार किया और रावण की अशोक वाटिका में रहकर भी अपने सतीत्व और धैर्य को अडिग रखा, वह हर मनुष्य के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है। आज के आधुनिक युग में, जहां रिश्तों में संवेदनशीलता कम हो रही है और मानसिक तनाव बढ़ रहा है, जानकी जयंती जैसे पर्व हमें ठहरकर सोचने और आत्म-निरीक्षण करने का अवसर देते हैं।

(लेखिका शिक्षाविद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

आध्यात्मिक चेतना आखिर क्या है?

संकलित
दर्शन

आज मनुष्य अत्यधिक भौतिकवादी तथा लालची हो गया है। बलिदान, त्याग, संतोष, प्रज्ञा, चिंतन-मनन, मुक्ति और मोक्ष जैसे शब्द हमारे शब्दकोश से धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, जो कि आध्यात्मिक मूल्यों के द्योतक रहे हैं। व्यापक उपभोगवादी संस्कृति तथा भोग-विलास से पोषित भौतिकवाद की नई उभरी संस्कृति ने आध्यात्मिक चेतना पर पर्दा डाल दिया है। धन-अर्जन, सत्ता तथा प्रसिद्धि की लालसा और सुखवादी जीवन-प्रणाली आज जीवन का परम लक्ष्य है। सभी धर्मों ने लालच को महापाप कहा है, परंतु आज लालच ही मुख्य प्रेरणा-द्वार है। ऋषि-मुनि आध्यात्मिक मूल्यों को सर्वोच्च महत्व देते हैं। हिंदू धर्म के आध्यात्मिक मूल्यों का अनुक्रम है-धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। अर्थ तथा काम संसारिक मूल्य हैं, जबकि धर्म तथा मोक्ष आध्यात्मिक मूल्य हैं, परंतु धर्म का स्थान सर्वदा प्रथम है। यह अर्थ तथा काम दोनों का प्रेरक तथा नियंत्रक है। जीवन के हिंदू दृष्टिकोण के अनुसार, सात्विक सर्वाधिक ऊंचा आदर्श है। इसके बाद राजसी का स्थान है, जो एक आदर्श नहीं, परंतु सामाजिक आवश्यकता है। तामसिक सबसे अधिक अपमानजनक वृत्ति है, जिससे सभी बुद्धिमान दूर रहते हैं। मनु की पद्धति में सतत्व को न्याय की संज्ञा दी गई है, राजस को आकांक्षा की तथा तमस को इच्छाओं की। महापुरुषों ने चिंतन-मनन को मनुष्य के परम आनंद के रूप में देखा। आंतरिक शांति तथा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए समर्पित जीवन ही मानव गतिविधियों का सवरेत्तम रूप है।

चंद्र देव को दक्ष ने दे दिया था शाप

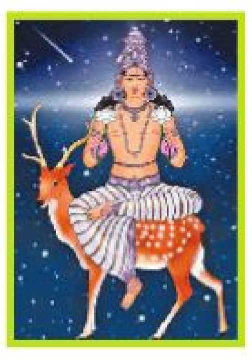

संकलित
प्रेरणा

चंद्र और दक्ष प्रजापति से जुड़ी कथा है। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्र देव से किया था। दक्ष की सभी पुत्रियों में रोहिणी सबसे सुदर थी। इसी वजह से चंद्र रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे और बाकी पत्नियों पर ध्यान नहीं देते थे। इस कारण दक्ष की शेष 26 पुत्रियों को रोहिणी से जलन होने लगी। इन 26 पुत्रियों ने ये बात अपने पिता प्रजापति दक्ष से कह दी। दक्ष ये सुनकर गुस्सा हो गए और उन्होंने चंद्र को धीरे-धीरे क्षीण होने यानी खत्म होने का शाप दे दिया। दक्ष के शाप से चंद्र देव धीरे-धीरे घटने लगा यानी खत्म होने लगे। चंद्र देव ने दक्ष के शाप का असर खत्म करने के लिए ब्रह्माजी से मदद मांगी। तब ब्रह्मा जी ने चंद्र को सलाह दी कि उन्हें प्रभास क्षेत्र (सोमनाथ का क्षेत्र) में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप करो। शिव जी की कृपा से तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ब्रह्मा जी की बात मानकर चंद्र ने प्रभाष क्षेत्र में शिवलिंग स्थापित किया और तपस्या शुरू कर दी। चंद्र के कठोर तप से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और दक्ष के शाप का असर कम करके अमर होने का वरदान दे दिया। दक्ष के शाप का असर कम होने से चंद्र कृष्ण पक्ष में क्षीण यानी खत्म होता है और शुक्ल पक्ष में चंद्र बढ़ने लगता है। पूर्णिमा को पूर्ण रूप हो जाता है। चंद्र देव ने शिव जी से प्रार्थना की थी कि वे प्रभाष क्षेत्र में ही वास करें। चंद्र देव की प्रार्थना मानकर भगवान ज्योति स्वरूप में प्रभाष क्षेत्र में विराजित हो गए। यहां चंद्र देव ने शिवलिंग स्थापित किया था, इसी वजह से इस शिवलिंग का नाम सोमनाथ पड़ा है।

अंतर्मन

आज की पाती

उपकरणों का सावधानी से प्रयोग करना जरूरी

विज्ञान ने हमें हर मौसम से बचने के लिए बहुत सी चीजें दी हैं। लेकिन अगर हम इनका सावधानी से प्रयोग न करें तो यह हमारे लिए कभी भी हानिकारक बन सकती हैं और अक्सर खबरें भी पढ़ने और सुनने को मिलती हैं कि इन चीजों के प्रयोग करते समय कोई हादसा हो गया। सर्दियों में गैस गीजर, कोयले की अंगीठी और अन्य गर्मी प्रदान करने वाले उपकरण लोगों की जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। सर्दियों के मौसम में नहाने के लिए लोग गैस से चलने वाले गीजर का भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसके प्रयोग में जरा सी भी असावधानी किसी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। गैस गीजर को बाथरूम में लगाने के साथ-साथ एक खिडक़ी जरूर रखें। लोगों को चाहिए कि जहां गैस गीजर लगा हो वहां हवा बाहर निकलने के लिए जगह होनी चाहिए अर्थात एडजोस्ट फैन बाथरूम में होना चाहिए।

- महेश काले, दुर्ग

करंट अफेयर

किम पेश कर सकते हैं पांच वर्षों की रणनीति

उत्तर कोरिया इस महीने के अंत में एक बड़ा पार्टी सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है, जिसमें नेता किम जोंग उन अगले पांच वर्षों के लिए देश की घरेलू और विदेश नीति की रूपरेखा पेश कर सकते हैं। सरकारी मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी। सत्तारूढ़ 'वर्कर्स पार्टी' का यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है, जब उत्तर कोरिया ने हाल के वर्षों में अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम तेज किए हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के साथ उसके रिश्ते और गहरे हुए हैं, लेकिन इससे अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ उसका तनाव भी बढ़ गया है। इस तरह का सम्मेलन इससे पहले किम ने वर्ष 2016 और 2021 में आयोजित किया था। उत्तर कोरिया की 'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी' (केसीएनए) ने खबर में बताया कि किम जोंग उन की अध्यक्षता में पार्टी के राजनीतिक ब्यूरो की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि सम्मेलन फरवरी के अंत में आयोजित किया जाएगा। हालांकि, सरकारी मीडिया ने अभी इसकी तारीख या एजेंडा का खुलासा नहीं किया है। यह सम्मेलन कई दिनों तक चल सकता है। हाल के हफ्तों में किम ने हथियारों के परीक्षणों की निगरानी की है और सैन्य ठिकानों तथा आर्थिक परियोजनाओं का दौरा किया है।

ऑफ बीट

जीवाश्मीकृत उल्टी से पुराने शिकारी के आहार का पता चला

यह जीवाश्म हड्डियों के एक सघन समूह के रूप में है। ब्रॉमाकर स्थल पर इससे पहले इस तरह का हड्डियों का जमाव कभी नहीं मिला था, जिससे संकेत मिलता है कि इन अवशेषों को किसी शिकारी ने निगला था और बाद में या तो मल के रूप में या फिर उगलकर बाहर निकाला था। कोप्रोलाइट (जीवाश्मीकृत मल) के मामलों में हड्डियों के अवशेष आम तौर पर कार्बनिक मूल की एक स्पष्ट तलछटी संरचना (मल पदार्थ) के भीतर संरक्षित पाए जाते हैं, जो फॉस्फोरस से समृद्ध होती है और हड्डियों के पाचन से जुड़ी जीवाणु गतिविधि का परिणाम होती है। हालांकि, इस नमूने में हड्डियों के अवशेष ऐसी किसी संरचना से घिरे हुए नहीं हैं। माइक्रो-एक्सआरएफ (एक्स-रे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री) के जरिए किए गए रासायनिक विश्लेषण में इस मैट्रिक्स में फॉस्फोरस की लगभग अनुपस्थिति की पुष्टि हुई। फॉस्फोरस की यह कमी रीगर्जिटालाइट (जीवाश्मीकृत उल्टी) की एक विशिष्ट विशेषता मानी जाती है, जबकि कोप्रोलाइट में पाचन की अधिक अवधि के कारण फॉस्फोरस की मात्रा काफी अधिक होती है। हमने इस जीवाश्म का त्रि-आयामी (सीटी स्कैन) परीक्षण भी किया।

ट्रेंड

बस्तर की सुंदरता

बस्तर की सुंदरता को देखकर लगता है कि मां दंतेश्वरी ने स्वयं इसे अपने हाथों से सजाया है। जब इस रती में किसान बीज छिड़कते हैं, तब यह पंडुम होता है। आम का मौसम आता है, तब यह पंडुम होता है। लोग जीवन को उत्सव के रूप में जीते हैं।
- द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति

चिचाकी रेलवे स्टेशन

चिचाकी रेलवे स्टेशन को अब महत्वपूर्ण ट्रेनों से जोड़ा गया है, जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिली है। मेरा निरंतर प्रयास है कि आने वाले समय में और अधिक ट्रेनों का ठहराव चिचाकी रेलवे स्टेशन पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि क्षेत्र की कनेक्टिविटी और सुदृढ़ हो सके।
-अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय महिला विकास मंत्री

500 ईवी बसें शुरू

दिल्ली, इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे अधिक संख्या वाला पहला राज्य बन गया है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में प्रभावी प्रगति हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा 500 ईवी बसों और दिल्ली-पानीपत अंतरराज्यीय बस सेवा का शुभारंभ।
- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

ट्रंप के सामने घुटने टेके

सच्चाई तो ये है कि पिछले कुछ दिनों से मोदी जी परेशान हैं, क्योंकि एपस्टीन फाइले में मोदी जी से जुड़ी बातें सामने आ गई हैं। जिसके बाद मोदी जी ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए और ट्रेड डील कर दी। देश के अन्नदाता, किसानों को बलि चढ़ा दिया।
- मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, कांग्रेस

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

अमेरिका से व्यापार समझौते पर बोले पीयूष गोयल

भारत 5 साल में यूएस से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने में 'सक्षम'

अमेरिकी बाजार किसानों को अधिक मूल्य देगा और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा

किसानों को नई निर्यात संभावनाएं मिलेंगी, जिससे उन्हें बेहतर दाम और लाभ मिलेगा

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत व्यापार समझौतों में ताकत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने हालिया अमेरिकी व्यापार समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अगले पांच साल में अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीद सकता है, जो अभी वह दुनिया के अन्य देशों से लेता है। उन्होंने इसे बहुत ही सुरक्षित बताया, क्योंकि उनका मानना है कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था अगले पांच साल में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर की मांग पैदा करेगी। भारत अगले पांच साल में ऊर्जा उत्पाद, विमान और पार्ट्स, कीमती धातु, तकनीकी उत्पाद और कोकिंग कोयला अमेरिका से खरीदने का इरादा रखता है। किसानों की आय पर जोर देते हुए गोयल ने कहा कि अमेरिकी बाजार किसानों को अधिक मूल्य देगा।

भारत बनेगा 30-25 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

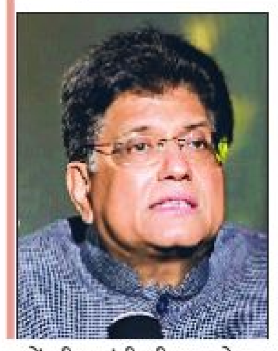
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

उन्होंने कहा कि आज हम 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन 2047 तक यह बढ़कर 30-35 ट्रिलियन डॉलर होगी, जब हम एक विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। यही भारत का आत्मविश्वास है। इस वृद्धि का अवसर हम अपने व्यापारिक साझेदारों को पेश कर रहे हैं। गोयल ने कहा कि भारत पहले ही कृषि और मत्स्य उत्पादों का 55 अरब डॉलर का निर्यात कर रहा है। गोयल ने बताया कि भारत पहले ही विमानों और इंजन के लिए 50 अरब डॉलर के ऑर्डर दे चुका है और अब अगले पांच साल में हवाई नौका क्षेत्र में 100 अरब डॉलर से अधिक की आवश्यकता होगी।

अमेरिका से व्यापार समझौते पर बोले शिवराज सिंह

भारतीय कृषि उत्पादों को कोई नुकसान नहीं, किसान व कृषि पूरी तरह सुरक्षित

अमेरिका ट्रेड डील से वेंटिलेटर पर चला गया विपक्ष

हमारे प्रमुख अनाज सब के सब सुरक्षित रहेंगे

विशेष प्रतिनिधि ▶▶ भोपाल

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ट्रेड डील के बाद विपक्ष वेंटिलेटर पर चला गया है। विपक्ष को आशंका थी कि डील के बाद शोर-शराबा करने का मौका मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के चलते उसकी मंसूबों पर पानी फिर गया। भारतीय कृषि और किसान की सारी चिंताओं का समाधान इस ट्रेड डील में किया गया है। डील से कृषि उत्पादों को कोई नुकसान नहीं है। किसान और कृषि पूरी तरह सुरक्षित है। चौहान रविवार को भोपाल स्थित अपने निवास में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की मूल ताकत कृषि उत्पादों को समझौते से बाहर रख कर भारतीय कृषि और किसान को सर्वोपरि रखा गया है।

बटर, ऑयल, पनीर, चीज को भारत में एंट्री नहीं

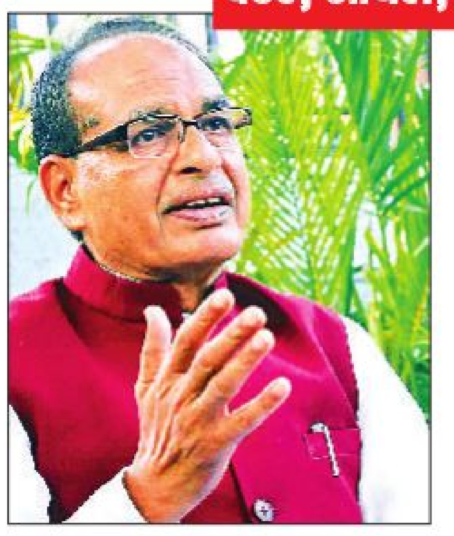

चौहान ने कहा कि बटर, ऑयल, पनीर, चीज को भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। कृषि और डेयरी उत्पादों के अलावा इस लिस्ट में कई मसाले भी सम्मिलित हैं। भारत अमेरिका से काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी और अन्य पाउडर मसाले नहीं मंगवाएगा। भारतीय किसानों के कई कृषि उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात किया जाएगा लेकिन अमेरिकी किसानों के कृषि उत्पादन को भारतीय बाजार में यह छूट नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इस तरह भारत के कृषि और डेयरी के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

खबर संक्षेप

फुले की प्रतिमा तोड़ने वालों पर हो सख्तीः छगन

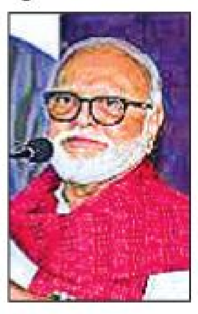

मुंबई। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने तेलंगाना में समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की निंदा की। उन्होंने इसे सामाजिक समानता की मूल भावना पर हमला बताया। भुजबल ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और दखल देने की मांग की। भुजबल ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

जैसलमेर में ट्रेन में धुएं से मची अफरा-तफरी

जैसलमेर। दिल्ली से जैसलमेर जा रही स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस में रविवार सुबह अचानक अफरा-तफरी मच गई। यहां ट्रेन के एक कोच के पहियों से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। घटना सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है। धुआं दिखाई देते ही लोको पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

25 किलो हेरोइन जब्त, दो गिरफ्तार

अमृतसर। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में सीमा पार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जखीरे के साथ 2 को गिरफ्तार किया है। डीजीपी ने बताया कि बीएसएफ ने पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में 25 किलो हेरोइन, 2 पिस्तौल और 60 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

असम में 14 करोड़ की ड्रग्स जब्त, एक अरेस्ट

गुवाहाटी। असम के कछार जिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 14 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। मुख्यमंत्री हिमंत सरमा ने बताया कि इस अभियान के दौरान 154 साबुन केस में छिपा कर रखी गई हेरोइन और 10,000 याबा टैबलेट जब्त की गई है। याबा टैबलेट भारत में अवैध हैं, क्योंकि इनमें मादक पदार्थ होता है, जो अवैध है।

इग्नू में 10 से 13 फरवरी तक चलेगा प्लेसमेंट

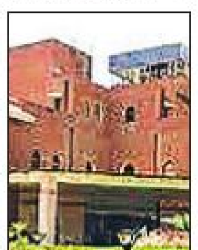

नई दिल्ली। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय अपने वर्तमान स्टूडेंट्स एवं पुराने छात्रों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करने जा रहा है। यह प्लेसमेंट 10 से 13 फरवरी तक देश के विभिन्न राज्यों के सेंटर्स पर आयोजित होगा। जो नौकरी की तलाश में हैं वे तय तिथि में ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके शामिल हो सकते हैं।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता पर बोला वस्त्र उद्योग मंत्रालय

118 अरब डॉलर के अमेरिकी बाजार का दरवाजा खुला, इससे निर्यात, निवेश और रोजगार बढ़ेंगे

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

भारत और अमेरिका के बीच हुए नए व्यापार समझौते ने भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए बड़ा जरवाजा खोल दिया है। इस समझौते के बाद अमेरिका का 118 अरब डॉलर का आयात बाजार भारतीय कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए ज्यादा सुलभ हो जाएगा। सरकार ने इसे निर्यात, निवेश और रोजगार बढ़ाने की दिशा में अहम कदम बताया है। अमेरिका पहले से ही भारत के वस्त्र निर्यात का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। वस्त्र मंत्रालय ने कहा क ि इस समझौते से भारतीय वस्त्र और परिधान उत्पादों पर लगने वाला 18 प्रतिशत जवाबी शुल्क घटेगा। इससे भारतीय निर्यातकों को कीमत के मामले में सीधा फायदा मिलेगा। मंत्रालय का कहना है कि अब भारत की स्थिति बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में मजबूत होगी। बड़े अंतरराष्ट्रीय खरीदार भी अब अपनी खरीद रणनीति में भारत को प्राथमिकता दे सकते हैं।

1. भारतीय निर्यतकों को होगा सीधा फायदा
2. भारतीय कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए होगा सुलभ
3. अन्य देशों की तुलना में भारत मजबूत होगा

भारतीय उत्पाद सस्ते और प्रतिस्पर्धी बनेंगे

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका को भारत का मौजूदा वस्त्र निर्यात करीब 10.5 अरब डॉलर का है। इसमें लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा परिधान का और करीब 15 प्रतिशत मेड-अप्स का है। शुल्क घटने से भारतीय उत्पाद सस्ते और प्रतिस्पर्धी बनेंगे।

2030 के निर्यात लक्ष्य में होगा सहायक

सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के वस्त्र निर्यात का लक्ष्य रखा है। मंत्रालय का कहना है कि नया व्यापार समझौता इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगा। वस्त्र निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी पांचवें हिस्से से ज्यादा रह सकती है।

परिधान के साथ

फुटवियर और रसायन क्षेत्र को मिलेगी राहत

इस अंतरिम व्यापार समझौते का फायदा सिर्फ कपड़ा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। परिधान, फुटवियर, प्लास्टिक, रबर और रसायन जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को भी राहत मिलेगी। आयात शुल्क घटने से इन सेक्टरों के उत्पादों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। उद्योग संगठनों का कहना है कि ऊंचे शुल्क के कारण हाल के महीनों में निर्यात प्रभावित हुआ था, अब स्थिति सुधर सकती है।

उद्योगों के लिए वैश्विक बाजार में पहुंच आसान होगी

एमएसएमई और उपभोक्ताओं को सीधी राहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को स्पष्ट किया कि यह ढांचा भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए वैश्विक बाजार में पहुंच आसान बनाएगा। उन्होंने कहा कि इससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लागत कम होगी। टैरिफ के गणित को समझाते हुए उन्होंने बताया कि अमेरिका मौजूदा 50 प्रतिशत के टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। इसके बदले में, भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आयात शुल्क खत्म या कम करेगा। इन अमेरिकी उत्पादों में ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, पशु चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट शामिल हैं।

उधर, अटकलों का बाजार गरम

रूस से तेल खरीद में बड़ी कटौती करेगा भारत!

अमेरिका के साथ टैरिफ में कटौती के बदले हुए समझौते के तहत भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद धीरे-धीरे कम करने की संभावना है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हालांकि नायरा एनर्जी जैसी तेल शोधनशालाओं (रिफाइनरी) के पास सीमित विकल्प होने के कारण ये आयात फिलहाल पूरी तरह बंद नहीं होंगे। जानकारों ने बताया कि तेल शोधनशालाओं को रूस से खरीद रोकने का कोई औपचारिक निर्देश नहीं मिला है।

समझौते पर बोले शाह

मेक इन इंडिया और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते को देश के तेज रफ्तार विकास इंजन को नया बल देने वाला कदम बताया है। 'एक्स' पर उन्होंने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने की दिशा में अहम है और इससे 'मेक इन इंडिया', किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, स्टार्टअप तथा मछुआरों को लाभ मिलेगा। युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

तेलंगाना स्पीकर को अंतिम चेतावनी

विधायकों की अयोग्यता पर 3 हफ्ते में लें फैसला, नहीं तो कार्यवाही शुरू

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने को तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) को अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देश दिया है कि वो भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने संबंधी शेष अयोग्यता याचिकाओं पर तीन सप्ताह के अंदर निर्णय लें। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से मौखिक रूप से कहा कि इस मामले पर रील्स न बनाएं। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच शुक्रवार को 31 जुलाई 2025 के अपने उस आदेश के अनुपालन की समीक्षा कर रही थी, जिसके तहत विधानसभा अध्यक्ष को कांग्रेस में शामिल होने वाले बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अवधि में निर्णय न लेने के कारण कोर्ट में अवमानना याचिकाएं दायर की गई थीं।

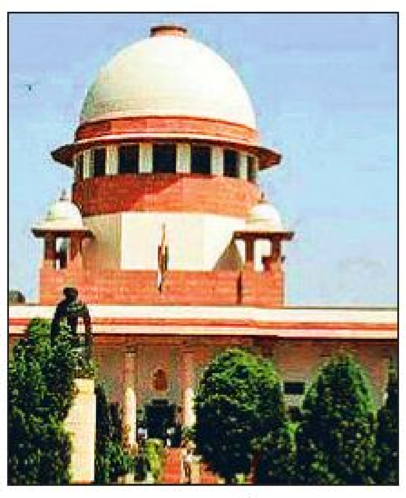

राज्य सरकार ने मांगा 3 सप्ताह का समय

गौरतलब है कि 16 जनवरी को सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी (तेलंगाना राज्य की ओर से) ने दो सप्ताह का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने यह उम्मीद जताते हुए मंजूर किया था कि कुछ प्रगति होगी। आज सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि एक मामले में फैसला हो चुका है, जबकि शेष दो मामलों में निर्णय आसन्न है और इसके लिए तीन सप्ताह का समय मांगा। उन्होंने यह भी कहा कि नगरपालिका चुनावों के कारण समय लगा और दूसरी ओर से भी समय मांगा गया था।

याचिकाकर्ता ने किया विरोध

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील ने फिर से समय दिए जाने का विरोध किया और कहा कि स्पीकर पहले ही तीन बार समय ले चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है और केवल एक ही सुनवाई क्यों हुई, यह सवाल उठाया। उनके अनुसार, कुछ मामलों में तथ्य निर्विवाद हैं- जैसे एक विधायक का कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ना/हारना और दूसरे मामले में विधायक की बेटी का कांग्रेस से जीतना-तो फिर निर्णय में देरी क्यों। 9 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट की एकल बेंच ने स्पीकर को चार सप्ताह में सुनवाई का कार्यक्रम तय करने का निर्देश दिया था। नवंबर 2024 में डिवीजन बेंच ने यह आदेश रद्द करते हुए कहा कि स्पीकर को उचित समय में निर्णय लेना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ताओं की अपील पर, जुलाई 2025 में शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश रद्द कर स्पीकर को तीन महीने में निर्णय करने का निर्देश दिया था।

पंजाब में बड़ा धमाका संभव

भाजपा में 'वापसी' करेंगे सिद्धू! कौर ने राहुल को कहा 'पप्पू'

एजेंसी ▶▶ अमृतसर

पंजाब की राजनीति में 2 महीनों से जारी अनिश्चितता और बयानबाजी के दौर का अंत आखिरकार एक बड़े धमाके के साथ हुआ है।

पूर्व विधायक डॉ. नवजोत कौर सिद्धू को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल ने शुक्रवार को इसकी औपचारिक घोषणा की। इस निष्कासन से पहले ही नवजोत कौर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अब साफ है पार्टी अब सिद्धू परिवार की बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा।

कड़वाहट चरम पर पहुंची

पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद डॉ. नवजोत कौर सिद्धू के तेवर और भी तल्ख हो गए हैं। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने राहुल को 'पप्पू' कहकर संबोधित किया।

पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बवाल

कांग्रेस ने किया प्रदर्शन और सरकार का 'पुतला' फूंका

एजेंसी ▶▶ पटना

सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने पटना स्थित सदाकत आश्रम में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया। कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका और आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सत्ता पक्ष दमनात्मक कार्रवाई कर रहा है। कांग्रेस ने कहा कि यादव की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है।

कांग्रेस को हमेशा साजिश दिख रहीः चिराग

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पप्पू यादव के मामले पर कहा कि- हर चीज को इतना बड़ा चढ़ा कर पेश करना कि हर चीज में साजिश हो रही है। जान से मारने यह नॉर्मल एक प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी को यूं अरेस्ट नहीं करते।

ट्रेनी विमान क्रैश, सभी सुरक्षित

विजयपुरा। कर्नाटक के विजयपुरा जिले के बाबलेश्वर क्षेत्र में रविवार को एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। गनीमत रही कि विमान में सवार दोनों लोग बाल-बाल बच गए हालांकि हादसे में उन्हें चोटें आई हैं और पास के अस्पताल में उनका इलाज जारी है। विमान रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग का था। बाबलेश्वर पुलिस स्टेशन की टीम ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।

गोगोई मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री सरमा का दावा

पाकिस्तान से सीधे संबंधों के मिले सबूत, एमएचए करे जांच

इसमें सियासत और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति हो गई तेज

एजेंसी ▶▶ गुवाहाटी

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तान लिंक को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में सियासत और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है।असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एसआईटी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए दावा किया है कि एसआईटी रिपोर्ट में अली तौकीर शेख एलिजाबेथ गोगोई और गौरव गोगोई तीनों के पाकिस्तान से सीधे संबंध होने के सबूत मिले हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट देखकर कैबिनेट मंत्री भी हैरान रह गए। सरमा ने कहा कि असम पुलिस की एसआईटी ने इस मामले की जांच की और रिपोर्ट सरकार को सौंपी। अब इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जाएगी।

केंद्रीय एजेंसी से जांच को लिखा

गोगोई की पत्नी का पाकिस्तान से संबंध

सरमा ने गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न को लेकर गंभीर आरोप लगाए। सीएम का कहना है कि गौरव की पत्नी के पाक से संबंध रहे हैं। एलिजाबेथ मार्च 2011 से मार्च 2012 तक पाक में काम कर चुकी हैं। उनके परिवार के संबंध अली तौकीर शेख के साथ बहुत घनिष्ठ, जो कथित तौर पर पाकिस्तान के हितों के लिए काम करता रहा है।

पाकिस्तान दूतावास की तस्वीर का जिक्र

सरमा ने एक पुरानी तस्वीर का भी जिक्र किया, जिसमें गौरव कुछ युवाओं को लेकर भारत में पाकिस्तान के दूतावास गए थे। उस समय भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित थे।

गोगोई ने हिमंता पर साधा निशाना

यह सी-ग्रेड फिल्म से भी बदतर

गौरव गोगोई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली और असम के उन पत्रकारों पर मुझे तरस आता है जिन्हें सदी की सबसे फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस झेलनी पड़ी। यह किसी सी-ग्रेड फिल्म से भी बदतर थी। मुख्यमंत्री ने बेहद बेतुके और झूठे तर्क दिए। यह सुपरफ्लॉप हमारी 'यात्रा' के बिल्कुल विपरीत है, जो मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा कब्जा की गई 12,000 बीघा जमीन का पर्दाफाश करने में सफल रही है।

यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा

बस से उतरे कई यात्रियों को कंटेनर ने कुचला, 6 की मौत

एजेंसी ▶▶ मथुरा

उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। यमुना एक्सप्रेस-वे पर माइलस्टोन 88 के निकट कंटेनर द्वारा कुचलने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा शनिवार तड़के करीब 2:45 बजे हुआ। यात्री बस से नोएडा से आगरा की ओर जा रहे थे और बस रुकने पर लघु शंका को उतरे थे। बस नोएडा से आगरा की ओर जा रही थी। बस रुकने पर यात्री उतरकर लघु शंका के लिए जा रहे थे, तभी एक कंटेनर ने यात्रियों को कुचल दिया। एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। लोगों ने कंटेनर के नीचे से सभी को निकाला। हाईवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा। परिजनों को हादसे की जानकारी दी गई है।

नव शक्ति

आयुष्यात आपण जे पेरतो तेच उगवते

कृतीशील विचारांची गरज

संघघटित हिंदू समाज घडवण्याच्या उद्देशाने स्थापना करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शतकमहोत्सवी वर्षानिमित्त देशभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात असताना दुसरीकडे वैचारिक मंथनही होत संघाच्या वाटचालीचा आढावा घेतला जात आहे. कोणतीही विचारधारा इतका प्रदीर्घ काळ टिकून राहणे ही सोपी बाब नाही. मात्र संघाची विचारप्रणाली स्वीकारणारा मोठा वर्ग आहे तसाच विरोध करणारा वर्गही प्रबळ आहे. दोन्ही वर्ग आपापले विचार मांडत प्रतिवाद करतात. संघ हा सर्वसमावेशक नाही, ही कायमच होणारी टीका. संघाच्या १०० वर्षे - नवे क्षितिज या कार्यक्रमात सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी संघ कोणाच्याही विरोधात नाही, देशासाठी काम करणाऱ्या संघाचे कार्य अद्वितीय असून ते जगभरातील लोकांना आकर्षित करत असल्याचे म्हणत संघावरील टीका खोडून काढण्याचे काम केले. संघात कोणत्याही जातीची व्यक्ती सर्वोच्च पदापर्यंत पोहचू शकते असेही त्यांनी स्पष्ट केले असले तरी ती व्यक्ती हिंदूच असेल हे नमूद करायला ते विसरले नाहीत. कोणाच्याही विरोधात नसलेला संघ समाजातील सर्वच स्तरात मिसळून सक्रीय राहिला असेल तर असे स्पष्टीकरण वारंवार देण्याची गरज का भासते हा संघ विरोधकांचा प्रश्न आहे. याचा अर्थ संघ देशातील संपूर्ण समाजाचा विश्वास संपादन करण्यात अयशस्वी ठरल्याचे स्पष्ट होते. भारतीय संस्कृती आणि मूल्यांना प्रोत्साहन देणे आणि एक सशक्त, आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण करणे हा संघाचा मुख्य उद्देश आहे. संघाची विचारधारा 'हिंदुत्व' असून, ती भारतीय संस्कृतीची एकता आणि बंधुता वाढवण्यावर भर देते, असे संघाचे अनुयायी मानतात. मग असे करण्याने समाजातील एक मोठा वर्ग दुरावतो का याचेही आत्मचिंतन संघाने करावयास हवे. हिंदू समाजामध्ये शिस्त, एकता आणि राष्ट्रवादाची भावना निर्माण करणे हे आपले उद्दिष्ट्य असल्याचे संघ निग्रहाने म्हणतो तेव्हा इतर धर्म आपोआपच वेगळे पडतात, हे उघड आहे. म्हणूनच संघाच्या राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेवर अनेकदा टीका होते की ती हिंदू-केंद्रित आहे आणि त्यामुळे देशातील अल्पसंख्यांकांमध्ये अविश्वास निर्माण होतो. अठरापगड जातीधर्माच्या या देशात विशिष्ट धर्माची पताका घेऊन देश एकसंध करता येईल का, हा मोठा प्रश्न आहे. आपल्या धर्माचा दुराभिमान समोरच्या भिन्न धर्मीय व्यक्तीलाही अतिरेकी विचार करण्यासाठी भाग पाडतो हे ध्यानात घ्यावयास हवे. देशभक्ती आणि राष्ट्राभिमान जागृत करून देशाला एक सक्षम राष्ट्र बनवण्याचे कार्य संघ करत असेल तर त्यात प्रत्येक भारतीय सहभागी करून घेणे हे लक्ष्य असले पाहिजे. एकीकडे आपल्याला सगळ्यांसोबत चालायचे आहे. कोणालाच मागे सोडायचे नाही. एकट्याला राहायचे असेल तर कोणत्याही नियमांची गरज नसते, असे सरसंघचालकांनी म्हणावयाचे आणि प्रत्यक्षात विशिष्ट वर्गाची साशंकता दूर करण्यात अयशस्वी व्हायचे ही विसंगती झाली. भारताने महाशक्ती म्हणून नव्हे तर विश्वगुरूची भूमिका वठवावी, अशीही अपेक्षा सरसंघचालकांनी व्यक्त केली असली तरी संकुचित दृष्टिकोन बाळगत भारत जगाच्या पटलावर विश्वगुरू होऊ शकत नाही. तो बाजूला फेकला जाईल, याचीही जाणीव संघाला ठेवावी लागेल. वास्तविक जगातील बदलती परिस्थिती, समीकरणे आणि काळानुसार संघाने विचारांमध्ये काही प्रमाणात लवचिकता आणत सर्वसमावेशकतेचे धोरण स्वीकारले तर संघ ही देशाची एक मोठी शक्ती ठरू शकते, इतकी मोठी ताकद या संघटनेत आहे. या संघटनेची बांधणी ही अभूतपूर्व आहे, हे वास्तव त्याचे विरोधकही मान्य करतील. गेल्या शतकभरात संघ भारताबाहेर संपूर्ण जगात ४० देशांमध्ये पोहोचला आहे. सुमारे पंधरा लाख स्वयंसेवक अहोरात्र काम करत असून संघाने एक शिस्तबद्ध कार्यपद्धती अवलंबली आहे. संघ स्वतःला एक बिगरराजकीय सांस्कृतिक संघटना म्हणवत असला तरी तो राजकीय पक्ष भाजपच्या पालकत्वाची भूमिका बजावतो हे काही लपून राहिलेले नाही. अराजकीय असल्याचा दावा करूनही संघाचे अनेक लोक निवडणुकीच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यापासून विद्यमान पंतप्रधानांपर्यंत अनेक नावे घेता येतील. म्हणजेच आपला अजेंडा राबवत देशाचे धोरण ठरवण्याचा संघाचा प्रयत्न आहे. उपरोक्त कार्यक्रमाच्या निमित्ताने अभिनेता सलमान खान, अदनान सामी यांच्यासह अनेक उद्योगपती आणि धुरिणांनी संघाच्या व्यासपीठावर लावलेली उपस्थिती पाहता संघ आता समाजातील प्रत्येक घटकाशी संवाद साधू इच्छित असल्याचे स्पष्ट होते. काळानुसार संघ पंच परिवर्तनसारख्या प्रयोगांवर काम करत आहे, ज्यात समाजातील प्रत्येक वर्गाला संघाशी जोडण्याचा समावेश असल्याचे म्हटले जाते. हे सकारात्मक असले तरी संघाला केवळ भाषाच बदलून चालणार नाही तर विचारही बदलावे लागतील आणि कृतीचीही जोड द्यावी लागेल.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शतकमहोत्सवी वर्षानिमित्त सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलेले मतप्रदर्शन स्तूत्य असले तरी संघाला केवळ भाषा बदलून चालणार नाही तर विचारही बदलावे लागतील.

मनन चिंतन

ह.भ.प. देवदत्त परुळेकर

सत्याच्या नावाखाली असत्य

अंतरींची बुद्धि खोटी । भरलें पोटीं वाईट ॥

तुकाराम महाराजांच्या या ओळी फक्त वैयक्तिक नीतिकथन नाहीत; त्या समाजाला दिलेला इशारा आहेत. कारण जेव्हा माणूस बाहेरून प्रामाणिकपणाचे, मूल्यांचे, राष्ट्रहिताचे बोल बोलतो, पण आतून मात्र स्वार्थ, लोभ आणि भीतीने चालतो—तेव्हा त्याची बुद्धी खोटी ठरते. अशी खोटी बुद्धी केवळ त्या व्यक्तीला नाही, तर हजारो लोकांना अडचणीत टाकते. याचे अत्यंत बोलके आणि भारतीय उदाहरण म्हणजे रामलिंग राजू—सत्यम कॉम्प्युटर्सचा संस्थापक. रामलिंग राजू हा एकेकाळी "आदर्श भारतीय उद्योजक" म्हणून ओळखला जात होता. मोठ्या IT कंपनीचा मालक, पुरस्कारांनी सन्मानित, परदेशात भारताचे नाव उज्ज्वल करणारा उद्योगपती—अशी त्याची प्रतिमा होती. तो बोलताना नेहमी मूल्ये, नैतिकता, पारदर्शकता यांची भाषा करत असे. कंपनीचे नावच "सत्यम" – म्हणजेच सत्य. पण या नावामागे काय दडले होते? वर्षानुवर्षे कंपनीच्या खात्यांमध्ये खोटे आकडे दाखवले जात होते. नफा नसतानाही नफा दाखवला जात होता.

गुंतवणूकदार, कर्मचारी, सरकार—सगळ्यांची फसवणूक होत होती. शेवटी एक दिवस राजूंनी स्वतः कबुली दिली. त्या पत्रात त्याने लिहिले की तो खोट्यांच्या जाळ्यात इतका अडकला होता की बाहेर पडण्याचा मार्गच उरला नव्हता. इथेच तुकाराम महाराजांची ओळ आठवते—पोटात वाईट भरले की बुद्धी खोटा मार्ग दाखवते. या फसवणुकीचा परिणाम काय झाला? हजारो कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अंधारात गेले. "सत्य" या शब्दावरच्या विश्वासाला तडा गेला. रामलिंग राजू रस्त्यावर उभा राहून लोकांना फसवत नव्हता. तो गोड बोलत होता, सभ्य दिसत होता, यशस्वी वाटत होता. आजच्या काळात आपण नाव, ब्रँड, यश, भाषण यावर पटकन विश्वास ठेवतो. पण हा अभंग आपल्याला थांबवतो आणि विचारायला लावतो— या चमकदार बाह्यरूपामागे अंतःकरण काय आहे? आपण स्वतःला चांगले भासवण्यासाठी जेव्हा सत्य थोडेसे वाकवतो, तेव्हा पोटात वाईट साठू लागते हे आपल्याला कळतही नाही. तुकाराम महाराज म्हणूनच बाहेरच्या आवडंबरापेक्षा आतल्या प्रामाणिकपणाला अधिक महत्त्व देतात. कारण अंतःकरण स्वच्छ नसेल, तर यश, पद, प्रतिष्ठा यापैकी काहीही माणसाला खरे समाधान देऊ शकत नाही.

मत आमचेही

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

हा सरकारच्या भोंगळ कारभाराचा ट्रेलर

मुंबई–पुणे एक्सप्रेस वेवरील कोंडी आणि राज्याच्या आपत्कालीन व्यवस्थेचे उघडे पडलेले वास्तव हे अत्यंत धक्कादायक आहे. ३२ तास प्रवासी एक्सप्रेस वेवर खोळंबले असताना सरकार, प्रशासन कुठे दिसलेच नाही.

मुंबई–पुणे एक्सप्रेस वे हा महाराष्ट्राच्या आधुनिक पायाभूत विकासाचा कणा मानला जातो. देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई आणि राज्याचे आयटी, औद्योगिक व शैक्षणिक केंद्र असलेले पुणे या दोन महानगरांमधील वेगवान, सुरक्षित आणि कार्यक्षम दळणवळण हे या महामार्गाचे घोषित उद्दिष्ट. उद्योग-व्यवसायाला गती, गुंतवणुकीला चालना आणि 'आधुनिक महाराष्ट्रा'चे प्रतीक अशी त्याची प्रतिमा सातत्याने उभी केली गेली. मात्र एका टँकरच्या अपघातामुळे हा महामार्ग तब्बल ३२ तास पूर्णपणे ठप्प पडतो, लाखो प्रवासी रस्त्यावर अडकून पडतात आणि प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस, नियोजित व मानवी मदत उपलब्ध होत नाही, तेव्हा हा प्रसंग केवळ अपघात म्हणून दुर्लक्षित करता येत नाही. ही घटना म्हणजे राज्याच्या पायाभूत व्यवस्थेतील गंभीर उणिवा, आपत्कालीन नियोजनाचा अभाव आणि नागरिकांप्रती असलेल्या प्राथमिक जबाबदाऱ्यांही सरकार व्यवस्थित पार पाडू शकत नाही याचे ठळक उदाहरण आहे.

फक्त अपघात नाही; व्यवस्थात्मक अपयश

अपघात नैसर्गिक किंवा अनपेक्षित असू शकतो. पण आधुनिक आणि जबाबदार राज्याची खरी कसोटी अपघातानंतरची व्यवस्था किती तत्पर, संवेदनशील आणि परिणामकारकपणे राबवली जाते यावर ठरते. मुंबई–पुणे एक्सप्रेस वेवरील या घटनेत ती कसोटी राज्य सरकार आणि प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले. लहान मुले, वृद्ध, आजारी नागरिक, गर्भवती महिला, हे सर्वजण तासन्‌तास वाहनांत अडकून पडले. पिण्याच्या पाण्याची सोय नव्हती, अन्नाची व्यवस्था नव्हती, महिलांसाठी स्वच्छतागृहे उपलब्ध नव्हती आणि वैद्यकीय मदतीचा मागमूसही दिसला नाही. अँब्युलन्स, आपत्कालीन वैद्यकीय पथके किंवा मदत केंद्रे यापैकी काहीच कार्यरत नव्हते. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे परिस्थितीबाबत अचूक आणि अधिकृत माहिती देणारी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. वाहतूक कधी सुरू होईल, पर्यायी मार्ग कोणता, किती वेळ लागेल, या प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांना सोशल मीडियावरील अफवांतून शोधावी लागत होती. हे केवळ प्रशासनिक अपयश नाही; हा लोकांच्या मानसिक सुरक्षिततेवर केलेला आघात आहे.

महागडा महामार्ग, स्वस्त व्यवस्था

मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्ग कोणत्याही दुर्गम, मागास किंवा प्रशासनापासून दूर असलेल्या भागात नाही. हा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक टोल आकारला जाणारा, सर्वाधिक महसूल देणारा आणि 'प्राधान्याने देखभाल' केली जाते असा दावा करण्यात येणारा महामार्ग आहे. तरीही येथे मूलभूत मानवी गरजा पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. यातून एक प्रश्न उभा राहतो, महामार्ग हा नागरिकांसाठी आहे की केवळ महसूल गोळा करण्यासाठी?

आकडे आणि अर्थ : एक थंड वास्तव

देशपातळीवर आणि राज्यपातळीवर रस्ते अपघातांचे प्रमाण व त्यातून होणारे मृत्यू सातत्याने चिंताजनक राहिले आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार दरवर्षी देशात लाखो रस्ते अपघात होतात आणि त्यात हजारो नव्हे, तर लाखोंच्या संख्येने नागरिक प्राण गमावतात. महाराष्ट्रही या वास्तवाला अपवाद नाही. गेल्या दशकभरात राज्यात रस्ते अपघातांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये कोणतीही ठोस, गुणात्मक घट झाल्याचे चित्र दिसत नाही. संसदेत आणि विधानसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरांतूनही हेच वास्तव समोर येते—दरवर्षी हजारो कुटुंबे अपघातांमुळे उद्ध्वस्त होत आहेत. याच काळात राज्य सरकार पायाभूत सुविधांवर प्रचंड खर्च करत आहे. २०२५–२६ च्या अर्थसंकल्पात सुमारे ८४ हजार ४७५ कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च प्रस्तावित आहे. मात्र या खर्चाचा फारच लहान भाग रस्ता सुरक्षा, आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि अपघात प्रतिबंधासाठी राखीव आहे. यातून एक गंभीर विसंगती समोर येते, रस्ते बांधले जात आहेत, पण लोकांचे प्राण वाचवण्याची व्यवस्था दुर्लक्षित आहे.

सुविधा नाहीत, फक्त वसुली

तब्बल ९४ किलोमीटरच्या या महामार्गावर कारसाठी सुमारे ३२० रुपये, हलक्या व्यावसायिक वाहनांसाठी ४९५ रुपये, बससाठी ९४० रुपये, तर मल्टी-एक्सल ट्रकसाठी १६३० ते २१६५ रुपये इतका प्रचंड टोल आकारला जातो. वसुलीसाठी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणाली, कॅमेरे, सेन्सर्स आणि स्वतंत्र यंत्रणा सज्ज आहेत. याच महामार्गावर सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्चून Intelligent Traffic Management System (ITMS) बसवण्यात आली आहे. AI-सक्षम कॅमेरे, ANPR, वेग मोजणारी यंत्रणा आणि २४×७ कंट्रोल रूम—हे सगळे प्रामुख्याने नियमभंग पकडण्यासाठी आणि e-challan काढण्यासाठी वापरले जाते. २०२४ च्या जुलैपासून लाखो चलान काढून कोट्यवधी रुपयांची दंडवसुली झाली आहे. मात्र प्रश्न असा आहे, जर हेच तंत्रज्ञान अपघाताच्या वेळी वाहतूक वळवण्यासाठी, लोकांना माहिती देण्यासाठी आणि मदत पोहोचवण्यासाठी वापरले गेले असते, तर ३२ तासांची कोंडी झाली असती का?

मदतीच्या नावाखाली प्रसिद्धीस्टंट

लोकांचा संताप उफाळून आल्यानंतर शासनाची तथाकथित 'प्रभावी' पीआर यंत्रणा सक्रिय झाली. आयटी सेलमार्फत व्हॉट्सॲप फॉरवर्ड्स तयार झाले, सत्ताधारी नेत्यांनी त्याच मजकुरावर सोशल मीडिया पोस्ट केल्या. प्रत्यक्षात मात्र रस्त्यावर अडकलेल्या नागरिकांचा भीषण अनुभव, त्यांची भीती, असहाय्यता आणि संताप या सगळ्याला जाणीवपूर्वक बाजूला सारण्यात आले. "सरकार तत्पर आहे", "यंत्रणेने उत्तम काम केले" अशा आत्मस्तुतीपर संदेशांचा मारा करण्यात आला. बिस्किटांचे पॅकेट वाटल्याचे फोटो, कंट्रोल रूममधील छायाचित्रे—हे सगळे प्रतिमा व्यवस्थापनाचे प्रकार ठरले. पण ज्या वेळी नागरिक अन्न-पाण्यावाचून, वैद्यकीय मदतीशिवाय अडकलेले असतात, त्या वेळी अशी मांडणी म्हणजे वास्तव झाकून माणसाच्या जीवाशी खेळ करण्यासारखेच आहे.

नेतृत्वाचा अभाव : जबाबदारी कुणाची?

या संपूर्ण प्रकारात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे नेतृत्वाचा पूर्ण अभाव. आपत्कालीन परिस्थितीत प्रत्यक्ष मैदानात उतरून निर्णय घेणारे, यंत्रणेला कामाला लावणारे नेतृत्व अपेक्षित असते. मात्र तब्बल ३२ तास सरकार आणि प्रशासन जणू काही घडलेच नाही अशा थाटात वागत होते. एकही जबाबदार वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचल्याचे दिसले नाही. संबंधित खात्याचे मंत्री, उपमुख्यमंत्री कोणीही प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेताना दिसले नाही. शेवटी नेहमीप्रमाणे 'चौकशी करू' ही ठोकळेबाज घोषणा करण्यात आली. पण अशा प्रसंगी चौकशी नव्हे, तर तातडीची कृती, जबाबदारी स्वीकारणे आणि लोकांचा त्रास कमी करणे हेच खरे नेतृत्व असते आणि ते इथे पूर्णपणे गायब होते.

टेंडरराज, कमिशन आणि अनास्था

गेल्या काही वर्षांत राज्यात टेंडर काढणे, कंत्राट देणे आणि कमिशन उचलणे हीच कारभाराची पद्धत रूढ झाली आहे. जिथे कंत्राटांचा केंद्रबिंदू फक्त नफा आणि टोल वसुली असतो, तिथे देखभाल, सुरक्षा, सोयी-सुविधा आणि आपत्कालीन मदत दुय्यम ठरते. कागदावर भव्य दिसणाऱ्या पायाभूत सुविधा प्रत्यक्षात नागरिकांसाठी असुरक्षित ठरतात. याला आळा घालण्यासाठी कंत्राटांमध्ये स्पष्ट सेवा-स्तर करार (SLA), नियमित स्वतंत्र ऑडिट आणि कठोर दंडात्मक तरतुदी लागू करणे अपरिहार्य आहे.

हा फक्त ट्रॅफिक जॅम नव्हता

मुंबई–पुणे एक्सप्रेस वेवरील ३२ तासांची कोंडी हा केवळ वाहतुकीचा प्रश्न नव्हता. तो राज्याच्या नियोजनाचा, संवेदनशीलतेचा आणि जबाबदारीचा आरसा होता. जर या इशाऱ्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर उद्या केवळ महामार्गच नाही तर लोकांचा शासनावरचा विश्वास, प्रशासनावरील अपेक्षा आणि सार्वजनिक जीवनही हळूहळू ठप्प होईल. ही फक्त ३२ तासांची कोंडी नव्हती; तो सरकारच्या भोंगळ बेजबाबदार कारभाराचा ट्रेलर होता.

माध्यम समन्वयक
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी

मूलभूत सुविधांची वानवा हे तर दुर्दैवच!

गोवंडी येथील झोपडपट्टीतील रहिवाशांना सार्वजनिक स्वच्छतागृहाची सुविधा न पुरवणे आणि मालाड मनोरीतील उघड्यावरील अंत्यसंस्कारांवरुन महापालिकेला कोर्टाने खडे बोल सुनावले हे अत्यंत योग्यच झाले.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील नागरी व्यवस्थापन करणाऱ्या मुंबई महापालिका प्रशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन प्रकरणात दिलेले तडाखे हे मुंबई शहर मूलभूत नागरी सुविधांबाबत कसे व किती मागासलेले आहे, याची साक्ष देणारे आहे. गोवंडी येथील बुद्धनगर झोपडपट्टीत सुमारे एक लाख ८३ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जमिनीवर चार हजाराहून अधिक रहिवाशांकरिता केवळ ६०सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारली आहेत. जी स्वच्छतागृहे आहेत ती देखील नादुरुस्त व अत्यंत बकाल अवस्थेतील असल्याने न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाची खरडपट्टी काढली. दुसरे प्रकरण मालाड मनोरीतील आहे. येथील वादग्रस्त भूखंडावर कोणतेही बांधकाम करण्यास स्थगिती दिली असताना उघड्यावर अंत्यसंस्कार करण्यास परवानगी दिलीच कशी? असा सवाल कोर्टाने केला. मनोरीतील या भूखंडावर उघड्यावर अंत्यसंस्कार होत असल्याची छायाचित्रे आवाज फाउंडेशनने न्यायालयासमोर सादर केली. पालिकेने अंत्यसंस्कारांना परवानगी दिलेली नाही. नागरीक स्वतःहून तेथे अंत्यविधी पार पाडतात, असा दावा पालिकेने केला. गोवंडीतील स्वच्छतागृहाच्या प्रकरणात चेतन सामाजिक प्रतिष्ठानने केलेल्या याचिकेची न्यायालयाने दखल घेतली. भारतीय संविधानाच्या कलम २१नुसार स्वच्छता सुविधा मूलभूत मानवाधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. ही वस्ती बेकायदा असल्याने तेथे नागरी सुविधा दिलेल्या नसल्याचा दावा महापालिकेने केला. मात्र एखादी वस्ती बेकायदा आहे म्हणून त्या वस्तीला नागरी सुविधा न पुरवणे समर्थनीय नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

कालप्रवाह

मुंबई शहरात एकीकडे उंचच उंच म्हणजे अगदी शंभर, सव्वाशे मजल्यांचे टॉवर उभे केले जात आहेत. मात्र सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, स्मशानभूमी यासारख्या मूलभूत सुविधांच्या नावाने बोंब आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या आरक्षित भूखंडावर अतिक्रमणे होत असताना प्रशासन डोळ्यावर कातडे ओढून घेते. महापालिका अधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, झोपडीमाफिया यांच्या संगनमताने बेकायदा झोपड्या सर्रास उभ्या राहतात. मात्र जेव्हा त्यांना नागरी सुविधा पुरवण्याची वेळ येते तेव्हा या वस्त्या बेकाय्रदा असल्याची जाणीव प्रशासनाला होते हे दुर्दैवी आहे. सार्वजनिक स्वच्छतागृहे हा तर अत्यंत दुर्लक्षित विषय आहे. अनेक वस्त्यांमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतागृहे नाहीत. जी आहेत त्यांचे दरवाजे तुटलेले आहेत. नळ-पाण्याची व्यवस्था नाही. दिवाबत्तीची सोय नाही. प्रचंड दुर्गंधीमुळे या स्वच्छतागृहांच्या वाऱ्यालाही कुणी उभे राहत नाही. रात्रीच्यावेळी ही स्वच्छतागृहे गर्दुल्ले व असामाजिक तत्त्वे यांचे अड्डे बनलेले आहेत. महिला, मुली इतकेच काय कुठलीही सर्वसामान्य व्यक्ती तेथे जाण्यास धजावत नाही. या समस्येवर मात करण्याकरिता महापालिकेने सशुल्क स्वच्छतागृहे सुरु केली. मात्र काही मोजके अपवाद वगळता बहुतेक ठिकाणी पैसे वसूल केले जात असले तरी अस्वच्छता व असुविधांबाबत जवळपास तशीच परिस्थिती आहे. सर्वसामान्य नागरीक सिगारेट, तंबाखू यावर पंधरा-वीस रुपये सहज खर्च करतील. मात्र सुस्थितीमधील स्वच्छतागृहांकरिता दोन रुपये मोजण्याची त्यांची तयारी नसते. स्वच्छतागृहाच्या कोपऱ्यात फुकट नैसर्गिक विधी उरकून जणू ते या पैसे वसुलीचा निषेध करुन मोकळे होतात.

स्मशानभूमी ही देखील दुर्लक्षित विषय आहे. मुंबईत अनेक स्मशानभूमीमध्ये गेल्या काही वर्षांत सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत हे नाकारता येत नाही. लाकडापेक्षा लोकांनी गॅस अथवा विद्युतदाहिनीचा वापर अंत्यसंस्कारांकरिता करावा, असा प्रयत्न सुरु असतो. परंतु काही ठिकाणी स्मशानभूमीत बकाली दिसून येते. अंत्यसंस्कारानंतर आजूबाजूला पडलेले हार, पाण्याच्या बाटल्या, प्लास्टिक पिशव्या हे चित्र अनेक ठिकाणी दिसते.

धक्के-बुक्के

संघ कोणाच्याही विरोधात नाही : सरसंघचालक
खरं आहे, भागवतसाहेब, संघ कोणाच्याही विरोधात नाही. संघाच्या मुंबईतील मोठ्या कार्यक्रमासाठी अभिनेता भाईजान सलमान खान यांना आमंत्रित केल्याने संघाच्या एकूणच चांगुलपणावर शिक्कामोर्तब झाले असेच म्हणावे लागेल.

चंद्रपूर पालिका सत्तासंघर्षात भाजपची ऑफर
नव्या घडामोडींमुळे सर्वाधिक जागा मिळवूनही काँग्रेसची डोकेदुखी वाढली आहे. पण गटबाजीचं ग्रहण लागलेली काँग्रेस सुधारणार कधी हा खरा प्रश्न आहे. पण, पहिले सव्वा वर्षांचे महापौरपद हे भाजपलाच हवे असून ठाकरेंच्या सेनेला हा प्रस्ताव कितपत मान्य होईल हा प्रश्नच आहे.

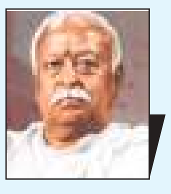

भारत तोडण्याचा विचार करणारे स्वत: तुटतील, अखंड भारत होईलच; भागवत
अशा दुर्दम्य इच्छाशक्तीमुळेच अखंड भारत उदयास येईल असा विश्वास ठेवायला हरकत नाही.

मुंबईत अल्पवयीन मुलाने भरधाव कार चालवल्याने विद्याविहार येथे भीषण अपघात
अल्पवयीन मुलांच्या ताब्यात गाड्या देऊ नयेत असा कायदा करूनही 'हीट अँण्ड रन'च्या घटना वरच्यावर घडताना दिसत आहेत. याचाच अर्थ श्रीमंतांना कायदे–नियम यांच्याशी काही देणेघेणे नाही.

यवतमाळमध्ये उर्दु शाळेत पाकिस्तानी गाणे गायले
तळपायाची आग मस्तकात जाईल अशी ही घटना महाराष्ट्रात घडणे गैर आहे. राष्ट्रप्रेमाचा उमाळा आलेल्या वातावरणात अशा घटना घडणे म्हणजे सरकारचा धाक उरलेला नाही असेच म्हणावे लागेल.

जनमनाचा कानोसा

कोळीवाडे ऐवजी गाबीतवाडे असा उल्लेख करावा

कोकण किनारपट्टीवरील पाचही जिल्ह्यातील मच्छीमार गावांचे सर्वेक्षण करून सीमांकन करण्याचा शासन निर्णय आहे. या दृष्टीने एक महत्त्वाची दुरुस्ती करण्याची नितांत गरज असल्याची लोकभावना सध्या कोकणातील रायगड,रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गाबीत मच्छीमार समाजातील बांधवांमध्ये दिसून येते. या संदर्भात अलीकडेच एक निवेदन अखिल भारतीय गाबीत समाज महासंघ व गाबीत समाज तक्रार निवारण मंच यांच्यावतीने राज्य शासनाला दिल्याचे समजते. तळकोकणात मच्छीमारी करणारांना कोळी असे म्हटले जात नसून, कोळी व गाबीत या दोन भिन्न जाती आहेत. त्यामुळे कोळीवाडा अशी नोंद झाली, तर गाबीत समाजाचे संपूर्ण अस्तित्वच संपुष्टात येईल. कोळी समाजाला अनुसूचित जमातीचे तर गाबीत समाजाला विशेष मागास प्रवर्गाचे लाभ मिळतात. गाबीत समाज हा पूर्वापार दर्यावर्दी असून त्याला आरमारी शौर्याचा वारसा लाभला आहे. मराठा आरमाराच्या अस्तानंतर उदरनिर्वाहासाठी हा समाज सागरी किनारी भागात वास्तव्य करून पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी तसेच गलबतावर काम करू लागला. त्यांच्या वस्त्या गाबीतवाडी या नावाने ओळखल्या जात असूनही, तशा प्रकारच्या नोंदी मात्र महसूल दप्तरी केल्या गेल्या नाहीत. परंतु आता शासन काहीसे सकारात्मक असल्याने आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. गाबीत समाजाची वस्ती असलेली घरे त्यांच्या मालकीच्या जमिनीवर नसून ती खाजगी, देवस्थान ट्रस्ट, वनविभागाच्या जमिनी तसेच सीआरझेड परिक्षेत्रानजीक आहेत. परिणामी आपली घरे नावावर करणे, दुरुस्ती करणे वा व्यवसाय करणे यामध्ये अनेक अडचणी येतात. अर्थात भूमी अभिलेख दप्तरी नोंद नसल्याने घराच्या खालची जमीन व मालकी ही ७/१२ मध्ये मूळ जमीन मालकाच्या नावे दर्शवलेली आढळते. यावर उपाययोजना करण्यासाठी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये गाबीत मच्छीमार महिलांच्या वतीने देवगड,मालवण व वेंगुर्ला येथील तहसीलदारांना आपली घरे ७/१२ मध्ये नोंद करण्यात यावी असे निवेदन दिले होते.

– **पांडुरंग भाबल**, भांडुप.

अंडर–१९ विश्वचषक विजेत्या युवा भारतीय क्रिकेट संघाचे अभिनंदन!

विरारच्या मराठमोळ्या आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वातील १९ वर्षांखालील भारतीय क्रिकेट संघाने आयसीसी अंडर-१९ एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेत अंतिम सामन्यात इंग्लंडला हरवून विश्वचषकावर आपले नाव दिमाखात कोरले. झिम्बाब्वेची राजधानी हरारे येथील हरारे स्पोर्ट्स क्लबच्या मैदानावर पार पडलेल्या अंतिम सामन्यात प्रथम खेळताना मैदानात वैभव सूर्यवंशी नावाचे वादळ आले. चौकार आणि षटकारांची बरसात करून १७५ धावांची तुफानी खेळी करत या वादळाने इंग्लंडच्या गोलंदाजीचा पालापाचोळा केला. सूर्यवंशीच्या या वादळी खेळीच्या बळावर भारतीय संघाने पहिल्या डावात ४११ धावांचा जो डोंगर उभा केला तो अर्थात इंग्लंड संघाला सर करता आला नाही. १०० धावांनी भारताने हा सामना जिंकला. भारतीय संघाने याआधी २००० साली (कर्णधार मोहम्मद कैफ), २००८ (कर्णधार विराट कोहली), २०१२ (कर्णधार उन्मुक्त चंद), २०१८ (कर्णधार पृथ्वी साव) आणि २०२२ साली (कर्णधार यश धूल) यांच्या नेतृत्वाखाली अंडर-१९ विश्वचषक जिंकण्याचा पराक्रम केला आहे. . अंडर-१९ विश्वचषक विजेत्या युवा भारतीय क्रिकेट संघाचे अभिनंदन!

– **प्रदीप अनुसया शंकर मोरे,**
महाकाली गुंफा मार्ग

'**जनमनाचा कानोसा**'साठी पत्र पाठवू इच्छिणाऱ्या वाचकांनी स्वतःचा फोटो आणि मोबाईल नंबरसह आपली पत्रे navshakti.news@gmail.com या ई मेलवर युनिकोडमध्ये मराठीत टाईप करून पाठवावीत. तसेच आपल्या मित्र -मैत्रिणींना व नातेवाइकांनाही सांगावे.

अनेक गुणांचा खजिना: खजूर

कधीतरी जेवण झाल्यानंतरही अवेळी भूक लागल्याची भावना होते, किंवा कधी अगदी गळून गेल्यासारखे वाटते, तर कधी काहीतरी गोड पण शरीरास पोषक असे काहीतरी खावेसे वाटते.. अश्या वेळी खजूर निवडावा. काही तरी गोड खाण्याची अनिवार इच्छा, वजन आणि आकारमानाची काळजी करायला न लावता, खजूर पूर्ण करतो. खजुराचे झाड हे जगामध्ये अस्तित्वात असणाऱ्या झाडांच्या प्रजातींमध्ये सर्वात जुन्या प्रजातींपैकी एक आहे. ही झाडे साधारण दहा हजार वर्षांपूर्वी सौदी अरेबिया मध्ये लावण्यात आली. इस्लाम धर्मामध्ये खजुराच्या सेवनाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. मुहम्मद पैगंबर आपल्या अनुयायांना खजूर आणि पाण्याचे सेवन करून रमजानच्या पवित्र महिन्यातील उपवासांची सांगता करण्यास सांगत असत अशी आख्यायिका आहे. सौदी अरेबिया येथे तीनशे हून ही अधिक निरनिराळ्या प्रकारच्या खजुरांच्या प्रजातींचे उत्पादन होते.

खजूरामध्ये अनेक प्रकारची जीवनसत्वे आणि क्षार आहेत. तसेच यामध्ये कॅल्शियम, लोह, फोस्फोरस, सोडियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, झिंक यांसारखे शरीरास पोषक क्षार आहेत. यामध्ये थियामीन, रिबोफ्लाविन, नियासिन, फोलेट, अ आणि के जीवनसत्वेही मुबलक प्रमाणात आहेत. हृदयास अपायकारक असणारे कोलेस्टेरोल खजूरामध्ये अजिबात नाही. त्यामुळे खजूर हा सर्व दृष्टींनी योग्य असा पदार्थ आहे.

खजुराच्या सेवनाने बद्धकोष्ठाच्या त्रासापासून आराम मिळतो. खजूर हा रेचक असून यामध्ये सोल्युबल फायबरची मात्र जास्त असते. त्यामुळे बद्धकोष्ठाचा त्रास असणाऱ्यांनी खजुराचे सेवन करावे. दोन ते तीन खजूर रात्रभर एक ग्लास पाण्यामध्ये भिजवून ठेवावेत आणि सकाळी उठल्यानंतर त्या पाण्यासकट खजूरांचे सेवन करावे. त्याचप्रमाणे शरीरामध्ये रक्ताची किंवा लोहाची मात्रा कमी असल्यास ही खजुराच्या सेवनाने फायदा होतो. खजूराने रक्तामधील लोहाची मात्रा वाढून अनिमिया दूर करण्यास मदत मिळते.

काही व्यक्तींना हवामानातील बदलामुळे ॲलर्जी सारखा त्रास होतो. सर्दी होणे, दम लागणे, त्वचेवर पुरळ उठणे अश्या निरनिराळ्या प्रकारच्या ॲलर्जी उद्भवू लागतात. हवामान सुधारले की त्याबरोबर या ॲलर्जी देखील नाहीशा होतात. खजूरामध्ये ऑर्गॅनिक सल्फर हे तत्व असते. या तत्वामुळे हवामानातील बदलांमुळे उद्भाविणाऱ्या ॲलर्जी नाहीशा होण्यास मदत मिळते. खजूरामध्ये असलेले पोटॅशियम हृदयाच्या आरोग्याकरिता अतिशय उपयुक्त आहे.

खजूरामध्ये ग्लुकोज, सुक्रोज आणि फ्रुक्टोज सारख्या नैसर्गिक शर्करा आहेत, ज्यांच्यामुळे शरीराला आवश्यक ती उर्जा मिळते. तसेच यामध्ये कॅलरीजची मात्राही अतिशय माफक आहे.

खजूरामध्ये असलेल्या सेलेनियम, तांबे आणि मॅग्नेशियम मुळे शरीरातील हाडे मजबूत राहण्यास मदत होते. गर्भारशी महिलांकरिताही खजूर अतिशय उपयुक्त आहे. याच्या सेवनाने गर्भारशी महिला आणि तिच्या होणाऱ्या बाळाला अनिमिया होण्याचा धोका उद्भवत नाही. तसेच गर्भाशयाच्या स्नायूंना पोषण मिळून प्रसूतीही सोपी होते. खजूरामध्ये असलेल्या लिनोलिक ॲसिड मुळे प्रसूतीनंतरचा रक्तस्त्राव नियंत्रित राहतो.

चेहऱ्यावरील खुली रंध्रे (पोअर्स) कामो करण्यासाठी आजमावा हे उपाय

आपला चेहरा चमकदार, नितळ, सुंदर दिसावा असे प्रत्येकालाच वाटत असते. पण जर चेहऱ्यावरील रंध्रे खुली (ओपन पोअर्स) आणि मोठी असतील, तर चेहरा निस्तेज, बेरूप दिसू लागतो. ज्यांची त्वचा तेलकट असते, अश्या व्यक्तींमध्ये ही समस्या प्रामुख्याने आढळून येते. तसेच मुलांच्या मानाने मुलींमध्ये ही समस्या जास्त आढळून येते. जसजसे वय वाढेल, तसतशी ही पोअर्सही मोठी होत जातात. ही समस्या कमी करण्यासाठी काही उपाय अवलंबता येतील. हे उपाय अगदी साधे सोपे, पण तितकेच प्रभावी देखील आहेत.

केळे खाल्ल्याने आपल्या आरोग्याला होणारे फायदे आपल्या सर्वांच्या परिचयाचे आहेत. पण त्याचबरोबर केळे आपल्या त्वचेसाठी देखील मोठे फायद्याचे आहे. केळ्याने आपल्या त्वचेचतील खराब झालेल्या टिश्यूज ना दुरुस्त करण्यास मदत मिळते. तसेच याच्या वापराने त्वचेला नैसर्गिक आर्द्रता मिळून, त्वचा चमकदार बनण्यास मदत होते. त्यामुळे कुस्करलेले केळे आठवड्यातून दोन वेळा चेहऱ्यावर लावल्यास त्वचेवरील ओपन पोअर्स कमी होऊन, त्वचा पुन्हा सतेज, नितळ दिसू लागते.

खुली रंध्रे कमी करण्यासाठी काकडी आणि लिंबाचा वापर केल्यानेही फायदा होतो. या साठी काकडीच्या रसामध्ये काही थेंब लिंबाचा रस घालून, हे मिश्रण चेहऱ्याला लावावे. हा उपाय सातत्याने केल्यास काही दिवसांतच ओपन पोअर्स नाहीशी होण्यास मदत मिळेल. तसेच दुध आणि ओट्स यांच्या मिश्रणाने देखील ओपन पोअर्स नाहीशी होतील. हा पॅक बनविण्यासाठी दोन चमचे ओट्समध्ये एक चमचा मध आणि एक चमचा गुलाबजल आणि थोडेसे दुध घालावे. हे मिश्रण एकत्र करून याची घट्ट पेस्ट बनवावी. ही पेस्ट आपल्या चेहऱ्यावर दहा मिनिटे लावून ठेवावी. त्यानंतर साध्या पाण्याने चेहरा स्वच्छ धुवावा. या पॅकच्या वापराने खुली रंध्रे नाहीशी होतीलच, शिवाय चेहऱ्यावर अन्य डाग असल्यास ते ही नाहीसे होतील.

तुळशीच्या रोपाजवळ शिवलिंग किंवा गणेश मूर्ती ठेवावी की नाही?

आपण एखाद्या झाडाजवळ छोटे दगडी शिवलिंग पाहतो. अनेक वेळा तुळशीच्या रोपाजवळ देखील हे ठेवलेल्याचे दिसते. एखाद्या मंदिरात तुळशीचे रोप लावले तर काही लोक तेथे छोटे शिवलिंग ठेवतात. तुळशीच्या रोपाजवळ शिवलिंग ठेवणे योग्य आहे की नाही?

शिवलिंग : शिवलिंग चुकूनही तुळशीजवळ ठेवले जात नाही. तुलसी पूर्वी वृंदाच्या रूपात जालंधरची पत्न ी होती, जिला भगवान शिवाने मारले होते. वृंदा दुःखी झाली आणि पुढे तुळशीच्या रोपात तिचे रुपांतर झाले. त्यामुळे त्यांनी भगवान शिवाला त्यांच्या अलौकिक आणि दैवी गुणांपासून वंचित ठेवले. दुसरे म्हणजे भगवान विष्णूने तुळशीला पत्नी म्हणून स्वीकारले आहे, त्यामुळे तुळशीजवळ शिवलिंग ठेवू नये आणि शिवलिंगावर तुळशीची पाने अर्पण करू नयेत.

गणेशमूर्ती: पौराणिक कथेनुसार, जेव्हा देवी तुळशीने गणपतीला पाहिले तेव्हा तिने त्याला तिच्याशी लग्न करण्याची विनंती केली. गणेशजींनी त्यास नकार दिला. संतप्त होऊन तुळशीने गणेशजींना शाप दिला की, त्यांची दोन लग्ने होतील. यामुळेच तुळशीच्या रोपाजवळ गणेशाची मूर्ती ठेवली जात नाही.

शाळीग्राम ठेवणे योग्य : तुळशीच्या रोपाजवळ श्री हरीचे आराध्य दैवत शालिग्राम ठेवता येते. याशिवाय लक्ष्मीची मूतीर्ही ठेवता येते. श्रीहरीशी संबंधित वस्तू ठेवू शकता.

लाईट गेली तर तुमचे वाय-फाय राऊटर बंद पडणार नाही, ते चालेल. हो. जेव्हा लाईट नसते, तेव्हा राउटर बंद होतो, वाय-फाय सिग्नलही गायब होतात. अशा परिस्थितीत लोकांचे ऑनलाईन काम अडकते. पण बाजारात एक असे डिव्हाइस देखील उपलब्ध आहे जे 4 ते 8 तासांचा बॅटरी बॅकअप देते. याची किंमत 2 हजार ते 8 हजार रुपयांपर्यंत आहे. चला तर मग याविषयीची माहिती पुढे जाणून घेऊया.

लाईट गेल्यावरही वाय-फाय राऊटर चालेल, 'हे' डिव्हाईस खरेदी करा, जाणून घ्या

घराची लाईट गेली की वाय-फाय अचानक बंद पडते. पण, आता हे तुम्ही टाळू शकता. आता लाईट गेली तरी तुमचे वाय-फाय राऊटर बंद पडणार नाही. जे लोक घरून काम करतात ते पूर्णपणे इंटरनेटवर अवलंबून असतात. राउटर हे घरातील सर्वात आवश्यक डिव्हाइस बनले आहे. परंतु जर लाईट गेली तर इंटरनेट बंद होते आणि सर्व काम थांबते. अशा परिस्थितीत, आपण एक लहान डिव्हाइस वापरावे, ज्याला मिनी डीसी यूपीएस म्हणतात. हे राउटरला बॅकअप पॉवर देते जेणेकरून लाईट गेली तरीही इंटरनेट चालू राहील. चला तर मग याविषयीची माहिती जाणून घ्या.

मिनी डीसी यूपीएस म्हणजे काय?

मिनी डीसी यूपीएस हे एक लहान बॅटरी बॅकअप डिव्हाइस आहे जे विशेषतः राउटरसाठी बनविलेले आहे. वीज कापली तरीही ते राउटर चालू ठेवते. जेव्हा घरात वीज येते तेव्हा ती स्वतःच चार्ज होत राहते. लाईट जाताच ते लगेच आपल्या बॅटरीतून लाईट देण्यास सुरवात करते. विलंब होत नाही, त्यामुळे राउटर बंद होत नाही. हे केवळ राउटरच नव्हे तर मोडेम, सुरक्षा कॅमेरे आणि इतर लहान डीसी डिव्हाइसेसना देखील उर्जा देऊ शकते. सामान्यतः हे राउटरच्या उर्जा वापरावर अवलंबून 4 ते 8 तासांसाठी बॅकअप देते. हे डिव्हाइस लहान आहे आणि राऊटरजवळ सहज ठेवता येते.

मिनी डीसी यूपीएसचे फीचर्स

या डिव्हाइसमध्ये 5श, 9श किंवा 12श आउटपुट सारखे वेगवेगळे पोर्ट आहेत. आपल्याला आपल्या राउटरच्या गरजेनुसार योग्य पोर्ट निवडावे लागेल. एकाधिक डिव्हाइस एकत्र जोडल्या जाऊ शकतात. यात बॅटरीची पातळी दर्शविणारा एक सूचक आहे, जेणेकरून आपण किती बॅटरी शिल्लक आहे हे जाणून घेऊ शकता.

जेव्हा लाईट येते तेव्हा ते स्वतःच चार्ज होते. हे इतके लहान आणि हलके आहे, म्हणून ते कोठेही नेले जाऊ शकते. काही मॉडेल्समध्ये यूएसबी पोर्ट देखील असतो जेणेकरून फोन चार्ज केला जाऊ शकतो. लाईट कापल्यावर ते आपोआप चालू होते.

मिनी डीसी यूपीएस किंमत

मिनी डीसी यूपीएसची किंमत 2000 ते 8000 रुपयांच्यादरम्यान आहे. त्याची किंमत आकार आणि बंदरावर अवलंबून असते हे स्पष्ट करा. या उपकरणामुळे घरून काम करणाऱ्यांपासून ते मीटिंग करणाऱ्यांपर्यंत काम अडकत नाही. ज्या भागात लाईटचा सर्वाधिक तुटवडा आहे, तिथे हे उपकरण खूप उपयुक्त ठरू शकते.

'हे' डिव्हाइस वापरणे सुरक्षित आहे का?

या डिव्हाइसमध्ये अनेक सेफ्टी फीचर्स देण्यात आले आहेत. यामुळे शॉर्ट सर्किट, जास्त पॉवर किंवा व्होल्टेज बदल टाळता येतात. ओव्हरचार्ज किंवा ओव्हरचार्ज केले तरीही डिव्हाइस सुरक्षित राहते. राउटर किंवा इतर कनेक्ट केलेल्या डिव्हाइसचे कोणतेही नुकसान होत नाही. हे सतत चालण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे, म्हणून दिवसाचे 24 तास प्लग इन करू शकते. बॅटरी चांगल्या प्रतीची आहे जी बराच काळ टिकते.

दडप पोहे

साहित्य : पोहे, खोवलेलं खोबरं, हिरव्या मिरच्या, शेंगदाणा, डाळिंबाचे दाणे, कांदा, कोथिंबीर, लिंबू, मीठ.

कृती : कांदा, हिरव्या मिरच्या आणि कोथिंबीर छान बारीक चिरून घ्यावं. दडप्या पोह्यांसाठी शक्यतो जाड पोहे वापरावे. हे पोहे जराशा पाण्यात भिजवावे. किंवा फार मऊ नको असतील तर त्यावर सरळ पाण्याचा एक हबका मारावा. मग त्यात खोबरं, कांदा, कोथिंबीर, शेंगदाणा, डाळिंबाचे दाणे, मिरची आणि मीठ घालून कालवून घ्यावेत. वरून लिंबू पिळावं. लगेचच खायला द्यावेत. जास्त काळ ठेवून दिल्यास पोहे वातड होण्याचा धोका असतो. तुम्हाला आवडत असेल तर यात भाजलेला पापडही कुस्करून घालता येऊ शकतो.

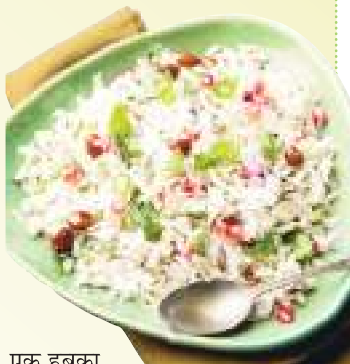

थंडीत कशी घ्याल त्वचेची काळजी ?

हिवाळा हा खरे तर सुखद ऋतू. पण या दिवसांत तापमान एकदम कमी होऊ लागल्यावर त्वचा आणि ओठ फुटणे, टाचांना भेगा पडणे, केस कोरडे पडणे या गोष्टी होतातच. जशी आपण थंडीपासून बचाव करण्यासाठी उबदार कपडे घालण्याची काळजी घेतो, तशीच त्वचेचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे.

- थंडीत त्वचेतला वात वाढतो आणि त्यातील ओलावा, स्निग्धपणा कमी होतो. कोरड्या पडलेल्या त्वचेमुळे दिवसा आणि रात्रीही त्वचेला कंड सुटतो, त्वचेला स्पर्श केल्यावर ती रखरखीत आणि ओबडधोबड लागते. त्वचा आणखीनच कोरडी पडली तर त्याची सालपटे निघू शकतात, खासकरून टाचांना भेगा पडतात, काहींची त्वचा खूप कोरडी आणि कडक होऊन ती खवल्यांसारखी दिसू लागते.
- काही जणांमध्ये या दिवसांत त्वचेला येणारी खाज तर इतकी प्रचंड असते, की त्या ठिकाणी खाजवून ओरखडे पडतात आणि रक्तही येते. अशा पद्धतीने खाजवून झालेली जखम दीर्घकाळ रेंगाळणाऱ्या इसबमध्ये परिवर्तित होणे आणि जास्तच त्रासदायक ठरू शकते.
- चेहरा थंडीमुळे उलतो. ओठावर आणि ओठाभोवतीही भेगा पडतात. कधी कधी ओठ फुटल्यामुळे खाताना किंवा बोलताना तोंड उघडल्यावर ओठांना चिरा पडून रक्त येते. अशा वेळी आपण नकळत सारखे ओठाला दात लावतो, ओठ ओले करण्यासाठी त्यावरून जीभ फिरवतो. हा उपाय ओठांच्या विरोधातच जातो! तोंडातील लाळेचा 'पीएच' हा 'अल्कलाइन' असतो. शिवाय त्यात काही पाचकरसही असतात. ओठ सतत लाळेच्या संपर्कात आल्याने ते आणखी विसविशीत होतात, आणखी फुटतात.
- बोचऱ्या थंडीमुळे चेहऱ्यावर कोरडेपणाचे डाग पडतात. त्वचेवर सतत मुलतानी मिट्टी लावून ठेवल्यासारखे खेचल्यासारखे वाटते. त्वचेतून स्निग्धता आणि पाणी उडून गेल्यामुळे त्वचेवरून प्रकाश परावर्तित होऊ शकत नाही आणि त्वचा निस्तेज दिसायला लागते. हे सगळे असे होऊ नये म्हणून त्वचेची सातत्याने काळजी घेणे, निगा राखणे गरजेचे आहे.

काही टिप्स

- **आंघोळीसाठी गार पाणी तर नकोच, पण खूप गरम पाणीही वापरू नये. त्याने त्वचा कोरडी पडते. कोमट वा मध्यम तापमानाचे पाणी वापरणे चांगले.**
- **आंघोळीच्या वेळी किंवा तोंड धुतानाही साबण, फेस वॉश किंवा अगदी बेसन पिठाचाही कमीतकमी वापर करणे बरे. उन्हाळ्यात अनेकांना स्क्रबर आणि शॉवर जेल वापरून आंघोळ करायला आवडते. थंडीत स्क्रबरने त्वचा घासणे नक्कीच टाळावे.**
- **आंघोळीनंतर टॉवलेने त्वचा खसाखसा पुसू नये. ओलसर त्वचेवरच चांगल्या प्रतीचे मॉइश्चरायझर, चक्क शेंगदाणा तेल लावावे. बाजारात नेहमी मिळणारी मॉइश्चरायझर आपल्या त्वचेस चालतील की नाही अशी शंका असल्यास त्वचारोगतज्ज्ञाचा सल्ला घेऊन त्यांनी सांगितलेली मॉइश्चरायझर किंवा ऑइंटमेंट लावावीत.**
- **वातानुकूलित यंत्रणेचा वापर कमीतकमी करावा. तासंन्तास एसीत बसणे टाळावे.**
- **आहारात 'ओमेगा ३ फॅटी ॲसिड्स' असलेल्या नैसर्गिक पदार्थाचा जरूर वापर करावा. या पदार्थामध्ये मेथीचे दाणे, अक्रोड, जवस, उडीद, राजमा, मासे अशा पदार्थाचा समावेश होतो. तसेच पुरेशा प्रमाणात पाणी पिणेही गरजेचे.**

रोज थोडा व्यायाम केल्यानेही मेंदूच्या कामात मोठी सुधारणा

असे म्हणतात की, निरोगी शरीरात निरोगी मन आणि निरोगी मेंदू राहतो. म्हणूनच फक्त पौष्टिक जेवण आणि व्यवस्थित दिनचर्याचं फक्त गरजेची नाही. तर, नियमित व्यायाम करणे गरजेचे आहे. एका अभ्यासानुसार रोज थोडा थोडा व्यायाम केल्याने आपला मेंदू चांगला राहतो. म्हणजेच तुमच्या मेंदूच्या कार्यप्रणालीत मोठी सुधारणा होते.

संशोधकांच्या एका टीमने हा अभ्यास उंदरांवर केला आणि बघितले की, रोज थोडासा व्यायाम केल्याने म्हणजेच मध्ये-मध्ये व्यायाम केल्याने जिन्स ॲक्टिव्ह होतात. जे मेंदूच्या हिप्पोकॅम्पस नावाच्या भागात असलेल्या न्युरॉन्समध्ये असलेल्या कनेक्शनला अजून मजबूत करतात. मेंदूचा हा भाग स्मरणशक्ती आणि शिकण्याच्या संबंधित महत्वाचा आहे.

आता तुम्हाला असं वाटेल, उंदरांकडून व्यायाम कसा करून घेतला. तर अभ्यासात असलेल्या उंदराना २ तासांसाठी एका रनिंग व्हीलवर ठेवले आणि त्या दरम्यान त्यांच्या मेंदूच्या कार्यप्रणालीला मोजण्यात आले. ेछ्री मध्ये प्रकाशित अभ्यासात रोज थोडा थोडा व्यायाम केल्याणे मेंदूत हिप्पोकॅम्पस भागात सिनेप्सेसची वाढ होते. याआधी प्राण्यांवर आणि माणसांवर झालेल्या अभ्यासात समोर आले आहे की, नेहमी व्यायाम केल्याने मेंदूत सकारात्मक बदल होतात.

गरोदर स्त्रियांमध्ये 'मूड स्विंग्स' का होतात? कशी कराल मात

गरोदरपणाचा काळ हा स्त्रियांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत नाजूक असतो. या दिवसात स्वतः स्त्री आणि तिच्या आजूबाजूच्या व्यक्तीदेखील तिची फार काळजी घेतात. मात्र स्त्रियांच्या शरीरात कळत नकळत अशा काही गोष्टी घडत असतात की त्याचा परिणामही होऊ श्कतो याकडे अनेक स्त्रिया, तिच्या आजुबाजूच्या व्यक्ती, परिवारातील मंडळींसाठी नवा असतो. गरोदरपणाच्या काळात शरीराच्या अवयवांमध्ये होणारे बदल, मॉर्निंग सिकनेस, उलट्या या लक्षणांसोबतच मूड स्विंग्सही होतात. महिलांमध्ये हे मूड स्विंग्स होण्यामागे अनेक कारणं आहेत.

का होतात गरोदर स्त्रीयांमध्ये मूड स्विंग्स?

- मूड स्विंग्स होण्यामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे शरीरात झपाट्याने होणारे बदल.
- गरोदरपणाच्या काळातील फिजिकल डिसकम्फर्ट
- गरोदरपणाच्या काळात विविध टप्प्यांवर वाढणारी भीती
- काही स्त्रियांमध्ये मूड स्विंग्स हे अत्यंत वेगाने होतात. बघता बघता हसणारी स्त्री रडायला लागते असे अनेकींचे अनुभव आहेत.

कशी कराल मूड स्विंग्सवर मात?

1. झोप

गरोदरपणाच्या काळात झोपेशी कधीच तडजोड करु नका. या काळात शरीरात होणारे बदल, सतत वॉशरूमला जाणं, वाढतं वजन, थकवा यामुळे झोप अत्यंत गरजेची आहे.

झोपताना फार काळ त्रासदायक स्थितीत पडू नका. दिवसभरात सुमारे 8-10 तास आराम करणं आवश्यक आहे.

दुपारच्या वेळेस पॉवर नॅप घ्या. यामुळे थकवा कमी होण्यास मदत होते. विकेंडला पुरेसा आराम करा.

2. साथीदाराशी बोला

तुमच्या इतकाच तुमचा साथीदारदेखील भविष्यात काय होईल याची काळजी करत असतो. त्यामुळे तुमच्यावरीण ताण एकटेच विचार करून वाढवण्यापेक्षा बोलून तो कमी करण्याचा प्रयत्न करा.

3.गरोदर स्त्रीयांशी, मैत्रिणींशी बोला

तुमच्या आजुबाजूला, नात्यामध्ये, मित्रपरिवारामध्ये गरोदर स्त्रिया असल्यास त्यांच्याशी बोला. तुमची भीती कमी होण्यास मदत होईल. त्यांच्यांसोबत काही वेळ घालवा, फिरायला जा. यामुळे ताण कमी होण्यास मदत होईल.

कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी मेथीचे दाणे आहेत गुणकारी

निरोगी आणि सुदृढ आरोग्य हवं असेल तर आहारामध्ये पौष्टीक आणि सकस पदार्थांचा समावेश आवर्जुन केला पाहिजे. यासाठी पालेभाज्या, कडधान्य, विविध प्रकारच्या डाळींचं सेवन करायला पाहिजे. मात्र अनेक वेळा आपण या पौष्टीक पदार्थांना डावलून फास्टफूडला प्राधान्य देतो. त्यामुळे आपल्या सकस आहार घेता येत नाही. तरीदेखील आपली आई, आजी वेगवेगळ्या शक्कल लढवून पालेभाज्या किंवा कडधान्य आपल्याला खायला घालतात. या पालेभाज्यांमध्ये पालक, मेथी, शेपू या भाज्या पाहिल्या की अनेक जण तोंड फिरवून घेतात. मात्र याच भाज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रथिने, खनिजे, लोह यांचा समावेश असतो. त्यातल्या त्यात मेथी ही एक अशी भाजी आहे जी चवीला कडू असली तरी आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची आहे. मेथीच्या पानांचा उपयोग आहारात भाजी म्हणून, तर बियांचा उपयोग मसाला पदार्थांत होतो. दाण्यासारख्या दिसणाऱ्या या 'मेथ्यां'मध्ये अतिशय आरोग्यकारी गुणधर्म आहेत.

मेथ्या खाण्याची पद्धत

मेथ्यांचे दाणे कधीही कच्चे खाऊ नयेत. हे दाणे कायम भिजवून किंवा भाजून खावेत. मेथ्या या चवीला अत्यंत कडू असून अनेक जण त्या भिजवून त्याचं पाणी पितात. तर काही जण त्याची भाजीही करतात.

फायदे

१. मधुमेह- मेथीमध्ये भरपूर फायबर आणि ट्रायगोनेलिन नावाचे एक द्रव्य असते. यांचा दुहेरी फायदा होतो. यामुळे शरीरात इन्शुलिनची संवेदनशीलता वाढते शिवाय वजनही कमी होते. म्हणूनच मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी नियमित मेथीचे दाणे खाणे उत्तम. ज्यांची रक्तशर्करा जास्त आहे अशांना ती नियंत्रित राहण्यास मेथ्यांचा उपयोग होतो.

२. ॲसिडिटी- ज्या लोकांना ॲसिडिटीचा त्रास आहे, त्यांना शरीरातील आम्लता कमी होण्यासाठी मेथ्यांचा उपयोग होतो.

३. बद्धकोष्ठता- सकाळी रिकाम्या पोटी मेथीचे दाणे खाल्याने पोट साफ राहते.

४. वजन कमी होते- मेथ्या खाल्ल्याने मेटाबॉलिक रेटही वाढतो, चरबी कमी होऊन वजन कमी होण्यास मदत होते.

५. त्वचा- मेथ्यांमुळे त्वचेवर येणारी मुरुमे कमी होऊन त्वचेचा तजेला वाढतो.

६. कोलेस्ट्रॉल- रात्री भिजवलेले मेथ्यांचे दाणे सकाळी खाल्ल्याने, रक्तातील चरबीचे प्रमाण कमी होऊ लागते. मेथ्यामध्ये असलेल्या विशेष अमायनो ॲसिड्समुळे हे साध्य होते. परिणामतः उच्च कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी होऊन ती नियंत्रित राहण्यास मदत होते. यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.

७. रक्तदाब- मेथ्यांमुळे उच्च रक्तदाब असणाऱ्यांना फायदा होतो. रक्तदाबाचे वाढलेले प्रमाण कमी होऊन कालांतराने गोळ्यांचे डोस कमी करता येतात.

८. केस गळणे- मेथ्यांचे दाणे रात्रभर पाण्यात भिजवून, सकाळी ते कुटून, त्याची पेस्ट बनवावी. आंघोळीपूर्वी तासभर ती पेस्ट केसांच्या मुळाशी लावून कोमट पाण्याने आंघोळ करावी आणि भरपूर पाण्याने केस स्वच्छ धुवावेत. यामुळे केस गळण्याचे कमी होते आणि केसातील कोंडा दूर होतो.

जर नेहमी नीट ब्रश करूनही तुमच्या तोंडाचा वास येत असेल, तर लगेच

जर नेहमी नीट ब्रश करूनही तुमच्या तोंडाचा वास येत असेल, तर लगेच डॉक्टरांना भेट द्या. संशोधनानुसार तोंडातून नेहमी वास येत असेल, तर टाइप २ मधुमेह, फुफ्फुसे, लिव्हर आणि किडनी संबंधित विकार असू शकतात.

फुफ्फुसांमध्ये असलेल्या इंफेक्शनमुळे ही खूप वेळा श्वासातून दुर्गंध येतो. लिव्हर इंन्फेक्शनमुळे ही अपचनाशी संबंधित त्रास होऊ लागतात. त्यामुळे श्वास आणि तोंडातून वास येतो.

टाइप-२ मधुमेह असल्यास शरीरात ग्लुकोजची कमतरता असते आणि त्यामुळे तहान खूप लागते, ज्यामुळे तुमचे तोंड कोरडे पडते. त्याचबरोबर मधूमेहामुळे शरीरात मेटाबॉलिक म्हणजेच पचनाशी संबंधित बदल होतात. त्यामपळे तोंडातून वास येतो.

किडनी विकारामुळे शरिरातील पचनक्रिया म्हणजे चयापचयाशी संबंधित (मेटाबॉलिक) बदल होतात. त्यामुळे तोंड कोरडे होते, म्हणुन तोंड कोरडं पडतं.

साखर जास्त खातं असाल तर या लक्षणांकडे दुर्लक्ष नको

गोड पदार्थ खाणं हे प्रत्येकाला आवडतं. पण अतिप्रमाणात गोडं खाणं शरीरासाठी नुकसानकारक आहे. शरीरात साखरेच प्रमाण जास्त झाल्याने आपल्याला अनेक मोठ्या आजारांना सामोरे जावं लागतं

- **नेहमी आजारी असणं-** साखर जास्त झाल्यामुळे प्रतिकारक्षमता कमी होते.
- **वजन वाढणे-** रक्तात साखरेच प्रमाण जास्त झालं की वजन वाढते.
- **तणाव आणि चिंता वाढणे-** रक्तातील साखरेच प्रमाण कमी जास्त होत असल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण होते.
- **जास्त तहान लागणं-** शरीरात पाण्याची कमतरता सतत जाणवते त्यामुळे मधुमेहाचा धोका वाढतो.
- **दात दुखी-** सतत गोड खाल्ल्याने दात खराब होतात. दातांच्या समस्या निर्माण होतात.

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

तीन 'इंजिने' असूनही 'लूज शंटिंग'!

'कुवतीची कोंडी' हे संपादकीय (७ फेब्रुवारी) वाचले. सार्वजनिक जीवनात नियमपालनाचा संपूर्ण अभाव, कोणीच कशासाठी उत्तरदायी नसणे, अशा सर्व गोष्टींचा परिपाक सध्या अनेक प्रसंगांत दिसून येतो आहे. टँकर उलटून रहदारीचा इतका प्रदीर्घ काळ बोजवारा उडणे, सुसाट डम्परखाली चिरडून होणारे अनेक मृत्यू, दिल्लीत बेजबाबदारपणे खोदलेल्या खड्ड्यात पडलेल्या तरुणाला कित्येक तास मदतच न मिळाल्याने सर्वांच्या डोळ्यांदेखत त्याचा बुडून झालेला मृत्यू, हे सारे मन विषण्ण करणारे आहे. शासनाचे सारे नियम व सूचना कित्येक महिने धाब्यावर बसवून इंडिगोने जशी अभूतपूर्व कोंडी विमानप्रवाशांची केली होती तशीच कोंडी आता 'द्रुतगती' प्रवास करणाऱ्यांच्या वाट्याला आली.

आताही मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाला 'मिसिंग लिंक'ची कशी गरज आहे ही चर्चा सुरू झाली आहे! हा म्हणजे 'आग रामेश्वरी, आणि बंब सोमेश्वरी' असा प्रकार आहे. अशीच बेशिस्त रहदारी आणि भोंगळ कारभार सुरू राहिला तर 'मिसिंग लिंक'वरही अशीच परिस्थिती सहज निर्माण होऊ शकते. साधी नागरी शिस्त व ती लावण्याची इच्छाशक्तीच 'मिसिंग' आहे हेच खरे दुखणे आहे.

मालगाडीच्या वाघिणींचे धोकादायक पद्धतीने 'लूज शंटिंग' केले जाते म्हणून त्यावर 'लूज शंटिंग न करे' अशी सूचना छापलेली असते. कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही अशा प्रकारे साऱ्या प्रशासनाचेच 'लूज शंटिंग' सुरू आहे की काय अशी शंका अशा अभूतपूर्व गोंधळाच्या प्रसंगांत येते. दोन वा आता तीन 'इंजिने' उपलब्ध असूनही अशी 'लूज शंटिंग'सदृश स्थिती जाणवणे हे महाराष्ट्रासारख्या राज्याला अजिबात भूषणावह नाही.

■ **प्रसाद दीक्षित,** ठाणे

तोवर व्यवस्था अपयशीच राहील...

'कुवतीची कोंडी' हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. मुंबई-पुणे महामार्गावरील घटना केवळ अपघात नव्हती, ती व्यवस्थेची परीक्षा होती आणि आपण नेहमीप्रमाणे तीत नापास झालो. हजारो नागरिकांना तासन् तास, जवळपास [illegible] केल्यासारखे अडकवून ठेवणे हे केवळ परिस्थितीजन्य नसून, ते भ्रष्ट कंत्राटी व्यवस्था, संवेदनशून्य राजकीय नेतृत्व व जबाबदारीपासून पळ काढणारे प्रशासन यांच्या अभद्र युतीचे फलित होते. या घटनेत पोलीस, अग्निशमन दल, प्रशासन व राजकीय नेतृत्व- सगळे आपापल्या कोशात व्यग्र होते. 'सुरक्षितता सर्वोच्च होती' हा एकच पोकळ मंत्र जपला गेला. हजारो नागरिकांना ३२ तास अडकवून ठेवणे, त्यांना पाणी, शौचालय, वैद्यकीय मदत, माहिती न देता कैद्यांसारखे वागवणे हे सुरक्षिततेचे व्यवस्थापन नव्हे, तर व्यवस्थेचे अपयश आहे.

जर्मनीत नागरिकांना अशा प्रकारे महामार्गावर अडकवून ठेवणं हे थेट मानवाधिकार उल्लंघन मानले जाते. जपान आणि सिंगापूरसारख्या देशांत प्रशासन सार्वजनिक माफी मागते. कारण तिथे चूक मान्य करणं ही कमजोरी नसून जबाबदारी घेतल्याचे लक्षण मानले जाते. आपल्याकडे तशी अपेक्षाही अवास्तव ठरेल, पण सर्वात गंभीर बाब म्हणजे आपली व्यवस्था अशा दुर्घटनांतून शिकायलाच तयार नसते. कुठल्याही प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याची इच्छाशक्ती नसल्याने कोणावरही दोष निश्चित होत नाही, कोणावरही कारवाई होत नाही, आणि म्हणूनच कुठलीही सुधारणा होत नाही. कारण समस्या अपघाताची नाही, तर अपघातानंतरच्या व्यवस्थेची निर्ढावलेली बेफिकिरी बदलत नाही ही आहे. जोपर्यंत अपयशाला किंमत मोजावी लागत नाही, तोपर्यंत अपयशच आपले प्राक्तन असेल.

■ **हेमंत सदानंद पाटील,** नालासोपारा

'वापरा व फेकून द्या' हेच धोरण?

'आताचे 'द्रोणाचार्य' अंगठा मागत नाहीत, तर 'एकलव्या'चा आत्मविश्वास खच्ची करतात' हा डॉ. अनिल हिवाळे यांचा लेख व 'ओबीसी समाजातील खदखद आणखी तीव्र?' हा देवेंद्र गावंडे यांचा सविस्तर वृत्तलेख (दोन्ही रविवार विशेष- ८ फेब्रु.) वाचले. दोन्हीही लेख वाचून आकलन केल्यावर असे दिसून येते की, भाजप राज्यात किंवा देशात ज्या ओबीसी घटकांच्या जिवावर सत्ता ओरपू-ओरपू भोगत आहे, त्या ओबीसी घटकाबद्दल भाजपला प्रत्यक्षात इम्पिरिकल डेटा जमवण्याची संधी घेता येता नाही- ती संधी होती, हे लेखकांनी नेमकेच नमूद केलेले आहे. सध्या भाजपने महाराष्ट्रासह इतरही काही राज्यांत मूळ ओबीसींना कडवट हिंदुत्वाची अशी काही गोळी दिली आहे की, ओबीसी घटकातील नेते व युवक कधी नव्हे एवढे हिंदू म्हणून त्वेषाने पेटून उठत आहेत, कट्टर हिंदूची भाषा बोलत आहेत. भाजपचे ओबीसींबाबत वापरा व फेकून द्या हे धोरण जोपर्यंत ओबीसी बांधवांना समजत नाही तोपर्यंत ओबीसी समाजघटकांचा होणारा सर्वांगीण ऱ्हास कोणीही रोखू शकत नाही.

■ **संतोष वर्पे,** वावी (नाशिक)

दुसऱ्या घटकालाही न्याय देणे गरजेचे

'आताचे द्रोणाचार्य अंगठा मागत नाहीत, तर 'एकलव्या'चा आत्मविश्वास खच्ची करतात...' हा डॉ. अनिल जगन हिवाळे यांचा लेख समतेच्या प्रश्नाची एक बाजू अधोरेखित करतो (रविवार विशेष- ८ फेब्रुवारी). वास्तविक, उच्च शिक्षण संस्थांमधील समतेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने 'विद्यापीठ अनुदान आयोगा'ने जारी केलेल्या अधिनियमातील (२०२६) संदिग्धतेवर बोट ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत स्थगिती दिली. हे योग्यच झाले. वंचित तसेच प्रस्थापित गटांवर अन्याय होणार नाही असा सुवर्णमध्य काढून विद्यापीठ अनुदान आयोगाला आता अधिक काळजीपूर्वक सुधारित अधिनियमाचा मसुदा न्यायालयात सादर करावा लागेल. देशात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (१९८९) अस्तित्वात आल्यापासून तथ्यहीन तक्रारी दाखल करण्याचे प्रमाण सुमारे ४० टक्के आहे. त्यामुळे या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो असे दिसून येते. म्हणूनच नवीन नियमांची चौकट तयार करताना समाजातील कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही हे पाहणे क्रमप्राप्त ठरते. समतेसाठी समन्याय आवश्यक ठरतो. एका घटकावर अन्याय करून दुसऱ्या घटकाला न्याय देणे अयोग्य आहे.

■ **डॉ. विकास इनामदार,** पुणे

कारवाईविनाच पुन्हापुन्हा संधी!

'लाडक्या बहिणींना पडताळणीसाठी पुन्हा संधी' हे वृत्त (लोकसत्ता- ७ फेब्रु.) वाचले. ही संधी महिला व बालकल्याण विभाग मंत्र्यांना वाचवण्यासाठीसुद्धा दिली जात आहे. कारण त्यांचेच हे म्हणणे आहे की लाडक्या बहिणींची पडताळणी पात्रता ही निरंतर प्रक्रिया आहे. म्हणजेच, राज्याची तिजोरी रिकामी होऊन गेली तरी चालेल. केवायसीमध्ये जे तपशील/पर्याय निवडण्यास सांगितले आहेत ते खरे निवडले गेले आहेत की नाही याची शहानिशा कोण करणार? कारण या योजनेची सुरुवातच कर देणाऱ्या महिलांनीसुद्धा या योजनेचा खोटा लाभ घेऊन झाली आहे. शासकीय २५० महिला कर्मचारी, ४५० पुरुषांनीही या योजनेचा गैरफायदा घेतला आहे. त्यांच्यावर कारवाई होणार होती ती कधी, कशी हे शासनाने जाहीर केलेलेच नाही. मग तीच पुनरावृत्ती कशावरून होणार नाही?

■ **नीता शेरे,** दहिसर पूर्व (मुंबई)

खडखडाट जाणवतो तो इथे...

''**अबोध बालका'ची** धास्ती?' या अग्रलेखात लेफ्टनंट जनरल थोरात यांच्या 'फ्रॉम रिव्हेली टू रिट्रीट' या आत्मचरित्राचा उल्लेख आहे. थोरात यांनी चीन कसा, कोणत्या भागातून आत शिरेल अन् त्यासाठी काय काय उपाय करायला हवेत याचा अहवाल तेव्हाचे मेजर जनरल थिमय्या यांना दिला होता, पण त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. झाले तसेच. नेहरूंना ही बाब समजल्यानंतर त्यांनी थोरात यांना भेटायला बोलावले अन् मला अगोदर का सांगितले नाही म्हणून थोरात यांना विचारले. त्यावर लष्कराच्या नियमात तसे बसत नाही म्हणून सांगितले नाही असे थोरात म्हणाले. ते ऐकून नेहरू यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले असेही थोरात यांनी चरित्रात लिहिले आहे.

सी. डी. देशमुख लोकसभेत, राजीनामा दिल्यानंतर अन् मंत्री नसतानाही, त्यांचे भाषण असेल तेव्हा नेहरू येऊन बसत. कान देऊन ऐकत. संयुक्त महाराष्ट्र प्रकरणात सीडींनी राजीनामा दिल्यानंतर जे भाषण केले तेव्हा ज्या शब्दांत नेहरूंवर टीका केली तितकी जहाल टीका त्याअगोदर अन् त्यानंतरही, ते हयात असेपर्यंत, कोणी केली नाही. पण नेंहरूंनी मनात आकस ठेवला नाही. सीडी नंतर दिल्ली विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले.

ही मंडळी टीकेला इतकी का भितात हेच कळत नाही. प्रतिवाद करण्यासाठी जी आकलन, बौद्धिक क्षमता लागते तिचा अभाव अन् चुका कबूल करून सुधारणा करण्याचा मनाचा मोठेपणा यांचा खडखडाट जाणवतो इथे.

■ **सुखदेव काळे,** दापोली (रत्नागिरी)

सरकारी काम अन...

कोयना धरण व्हावे म्हणून १९५०पासून लोकांकडूनच वारंवार मागणी झाली. धरणाचे काम सुरू झाल्यानंतर १० वर्षांनी पूर्ण झाले. मात्र प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन हा मुद्दा त्यानंतर ऐरणीवर आला. हे पुनर्वसन नियोजनाविनाच झाल्याचा निष्कर्ष डॉ. इरावती कर्वे व जाई निंबकर यांनी अभ्यासान्ती मांडला...

चित्ततोष खांडेकर
नदी विषयक संशोधक अभ्यासक
chittatoshresearch@gmail.com

नदीकारण

भारतरत्न एम. विश्वेश्वरय्या यांच्या संकल्पनेतून जन्माला आलेली कोयना धरणाची संकल्पना ही मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्राला वीज देऊ शकणारी अभूतपूर्व योजना होती. उद्योगांना आणि कारखान्यांना चालना देऊन महाराष्ट्राचा झपाट्याने विकास करण्याची क्षमता या प्रकल्पात होती. म्हणूनच स्वातंत्र्यानंतर कोयना धरण होण्यासाठी पहिले आंदोलन तत्कालीन मुंबई प्रांतात उभे राहिले. या आंदोलनाला संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीची आणि मराठी-गुजराती वादाची किनार होती. मंत्रिमंडळातील गुजराती नेते तापी नदीवरील उकाईच्या- गुजरात आणि मुंबईला वीज देऊ शकणाऱ्या- प्रकल्पासाठी हट्ट धरत होते; तर मराठी नेते कोयना धरणासाठी आग्रही होते.

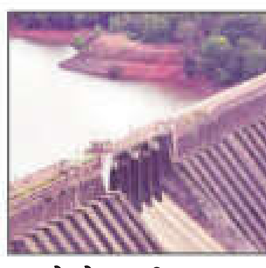

मुंबईतील गिरणी कामगार, कोयना काठचे शेतकरी, मराठा चेम्बर ऑफ कॉमर्ससारख्या संस्था, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील आचार्य अत्रेंसारखे नेते, अशा सर्व स्तरातील लोक कोयना धरणासाठी लढत होते. १९५०-१९५३ ही तीन वर्षं यासंदर्भात अनेक मोहिमा राबवल्या गेल्या. १९५१ मध्ये कोयनातीरी झालेल्या हेळवाक येथील परिषदेत तर हा प्रकल्प पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत राबवावा अशा आशयाची ठराववजा मागणी तत्कालीन सरकारला करण्यात आली. पण मराठी-गुजराती मंत्र्यांच्या वादात आणि प्रशासकीय कामात हा प्रकल्प अडकला. स्वातंत्र्याला चार-पाच वर्षं झाली तरी त्यासंदर्भात प्रशासकीय निर्णय होतच नव्हते. अखेर यशवंतराव चव्हाण आणि बाळासाहेब देसाई यांच्या पाठपुराव्यामुळे या प्रकल्पाला मान्यता मिळाली (१९५४) आणि धरणाचे काम वेगाने (१९५६ नंतर) सुरू झाले.

धरणामुळे १२,००० कुटुंबे विस्थापित होतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. सरकारी आकडेवारीनुसार तब्बल ९१७१ कुटुंबे (पाटण, जावळी आणि महाबळेश्वर या तीन तालुक्यांतील गावे) या प्रकल्पामुळे विस्थापित होणार होती. जेव्हा कोयनेचा प्रकल्प उभा राहत होता तेव्हा पुनर्वसनाची संकल्पना पूर्णपणे आकाराला आली नव्हती. विस्थापितांना आर्थिक मोबदला देणे किंवा जास्तीत जास्त राहायला आणि कसायला जमिनी देणे यापलीकडे इंग्रजांनी धरणग्रस्तांसाठी काहीच केले नव्हते. धरणग्रस्त फक्त आपले गाव किंवा जमीन धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात गमावत नसतात तर वर्षानुवर्षं जपलेली त्यांची संस्कृती, जमिनीशी असलेले अतूट नाते, नदीकाठी उभी राहिलेली एक सक्षम अर्थव्यवस्था हे सारेच गमावत असतात. त्यामुळे फक्त रक्कम किंवा कुठलीशी जमीन देऊन त्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत. त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना नवीन ठिकाणी स्थिरस्थावर होण्यास मदत करावी लागते. सुपीक जमीन देणे, राहायला चांगली गावठाणाची जागा देणे, वीज, पाणी, रस्ता अशा नागरी सुविधा मुबलक प्रमाणात देणे - थोडक्यात विस्थापितांच्या जगण्याचे मूलभूत प्रश्न सोडवणे म्हणजे पुनर्वसन होय. पण एक तर प्रशासनाने विस्थापितांना तुटपुंजा मोबदला दिला किंवा कुठलीशी जमीन दिली. या गोष्टीही बहुसंख्य विस्थापितांना मिळाल्या नाहीत.

कोयना धरणग्रस्तांसाठी संघर्ष करणारे सामाजिक कार्यकर्ते भारत पाटणकर यांचा दावा असा की, पाटण तालुक्यातील केवळ आठ गावांना पुन्हा वसवण्यात आले. मग इतर विस्थापितांचे काय झाले? काही विस्थापित खोऱ्यातील डोंगरांवर गेले आणि धरणक्षेत्रात न बुडालेल्या जमिनींवर शेती आणि पशुपालन करू लागले. अर्थात धरणक्षेत्रात त्यांची सुपीक जमीन गेली होती. काही विस्थापित गाव कायमचा सोडून मुंबईतील गिरण्यांमध्ये कामगार झाले. तर काही विस्थापितांनी रायगड, ठाणे, पालघर भागात ओळखीने जागा शोधून गावठाणे वसवली. त्यातील बहुतेकांना नोकरीसाठी मुंबईसारख्या शहरांकडेच पाहावे लागले. राज्यातील वेगवेगळ्या भागांत हे विस्थापित विखुरले.

ज्यांना जमीन आणि गावठाण देऊन सरकारने पुन्हा वसवले अशा काही हजार कुटुंबांची अवस्था कशी होती? १९६५-६६ मध्ये डेक्कन कॉलेजमधील प्राध्यापिका इरावती कर्वे यांनी जाई निंबकर यांच्यासह सगळ्या पुनर्वसित गावांमध्ये फिरून माहिती घेतली. त्याचा अहवालही १९६७मध्ये प्रकाशित झाला. या अहवालानुसार, पुनर्वसित गावातील कुटुंबांची अवस्था भयानक होती. या धरणग्रस्तांच्या कुटुंबात सोयरीक करायलाही कोणी तयार होत नव्हते. त्यांच्या गावामध्ये वीज वा पाणीपुरवठ्याच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. त्यांना एकतर पडीक किंवा कमी सुपीक जमीन देण्यात आली होती. तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी या लोकांना नवीन जमिनींची नीटशी कल्पनाही दिली नव्हती. ज्यांचे पुनर्वसन झाले त्यांची अशी भयाण परिस्थिती, तर ज्यांचे झाले नाही त्यांचे काय?

घरास-घर, एकरास-एकर

धरणग्रस्तांसाठीचे हे प्रश्न सवार्त आधी उचलून धरले क्रांतिसिंह नाना पाटील यांनी. इंग्रजांविरोधात प्रतिसरकार उभे करणाऱ्या पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी 'प्रति-विकासाचा' नारा दिला. घरास-घर आणि एकरास-एकर मिळणे हा धरणग्रस्तांचा हक्क आहे अशी मांडणीच त्यांनी केली. पण या साऱ्या मागण्यांना 'हो करतो' असे सोज्वळ उत्तर प्रशासनाने दिले आणि प्रश्न पुढे ढकलला. मग कोयनेसह इतर धरणांच्या विस्थापितांनी एकत्र येऊन 'महाराष्ट्र राज्य धरणग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त परिषद' १९६२ मध्ये स्थापन केली. लाल निशाण पक्ष आणि दत्ता देशमुख यांच्या प्रयत्नांनी धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. 'आधी पुनर्वसन मग धरण' या नाऱ्याने प्रशासनाला जाग आली. देशमुखांच्या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रात पुनर्वसनाचा कायदा १९७६ मध्ये पारित झाला. असा कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. कायदा आला पण कोयना धरणग्रस्तांचे प्रश्न काही सुटले नाहीत. ६०च्या दशकात सुरू झालेली धरणग्रस्तांची चळवळ हत्तीसारख्या सावकाश काम करणाऱ्या प्रशासनाला कंटाळून बंद झाली. आहे त्या परिस्थितीत जगण्याचे मार्ग शोधायला विस्थापितांनी सुरुवात केली.

१९८८मध्ये कोयनेच्या नदीकारणाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला. श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेत्यांनी धरणग्रस्तांचा हुंकार ऐकला आणि १५-२०,००० विस्थापितांचे आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर सुरू झाले. आपल्या हक्कांसाठी प्रशानसाशी लढणारी ही दुसरी पिढी होती. पण आता प्रश्न वेगळेच होते. धरणग्रस्तांची सरकारी कागदपत्रे कुठे आहेत, हे नवीन प्रशासकांनाच माहीत नव्हते. दुसरी गोष्ट प्रशासनावरील कामाचा भार इतका वाढला होता की या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला पुरेसा वेळ जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नव्हता. तिसरी गोष्ट आता यांचे पुनर्वसन करायचे कुठे हा प्रश्न 'आ'वासून उभा होता. या तिन्ही समस्यांचे उत्तर शोधण्याचे काम शेवटी श्रमिक मुक्ती दल आणि संबंधित संघटनांच्या नेत्यांनीच केले. सरकारी इमारतींमध्ये गडप झालेली कागदपत्रे शोधणे, कोणत्या धरणाच्या लाभ क्षेत्रात जमिनी शिल्लक आहेत हे हुडकणे आणि प्रशासनाचा पाठपुरावा करून पुनर्वसनाचे काम सुरू करणे यासाठी जंग जंग पछाडले गेले. परिणामी १९८८-२००० या काळात अनेक विस्थापितांचे हळूहळू पुनर्वसन झाले. अर्थात त्यातही भ्रष्टाचार, फसवणूक, जातीचे राजकारण हा सगळा प्रकार झालाच. पण तरीही वडलांची गेलेली जमीन मुलाला आणि आज्याची नातवाला मिळू लागली.

पण म्हणून विस्थापितांचे प्रश्न संपले नाहीत. शासनदरबारी फक्त जमिनीचा सात-बारा असलेल्या कुटुंबांची नोंद होती. जमीन नसलेल्यांची तसेच काही अल्पभूधारकांची नावेही या यादीत नव्हती. यापैकी बरेचसे पूर्वीच्या अस्पृश्य जातींमधील होते. याखेरीज आधीच्या टप्प्यात पुनर्वसन न झालेलीही काही कुटुंबे आहेतच. या सगळ्यांचा लढा आजही सुरू आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर मोर्चे काढून, मंत्र्यांशी चर्चा करून, कोर्टात धाव घेऊन हे विस्थापित आजही आपला हक्क मागत आहेत. क्लिष्ट सरकारी प्रक्रियेतून यांचे प्रश्न कसे सोडवावे ही समस्या आहेच.

कोयना प्रकल्पाचे पुनर्वसन नियोजनाविनाच झाल्याचा शेरा इरावती कर्वे यांनी ६०च्या दशकातच दिला होता. पण याचा अनुभव धरणग्रस्तांच्या तीन पिढ्यांना यावा याहून मोठे दुर्दैव काय? 'सरकारी काम अन साठ वर्षे थांब' असे म्हणायची वेळ आज धरणग्रस्तांवर आली आहे. शिवाय ज्या शहरांच्या विकासासाठी ही धरणे उभी राहतात, त्या शहरातील नद्यांचे आणि स्थानिकांचे काय होते? याची उत्तरे पुढील लेखात शोधू.

संदर्भ:

A survey of people displaced through Koyna dam: a detailed survey: Iravati Karve and Jai Nimbakar

State Formation from Below: Social Movements of Dam Evictees and Legal Transformation of the Local State in India, 1960–76 by Arnab Roy Chowdhury. 2018, **Journal of South Asian studies**

कहाणी कोयनेची- उषा तांबे, राजहंस प्रकाशन

महाराष्ट्राचे अर्थकारण- श्री.आ.भट, रसिक प्रकाशन

भारत पाटणकर यांची एक तासाची (लेखकाने घेतलेली, रेकॉर्डेड) **मुलाखत.**

Asserting the Rights of the Toiling Peasantry for Water Use: The Movement of the DamOustees and the Drought Affected Toilers in South Maharashtra by Bharat Patankar and Anant Phadke; in Peter P. Mollinga, Ajay Dixit and Kusum Athu korala (eds), **Integrated Water Management in South Asia** (Delhi: Sage, 2006), pp. 352–88.

कुतूहल

माणसं तोतरं का बोलतात?

काही माणसं बोलताना अडखळतात. सिनेमात बऱ्याचदा विनोदासाठी किंवा गंमत म्हणून असं अडखळत बोलणारं पात्र असतं. नेहमीच्या आयुष्यात मात्र याकडे दोष किंवा वैगुण्य म्हणून बघितलं जातं. लहान मूल सुरवातीला बोबडं बोलतं. कालांतराने हळूहळू तो बोबडेपणा कमी होत जातो. बोबडेपणात काही उच्चार चुकीचे होतात. जसं, 'र' चा उच्चार 'ल' म्हणून केला जातो. तोतरेपणात मात्र एकच शब्द बराच वेळ घेत अडखळत उच्चारला जातो. काही वेळा एखादा शब्द उच्चारताना लांबला जातो किंवा पुन्हा पुन्हा उच्चारला जातो. काहीजणांचा तोतरेपणा काही अक्षरांच्या बाबतीत, तर काही जणांचा प्रासंगिक असतो. यामुळे अनेकदा या व्यक्ती संवाद साधणं टाळतात.

सौजन्य : क्रिएटिव्ह कॉमन्स

तोतरेपणा हा एक वाचा-दोष आहे. बोलताना जीभ, ओठ, दात, टाळू, पडजीभ, स्वरयंत्र, स्वरनलिका आणि फुफ्फुसं या अवयवांचा वापर होतो. या अवयवांचं नियंत्रण, समन्वयन आणि भाषेचं ज्ञान हे काम मेंदू करतो. बोलताना ओठ, जीभ आणि स्वरयंत्राच्या स्नायूंमध्ये अनावश्यक ताण आला तर बोलणं अडखळतं.

तोतरेपणाचे तीन प्रकार आहेत. वयाच्या दोन ते पाच या वयोगटात, भाषेची ओळख होत असताना असणारा तोतरेपणा हा सामान्य मानला जातो. या प्रकारात संवाद वाढला, भाषेचं ज्ञान वाढलं की हळूहळू तोतरेपण कमी कमी होत जातं आणि मूल व्यवस्थित बोलू लागतं. दुसरा प्रकार म्हणजे मेंदूच्या किंवा मज्जासंस्थेच्या दुखापतीमुळे, आजारामुळे आलेला तोतरेपणा. तिसरा प्रकार म्हणजे मानसिक आजार किंवा मानसिक आघातामुळे आलेला तोतरेपणा!

अर्थात सर्व प्रकारच्या तोतरेपणात, वैगुण्याला नावं ठेवण्यापेक्षा, त्या व्यक्तीला चिडवण्यापेक्षा इतरांनी आधार देणं फार महत्त्वाचं ठरतं. वाचा उपचार (स्पीच थेरपी) पद्धतीचा उपयोग करून तोतरेपणावर मात करता येते. या उपचारांमध्ये औषधांचा वापर करत नाहीत. मात्र नैराश्य आलं किंवा मानसिक ताण असेल तर त्यासाठी औषधं दिली जातात. बोलताना होणारी जीभेची हालचाल, ओठ, टाळू यांची हालचाल, बोलताना स्नायूंवर येणारा ताण, श्वासोच्छवास यासाठी उपचारांमध्ये व्यायाम करुन घेतले जातात. बोलण्याच्या अवयवांची हालचाल जेव्हा व्हायला हवी तेव्हा, ती तशीच व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जातात. याशिवाय तोतरं बोलणाऱ्या व्यक्तींच्या मानसिक स्वास्थ्याची काळजी घेणं आवश्यक आहे. त्यांना सारख्या त्यांच्या चुका दाखवत राहिलं, त्यांना बोलताना अडवलं तर ते बोलायचंच टाळतात. त्याऐवजी त्यांनी सावकाश बोलावं, त्यांची वाक्यं लहान असावीत यासाठी प्रयत्न केले तर त्यांचा तोतरेपणा कमी होऊ शकतो.

अनघा अमोल वक्टे
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

व्यक्तिवेध

अध्यापन हे ज्ञानाचे हस्तांतर असते, तर अनुवाद हा भाषांमधील दुवा असतो. प्रा. राजेंद्र डेंगळे यांनी दोन्ही बाबतींत केलेले काम अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रा. डेंगळे यांनी दीर्घ काळ अध्यापन व जर्मन साहित्याचा मराठीत, मराठी साहित्यकृतींचा जर्मनमध्ये अनुवाद केला. मराठी आणि जर्मन भाषांतील ते महत्त्वाचा दुवा होते.

प्रा. राजेंद्र डेंगळे

प्रा. डेंगळे यांनी तत्कालीन पुणे विद्यापीठातून (आताचे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ) तत्त्वज्ञान आणि जर्मन भाषेचे शिक्षण घेतले. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून (जेएनयू) जर्मन साहित्य विषयातील पदव्युत्तर पदवी (एम.ए.) १९७९ मध्ये मिळवून १९९० मध्ये त्याच विद्यापीठातून पीएच.डी.ही पूर्ण केली. त्यानंतर जेएनयूमध्येच त्यांनी चार दशकांहून अधिक काळ अध्यापन केले. या दरम्यान त्यांनी जेएनयूमधील भाषा, साहित्य व संस्कृती अध्ययन संस्थेचे अधिष्ठाता म्हणूनही जबाबदारी निभावली. अलीकडेच २०२१मध्ये ते जेएनयूमधून निवृत्त झाले. साहित्य सिद्धान्त, जर्मन साहित्याचा इतिहास, आधुनिक जर्मन साहित्य आणि सांस्कृतिक अध्ययन हा त्यांचा अध्यापन, अभ्यासाचा विषय होता.

जर्मन ॲकॅडेमिक एक्स्चेंज सर्व्हिसकडून (डाड) मिळालेल्या डॉक्टरेट व पदव्युत्तर शिष्यवृत्तींमुळे त्यांना बीलेफेल्ड, बॉन, हायडेलबर्ग, बायरॉईथ, व्हुपर्टाल आणि फ्रायबर्ग अशा विद्यापीठांत अभ्यास आणि संशोधनाची संधी मिळाली. या विद्यापीठांतील प्राध्यापकांसह त्यांना काम करता आले. त्या अनुभवातून त्यांना युरोपीय साहित्य परंपरेचा अधिक सखोलपणे अभ्यास करता आला. इतकेच नाही, तर त्यांनी तो अभ्यास भारतीय संदर्भात मांडण्याचा प्रयत्न केला. २००४ ते २०१० या काळात त्यांनी गोएथे सोसायटी ऑफ इंडियाचे सचिव म्हणून काम केले. तसेच संस्थेच्या वार्षिक नियतकालिकाच्या प्रकाशनाची जबाबदारी सांभाळली. या माध्यमातून भारत-जर्मनी यांच्यातील साहित्यिक संवाद अधिक अर्थपूर्ण होण्यावर त्यांनी भर दिला.

डॉ. डेंगळे यांनी मराठीतून जर्मनमध्ये, तसेच जर्मनमधून मराठीमध्ये अनेक ग्रंथ आणि साहित्यकृतींचा अनुवाद केला आहे. एडन फोन होर्वाथ आणि फ्रीडरिश शिलर अशा लेखकांवरील त्यांचे कार्य विशेष मानले जाते. अनुवादक म्हणून त्यांनी नोबेलविजेत्या हर्टा म्युलर, पॉल क्ली, विश्राम बेडेकर, प्रभाकर बर्वे, रोन्या ओथमन यांच्यासह अनेकांच्या जर्मन साहित्यकृतींचे मराठी आणि हिंदीत अनुवाद केले. अत्यंत अभ्यासू, चिकित्सक पद्धतीने काम करण्यावर त्यांचा भर होता.

साहित्यशास्त्र आणि तत्त्वज्ञान याबाबत त्यांनी सदैव चिंतन केले. त्यांचा अभ्यास, चिंतनाचा फायदा त्यांच्या विद्यार्थ्यांना झाला. विद्यार्थ्यांच्या अनेक पिढ्या त्यांनी घडवल्या. कडक शिस्तीचे असले, तरी विद्यार्थिप्रिय शिक्षक म्हणून त्यांची ओळख होती. विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाला त्यांनी प्रोत्साहन दिले. दिशा दिली. वैचारिक, साहित्यिक बैठकही दिली.

प्रा. डेंगळे हे बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व होते. अध्यापन, अनुवादासह त्यांना अभिनय, शास्त्रीय संगीतामध्ये विशेष रस होता. त्यांनी घाशीराम कोतवाल या नाटकासह काही नाटके, चित्रपटांत अभिनयही केला होता. त्यांना दृश्यकलेचे विशेष भान होते. ते शिल्पकारही होते. त्यांच्या निधनामुळे साहित्य, तत्त्वज्ञानाच्या वाटेवरचा ज्ञानमार्गी हरपला आहे.

राजवाडे विचारविश्व

राजवाड्यांचे एक प्रेरणाकेंद्र : 'नवनीत'

मराठी भाषेच्या काव्यवैभवाची थोरवी वि.का.राजवाडे यांच्या - आणि अन्य अनेक मराठी तरुणांच्याही - मनावर बिंबवण्याचे काम अप्रत्यक्ष पद्धतीने पार पाडणारे प्रभावी वाङ्मयसेवक म्हणून परशुराम बल्लाळ ऊर्फ परशुरामपंत तात्या गोडबोले यांचा अगदी संक्षिप्त परिचय या टप्प्यावरच करून घेणे योग्य ठरेल.

मराठेशाहीच्या अखेरच्या पर्वात, १७९९ साली जन्मलेल्या परशुरामाने वाईला शिक्षण घेऊन झाल्यावर पुढे पुण्यात येऊन जोगांच्या पेढीवर कारकुनी करत असतानाच मराठी काव्याचा अभ्यास आरंभला. त्याचा त्या क्षेत्रातला व्यासंग वाढला. पुढे योगायोगाने त्यांचा परिचय मेजर थॉमस कँडी यांच्याशी झाला. कँडी जेव्हा मराठी ट्रान्स्लेटरच्या पदावर रुजू झाला, तेव्हा त्याला साहजिकच स्थानिक तज्ज्ञाच्या मदतीची गरज भासली. त्याने परशुराम गोडबोले यांची आपला खास पंडित म्हणून नेमणूक केली. ते त्या पदावर अखेरपर्यंत काम करत राहिले. संस्कृत 'पंडिती' कोश तयार करणाऱ्या संपादक मंडळातले त्यांचे काम खूप नावाजले गेले; तसेच 'वेणीसंहार', 'शाकुंतल', 'मृच्छकटिक', 'नागानंद' व 'पार्वतीपरिणय' या संस्कृत नाटकांचे त्यांनी केलेले अनुवाददेखील प्रशंसेला पात्र ठरले.

त्यापेक्षाही अधिक लोकप्रिय व परिणामकारक ठरलेले परशुरामपंत गोडबोले यांचे काम म्हणजे 'नवनीत' या शीर्षकाखाली त्यांनी संकलित केलेले मराठी संत-पंत-तंत कवींच्या काव्यातील वेचे. 'नवनीत' अर्थात 'महाराष्ट्र भाषेंतील कवितांचे वेंचे' या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती १८५४ साली शिळाछापावर पुणे पाठशाळेतील छापखान्यात मुद्रित केली होती. त्याच्या प्रस्तावनेत आपला हेतू स्पष्ट करताना तात्यांनी लिहिले होते, 'कोणतीही भाषा सुधारण्यास व मनाची शक्ती वाढवण्यास कविता हे एक मोठे साधन आहे. सांप्रत सर्व विद्या शिकवण्याचे प्रयत्न चालले आहेत; त्यात कविता शिकवण्याचे साधन कमी आहे. ते अवश्य असले पाहिजे, असे बहुतांचे मत आहे. तोच उद्देश हे पुस्तक रचण्याचा आहे.'

हेतू स्पष्ट केल्यावर परशुरामपंत तात्यांनी प्रस्तावनेत पुढे अगदी थोडक्यात पण त्यांनी संकलित केलेल्या काव्याच्या बहुविधतेची माहिती दिली होती. त्यांनी म्हटले होते, 'महाराष्ट्र देशात जी मराठी भाषा चालत आहे, तिला प्राकृत भाषा म्हणतात. या प्राकृत भाषेत कविता करणारे मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, मुक्तेश्वर, वामनपंडित, रामदास, तुकाराम, मोरोपंत, अमृतराय इत्यादिक बहुत होऊन गेले. त्यांनी पुष्कळ प्रकारच्या कविता केल्या आहेत. ज्याला मराठी भाषेचे ज्ञान चांगले असावे, अशी इच्छा असेल, त्याने प्राचीन व अर्वाचीन कवींचे प्राकृत ग्रंथ पुष्कळ वाचणे आवश्यक आहे. साधारणपणे गद्यात लिहिलेल्या विषयांपेक्षा कवितेत वर्णिलेला विषय वाचणार्यांस गोड लागतो; कारण की कवितेत भक्ती आदि भाव व करुणश्रृंगारादि रस असतात, तसेच उपमादिक अनेक अर्थालंकार व अनुप्रास-यमकादि शब्दालंकार असतात. त्यामुळे वाचणाऱ्यांचे मनोरंजन होते...'

आणि प्रस्तावनेच्या शेवटच्या भागात आपल्या पुस्तकाची शिफारस करताना तात्यांनी म्हटले होते की, 'मराठी भाषेत कविताग्रंथ पुष्कळ व मोठाले आहेत. त्यात छंद व चालीही अनेक प्रकारच्या आहेत. त्यांची गोडी लागून तिकडे तरुणांच्या मनाची प्रवृत्ती व्हावी ह्याकरता मराठीतल्या बहुतेक कवितांतील थोडे थोडे वेचे घेऊन हे एक लहानसे पुस्तक तयार केले आहे. हे मन लावून वाचले असता कवितांचे प्रकार, त्यातील चमत्कार व रस वगैरे सर्व थोडक्यात समजतील. ह्या लहान पुस्तकाचा अभ्यास चांगला झाला असता (मूळ) मोठाले ग्रंथ पाहण्यास मार्ग सुलभ होईल.'

जरी परशुरामपंत गोडबोले यांनी आपले पुस्तक लहान असल्याचे म्हटले असले, तरी ते चांगलेच जाडजूड जवळजवळ पाचशे पानांचे होते. विशेष म्हणजे 'नवनीत' या पुस्तकाची भूमिका कायम ठेवून पुढे इंग्रज शिक्षणाधिकार्यांच्या आदेशावरून समाविष्ट वेच्यांमध्ये अनेकदा फेरबदल करून नवनव्या आवृत्त्या काढल्या गेल्या. शंभर वर्षांच्या अवधीत १८ आवृत्त्या निघाल्या. अठरावी शतसांवत्सरिक आवृत्ती प्रा.अनंत काकबा प्रियोळकर यांनी १९५४ मध्ये सुधारून वाढवली (६१८ पृष्ठे) आणि पुढे ती मुंबई राज्य शिक्षणखात्याने १९५७ साली प्रकाशित केली.

राजवाडे यांच्या प्रेरणाकेंद्रांबद्दलची ही माहिती घेतल्यावर पुढील लेखांकापासून पुन्हा एकदा राजवाडे यांच्या आयुष्याचा मागोवा घेत जाऊ या.

- आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

मेरी मर्जी!

व्यापार कराराचा तपशील ट्रम्प यांनी जाहीर केल्यावर भारताच्या वाणिज्यमंत्र्यांनीही पत्रकार परिषदेत काही बाबी स्पष्ट केल्या; पण रशियन तेलखरेदीचा प्रश्न टाळला...

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना नक्की कसली घाई आहे; हे कळायला मार्ग नाही. त्यांच्या देशात काही निवडणुका नाहीत आणि आहेत त्यात ट्रम्प हे उमेदवार नाहीत. पण तरी त्यांची घोषणांची लगबग काही संपायचे नाव नाही. ''भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराचा मसुदा चार-पाच दिवसांत येईल'' असे आपले वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितल्यानंतरच्या दिवसाचा सूर्य उगवायच्या आत तिकडे अमेरिकेत अध्यक्ष ट्रम्प यांनी प्रशासकीय आदेश प्रसृत करून या व्यापार कराराचा तपशील जाहीर केला आणि भारत-अमेरिका संयुक्त निवेदनही प्रसिद्ध केले. हे असे काही शनिवारी ब्रह्म मुहूर्तावरच होणार आहे असे उभयतांत ठरले असते तर आपल्या नेत्यांस घोषणेची संधी मिळती. ती ट्रम्प यांच्या कृतीने हुकली. आणि दुसरे असे की गोयल यांनीही कराराच्या मसुद्याचा 'चार-पाच' दिवसांचा वायदा केला नसता. असो. भारत-पाकिस्तान शस्त्रसंधी असो की व्यापार करार, हे ट्रम्प आपल्या नेत्यांना प्रथम घोषणा करण्याची संधी काही देत नाहीत. अर्थात म्हणून या कराराचे महत्त्व काही कमी होत नाही. ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय आदेशानंतर शनिवारी दुपारी गोयल यांनीही राजधानीत पत्रकार परिषद घेऊन या कराराचा खर्डा जाहीर केला. ''हा करार संपूर्णपणे भारताच्या हिताचा असून भारतीय उत्पादने अन्य देशांच्या तुलनेत अमेरिकेत आता सर्वाधिक करसवलत अनुभवतील,'' असे गोयल म्हणाले. ही बाब स्वागतार्ह. भारतीय उत्पादनांवरील आयात कर आता १८ टक्के इतका होईल. गोयल यांनी कोणकोणत्या भारतीय उत्पादकांस याचा फायदा होईल याचा तपशीलही सादर केला. मोटारींचे/ विमानांचे सुटे भाग, चहा, औषधे, हिरे निर्यातदार आदी अनेक क्षेत्रांतील उद्योगांस या करारामुळे व्यापक व्यापारसंधी निर्माण होतील. याची गरज होती.

कोणकोणत्या भारतीय उत्पादकांस अमेरिकी व्यापार कराराचा फायदा होणार हा प्रश्न जितका महत्त्वाचा आहे त्यापेक्षा अधिक कोणकोणती अमेरिकी उत्पादने भारतीय बाजारात अधिक सहज येणार; हा आहे. गोयल यांच्या म्हणण्यानुसार भारताने कृषी क्षेत्राभोवती योग्य ते कुंपण घातले असून भारतीय शेतकऱ्यांना त्यामुळे अजिबात धोका नाही. आपण सोयाबीन, सोया तेल, मका, मक्यापासून बनलेले इथेनॉल आदींच्या आयातीस होकार दिलेला नाही. आपल्याकडे इथेनॉल हे बव्हंश उसापासून बनते आणि अमेरिकेत मक्यापासून. ते निघाल्यानंतर तेथे उरलेल्या चिपाडांचा उपयोग पशुखाद्य निर्मितीसाठी केला जातो. त्यात प्रथिनांचे प्रमाण लक्षणीय असते. भारतात आता त्याची अमेरिकेतून प्रचंड आयात होईल. आपल्याकडे पशुखाद्य बनते ते सोयाबीन वा सरकी यांच्यातील तेल काढून घेतल्यानंतर उरलेल्या कडब्यापासून. पण अमेरिकी पशुखाद्याच्या तुलनेत आपले पशुखाद्य दुय्यम. या करारामुळे आपल्या पशुपक्ष्यांस आता 'इम्पोर्टेड' आणि अधिक पोषक खाद्य मिळेल. ही चांगलीच बाब. मका आणि जनुकीय सुधारित वाणांतून तयार झालेल्या अन्य कृषी घटकांच्या आयातीस आपला विरोध आहे. आपल्याकडे डावे आणि उजवे हे दोघेही समसमान विज्ञानदुष्टता दर्शवतात. जनुकीय सुधारित वाणांवर त्यांचा विश्वास नाही. त्यामुळे या करारानंतरही ही जनुकीय सुधारित उत्पादने भारतीय बाजारात येणार नाहीत. पण अमेरिकेतील मका हा जनुकीय सुधारित वाणांतून बनतो. त्यापासून बनलेले हे इम्पोर्टेड पशुखाद्य भारतीय पशू/पक्षी गोड मानून घेतील. त्यांचा जनुकीय वाणांस विरोध नाही. पण याचा थेट परिणाम होईल तो सोयाबीन उत्पादकांवर. आधीच सोयाबीनचे दर हा आपल्याकडे चिंतेचा विषय. आता वर सोयाबीनची पशुखाद्य उपयुक्तताही कमी होणार. सबब सोयाबीन शेतकऱ्यांनी या कराराविरोधात तक्रारीचा सूर लावल्यास आश्चर्य नाही. युरोपप्रमाणे अमेरिकी वाईनही आता भारतात अधिक मुबलक आणि अधिक स्वस्त उपलब्ध होईल. येथील वाईन उत्पादकांची याबाबतही प्रतिक्रिया तितकीशी स्वागतार्ह नसेल. हा झाला कोणाचे काय, किती स्वस्त/महाग होणार याबाबतचा ऊहापोह.

... अमेरिकेकडून आपण पशुखाद्यही घेणार, एकंदर अमेरिकी मालाची खरेदी दुपटीहून अधिक वाढवावी लागणार, हे मुद्दे आहेतच...

परंतु ट्रम्प यांनी मांडलेले दोन मुद्दे हे या कराराच्या 'परस्पर समसमानतेविषयी' (रेसिप्रोसिटी) गंभीर प्रश्न निर्माण करतात. शनिवारच्या पत्रकार परिषदेत गोयल यांस यातील एका मुद्द्याविषयी प्रश्न विचारला गेला. हा मुद्दा म्हणजे ट्रम्प यांनी शनिवारीच पुनरुच्चार केला तो रशियन तेल खरेदी न करण्याच्या भारताने दिलेल्या वचनाचा. ''हा प्रश्न परराष्ट्रमंत्र्यांना विचारा'' असे तुटक आणि तुसडे वाटेल असे उत्तर गोयल यांनी या प्रश्नावर दिले. त्यातून काही योग्य संदेश गेला नाही. हा वाणिज्यिक मुद्दा परराष्ट्रमंत्र्यांचा कसा? त्यांना विचारले तर ते वाणिज्य मंत्रालयाकडे बोट दाखवतील. आपणास दररोज ५५-५८ लाख बॅरल खनिज तेलाची गरज असते आणि त्यापैकी ८२-८५ टक्के इतके तेल हे परदेशांतून आणावे लागते. या परदेशी तेलातील ३५ टक्के तेल आपण रशियाकडून घेतो. ती खरेदी पूर्ण बंद करणे आपणास परवडणार नाही, हे उघड आहे. 'रशियन तेल खरेदी न करण्याचे वचन आपण अजिबात दिलेले नाही', असे धडधडीत विधान आपल्या एकाही नेत्याने केलेले नाही. पण त्याच वेळी आपण हे रशियाकडील तेल यापुढेही खरेदी करत राहू, असेही आपण म्हणत नाही. 'ऊर्जा सुरक्षा आपल्यासाठी सर्वात महत्त्वाची', असे वैश्विक विधान आपले नेते या मुद्द्यावर करतात. पण ट्रम्प यांचे तसे नाही. या व्यापार कराराचा लेखी मसुदा जाहीर करताना त्यांनी भारताच्या या वचनाचा पुनरुच्चार केला. इतकेच नव्हे तर ''भारत यापुढे रशियन तेल खरेदी करणार नाही'', असे स्पष्टपणे या मसुद्यात ते नमूद करण्यात कचरत नाहीत. त्याचवेळी असे कोणतेही वचन ते आपणास देत नाहीत. म्हणजे या मुद्द्यावर भारत-अमेरिका यांच्यात 'परस्पर समानता' नाही. ही बाब इथेच संपत नाही.

ट्रम्प त्यापेक्षाही पुढे जातात आणि भारत 'शब्द दिल्यानुसार' रशियाकडून तेल खरेदी खरोखरच बंद करतो की नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी एका समितीची घोषणाही ते करतात. या समितीत फक्त अमेरिकेने नियुक्त सदस्यच असतील आणि हे सर्व भारत 'प्रत्यक्षपणे' वा 'अप्रत्यक्षपणे' रशियन तेल खरेदी करतो किंवा काय यावर 'लक्ष' ठेवतील. या समितीस काही 'आक्षेपार्ह' आढळले तर भारतास आपले म्हणणे मांडण्याची संधी असेल का, ही बाब तूर्त स्पष्ट नाही. पण भारताने या उप्पर रशियाकडून काही तेल खरेदी केलीच तर ट्रम्प हे भारतास दिलेल्या आयात करार सवलतींचा फेरविचार करतील. थोडक्यात पुन्हा भारतास 'शिक्षा' करण्याचा अधिकार ते स्वतःकडे राखून ठेवतात. पण अन्य अशा काही मुद्द्यांवर अमेरिकेस 'धडा शिकवण्याची' कोणतीही सोय भारतास नाही. म्हणजे याहीबाबत या करारात 'परस्पर समानता' दिसत नाही. तिसरा मुद्दा आहे तो ५०,००० कोटी डॉलरच्या उत्पादनांची खरेदी पाच वर्षात अमेरिकेकडून करण्याचा. वर्षाला १०,००० कोटी डॉलरची खरेदी असे हे प्रमाण. सध्या वर्षभरात आपण ४१०० कोटी डॉलर मूल्याची खरेदी अमेरिकेकडून करतो. ती आता दुपटीपेक्षा अधिक वाढवावी लागणार. हे कसे करणार? पण हा या कराराचा अंतरिम मसुदा आहे. ही समाधानाची बाब. अंतरिमचे रूपांतर अंतिम मसुद्यात होताना यात भारतासाठी लाभदायक ठरतील असे बदल होतील ही आशा. या संदर्भात दक्षिण कोरियाचे उदाहरण शहाणपणाचे. या देशाशी जाहीर झालेला अंतिम करार अध्यक्ष ट्रम्प यांनी असाच एकतर्फी रद्द केला. तेव्हा जो ट्वीटने देतो तो ट्वीटने काढूनही घेऊ शकतो, याचा विसर पडू न दिलेला बरा.

राजधानीत गोयल या कराराविषयी पत्रकार परिषद घेत असताना आर्थिक राजधानीत सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी हा करार 'भारताच्या मर्जीनुसार व्हावा' अशी रास्त अपेक्षा व्यक्त केली. पण तूर्त ट्रम्प यांचे वर्तन 'मैं चाहे ये करू, मैं चाहे वो करू... मेरी मर्जी' असे आहे. ही बाब काळजी वाटावी अशीच.

लाल किल्ला

मोदींचे ते तीन दिवस...

महेश सरलष्कर
mahesh.sarlashkar
@expressindia.com

हे दिवस अभिभाषणावरील चर्चेचे. राहुल गांधींचे आव्हान मोदींनी स्वीकारलेच नाही, हे या काळातच दिसले. लोकसभेत मोदींच्या जिवाला धोका होता, असे लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्लांना सभागृहात म्हणावे लागले आणि लोकसभेऐवजी राज्यसभेतील भाषणातून स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी मोदी काँग्रेसला दूषणे देऊ लागले...

संसदेमध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेचे तीन दिवस म्हणजे अँटी-क्लायमॅक्स होता. राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींना एकप्रकारे आव्हान दिले होते. त्यांनी असे आव्हान अनेकदा दिलेले होते आणि अशी आव्हाने मोदींनी संसदेच्या सभागृहांमध्ये परतवून लावली होती. 'मी एकटा सगळ्या विरोधकांना पुरून उरेन', असे मोदी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी लोकसभेत म्हणाले होते. राहुल गांधी मोदींना आव्हान देतात मग मोदी विरोधकांवर शाब्दिक हल्लाबोल करून त्यांच्यावर मात करतात हा अनुभव नेहमीचा. त्यामुळेच राहुल गांधींनी आता मोदींना आव्हान देऊच नये असे म्हटले जात असे. राहुल गांधी मोदींच्या हातात विनाकारण कोलीत देतात अशी चर्चा नेहमीच होत असते. पण, या वेळी राहुल गांधींचे आव्हान मोदींनी स्वीकारले नाही. एकप्रकारे मोदींनी स्वतःचा अपमान करून घेतला असे पाहायला मिळाले. संसदेतील हे तीन दिवस म्हणजे मोदींची आत्म-दया (सेल्फ पिटी) होती. अशी नामुष्की मोदींवर पंजाबमध्ये आली होती. त्या वेळी भाजपचे कार्यकर्ते पुलावर मोदींची वाट पाहात होते, त्यांना बघून मोदी मागे फिरले आणि सांगा तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना, मोदींचा जीव वाचला म्हणून, असे मोदी म्हणाले होते. तेव्हा पंजाबमध्ये काँग्रेसचे सरकार होते. तिथेही त्यांना कोणी तरी हल्ला करेल अशी भीती वाटली होती. वास्तविक ते कार्यकर्ते भाजपचे होते आणि ते मोदींच्या स्वागतासाठी आले होते. आताही लोकसभेत मोदींना जिवाची भीती वाटली. मोदी लोकसभेत सुरक्षित नसतील ते भारतात कुठे असणार?

माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाला केंद्र सरकारने परवानगी दिली नाही, कारण त्यामध्ये चिनी घुसखोरीवेळी मोदी व संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अमेरिकेमध्ये ९/११च्या हल्ल्यात न्यूयॉर्कमधील ट्विन-टॉवर उद्धवस्त केले गेले. तेव्हा तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांची केविलवाणी अवस्था झाली होती. खरे तर मोदींबाबत तितके काही झालेले नाही. पण जे योग्य वाटेल ते करा, असा मोदींचा संदेश होता. निर्णायक क्षणी देशाच्या नेतृत्वाला निर्णयच घेता येत नसेल तर काय करणार, असा हतबल करणारा सवाल जनरल नरवणे यांनी 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी'मध्ये उपस्थित केला आहे. हा मजकूर राहुल गांधी लोकसभेत वाचून दाखवण्याचा प्रयत्न करत असताना राजनाथ आणि अमित शहा वगैरे मंत्र्यांनी त्यांना रोखले. त्या वेळी मोदीही लोकसभेत होते. मोदींसमोर त्यांची पाठराखण केली नाही तर काही खरे नाही हा विचार करून या वरिष्ठ मंत्र्यांनी राहुल गांधींना विरोध केला. सर्वात मोठी कोंडी तर राजनाथ यांची झाली. ते मोदीविरोधक जरूर असतील, पण त्यांच्याही विरोधात नरवणेंनी लिहिले असल्याने मोदींचे हे मंत्री लोकसभेत हतबल झाले. मग त्यांनी राहुल गांधींना बोलू दिले नाही. राहुल गांधींनी हेका न सोडल्याने मोदींचे वरिष्ठ मंत्री एक-एक पाऊल मागे जाताना दिसले. त्यांच्या आक्रमकपणाची लक्तरे लोकसभेत निघाली. त्यावर कडी म्हणजे मोदींनी आपल्याच मंत्र्यांना आणि सदस्यांना वाऱ्यावर सोडले. मोदी लोकसभेत उत्तर देण्यासाठी आले असते तर कदाचित भाजपच्या सदस्यांना लढण्यासाठी बळ मिळाले असते, पण काँग्रेसच्या महिला खासदारांना दोष देऊन मोदींनी येणे टाळले. ही भाजपच्या सदस्यांसाठी धक्कादायक बाब ठरली. एरवी हेच सदस्य मोदींचा सभागृहात जयघोष करत असतात. मोदींनी लोकसभेकडे पाठ फिरवण्यापूर्वी भाजपच्या सदस्यांनी 'मोदी-मोदी'चा जयघोष केला होता.

मोदींची लोकसभेमध्ये न येण्याची कृती 'एनडीए'च्या घटक पक्षांतील खासदारांमध्ये चुकीचा संदेश देऊन गेली. 'आम्ही असतो तर मोदींचे भाषण करून दाखवले असते', ही 'एनडीए'मधील घटक पक्षांच्या खासदारांची प्रतिक्रिया बोलकी म्हणता येईल. लोकसभेत मोदींच्या जिवाला धोका होता, असे लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्लांनी सभागृहात म्हणणे म्हणजे केंद्र सरकारचा पराभव ठरतो. संसदेमध्ये आत्ताच्या घडीला इतकी प्रचंड सुरक्षाव्यवस्था तैनात आहे की, मोदींच्या जिवाला धोका असे म्हणणे निव्वळ हास्यास्पद आहे. सभागृहामध्ये कुठल्याही सदस्याच्या हातात काठी-लाठी, हत्यार काहीही नसते. काँग्रेसच्या महिला खासदारांनी मोठा फलक आणला होता हे खरे आणि त्या मोदींच्या आसनाभोवती गोळा झाल्या होत्या हेही खरे, पण महिला खासदारांनी मोदींना अपाय केला असता, असे सूचित करणे हा मूर्खपणा ठरतो. मोदी सभागृहात आले असते तर त्यांच्या सुरक्षेसाठी मार्शल आले असते. त्यांनी काँग्रेसच्या महिला खासदारांना रोखले असते. आक्रमक झालेल्या महिला खासदारांना सभागृहाबाहेर काढता आले असते. शिवाय, महिला खासदारांकडे खरेच इतकी ताकद होती की, त्यांनी मोदींचे बरे-वाईट केले असते, हा प्रश्न बिर्लांनी स्वतःला विचाराला हवा होता. मोदी सभागृहात असते तर त्यांना भाषण करण्यापासून कोणीही रोखले नसते. मोदींना मागच्या बाकांवरून भाषण करता आले असते. मोदींच्या मंत्र्यांनीच हा पर्याय शोधून काढलेला आहे. अनेकदा विरोधक गोंधळ करतात तेव्हा मंत्री मागच्या बाकांवरून भाषण करतात. 'रामजी' विधेयक संमत करताना केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी हाच मार्ग काढला होता. मोदींनाही तसे करता आले असते.

अशा वेळी त्यांच्याभोवती हट्टेकट्टे भाजपचे खासदार बसले असते तरी मोदी सुरक्षित राहिले असते. तिथेपर्यंत तरी काँग्रेसच्या महिला खासदारांना पोहोचता आले नसते. शिवाय, शिस्तभंगाची कारवाई तातडीने करून त्यांना सभागृहाबाहेर काढता आले असते. मग, निर्धास्तपणे मोदींना आपल्या भाषणात राहुल गांधींच्या आरोपांच्या चिंधड्या उडवता आल्या असत्या. हे मोदींनी केले नाही. त्यामुळे जनरल नरवणे चिनी घुसखोरीनंतर मोदींच्या निर्णयक्षमतेवर शंका घेत असतील तर त्यामध्ये काही चुकीचे नाही असे दिसते. जनरल नरवणेंचे मोदींबद्दलचे निरीक्षण अचूक असल्यानेच त्यांच्या पुस्तकाला केंद्र सरकारने परवानगी दिली नसावी!

राज्यसभेत मोदींनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या चर्चेला उत्तर दिले खरे, पण बूँद से गई, वो हौद से नही आती, असे म्हणतात तसा हा प्रकार होता. मोदींनी राज्यसभेत 'मी एकटा पुरेसा आहे', असे कितीही वेळा म्हटले तरी त्यांच्या भाषणातील आवेश कधीच निघून गेला होता. मोदींनी काँग्रेसला, पं. नेहरूंना लाखोल्या वाहिल्या. तसे ते नेहमीच करतात, त्यामुळे त्या आरोपांमध्ये काही नावीन्य नव्हते. मोदींचे समर्थक आणि भाजपचे पाठीराखे यांनाही मोदींची काँग्रेसविरोधी भाषा पाठ झाली आहे. राज्यसभेत मोदींनी राहुल गांधींच्या आरोपांना उत्तर देण्याचे धाडस केले नाही. त्यांनी ना चीनचा उल्लेख केला, ना नरवणेंच्या पुस्तकाचा. आताशा मोदींच्या भाषणांमध्ये वा केंद्रीयमंत्र्यांकडून देखील चीनचा उल्लेख होत नाही. राज्यसभेतही तो झाला नाही, हे पराभूत मनोवृत्तीचे लक्षण मानायचे काय? चीन सोडून मोदींनी नाहक आदिवासी महिला, दलित आणि शीख असे सगळे मुद्दे उपस्थित करून काँग्रेस कसा या समूहांच्या विरोधात आहे असे ठसवण्याचा प्रयत्न केला, पण हा मुद्दादेखील फारसा उचलला गेला नाही. केंद्रीय मंत्री रवनीतसिंग बिट्टू हे काँग्रेसचे नेते होते, त्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला. ही गद्दारी असल्याचे राहुल गांधींचे म्हणणे होते. त्याचा बिट्टू शीख असल्याशी काहीही संबंध नव्हता. शिवाय, राहुल गांधींनी राष्ट्रपतींबद्दल कोणतेही अपशब्द काढले नाहीत. ना दलित सदस्यांबद्दल कुठल्या काँग्रेसच्या सदस्यांनी टिप्पणी केली. असे विनाकारण आरोप करणे म्हणजे मोदींनी यावेळचा लोकसभेतील डाव हरल्याची कबुली होती. पं. नेहरूंबद्दल बीभत्स बोलत राहणे हा भाजपच्या सदस्यांचा पॅटर्न झालेला आहे. निशिकांत दुबेंना पं. नेहरूंवर टीका करण्याचा आदेश दिला गेला असेल. त्यामुळे ते बोलले. पण त्यांची लोकसभेतच काँग्रेसच्या महिला खासदारांनी पळता भुई थोडी कशी केली हे पत्रकार कक्षात उपस्थित तमाम पत्रकारांनी पाहिले. लोकसभेत लॉबीतूनही दुबेंना पळून जावे लागले हेही पाहिले. जनरल नरवणेंच्या पुस्तकावरून मोदी-राजनाथ यांनी विनाकारण वाद ओढवून घेतला आणि त्यात ते स्वतः पडले. त्यातून त्यांना बाहेर कसे पडावे हे कळलेच नाही. राज्यसभेतील भाषणातून स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न मोदींनी जरूर केला, पण त्यातून काहीच साध्य झाले नाही. संसदेच्या आवारात राहुल गांधी मात्र जनरल नरवणेंच्या पुस्तकाची प्रत घेऊन फिरत होते, त्यातून राहुल गांधी मोदींविरोधातील आरोप अधोरेखित करत होते. हे सगळे उघडपणे सुरू असताना भाजपला फक्त हात चोळत बसण्याशिवाय काहीही करता आले नाही हेच खरे.

अन्वयार्थ

स्वयंघोषित 'जिहादी जनरल'ची नामुष्की

बलुचिस्तान प्रांतात अनेक ठिकाणी बलोच बंडखोरांकडून सुरू झालेल्या हल्ल्यांना तोंड देताना हतबल झालेल्या पाकिस्तानी लष्करशाही आणि सरकारसाठी, राजधानी इस्लामाबादमध्ये एका शिया मशिदीत झालेला भीषण बॉम्बस्फोट हा आणखी एक हादरा ठरला. बलुचिस्तानमधील हल्ल्यांबद्दल भारताकडे बोट दाखवण्याची पळवाट तरी होती. पण इस्लामाबादच्या स्फोटाबद्दल कुणाला जबाबदार धरणार हा प्रश्नच. बलुचिस्तान व खैबर पख्तुनख्वा या सीमावर्ती प्रांतांमध्ये राजरोस हल्ले होत आहेत. ते दहशतवादी हल्ले आहेत असे सांगून शाहबाझ शरीफ सरकार कारवाया तीव्र करत आहे. त्याचा काहीही उपयोग होताना दिसत नाही. खैबर पख्तुनख्वा प्रांताच्या अफगाणिस्तान सीमावर्ती भागांत तेहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) या संघटनेने सातत्याने हल्ले सुरू ठेवले आहेत. या संघटनेला अफगाण तालिबान राजवटीचा पाठिंबा असल्याचे पाकिस्तान सरकारचे म्हणणे. म्हणजे बलुचिस्तानमधील अस्थैर्यासाठी भारत जबाबदार, तर खैबर पख्तुनख्वा अस्थिर करण्यास अफगाणिस्तान तालिबानचा हातभार. या आरोपांतून पाकिस्तान सरकार व लष्कर जबाबदारी झटकत राहतात. मुळात तालिबान काय किंवा तेहरीके तालिबान काय, ही पाकिस्ताननेच जन्माला घातलेली विखारी पिलावळ.

धर्माधारित दहशतवाद पोसण्याची सवय लागली, की त्याचा वापर केवळ आपल्या शत्रूंविरुद्धच करता येईल ही गफलत पाकिस्तानचे लष्करी आणि राजकीय नेतृत्व वर्षानुवर्षे करत राहिले. मध्यंतरी या बाबतीत थोडे काही शहाणपण तेथे झिरपते आहे असे वाटत असतानाच सय्यद असिम मुनीर यांचा उदय झाला. त्यांनी पाकिस्तानी लष्कराचे जिहादीकरण, पराकोटीचा भारतद्वेष आणि राजकीय नेतृत्वाचे सातत्याने खच्चीकरण ही त्रिसूत्री अवलंबली ज्यातून पाकिस्तानी व्यवस्थेचे दिवसागणिक मातेरे होत चाललेले दिसते. अमेरिकेचे लहरी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर मुजरे केल्यामुळे त्यांची मर्जी जिंकल्याच्या आविर्भावात 'मुनीरशहा' आणि राजीखुशीने त्यांच्या हातातील बाहुले बनलेले पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ वावरत होते. या काळात ट्रम्प यांच्या टॅरिफशाहीचे चटके भारताला बसत असल्यामुळे या दुकलीला आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या. पण ट्रम्प यांचे वायदे पोकळ असतात, त्यांना देण्यापेक्षा समोरच्याकडून काढून घेण्यातच रस असतो आणि 'मित्रां'साठी त्यांची दोस्ती अखेर मगरमिठीच ठरते, याची प्रचीती पाकिस्तानला येऊ लागली आहे. भारतावरील आयात शुल्कात मोठी कपात करून ट्रम्प यांनी मैत्रीची फेरआखणी केली. त्याआधी भारताशी युरोपीय महासंघाने व्यापार करार करून त्या मोठ्या बाजारपेठेतील भारतीय वस्तुमाल निर्यात छोट्या आशियाई देशांच्या तुलनेत अधिक फायदेशीर ठरवली. धार्मिक विद्वेष व राजकीय दडपशाहीवर पोसलेल्या पाकिस्तानी लष्करशाही आणि विदूषकी सरकारने तेथील मोडकळलेल्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणेचे कसलेच प्रयत्न केलेले नाहीत. महागाई, टंचाई व दरवर्षी निसर्गापत्तीच्या तडाख्यांनी ग्रासलेल्या तेथील जनतेचा असंतोष त्यामुळेच वारंवार उफाळून येतो . बलुचिस्तान व खैबर पख्तुनख्वा प्रांतांते हेच दिसून येते.

या समस्येवर पाकिस्तान जितक्यांदा इतर देशांकडे बोट दाखवत राहील, तितकी ही समस्या चिघळत जाईल. बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचा सर्वांत मोठा प्रांत आणि सर्वाधिक संसाधनसमृद्ध. पण वर्षानुवर्षे पंजाबी राज्यकर्ते व लष्करशहांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे मागास राहिलेला. आधी या प्रांतामध्ये पायाभूत सुविधांची कामे करण्यासाठी चिनी कंपन्यांना कंत्राटे दिली गेली. आता तेथून सोने व इतर खनिजे खणून काढण्यासाठी अमेरिकी गुंतवणूक येत आहे. पण चीन असो वा अमेरिका, त्यांच्या येण्याने स्थानिकांच्या आयुष्यात कोणताही फरक पडणार नाही हे कळून चुकल्यामुळेच गेल्या १०-१५ वर्षांत बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) आणि इतर संघटनांकडून पाकिस्तानी सरकार आणि चिनी आस्थापनांवर हल्ले सुरू झाले. जोवर बलुचिस्तान प्रांतात सर्वांगीण आणि स्थानिक समावेश विकास होत नाही, तोवर तेथे असंतोष राहणारच. पण तेथील जनतेला फुटीरतावादी ठरवणे आणि भारतीय हस्तक्षेपाचा बागुलबुवा उभा करणे असा खेळ पाकिस्तान सरकार खेळत आहे. तो त्यांच्यावरच उलटू लागला आहे. 'बीएलए'ने जानेवारीच्या अखेरीस बलुचिस्तानच्या १२ जिल्ह्यांत ४० ठिकाणी सुनियोजित हल्ले केले. क्वेटा या राजधानीच्या शहरालाही लक्ष्य केले. हा प्रतिकार मोडून काढण्यात पाकिस्तानी लष्काराला अजूनही यश आलेले नाही. दोन वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारे हल्ला करण्यात आला. रेल्वेगाडीचे अपहरणही गेल्या वर्षी करण्यात आले. कधी बलुचिस्तान, कधी खैबर पख्तुनख्वा, कधी इस्लामाबाद अशा विविध ठिकाणी होत असलेले हल्ले युद्धखोर पाकिस्तानची दैना दर्शवतात. स्वयंघोषित जिहादी जनरलच्या अमदानीत ते होणे हे तर आणखीच नामुष्कीजनक.

विश्लेषण

सौर कृषिपंपाच्या समस्या कशा सुटणार?

मोहन अटाळकर
mohan. atalkar@expressindia. com

'मागेल त्याला सौर कृषिपंप' योजनेत महाराष्ट्राने आघाडी घेतली; पण अनेक भागांतील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अडचणीची ठरू लागली आहे...

'मागेल त्याला सौर पंप' योजना काय?

शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज उपलब्ध व्हावी, या हेतूने राज्य सरकारने 'मागेल त्याला सौर पंप' योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतीच्या क्षेत्रानुसार ३,५ आणि ७.५ अश्वशक्ती (एचपी) क्षमतेचे पंप दिले जात आहेत. १२ मे २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार लाभार्थी निवडीच्या निकषानुसार, शेतकऱ्याकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रानुसार त्याला अनुदानावर मिळणाऱ्या पंपाची क्षमता ठरते. २.५ एकरपर्यंत भूधारणा असेल, तर ३ अश्वशक्ती क्षमतेचा, २.५१ ते ५ एकर भूधारणा असेल, तर ५ अश्वशक्ती; तर ५ एकरहून जास्त भूधारणेसाठी ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषिपंप शेतकऱ्याला मिळतो. या योजनेत शेतकऱ्यांना 'प्रधानमंत्री कुसुम' योजनेतून केंद्र सरकारकडून ३० टक्के तर राज्य सरकारकडून ६० टक्के अनुदान मिळते. त्यामुळे केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सिंचनासाठी कृषिपंपासह संपूर्ण संच मिळतो. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना केवळ ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा लागतो.

किती कृषिपंपांचे विद्युतीकरण झाले?

राज्यात २०२५ अखेर सुमारे ५० लाख कृषिपंपांचे विद्युतीकरण झालेले आहे. पण, अद्याप कृषिपंपांच्या विद्युतीकरणाचा अनुशेष आहे. या पार्श्वभूमीवर २०२० पासून 'प्रधानमंत्री कुसुम' योजना सुरू झाली. राज्यासाठी ५.०५ लाख ऑफ-ग्रिड स्वतंत्र सौर कृषिपंप मंजूर झाले आहेत. यापैकी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास संस्थेला २.५५ लाख तर महावितरणला २.५० लाख सौर कृषिपंप मंजूर करण्यात आले. सुमारे ७ लाख २७ हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला आहे. शेतकऱ्यांसाठी १६ हजार मेगावॉट स्वतंत्र सौर वीजनिर्मिती केली जात आहे.

सरकारचे धोरण काय?

शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी सध्या सौर कृषिपंपांना अधिक प्रोत्साहन व सवलती देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. ही हरित ऊर्जा स्वस्त असून पंप दिवसभरात कधीही वापरता येईल. या योजनेत साडेआठ लाख शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंप देण्यात येतील. त्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकार देणार आहे. आताही सौर कृषिपंप योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांचा १० टक्के हिस्सा भरावा लागतो, मात्र त्यातून वीज मोफत उपलब्ध होईल, असे सांगण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांच्या अडचणी कोणत्या?

सौर कृषिपंपांसाठी मागणी नोंदवल्यानंतर मंजुरीसाठी वर्षभर प्रतीक्षा करावी लागते. सौर कृषिपंप कंपन्या शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून आमच्याच कंपनीच्या पंपाची निवड करण्याचा आग्रह धरतात. अनेक पात्र शेतकऱ्यांची निवड झाल्यानंतरही महाऊर्जा किंवा महावितरणकडून लाभार्थींना वेळेवर संदेश प्राप्त होत नाहीत. उपलब्ध कोटा असलेल्या कंपन्यांपैकी एका कंपनीचीच निवड करावी लागते. पंप, पंपाचा आकार, सौर यंत्राची क्षमता, हेडचा आकार, दिवसभरात पाणी उपसण्याची क्षमता याची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. संयत्राचा वापर पाणी उपसा करण्यासाठी केला जात नाही, अशा वेळी शेतकऱ्यांना घरगुती वापरासाठी वीजनिर्मितीची कुठलीही सुविधा उपलब्ध होत नाही, असे अनेक प्रश्न आहेत.

विदर्भातील शेतकऱ्यांची मागणी काय?

माकडांच्या उपद्रवामुळे सोलर प्लेट्स फुटण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे यंत्रणा नादुरुस्त होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. ढगाळ वातावरण निर्माण होताच सौर कृषीपंप बंद पडतात. दुरुस्तीसाठी शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक बोजा पडतोच पण परिणामी, ऐन हंगामात पिकांचे ओलीत करणे कठीण होते. अनेक भागांत शेती पंपांसाठी नव्या वीजजोडण्या देण्यास वीज वितरण कंपनी नकार देत असून शेतीसाठी सौर ऊर्जा योजनेची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. विदर्भातील शेतशिवारात वन्यप्राण्यांचा हैदोस आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे सौर कृषिपंप योजना अनेक भागांतील शेतकऱ्यांसाठी गैरसोयीची ठरली आहे. ज्या विदर्भाने राज्याला वीज दिली, औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी जमिनी दिल्या, त्याच भागातील शेतकऱ्यांना नियमित वीजपुरवठा नाकारला जाणे दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. सौर कृषिपंप योजना ऐच्छिक असावी आणि मागेल त्याला शेतीसाठी वीज कनेक्शन उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी आहे.

पर्यटन लाटेवर स्वार ‘द ताज’

माझा पोर्टफोलिओ

अजय वाळिंबे

वर्ष १९०३ मध्ये स्थापन झालेली इंडियन हॉटेल्स दक्षिण आशियातील हॉटेल्सची सर्वात मोठी साखळी चालवते. कंपनी तिच्या उपकंपन्या आणि सहयोगी कंपन्या ‘ताज हॉटेल्स रिसॉर्ट्स अँड पॅलेसेस’ या प्रमुख नाममुद्रेने ओळखल्या जातात, ज्यांच्याकडे ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत, जगभरात चार खंड, १४ देश आणि २०० हून अधिक ठिकाणी २८,००० हून अधिक खोल्यांची क्षमता असलेली २६८ कार्यरत हॉटेल आहेत. यामध्ये भारत, उत्तर अमेरिका, इंग्लंड, आफ्रिका, आखाती देश, मलेशिया, श्रीलंका, मालदीव, भूतान आणि नेपाळमधील उपस्थितीचा समावेश आहे. इंडियन हॉटेल आपल्या ताज हॉटेल्स रिसॉर्ट्स अँड पॅलेसेस, विवांता, सिलेक्टशन्स, जिंजर, गेटवे, एएमए आणि ट्री ऑफ लाइफ या नाममुद्रांच्या माध्यमातून बाजारातील लक्झरी, अपस्केल आणि व्हॅल्यू या सर्व विभागांमध्ये उपस्थित आहे. या समूहाची विमान केटरिंग, स्पा, वन्यजीव लॉज आणि सर्व्हिस अपार्टमेंट या क्षेत्रांमध्येही उपस्थिती आहे.

हॉटेल पोर्टफोलिओ

कंपनीकडे ५७,००० हून अधिक खोल्यांसह ५७० कार्यरत हॉटेल आहेत. तसेच, कंपनीने आणखी ९२ हॉटेल उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी काही हॉटेलचे काम सुरू झाले आहे, यामध्ये सर्व मिळून १२,९५३ खोल्यांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये ताज (२६ हॉटेल्स, ४६११ खोल्या), विवांता (२७ हॉटेल्स, ३,७९७ खोल्या), सिलेक्टशन्स (१३ हॉटेल्स, १,५१८ खोल्या) आणि जिंजर (२६ हॉटेल्स, ३,०२७ खोल्या) या पोर्टफोलिओमध्ये वाढ होत आहे.

हॉटेल ब्रँड्स आणि ब्रँड मूल्य

कंपनी विविध विभागांना सेवा देणाऱ्या लक्झरी ताज, अपस्केल/अपर अपस्केल विवांता/सिलेक्टशन्स आणि मिडस्केल/लीन लक्झरी जिंजर विभाग या चार मुख्य ब्रँड्सअंतर्गत आपली हॉटेल्स चालवते.

कंपनी अपस्केल विभागातील ‘गेटवे’ या पूर्ण-सेवा हॉटेलची आवृत्तीदेखील सादर करणार आहे, जी महानगरे आणि टियर-२ व टियर-३ शहरांमधील उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील वाढीच्या संधीचा फायदा घेईल. १५ हॉटेल्सपासून सुरू होणारा हा प्रवास रोल-आउट बेकल आणि नाशिक येथील उद्घाटनाने सुरू झाला आणि आता बंगळूर, ठाणे आणि जयपूर यांसारख्या ठिकाणी विस्तार केला जात आहे. ही नाममुद्रा २०३० पर्यंत १०० हॉटेल्सच्या पोर्टफोलिओपर्यंत पोहोचेल. सुमारे १२० वर्षांहून अधिक जुना वारसा असलेली आणि बाजारातील नवीनतम बदलांना सामोरे जाणारी ‘ताज’ ही जागतिक स्तरावरील एक सुप्रसिद्ध हॉटेल ब्रँड आहे. ब्रँड फायनान्सच्या २०२४ च्या अहवालानुसार, ताजला ‘जगातील सर्वात मजबूत हॉटेल ब्रँड’ म्हणून मानांकन देण्यात आले. देशांतर्गत बाजारपेठेत, ताज हे आलिशानतेचे प्रतीक आहे, जे ‘द ताजमहाल पॅलेस अँड टॉवर, मुंबई’, ‘ताज लेक पॅलेस, उदयपूर’, ‘ताज फलकनुमा पॅलेस, हैदराबाद’ आणि ‘ताज मानसिंग, दिल्ली’ यांसारख्या प्रतिष्ठित मालमत्तांचे व्यवस्थापन करते. ‘ताज’ नाममुद्रेअंतर्गत असलेल्या मालमत्ता ऐतिहासिक राजवाडे/उच्च-श्रेणीच्या आलिशान मालमत्ता आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून कंपनी आलिशान आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना लक्ष्य करते. कंपनीने गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येक नाममुद्रेची आणि त्यांच्या मूल्य प्रस्तावांची स्पष्ट विभागणी करून, मागे पडलेल्या इतर नाममुद्रांना मजबूत केले आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत, कंपनीकडे भारत आणि परदेशात एकूण २०० हून अधिक ठिकाणी, ‘ताज’, ‘विवंता’, ‘सिलेक्टशन्स’, ‘जिंजर’, ‘गेटवे’, ‘अमा’ आणि ‘ट्री ऑफ लाइफ’ या नाममुद्रेअंतर्गत २६८ कार्यरत हॉटेल आणि २८,००० हून अधिक कार्यरत खोल्या आहेत.

साहाय्यक व्यवसाय

क्यूमिन - हे एक गॉरमेट (Gourmet) डिलिव्हरी मंच आहे, जे क्यूमिन शॉप, क्यूमिन ट्रक आणि क्यूमिन कॅफे यांसारख्या मंचाद्वारे विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ, मल्टी-फिस्ट मेनू आणि इतर सेवा देते. कंपनी क्यूमिनला जिंजरसोबत संरेखित करत आहे.

अमा – खासगी बंगले आणि व्हिला, यामध्ये १७५ कार्यरत मालमत्ता असून, १७४ मालमत्तांचे नूतनीकरण चालू आहे.

ताज सॅट्स - ताज सॅट्स हा ताज आणि सॅट्स लिमिटेड यांच्यातील एक संयुक्त उपक्रम आहे. आज ६० टक्के बाजारातील हिश्शासह ताज सॅट्स एअरलाइन केटरिंगमध्ये बाजारपेठेतील अग्रणी आहे.

भांडवली खर्च

आर्थिक वर्ष २०२५ ते २०२७ साठी सुमारे २५०० कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाची योजना आहे. ताज महाल-नवी दिल्ली, ताज लँड्स एंड-मुंबई, सेंट जेम्स कोर्ट-लंडन आणि उषा किरण पॅलेस-ग्वाल्हेर येथे नूतनीकरणाची कामे पूर्ण झाली आहेत आणि सुरू आहेत.

कंपनीने नोव्हेंबर महिन्यात मुळशी येथील रिसॉर्टमध्ये सुमारे २५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून ५१ टक्के हिस्सा ताब्यात घेतला आहे, तर नुकताच आपल्या उपकंपन्यामार्फत ब्रिज हॉस्पिटलिटीबरोबर करार करून सुमारे २२ हॉटेल्सचा पोर्टफोलियो ताब्यात घेतला आहे. याकरिता सुमारे २२५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

दुसऱ्या तिमाहीत कंपनीने २,१२४ कोटी रुपयांच्या उलाढालीवर २८५ कोटी रुपयांचा नक्त नफा कमवला आहे. तर सहामाहीत २१ टक्के वाढ साधून ४,०८२ कोटी रुपयांच्या उलाढालीवर ५८१ कोटी रुपयांचा नक्त नफा कमावला आहे. गेल्या वर्षातील सहामाहीच्या तुलनेत तो १७ टक्के अधिक आहे. उत्तम व्यवस्थापन, चालू असलेले विस्तारीकरण प्रकल्प आणि उत्तम नाममुद्रा यामुळे इंडियन हॉटेल्सचे भवितव्य उज्ज्वल वाटते. सध्या नीचांकी पातळीवर उपलब्ध असलेला हा शेअर तुम्हाला दीर्घकाळात उत्तम फायदा देऊ शकेल. कंपनीचे तिसऱ्या तिमाहीचे आर्थिक निष्कर्ष १२ फेब्रुवारीला जाहीर होतील. निकाल बघून शेअर खरेदीचा निर्णय घेता येईल.

शेअरबाजारातील अनिश्चितता पाहता हा शेअर सुचवलेल्या किमतीपेक्षा कमी भावात मिळू शकतो, म्हणून प्रत्येक मंदीत तसेच टप्प्याटप्प्याने शेअर खरेदीचे धोरण ठेवावे.

माझा पोर्टफोलियो अंतर्गत सुचवलेल्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये लेखकाची वा त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांची (उपलब्ध माहितीप्रमाणे) कुठलीही गुंतवणूक नाही किंवा असल्यास ती कंपनीच्या भरणा झालेल्या भाग भांडवलाच्या १% पेक्षा कमी आहे. तसेच सुचवलेल्या कंपनीशी लेखकाचा कुठलाही संबंध नसून त्याने कंपनीकडून कुठलेही मानधन अथवा भेटवस्तू घेतलेली नाही.

इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड (बीएसई कोड -५००८५०)

शुक्रवारचा बंद भाव :
रु. ६८३/-

वर्षभरातील उच्चांक/ नीचांक :
रु. ८५९/६२७

बाजार भांडवल : **रु. ९७,२९९ कोटी**

भरणा झालेले भागभांडवल
१४२.३४ कोटी

शेअर होल्डिंग पॅटर्न (%)

प्रवर्तक	३८.१२
परदेशी गुंतवणूकदार	२६.१४
बँका/ म्यु. फंड/ सरकार	१९.५३
इतर/ जनता	१६.२०
डेट इक्विटी गुणोत्तर	०.२८%

वेबसाइट: www.ihcltata.com

संक्षिप्त विवरण

- शेअर गट : लार्ज कॅप
- प्रवर्तक : टाटा समूह
- व्यवसाय क्षेत्र : आदरातिथ्यसेवा / हॉटेल्स
- पुस्तकी मूल्य : रु. ८९.३
- दर्शनी मूल्य : रु. १/-
- गतवर्षीचा लाभांश : २२५%

शेअर शिफारशीचे निकष

- प्रति समभाग उत्पन्न : ११.८४ रु.
- पी/ई गुणोत्तर : ५७.६
- समग्र पी/ई गुणोत्तर : ३१.२
- इंटरेस्ट कव्हरेज गुणोत्तर : १२.३
- बीटा : १.४
- गुंतवणूक कालावधी : २४ महिने
- रिटर्न ऑन कॅपिटल एम्प्लॉइड : १७.२%

सोळावं वरीस धोक्याचं

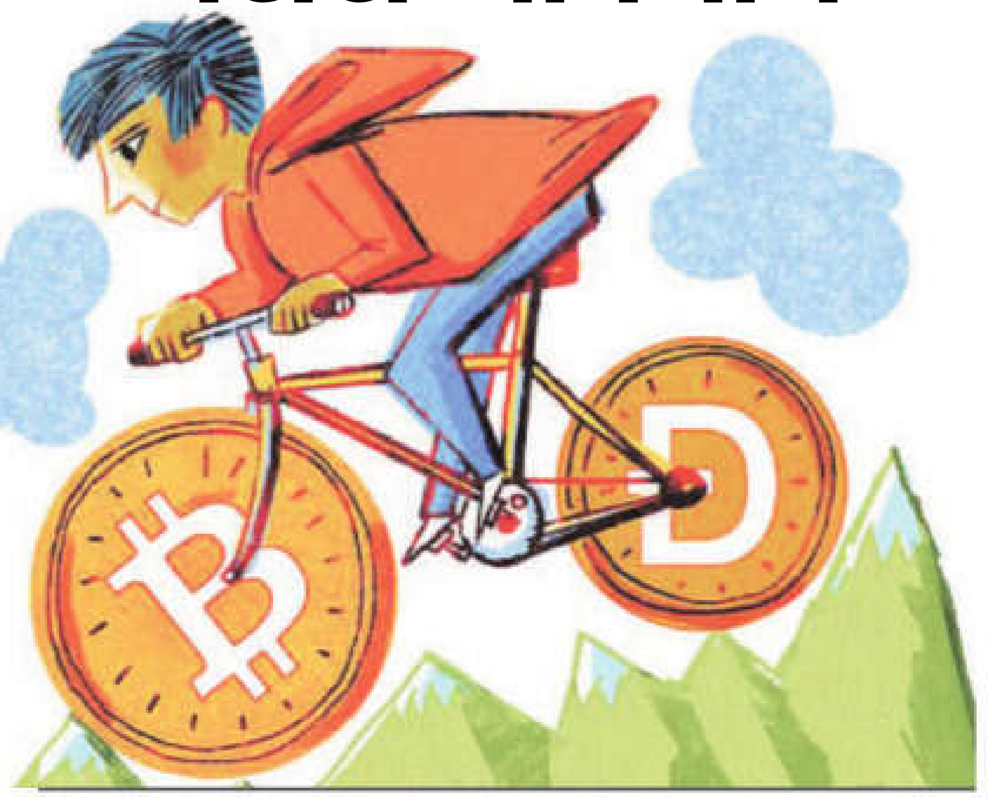

आहे आभासी तरी

डॉ. अजित जोशी

कायद्याच्या सज्ञानतेच वय जरी अठरा असलं तरी आपल्याकडे पहिल्यापासूनच सोळावं वर्ष म्हणजे महत्त्वाचं वळण मानलं जातं. वर्ष २०१० सालचा पहिला व्यवहार लक्षात घेतला तर हे चलन आता सोळाव्या वर्षात पोचलेल आहे आणि पहिल्या दोन महिन्यातच सोळाव्या वर्षाचे झटके आभासी (क्रिप्टो) चलनाने दिले. अवघ्या दहा-बारा दिवसांच्या अवधीत तमाम चलनांची किंमत अर्ध्यावर आली. गुंतवणूकदारांचे जवळपास दोन लाख कोटी डॉलर एवढं नुकसान झाले. या चलनामध्ये काही अर्थ आहे का? हे नुसतच तंत्रज्ञानाचं ‘फॅड’ आहे. फक्त गुन्हेगारी प्रवृत्तीसाठी वापरली जाणारी संसाधन आहे. या चर्चांना आणि क्रिप्टो चलनाच्या मृत्यूच्या भविष्यवाण्यांना जोर आला. खरं सांगायचं तर सत्य अतिशय वेगळं आणि याच्याबरोबर उलट आहे.

पण या खळबळजनक घटनांकडे जाण्याआधी क्षणभर थांबू. गेल्या दोन भागात आपण क्रिप्टो संकल्पनेची मूळ, त्याच्या मागची रचना, त्यामुळे त्या चलनाने मिळवलेलं महत्त्वाचं स्थान, यावर खूप चर्चा केली. त्यातूनही सगळं काही उमगेल असं नाही. कारण कल्पना हेच चलन ही एक अभिनव रचना, या संपूर्ण आर्थिक गणिताच्या मागे आहे आणि त्यामुळे जसं हे या चलनाचे बलस्थान आहे तसाच कच्चा दुवा सुद्धा. ‘चलनाचं एकमेव काम हे वस्तू आणि सेवांच्या देवाण- घेवाणीत माध्यम हे आहे आणि त्यामुळे चलनाचे मूल्य हे फक्त वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनांमधूनच किंवा संपत्तीच्या उपलब्धतेतून निश्चित व्हायला हवं’ हा चलन या संकल्पनेचा मूलभूत पाया आहे. अनेक वर्षांच्या सरकार पुरस्कृत कागदी नोटांनी तो अगदी खिळखिळा केलेला आहे. आणि त्यामुळेच हे चलन समजणं थोडं कठीण होतं. पण गोंधळात पडल्यावर वर उल्लेखलेल्या मूळ तत्त्वांकडे परत परत गेल्यामुळे नक्कीच या संकल्पना समजणं सोपं होईल.

तर या बाजाराच्या चालू घडामोडींकडे परत जाताना प्रश्न असा येतो की, अवघ्या काही दिवसात या चलनांच्या बाजारात एवढा भूकंप कशामुळे घडला. पण या प्रश्नाचे उत्तर क्रिप्टो चलनात नाही. २० जानेवारीला जपानचा कर्जरोखे बाजार संकटात सापडला. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अडीच पट कर्ज पोहोचलं. कर्ज जेवढे धोक्याचं, तेवढा त्याचा व्याजदर अधिक हा वित्तशास्त्राचा मूलभूत नियम आहे. त्यामुळे तिथला व्याजदर ३.९१ टक्क्यांएवढा गगनाला भिडला आहे. तशात ३० जानेवारीला केविन वॉर्श या वाढत्या व्याजदरांचा समर्थक मानल्या गेलेल्या अर्थतज्ज्ञाची शिफारिश फेडरल रिझर्व्ह म्हणजेच अमेरिकेतल्या मध्यवर्ती बँकेच्या प्रमुख पदासाठी झाली. त्यामुळे जगभरातल्या भांडवली बाजारात व्याजदर वाढायला लागले. पण कर्जातला धोका वाढला तरी इतर अनेक गुंतवणुकांमध्ये त्याहून अधिक जोखीम असते. साहजिकच जेव्हा कर्जरोख्यांवरचे दर वाढतात तेव्हा जोखमीच्या गुंतवणुकीतील पैसे काढून ते झपाट्याने कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवले जातात. वेगवेगळ्या बाजारातल्या जोखमीना सांभाळून घेणारे हेज फंड, जगातल्या बचती किंवा निवृत्ती वेतन (पेन्शन) यांचे निधी, एखादी मालमत्ता थेट घेण्याऐवजी कागदी हुंड्यांच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना उपलब्ध करून देणारी ‘ईटीएफ’ किंवा भांडवल बाजारात सामान्यांचा पैसा आणणारे म्युच्युअल फंड असे अनेक संस्थात्मक गुंतवणुकीचे अनेक प्रकार आहेत. आधुनिक भांडवल बाजारात कर्जरोखे, सरकारी रोखे, मौल्यवान धातू, धान्य किंवा शेअर बाजार हे वेगवेगळे मालमत्तेचे प्रकार, या अवाढव्य अशा गुंतवणूक निधींच्या माध्यमातून एकमेकांशी जोडले गेलेले असतात. यातल्या कुठल्याही एका बाजारात झालेल्या उलथा पालथीमुळे आपोआप बाकीचे बाजार हादरतात. गेल्या पंधरा दिवसात, वर उल्लेखलेल्या घटनांमुळे जगभरातल्या बलाढ्य संस्थागत गुंतवणूकदारांच्या निधीचा ओघ अधिक जोखीम असलेल्या मालमत्तांकडून कर्जरोखे स्वरूपातल्या मालमत्तांकडे वहायला लागला.

एखादा वणवा पसरावा त्याप्रमाणे जोखीम अधिक असलेल्य मालमत्तांच्या किमती घसरायला सुरुवात झाली. यात सोन्या-चांदीच्या घसरल्या, जगभरातले शेअर बाजार घसरले, तसाच फटका क्रिप्टो चलनालाही बसला. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आतापर्यंत असं मानलं जात होतं की, कृत्रिम प्रज्ञा अर्थात ‘एआय’ तंत्रज्ञानामुळे मोठ्या प्रमाणावर सॉफ्टवेअर क्षेत्राचा फायदा होईल आणि त्यामुळे पश्चिमात्य देशातील आयटी कंपन्यांच्या किमती वाढत होत्या. गूगल किंवा ॲमेझॉनयासारख्या उद्योगांनी जवळपास २०० कोटी डॉलरच्या आसपास अवाढव्य भांडवली रकमा नवीन तंत्रज्ञानात गुंतवायच्या ठरवलेले होत्या. एका बाजूला प्रश्न असा होता की, एवढ्या प्रचंड गुंतवणुकीचा मोबदला कधी मिळणार? पण तशात ४ फेब्रुवारीला अत्याधुनिक ‘एआय’वर आधारित ‘अँथ्रॉपिक’ या नवउद्यमीची (स्टार्टअप) घोषणा झाली. तंत्रज्ञान अशा टप्प्यावर यायला लागलं की, मोठ्या आयटी कंपन्यांना फायदा होण्याऐवजी त्या कदाचित अनावश्यकच होऊन जातील का काय अशी भीती निर्माण झाली. त्यांचे शेअर आपटायला लागले. चढ्या व्याजदरांच्या वणव्यात एक अख्खी तेल विहीरच ओतली गेली. क्रिप्टोचलन त्यात अजूनच होरपळलं गेलं.

मात्र या धुरळ्यामध्ये कित्येक लक्षात घेण्यासारख्या गोष्टी आहेत ज्या लपता कामा नयेत. पहिली गोष्ट म्हणजे यापूर्वीही क्रिप्टो जगतात अशी भीषण हिमयुग आलेली होती. मात्र त्यामागे या चलनामागची नाविन्यपूर्ण कल्पना, त्यामागचं तंत्रज्ञान, त्यावर होणारा सट्टा, थोडक्यात एकूणच या क्षेत्रात असलेल्या पायाभूत उणिवा हीच कारणं अनेकदा होती. ही अशी पहिली वेळ आहे, जेव्हा चलनांच्या गडगडलेल्या किमती मागची कारण ही आंतरिक (इंटर्नल) नसून एकूणच जागतिक वित्तव्यवस्थेची आहेत. बिटकॉइन नावाचं खोडसाळ बाळ आणि त्याची भावंड, त्यांचं कौतुक असणाऱ्या मूठभर गुंतवणूकदारांच्या परिवारातून जागतिक वित्तीय संस्थांच्या बड्या जगात आलेली आहेत, याचाच हा एक पुरावा आहे. अर्थात, सगळ्याच बाळांचा निभाव मोठ्यांच्या जगात लागतोच असं नाही. या न्यायाने बिटकॉइनकडे बलाढ्य वित्तीय निधी काय दृष्टिकोनातून पाहतील आणि त्यांचे भविष्य कसे आकाराला येईल, याबद्दल भीती आणि कुतूहल गुंतवणूकदारांच्या मनात असणं स्वाभाविक आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, आत्तापर्यंत क्रिप्टोचलनाला आयटी उद्योगांच्या सोबत पाहिलं जात होतं. त्यामधली जोखीम सामाईक आहे असं मानलं जात असे आणि त्यामुळे साधारण समान स्वरूपाचे गुंतवणूकदार दोन्हीकडे पैसे लावत. मात्र नीट पाहू जाता क्रिप्टो चलन जरी तंत्रज्ञानावर आधारित असलं तरी मूलतः ते एक वित्तीय सेवा किंवा फायनान्शिअल सर्व्हिस आहे. हा मूलभूत फरक जर गुंतवणूकदारांमध्ये अधिकाधिक मान्यताप्राप्त झाला तर आयटी उद्योगांमधल्या खाचखळग्यांचे धक्के क्रिप्टोला लागणार नाही. तेव्हा या दोन वाटा वेगळ्या होतात का हे पाहणं आत्ताच्या वळणावर महत्त्वाचं ठरेल. तसं झालं तर तंत्र क्रांती मधल्या चढ-उतारांपासून क्रिप्टोचलन सुरक्षित राहील.

पण तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या पडझडीमुळे बलाढ्य संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा क्रिप्टो गुंतवणुकीतला हिस्सा अधोरेखित झाला. एकदा कमी व्हायला लागल्यावर क्रिप्टो चलनाची अचानक घसरगुंडी उडाली, यामागे ईटीएफ गुंतवणुकीचा मोठा सहभाग होता. यामध्ये धोरणात्मक निर्णयांपेक्षा ईटीएफ निधींची यांत्रिक कार्यपद्धती कारणीभूत आहे. या प्रकारचे निधी किमती कमी व्हायला लागल्यानंतर तरीही मालमत्ता न विकण्याचे निर्णय घेऊ शकत नाही. सहाजिकच त्या कमी व्हायला लागल्या की, ईटीएफ निधी विक्री सुरू करतात आणि त्यामुळे किमती अजून कमी होतात असं एक दुष्टचक्र सुरू होतं. मात्र या सगळ्यांमधून आज किमती कमी झाल्या आहे खरं असलं तरी मोठे संस्थात्मक गुंतवणूकदार अधिकाधिक या चलनाकडे वळलेले आहेत हेही सत्य आहे. आता हे सत्य दोन्ही बाजूने पाहता येईल. एकीकडे संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी येणं हे ती गुंतवणूक अधिकाधिक प्रस्थापित आणि सामान्यांसाठी सुरक्षित असण्याचे लक्षण मानलं जातं. पण हेही लक्षात घ्यायला हवं की मुलंतः क्रिप्टोचलनाचा उदय हाच मुळी बलाढ्य वित्त संस्थांच्या अनिश्चित हिलकाव्यांपासून सुरक्षितता म्हणून झालेला आहे. अशा प्रकारे जर क्रिप्टो चलन वित्त संस्थांच्या रचनेमध्ये सामायिक झालं तर त्याच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचं वेगळेपण आणि मूल्य संपेल का? ही ही भीती आहे.

थोडक्यात एखाद्या शोडशवर्षीय तरुण-तरुणी प्रमाणे आयुष्यात आलेल्या यौवनाची आव्हानं क्रिप्टो चलनासमोर उभी आहेत. यात स्वतःच्या ओळखीचे प्रश्न आहेत, तशी बाहेरच्या जगात टाकलेल्या पावलांची असुरक्षितता सुद्धा. पण त्याच वेळेला तिथून मिळालेली ओळख आणि आता आपण बाल्यावस्थेत उरलेलं नाही हा आत्मविश्वासही क्रिप्टोचलनाला पुढच्या वाटचालीसाठी उपयोगी पडेल. गुंतवणूकदार मात्र सध्या तरी सोळावं वरीस धोक्याचं असं म्हणत असतील.

लेखक एका व्यवस्थापन संस्थेमध्ये वित्त विभागात सहयोगी प्राध्यापक आहेत
ajitatresearch@gmail. com

प्राप्तिकर कायद्यातील टीसीएसच्या तरतुदी

कर-समाधान

प्रवीण देशपांडे

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात कररचनेत जरी बदल केला नसला तरी करदात्यांना काही प्रमाणात परदेशी व्यवहारांवर आकारला जाणारा (टीसीएस) दर कमी करून दिलासा दिला आहे. यामुळे करदात्याचे करदायित्व कमी किंवा वाढत नाही तर करदात्याच्या रोकड सुलभतेवर त्याचा परिणाम होतो. या टीसीएसमुळे करदात्याचे पैसे काही काळासाठी गुंतून राहू शकतात. लिब्रराईज्ड रेमिंटन्स स्कीमच्याअंतर्गत (एलआरएस) परदेशी पैसे पाठविल्यास त्यावर कर गोळा करण्यात येतो तो टीसीएस लिबरलाईज्ड रेमिटन्स स्कीमच्याअंतर्गत निवासी भारतीय एका आर्थिक वर्षात २,५०,००० अमेरिकी डॉलर (म्हणजेच सध्याच्या दरानुसार २ कोटी २५ लाख रुपये) भारताबाहेर पाठवू शकतो. या योजनेअंतर्गत ठरावीक रकमेपेक्षा जास्त रक्कम भारताबाहेर पाठविल्यास करदात्याकडून कर गोळा (टीसीएस) केला जातो. असे पैसे पाठविणाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी, करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी या टीसीएसच्या तरतुदी प्राप्तिकर कायद्यात आणण्यात आल्या. या तरतुदी निवासी भारतीयांना या योजनेच्या अंतर्गत पैसे पाठविल्यास लागू होतात. अनिवासी भारतीयांनी एनआरओ किंवा एनआरई खात्यातून भारताबाहेर पैसे पाठविल्यास त्यावर हा टीसीएस लागू होत नाही. अनिवासी भारतीयांसाठी ही योजना लागू होत नाही. त्यांच्यासाठी भारताबाहेर पैसे पाठविण्याची मर्यादा, एका आर्थिक वर्षासाठी, १० लाख अमेरिकी डॉलर (म्हणजेच सध्याच्या दरानुसार ९ कोटी रुपये) इतकी आहे.

हा टीसीएस कोणत्या दराने करावयाचा हे कोणत्या कारणासाठी पैसे पाठवायचे आहेत आणि किती पैसे पाठवायचे आहेत यावर अवलंबून आहे. प्राप्तिकर कायद्यानुसार हे पैसे पाठविणे प्रामुख्याने तीन प्रकारात विभागले आहे. एक शैक्षणिक आणि वैद्यकीय कारणासाठी, दुसरा परदेशातील सहलीसाठी आणि तिसरा इतर कारणासाठी. प्रत्येक कारणासाठी किती टीसीएस वसूल केला जातो, हे करदात्याने जाणून घेतले पाहिजे.

- **शैक्षणिक आणि वैद्यकीय :** या कारणासाठी करदात्याने एका आर्थिक वर्षात भारताबाहेर पैसे पाठविल्यास प्रथम १० लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर टीसीएस वसूल केला जात नाही. रक्कम १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर या १० लाख रुपयांच्यापेक्षा जास्त रकमेवर ५ टक्के टीसीएस वसूल केला जातो. या अर्थसंकल्पात, १ एप्रिल, २०२६ पासून, हा दर २ टक्के इतका सुचविण्यात आला आहे. करदात्याने शिक्षणासाठी भारताबाहेर पैसे पाठविताना बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून शैक्षणिक कर्ज घेतले असेल तर त्यावर टीसीएस वसूल केला जात नाही. शैक्षणिक खर्चात, परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या व्यक्तीचा भारत आणि परदेशी गंतव्यस्थानादरम्यान प्रवास तिकिटांच्या खरेदीसाठी पाठवलेले पैसे, शैक्षणिक संस्थेला दिलेली ट्युशन आणि इतर शुल्क, या कारणासाठी इतर दैनंदिन खर्च (आरोग्यसेवा, भोजन, निवास आणि स्थानिक वाहतूक) याचा समावेश होतो. वैद्यकीय खर्चात परदेशात वैद्यकीय उपचार करण्याच्या व्यक्तीच्या (आणि त्याच्याबरोबर एक सेवक) भारत आणि परदेशी गंतव्यस्थानादरम्यान प्रवास तिकिटांच्या खरेदीसाठी पाठवलेले पैसे, वैद्यकीय उपचारासाठी, या कारणासाठी इतर दैनंदिन खर्च (वैद्यकीय सेवा, इतर आरोग्यसेवा, भोजन, निवास आणि स्थानिक वाहतूक) याचा समावेश होतो.
- **परदेशातील सहलीसाठी :** परदेश सहली आयोजित करणाऱ्या व्यक्तींवर टीसीएस घेण्याची जबाबदारी आहे. प्रथम १० लाख रुपयाच्या विक्रीवर ५ टक्के टीसीएस आणि ही रक्कम १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर या १० लाख रुपयांच्यापेक्षा जास्त रकमेवर २० टक्के टीसीएस वसूल केला जातो. या अर्थसंकल्पात, १ एप्रिल, २०२६ पासून, हा दर सरसकट २ टक्के इतका सुचविण्यात आला आहे. म्हणजेच कितीही रक्कम असली तरी त्यावर २ टक्के टीसीएस वसूल केला जाईल. परदेश टूर पॅकेज म्हणजे ज्यात भारताबाहेरील देशाला किंवा देशांना भेट देणाऱ्या व्यक्तींचा प्रवासखर्च किंवा हॉटेल मुक्काम किंवा बोर्डिंग किंवा लॉजिंग किंवा इतर कोणत्याही खर्चाचा समावेश केला जातो. फक्त आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचे तिकीट किंवा स्वतंत्रपणे परदेशी हॉटेल खर्चासाठी एलआरएसअंतर्गत पैसे पाठविल्यास ते परदेशी टूर पॅकेज म्हणून समजले जात नाही. परदेशी टूर पॅकेजवर विक्रेत्याने टीसीएस वसूल केला असेल तर, त्या रकमेवर पुन्हा अधिकृत वितरकाकडून टीसीएसची वसुली केली जाणार नाही.
- **इतर कारणांसाठी :** इतर कारणांसाठी करदात्याने एका आर्थिक वर्षात भारताबाहेर पैसे पाठविल्यास प्रथम १० लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर टीसीएस वसूल केला जात नाही. रक्कम १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर या १० लाख रुपयांच्यापेक्षा जास्त रकमेवर २० टक्के टीसीएस वसूल केला जातो. यामध्ये करदात्याने अनिवासी भारतीयाला पाठविलेली भेट, दिलेले दान, स्थावर मालमत्ता खरेदी, गुंतवणूक वगैरे कारणांसाठी पाठविलेले पैसे, याचा समावेश होतो, यासाठी हा २० टक्के दर लागू होतो. उदा. एका निवासी भारतीयाने त्याच्या नातेवाईकाला १५ लाख रुपयांची भेट परदेशात पाठविल्यास प्रथम १० लाख रुपयावर टीसीएस नसेल आणि बाकी ५ लाख रुपयांवर २० टक्के म्हणजेच १ लाख रुपये इतका टीसीएस अधिकृत वितरक त्याच्याकडून घेईल. थोडक्यात १५ लाख रुपये भारताबाहेर पाठविण्यासाठी, अधिकृत वितरक, त्या निवासी भारतीयाकडून एकूण १६ लाख रुपये घेईल.

अधिकृत वितरकाने वसूल केलेला टीसीएस करदात्याच्या पॅनवर (स्थायी खाते क्रमांक) भरला जातो. यासाठी करदात्याला अधिकृत वितरकाकडून फॉर्म २७ डी मध्ये टीसीएसचे प्रमाणपत्र मिळते. अधिकृत वितरकाने भरलेला हा कर करदाता त्याच्या २६ एएस/एआयएसमध्ये तपासू शकतो. करदाता हा टीसीएस आपल्या करदायित्वातून वजा करू शकतो किंवा करदाइयित्व शून्य असेल तर, करदाता करपरताव्याचा (रिफंड) दावा करू शकतो. यासाठी कादात्याला विवरणपत्र दाखल करूनच असा दावा करता येतो.

१० लाख रुपयांची मर्यादा ही प्रत्येक कारणांसाठी स्वतंत्रपणे लागू नसून एकत्रतिपणे लागू आहे. पैसे कोणत्या कारणासाठी पाठविले हे विचारात घेतले जात नाही.

आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे भारताबाहेर पैसे पाठविल्यास त्यावर सध्यातरी टीसीएस लागू नाही.

करदात्याकडे पॅन (स्थायी खाते क्रमांक) नसेल तर वाढीव दराने टीसीएस वसूल केला जातो. असा वाढीव दराने टीसीएस टाळण्यासाठी करदात्याने पॅन घेणे गरजेचे आहे.

करदात्याने भारताबाहेर पैसे पाठविताना या तरतुदींचा विचार केल्यास या रकमेवर लागणारा टीसीएस लक्षात घेऊन आपला उद्गम कर भरावा किंवा नोकरदार करदात्यांसाठी, मागील वर्षापासून, ही टीसीएसची रक्कम आपल्या कंपनीला कळविल्यास पगारावर उद्गम कर (टीडीएस) कमी कापला जाईल. करदात्याने नियोजन करून एका आर्थिक वर्षातील परदेशातील हस्तांतरण १० लाख रुपयांपेक्षा कमी ठेवल्यास टीसीएस टाळता येतो.

लेखक सनदी लेखापाल आहेत.
pravindeshpande1966 @gmail.com

मुठभेड़ में 3 बदमाश पकड़े गए, 2 को पैर में गोली लगी

यमुनानगर में अस्पताल और मॉल पर फायरिंग कर भागे थे

यमुनानगर | यमुनानगर में अस्पताल व मॉल पर फायरिंग कर भागे 3 बदमाशों को पुलिस ने 6 घंटे में ही पकड़ लिया। मुठभेड़ में 2 बदमाश के पैर में गोली लगी। तीसरा बाइक से गिरने से घायल हो गया। आरोपी गुरलाल सिंह कुरुक्षेत्र और 2 नाबालिग तरावड़ी के हैं।

शनिवार रात 11 बजे मुंह पर कपड़ा बांधे बदमाश बाइक पर रेलवे रोड स्थित वरयाम सिंह अस्पताल पहुंचे। अंदर घुसकर रिसेप्शन पर 13-14 राउंड फायर किए। गोलियां दीवार व सोफे में लगीं। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कुछ देर बाद सिटी मॉल पर 3-4 फायर किए। मॉल के शीशों में छेद हो गए। वे गैंगस्टर काला राणा व बदमाश शुभम पंडित के नाम से धमकी की पर्ची फेंककर भाग गए। पुलिस ने नाकेबंदी कर तलाश शुरू की। रविवार सुबह 5 बजे अंसल टाउन के पास रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। दोनों ओर से 25 से 30 फायर हुए। बदमाशों से 1 देशी व 1 विदेशी पिस्टल बरामद हुई है।

भास्कर इनसाइट हरियाणा में एनकाउंटर के 94% मामलों में पुलिस की बंदूक का बदमाशों के पैरों पर अचूक निशाना

13 माह में 108 एनकाउंटर... 6 बदमाशों की मौत, 138 के पैर में लगी गोली

भास्कर न्यूज़ | पानीपत/रोहतक/प्रदेश के अन्य जिलों से

हरियाणा में बदमाश अब पुलिस के डंडे नहीं, बंदूक के निशाने पर हैं। दैनिक भास्कर ने जनवरी 2025 से अब तक पुलिस व बदमाशों में हुई मुठभेड़ के आंकड़े जुटाए। इसमें सामने आया कि 13 माह में 19 जिलों में 108 मुठभेड़ हुई। इनमें 6 बदमाश मारे गए। 138 के पैरों में गोली लगी। यानी करीब 94% मामलों में पुलिस की बंदूक का बदमाशों के पैरों पर अचूक निशाना लगा।

झज्जर में 15 जनवरी को मुठभेड़ में डीघल के पंकज अहलावत को पैर में गोली लगी थी। खाप पंचायत ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताया। अब एसआईटी जांच कर रही है। प्रदेश में कुछ वर्षों में व्यापारियों, नेताओं, संस्थानों पर फायरिंग के मामले बढ़े हैं। लॉरेंस, रोहित गोदारा, हिमांशु भाऊ, काला राणा, कुलबीर सिंधू, काला जठेड़ी, दीपक नांदल, शुभम पंडित जैसे गैंगस्टर्स के नाम पर बदमाश रंगदारी व फिरौती मांगते हैं। 2025 में एसटीएफ ने संगठित अपराध से जुड़े 810 बदमाशों को गिरफ्तार किया।

सोनीपत में मुठभेड़ तो रोहतक में पैर में गोली के मामले ज्यादा

जिला	मुठभेड़	बदमाश की मौत	पैर में गोली लगी
रोहतक	13	0	27
सोनीपत	16	1	19
पलवल	15	0	14
नूंह	7	0	13
गुरुग्राम	10	1	12
कुरुक्षेत्र	8	0	8
पानीपत	7	0	8
यमुनानगर	6	2	7
हिसार	4	0	5
फरीदाबाद	5	0	5
अम्बाला	5	1	4
फतेहाबाद	2	0	4
जींद	2	0	3
भिवानी	2	0	3
रेवाड़ी	2	0	3
हांसी	1	0	1
महेंद्रगढ़	1	0	1
झज्जर	1	0	1
कैथल	1	1	0
कुल	108	6	138

मंत्री बोले- किसी की तरफ आंख उठाकर देखा तो पिंडी के आर-पार सुराख होगा

नरवाना | कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने रविवार को बाबा गैबी साहब मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के समापन अवसर पर मंच से बदमाशों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, 'कोई गुंडा तत्व मेरी बहन-बेटी की तरफ, मेरे व्यापारी भाई की तरफ, मेरे मजदूर और कमजोर वर्ग की तरफ आंख उठाकर न देखे। अगर कोई देखेगा तो उसकी पिंडी के आर-पार सुराख होगा।

भास्कर एक्सपर्ट

शुभम गर्ग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, पीजीआईएमएस, रोहतक

पैर में गोली लगने पर लंबे समय चल नहीं सकते

पैर में गोली लगने से लंबे वक्त तक चल नहीं सकते। दौड़ना तो बहुत मुश्किल है। हड्डी कई टुकड़ों में टूट सकती है। इसे कम्यूनिटेड फैक्चर कहते हैं। हड्डी में ड्रिलिंग प्रभाव से बड़ा छेद हो सकता है। ऊतक, हड्डियां गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। टूटी हड्डी के टुकड़े शरीर में रह जाएं तो दर्द या संक्रमण हो सकता है।

पुलिस सेल्फ डिफेंस में ही करती है एनकाउंटर

पुलिस एनकाउंटर सेल्फ डिफेंस में करती है। बदमाश सामने से फायरिंग करता है तो पैर पर गोली मारती है। फायरिंग जारी रहने पर जान बचाने के लिए कहीं भी गोली लग सकती है। हमारा मकसद अपराध खत्म करना है। -**अजय सिंघल**, डीजीपी, हरियाणा

प्रधान सचिव वित्त की प्रेजेंटेशन ने बढ़ाई चिंता, भर्तियों के लिए यूपीएस पर करना पड़ सकता है विचार

आरडीजी खत्म होने से प्रदेश की वित्तीय सेहत बिगड़ी, डीए, एरियर व सब्सिडी पर संकट: प्रधान वित्त सचिव

भास्कर न्यूज़ | शिमला

16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) समाप्त किए जाने के बाद राज्य सरकार के सामने गंभीर वित्तीय संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में वित्त विभाग ने साफ कह दिया है कि मौजूदा हालात में न तो कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) दिया जा सकेगा और न ही लंबित एरियर का भुगतान संभव होगा। रविवार को प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और सत्ता पक्ष के विधायकों सहित मीडिया के सामने प्रेजेंटेशन दी।

प्रेजेंटेशन में बताया गया कि हिमाचल की आर्थिक गाड़ी वर्षों से आरडीजी के सहारे चल रही थी। 15वें वित्त आयोग के दौरान हिमाचल को पांच वर्षों में 37,199 करोड़ रुपए का आरडीजी मिला था, जिसके समाप्त होने से राज्य के संसाधनों पर भारी दबाव आ गया है। प्रदेश की आय सीमित है, जबकि बजट का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, कर्ज के ब्याज और मूलधन चुकाने में खर्च हो जाता है।

कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए पिछले वेतन आयोग का लगभग 8500 करोड़ रुपए का एरियर और डीए व डीआर का करीब 5000 करोड़ रुपए भी बकाया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी मुश्किलें बढ़ गई हैं और भविष्य की भर्तियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) पर विचार करना पड़ सकता है। वित्त विभाग ने दो साल से खाली पड़े पदों को समाप्त करने, नई भर्तियों पर रोक लगाने, मौजूदा स्टाफ के युक्तिकरण और करीब 30 प्रतिशत सरकारी संस्थानों को मर्ज करने की सलाह दी है। इसके साथ ही कई योजनाओं को बंद करने और नए विकास कार्य शुरू न करने के संकेत भी दिए गए हैं।

वित्त विभाग द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू।

आरडीजी सरकार नहीं, जनता के हक का मुद्दा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आरडीजी का खत्म होना किसी सरकार का नहीं, बल्कि प्रदेश के लोगों के अधिकारों का सवाल है। प्रदेश के कुल बजट का करीब 12.7 प्रतिशत हिस्सा आरडीजी से आता था, जिससे हिमाचल देश के सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा विधायकों को भी इस प्रस्तुति के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं आए और यदि वे आते तो प्रदेश की वित्तीय स्थिति की गंभीरता को समझ पाते। सरकार इस मुद्दे पर भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री से मिलने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश की कर संग्रहण वृद्धि दर घटकर लगभग 8 प्रतिशत रह गई है, जबकि पहले यह 13 से 14 प्रतिशत थी। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि जिन विद्युत परियोजनाओं ने अपना पूरा ऋण चुकता दिया है, उनमें कम से कम 50 प्रतिशत रॉयल्टी राज्य को दी जाए और 40 वर्ष पूरे कर चुकी परियोजनाएं प्रदेश को लौटाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2012 से अब तक बीबीएमबी के लगभग 4500 करोड़ रुपए के बकाया का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। इसके अलावा शानन पावर प्रोजेक्ट को वापस लेने के लिए कानूनी लड़ाई जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। अपने संसाधनों से प्रदेश ने अब तक 26,683 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि पर्यटन के अलावा प्रदेश के पास सीमित संसाधन हैं।

बिजली सब्सिडी समेत कई योजनाएं पर लग सकता है कट : वित्त सचिव ने बताया कि आरडीजी खत्म होने के कारण बिजली सहित लगभग सभी सब्सिडी शून्य करनी पड़ सकती हैं। इस वित्तीय वर्ष में बिजली सब्सिडी पर 1200 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जिसे आगे जारी रखना मुश्किल होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर इस वर्ष 1661 करोड़ रुपए खर्च हुए, उस पर भी पुनर्विचार की जरूरत बताई गई है। हिमकेयर और सहारा जैसी योजनाओं के 400 से 500 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान, करीब 2000 करोड़ के लंबित बिल और हाईकोर्ट के आदेशों से जुड़े लगभग 1000 करोड़ के भुगतान ने सरकार की चिंता और बढ़ा दी है। देवेश ने बताया कि जीएसटी आने से सारी शक्तियां खत्म हो गई, सरकार अपने स्तर पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती। लोन भी 10 हजार करोड़ ही ले सकते हैं, जबकि 13000 करोड़ ब्याज के वापस करने पड़ते हैं।

भास्कर सवाल आरडीजी बंद होने से 16000 करोड़ रुपए के नुकसान का राज्य सरकार कैसे कर पाएगी भरपाई...

आरडीजी बंद होने से 16000 करोड रु. का गैप भरना सरकार के लिए चुनौती रहेगा। बता दें कि सरकार की 52000 करोड़ रुपए की आय है। जबकि खर्चा 68000 करोड़ रु. सालाना है। यानि 16000 करोड़ रुपए का गैप की भरपाई के लिए सरकार आरडीजी से मिलने वाली 10 हजार करोड़ रुपए पर निर्भर थी। इसके बावजूद 6000 करोड़ रुपए का और अंतर रहना था लेकिन 10 हजार करोड़ रुपए सालना मिलने से सरकार की बढ़ी टेंशन दूर होनी थी जिसे 16वें वित्तायोग ने बंद कर दिया है। प्रदेश के बजट में आरडीजी का शेयर 13 प्रतिशत था जो अब बंद हो गया है। सरकार इसकी भरपाई कैसे कर पाएगी।

सक्रियता • पंजाब में चुनाव करीब 1 साल बाद, हरियाणा की सियासत गरम

मुख्यमंत्री नायब सैनी के पंजाब में हरियाणा मॉडल के दावे पर आप करेगी काउंटर

मनोज कुमार | चंडीगढ़

पंजाब विधानसभा के चुनाव में करीब एक साल है। इससे राजनीति पूरी तरह उफान पर है। पड़ोसी राज्य होने से पंजाब का असर हरियाणा की सियासत भी गरम हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पंजाब में लगातार सक्रियता से यह माना जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व ने पंजाब चुनाव तैयारी की जिम्मा उन्हें दे दिया है। पटियाला से मोहाली तक हरियाणा सीमा से लगे वहां के क्षेत्र में सैनी वोट काफी हैं। इसके अलावा उनका फोकस ओबीसी वोटर वाले क्षेत्रों में हैं। सीएम द्वारा पंजाब में हरियाणा मॉडल और यहां की योजनाओं की चर्चा करने से अब सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। हर बात का काउंटर करने के लिए आप नेतृत्व ने हरियाणा नेतृत्व को एक्टिव कर दिया है। ऐसे में चुनाव के वक्त चंडीगढ़ में शुरू किया गया प्रदेश पार्टी कार्यालय भी सक्रिय किया है, जिसमें हरियाणा पर अब और गहनता से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा हरियाणा होने वाली हर छोटी-बड़ी घटनाओं का पूरा खाका तैयार होगा। हरियाणा सरकार की योजनाओं पर पूरा अध्ययन होगा, ताकि पंजाब में हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी की ओर से रखी जाने वाली हर बात का उसी वक्त काउंटर कर यहां की स्थिति से पंजाब के वोटर्स को अवगत कराया जा सके।

हरियाणा के मुख्यमंत्री का लगातार बढ़ रहा पंजाब में संपर्क

पिछले करीब एक साल से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में एक्टिव हैं। लगातार उनके दौरे हो रहे हैं। वहां के उद्योगपतियों, सामाजिक-धार्मिक संगठनों, सरपंचों से मुलाकात हो रही है। वे वहां के कार्यक्रमों में भी शिरकत कर रहे हैं। वहां लगातार लाडो लक्ष्मी योजना, नौकरी, उद्योग की बात कर पंजाब में हरियाणा मॉडल लागू करने की बात कर रहे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री सैनी का भाषण भी पंजाबी में हो रहा है। उनका पंजाब के लोगों से लगातार संपर्क चल रहा है।

हर वादे-योजना की खोलेंगे पोलः ढांडा

आप के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने एक दिन पहले ही हरियाणा के मुद्दे पर चंडीगढ़ में पत्रकारवार्ता भी की है। ढांडा का कहना है कि हरियाणा में बेरोजगार काफी है। यहां भर्तियों में पद खाली रह रहे हैं। हम भाजपा के हर वादे-योजना की पोल खोलेंगे। पंजाब में खेलों की बात करते हैं, लेकिन हरियाणा में दो-दो खिलाड़ियों की खराब इन्फ्रास्ट्रक्चर की वजह से मौत हो गई। पंजाब सीएम भगवंत मान उनके परिजनों से मिले। अब पेंशन और बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं।

आईएएस अफसरों के निलंबन पर आप घिरी; जाखड़ का आप पर हमला, कहा- भ्रष्ट आचरण का साथ न देने की सजा दी गई

भास्कर न्यूज़ | चंडीगढ़

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर संतुष्टि जताई है। समझौता पंजाब के औद्योगिक विकास को गति देगा और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। उन्होंने आईएएस अफसरों के निलंबन पर आप को घेरा और कहा, उनको भ्रष्ट आचरण का साथ न देने की सजा दी गई। जाखड़ ने आप और कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आप की तरफ से कल से इस संबंधी अच्छा या बुरा बयान नहीं आया। सीएम अपने वीजा के चक्कर में लगे हैं। वह वीजा कैंसिल होने से सदमे में हैं, जबकि कांग्रेस में सीएम कुर्सी की रेस में जो थोड़े पीछे समझे जा रहे हैं, उन्होंने एक-दो बयान जरूर दिए हैं। जाखड़ ने कहा कि आप और कांग्रेस के नेताओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित में समझौते के लिए सरकार को बधाई देनी चाहिए थी, लेकिन वे रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रहे हैं।

गैर कानूनी आदेशों के खिलाफ अफसरों का खड़ा होना अच्छी बात : राजा वड़िंग -पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने आप सरकार के कुछ गैरकानूनी आदेशों को मानने से इनकार कर दिया था। यह अच्छी बात है कि अधिकारियों ने आप के गैर कानूनी आदेशों के खिलाफ खड़ा होना शुरू किया है, जो हमेशा से नौकरशाही और पुलिस का दुरुपयोग करने की कोशिश करती रही है। सरकार को निलंबन के कारण जरूर बताए थे।

राज्यपाल का खडूर साहिब दौरा, दरबार साहिब में टेका माथा

धार्मिक-सामाजिक संस्थाएं नशामुक्त पंजाब के लिए एकजुट हों : कटारिया

भास्कर न्यूज़ | वैरोवाल

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने खडूर साहिब के गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब (अंगीठा साहिब श्री गुरु अंगद देव जी) में माथा टेका और गुरु चरणों में हाजिरी भरकर सर्वत्र के भले की अरदास की। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने राज्यपाल को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। बाद में राज्यपाल निशान-ए-सिखी संस्था में पहुंचे। राज्यपाल ने यूपीएससी, जेईई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने छात्रों को कड़ी मेहनत, अनुशासन और सेवा भाव के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

राज्यपाल ने निशान-ए-सिखी संस्था के प्रयासों की सराहना की और कहा कि ऐसे संस्थान युवाओं को सही दिशा देकर पंजाब को नशामुक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं से अपील की कि वे युवाओं के

उज्ज्वल भविष्य के लिए एकजुट होकर प्रयास करें। राज्यपाल ने संस्था के कॉरिडोर में आम का पौधा रोपा और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया।

राज्यपाल ने तरनतारन के वैरोवाल स्थित जैन मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना की और जैन समुदाय के सदस्यों से संवाद किया। उन्होंने शांति, अहिंसा, अनुशासन और सामाजिक समरसता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने में मंदिर की भूमिका की सराहना की। कटारिया ने कहा कि ऐसे आध्यात्मिक संस्थान समाज में नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने और सामाजिक एकता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

बच्चे की हत्या : एक ही वार में काट दिया था गला

लुधियाना | कासाबाद में 2 दिन से लापता अमन (9) का गला रेतकर हत्या के मामले में रविवार को सिविल अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम हो गया। जांच में आया कि सिर्फ एक ही वार में गले को काटा गया है। जख्म की गहराई 11 सेंटीमीटर निकली है। हत्यारे ने पूरे जोर से गले को काटा है। बच्चे से दुष्कर्म की पुष्टि के लिए सैंपल भेजे गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। जिसके बाद शाम को परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है।

10 जनवरी को पतंगबाजी को लेकर अमन के माता-पिता की पड़ोस के एक फैक्ट्री कर्मचारी से लड़ाई हुई थी। दरअसल, अमन की पतंग पास स्थित फैक्ट्री में चली गई। जब अमन पतंग लेने गया तो वहां एक युवक ने पतंग देने से मना किया। जिस बात पर अमन ने उसकी डोर को काट दिया। लड़के का चाचा भी वहां आ गया। फिर लड़के का चाचा अमन को पकड़कर घर पर लेकर गया था।

प्रदेश की सियासत में 'जाति' पर जंग • टिप्पणी पर आप ने प्रताप बाजवा को घेरा

आप का रोष प्रदर्शन आज... चीमा बोले- कांग्रेस 24 घंटे में माफी मांगे, वरना होगी कानूनी-राजनीतिक कार्रवाई

भास्कर न्यूज़। चंडीगढ़

विस में विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा के मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ को लेकर की गई टिप्पणी पर सियासी घमासान तेज हो गया है। आप नेताओं ने टिप्पणी को पूरे दलित वर्ग का अपमान करार दिया और सोमवार को रोष प्रदर्शन का ऐलान किया। वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने कहा, कांग्रेस और प्रताप बाजवा 24 घंटे में माफी मांगें, वरना कानूनी और राजनीतिक कार्रवाई होगी।

चीमा ने कहा कि हरभजन सिंह ऐसी शख्सियत हैं, जिन्होंने गरीबी से निकलकर सिविल सर्विस की परीक्षा पास की और ईटीओ बने। यही नहीं वह समाज सेवा की भावना से नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति पर जातिसूचक टिप्पणी न केवल एक मंत्री, बल्कि दलित समाज का अपमान है। कभी मटीरियल, कभी नाम लेकर और अब बाजेवाला कहकर अपमान किया जा रहा है।

वन मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि प्रताप बाजवा की यह टिप्पणी सामंती मानसिकता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि जो लोग मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, 2027 में जनता उनका खुद बैंडबाजा बजाएगी। इधर, आप पंजाब के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने कहा कि बाजवा की टिप्पणी से साफ है कि कांग्रेस नेताओं के भीतर दलित समाज के प्रति कितनी नफरत भरी है। क्या मेहनतकश परिवारों से निकलकर कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता।

विपक्ष नेता के बचाव में उतरी कांग्रेस, कहा- जाति पर नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार पर थी टिप्पणी

कांग्रेस ने आप पर विपक्ष नेता की टिप्पणी को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाजवा ने जाति पर नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार पर टिप्पणी की थी। डिप्टी सीएलपी नेता अरुणा चौधरी ने कहा, दलित समाज जातिवादी टिप्पणियों को पहचानने में सक्षम है, इसलिए आप को खुदभू घोषित रक्षक बनने की जरूरत नहीं है। पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह डैनी बंडाला ने कहा कि आप मानसिक संतुलन खो चुकी है। बाजवा ने चेताया था कि पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों में आप शामिल है, को जवाबदेह ठहराया जाएगा। कांग्रेस एससी सेल चेयरमैन कुलदीप वैद, विधायक विक्रम चौधरी, विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल भी विपक्ष नेता के बचाव में आए हैं।

12 को मंडी के विभिन्न क्षेत्रों में करेगी विरोध

किसान सभा ने मनरेगा को खत्म करने के फैसले का किया विरोध

भास्कर न्यूज़ | मंडी

हिमाचल किसान सभा की जिला कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कमेटी ने 12 फरवरी की अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन हड़ताल को पूरा समर्थन देते हुए किसानों के मुद्दों व अन्य किसान मांगों को लेकर इस हड़ताल के तहत मंडी, जोगेंद्रनगर, सरकाघाट, सुंदरनगर, बालीचौकी व जंजैहली में संयुक्त प्रदर्शनों में हिस्सा लेने का फैसला लिया है। राज्य उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष कुशाल भारद्वाज ने बताया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका को व्यापक रियायतें देना भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि और राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। मोदी सरकार जो बिजली संशोधन बिल 2025 लाई है, उसका असली मकसद बिजली बोर्डों को कमजोर करके बिजली क्षेत्र को निजी कंपनियों के हवाले करना है। बैठक में फैसला लिया गया कि 29 मार्च को किसान सभा का त्रिवार्षिक जिला सम्मेलन मंडी में होगा। 8 से 21 मार्च के बीच सभी ब्लॉक एवं जोनल कमेटियों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 13 फरवरी से 5 मार्च तक सभी इकाइयों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बल्ह में प्रस्तावित हवाई अड्डे के विरोध में तथा प्रशासनिक आदेश से बनी सोशल इंपैक्ट कमेटी को लोकतांत्रिक तरीके से चुनने की मांग पर 9 फरवरी को किसान सभा का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त मंडी से मिलकर प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपेगा।

भास्कर खास पानीपत के पदमश्री नरेंद्र का मुर्रा नस्ल का भैंसा जीत चुका देशभर में 21 फर्स्ट प्राइज

₹15 करोड़ का भैंसा, नाम: विधायक जी, लाइफ स्टाइल वीआईपी जैसी, पशु मेले में मुर्रा वयस्क-मुर्रा ब्रीड में चैम्पियन बना, 3 लाख के इनाम जीते

संजीव राणा | कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र के केडीबी मेला ग्राउंड में चल रहे 41वें पशु मेले में पहुंचा भैंसा अपने नाम- विधायक जी और वीआईपी लाइफ स्टाइल को लेकर चर्चा में है। दर्शक साढ़े चार साल के मुर्रा नस्ल के झोटे की ऊंची-लंबी कद-काठी (14 फीट लंबा और साढ़े पांच फीट ऊंचा) और चमकदार काले शरीर को देखकर हैरान हो रहे हैं। यह झोटा पानीपत के पद्मश्री नरेंद्र सिंह डिडवाड़ी का है।

नरेंद्र का दावा है कि झोटे की कीमत 15 करोड़ रुपए लगाई जा चुकी है, लेकिन वे इसे बेचना नहीं चाहते। पशु मेले में विधायक जी ने मुर्रा वयस्क श्रेणी में पहला स्थान (51 हजार रुपए इनाम) हासिल किया और ब्रीड चैंपियन का खिताब (2.50 लाख रुपए इनाम) भी अपने नाम किया। विधायक जी' कोई साधारण झोटा नहीं है। यह मशहूर झोटे 'गोलू' का पोता और 'गोलू-2' का बेटा है, जिन्होंने कई राष्ट्रीय पशु मेलों में नाम कमाया।

21 जीत का रिकॉर्ड

करीब दो साल की उम्र से ही 'विधायक' पशु मेलों में हिस्सा लेने लगा था। अब तक वह 21 मेलों में पहला पुरस्कार जीत चुका है। कई प्रतियोगिताओं में दूसरे स्थान पर भी रहा है। कुरुक्षेत्र मेले में मुर्रा वयस्क श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल करने के साथ-साथ ब्रीड चैंपियन बनने से उसकी पहचान और मजबूत हुई है।

खास देखभाल और रहन-सहन... लंबी-ऊंची कद-काठी के इस झोटे का रहन-सहन भी खास है। फार्म में इसके लिए अलग से स्विमिंग पूल बनाया गया है। नियमित ग्रूमिंग और हर रोज सरसों के तेल से मालिश की जाती है। मौसम के अनुसार इसे गर्मियों में एसी और सर्दियों में हीटर वाले कमरे में रखा जाता है। जबकि मेलों में ले जाने के लिए विशेष एसी वाहन की व्यवस्था की जाती है। यह दिनभर में करीब 10 किलो फीड लेता है, जिसमें चना और गेहूं प्रमुख होते हैं। बेहतर नस्ल और खानदानी जीन के कारण यह झोटा मेलों में लगातार आकर्षण का केंद्र बनता है।

भास्कर एक्सक्लूसिव वाटर टैंक में खराब हो रहा पेयजल

ईंटों के बेस से बने 240 वाटर टैंकों में भूमिगत जल का रिसाव, अब आरसीसी से बनेगा तल

मनोज कुमार | चंडीगढ़

हरियाणा में अब वाटर टैंकों में भूमिगत जल के आने की समस्या खत्म करने की तैयारी है। कई जिलों में भूमिगत जल टैंकों के पानी में मिलकर उसे खराब कर देता है, जिससे बीमारियां फैलती हैं।

जनस्वास्थ्य विभाग की तकनीकी टीम की जांच में पाया गया कि कई टैंक काफी पुराने हैं और उनका बेस (तला) ईंटों का बना हुआ है। इसी कारण भूमिगत पानी पेयजल में शामिल हो रहा है। अब राज्य में इन टैंकों का बेस आरसीसी से बनाया जाएगा। विभाग ने ऐसे 240 टैंक चिह्नित किए हैं। विभाग इस पर काम कर रहा है, जिसे बजट में शामिल किया जा सकता है।

इन जिलों के वाटर टैंकों में सबसे ज्यादा दिक्कत

प्रदेश में सेम (जलभराव और खारी मिट्टी) की समस्या मुख्यरूप से दक्षिणी और मध्य जिलों में है। इनमें रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, जींद, हिसार, चरखी दादरी और फतेहाबाद प्रमुख हैं। सिरसा के कुछ हिस्सों में भी यह दिक्कत है। रोहतक में 61.47%, झज्जर में 40.7% और सोनीपत में 32.95% जमीन प्रभावित है। ये जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

1995 की बाढ़ के बाद कई जिलों का भूजल ऊपर आया

हरियाणा में नहरों का जाल बिछा हुआ है। 1995 में आई बाढ़ के बाद सेम की समस्या ज्यादा बढ़ी। नहरों के विस्तार के बाद भी यह समस्या बढ़ती गई। बाढ़ के बाद कुछ जिलों में भूमिगत पानी ऊपर आ गया।

परेशानी का स्थायी समाधान होगाः मंत्री

वाटर टैंकों में भूमिगत जल आने की परेशानी का स्थायी समाधान किया जाएगा। पहले टैंकों का तला ईंटों का बनाया जाता था, अब इसे आरसीसी का बनाया जाएगा, जिससे नीचे से पानी का रिसाव नहीं होगा। -**रणबीर गंगवा**, मंत्री, जनस्वास्थ्य विभाग

बिजनेस एक्सप्लेनर • बिटकॉइन सिर्फ 4 महीने में 49% टूट चुका, ये निवेश का मौका होना चाहिए, फिर भी निवेशक क्रिप्टोकरेंसी में खरीदारी से क्यों बच रहे?

क्रिप्टोः कीमत के साथ ही भरोसा भी घटा; 'डिजिटल गोल्ड' से दूर हो रहीं बड़ी संस्थाएं

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

क्रिप्टोकरेंसी बाजार इन दिनों सिर्फ गिरावट नहीं, बल्कि भरोसे के संकट से भी गुजर रहा है। कभी 'डिजिटल गोल्ड' कहे जाने वाले बिटकॉइन की कीमत सिर्फ 4 महीनों में रिकॉर्ड स्तर से करीब 49% घट चुकी है। आमतौर पर इतनी बड़ी गिरावट को निवेश का मौका माना जाता है, लेकिन निवेशक उलझन में हैं- यह मौका है या चेतावनी? वजह साफ है, गिरावट सिर्फ कीमतों में नहीं आई, बल्कि पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम पर भरोसे में दिख रही है। अक्टूबर 2025 की शुरुआत में बिटकॉइन ने 1,25,482 डॉलर का ऑल-टाइम हाई छुआ था। तब अनुमान लगाया जा रहा था कि यह जल्द 1.5 लाख डॉलर (1.36 करोड़ रुपए) से ऊपर निकल जाएगा। लेकिन फरवरी 2026 के पहले हफ्ते तक इसकी कीमत गिरकर 63,597 डॉलर रह गई। यानी चार महीनों में लगभग आधी वैल्यू साफ हो गई।

बिटकॉइन की कीमतों में लगातार गिरावट यह संकेत देती है कि पारंपरिक और संस्थागत निवेशक अब इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। क्रिप्टो के प्रति समग्र निराशा बढ़ रही है और यह बाजार के लिए चिंता की बात है।

आशंकाएं बढ़ीं: 2025 में 1.1 करोड़ क्रिप्टो टोकन बाजार से गायब हुए

- **संस्थागत पलायनः** बिटकॉइन को 'डिजिटल गोल्ड' मानकर निवेश करने वाली बड़ी संस्थाएं अब इससे दूरी बनाने लगी हैं। इसके चलते बिटकॉइन ईटीएफ से लगातार निकासी ने इस बाजार पर बिकवाली का दबाव बढ़ा दिया है।
- **भरोसे पर चोटः** सिर्फ 4 महीनों में 49% से ज्यादा गिरावट से यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या क्रिप्टो वाकई सुरक्षित वैकल्पिक निवेश है।
- **टोकन गायब होने का संकटः** 2025 में 1.1 करोड़ क्रिप्टो टोकन बाजार से गायब हो गए। इससे निवेश की सुरक्षा को लेकर आशंकाएं गहरा गई हैं।
- **अनुमान पर बढ़ता दांवः** निवेशक अब सीधे बिटकॉइन खरीदने के बजाय पॉलीमार्केट जैसे प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म्स पर दांव लगा रहे हैं। यानी लोग क्रिप्टो खरीदकर रखने के बजाय उसके भविष्य पर सट्टा लगाने लगे हैं।

मौजूदा निचले स्तर पर निवेश कितना सुरक्षित हो सकता है?

- **जोखिम साफ दिख रहाः** यदि संस्थागत निवेशक क्रिप्टो से बाहर निकलते रहे, तो खुदरा निवेशकों के लिए बाजार को संभालना मुश्किल होगा। डॉयचे बैंक इसे बड़ा बदलाव मानता है, जो छोटे निवेशकों के लिए खतरनाक है।
- **ये आम गिरावट नहींः** वैकल्पिक निवेश फर्म स्काईब्रिज के मैनेजिंग पार्टनर एंथनी स्कारामुची का कहना है कि ये आम गिरावट नहीं है। बाजार में कोई ठोस कारण नहीं था, जिससे इतनी बड़ी गिरावट आए। यह निवेशकों के घटते भरोसे का नतीजा है।

बिटकॉइन वापस $1.25 लाख पर लौटेगा, इसके आसार कम

डॉयचे बैंक को नहीं लगता कि बिटकॉइन जल्द अपने पुराने रिकॉर्ड स्तर पर लौटेगा। बैंक के मुताबिक, बिटकॉइन अब शुद्ध सट्टेबाजी वाली संपत्ति से निकलकर वास्तविक वैल्युएशन की तलाश में है। इस प्रक्रिया में उसे यह तय करना होगा कि उसकी भूमिका सिर्फ निवेश की है या भविष्य में आम भुगतान का माध्यम भी बन सकता है।

बड़ा झटका, जनवरी में 90 लाख करोड़ रुपए घटा क्रिप्टो बाजार का आकार

- 2026 में अब तक बिटकॉइन की वैल्यू 28% घट चुकी है। अन्य प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी इथेरियम और सोलाना में तो लगभग 37% गिरावट आ चुकी है।
- अकेले इस साल जनवरी में ही क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के कुल वैल्युएशन में 90 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की भारी-भरकम गिरावट आ चुकी है।
- अमेरिकी निवेश व रिसर्च कंपनी स्टिफेल का अनुमान है कि बिटकॉइन 38,000 डॉलर तक आ सकता है। मतलब 40% और गिरावट की आशंका है।

पैसे की जल्द जरूरत हो तो दूर रहेंः क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट लोगों के जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाने का नतीजा है। अब क्रिप्टो में निवेश के बारे में वही लोग सोचें, जो भारी उतार-चढ़ाव झेल सकते हैं। जिन लोगों को जल्द पैसों की जरूरत हो उनके लिए यह सही विकल्प नहीं है। ये भी ध्यान में रखें कि भारत में क्रिप्टो से आय पर 30% है। **-आदिल शेट्टी,** सीईओ, बैंकबाजार

प्राइमरी मार्केट

इस हफ्ते तीन आईपीओ जुटाएंगे ₹3,871 करोड़

मुंबई| इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट में दो मेनबोर्ड और एक एसएमई आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। इनके जरिये ये कंपनियां कुल 3,870.87 करोड़ रुपए जुटाएंगी। मेनबोर्ड पर फ्रैक्टल एनालिटिक्स और आय फाइनेंस के आईपीओ 09 फरवरी को खुलेंगे।

- **फ्रैक्टल एनालिटिक्सः** यह देश की ऐसी पहली कंपनी है, जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सेक्टर में काम करती है और यूनिकॉर्न बन चुकी है। अब 9 फरवरी को खुलने वाले आईपीओ के जरिये बाजार से 2,834 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है।
- **आय फाइनेंसः** गुरुग्राम की यह कंपनी छोटे कारोबारियों को लोन देती है। इसका 1,010 करोड़ रुपए का पब्लिक इश्यू भी 09 फरवरी को ही खुलेगा। साल 2014 में शुरू हुई यह कंपनी उन सूक्ष्म और लघु उद्योगों (एमएसएमई) को पैसा देती है, जिन्हें बैंकों से फंड मिलने में दिक्कत आती है।
- **मरुशिका टेक्नोलॉजीः** एसएमई सेगमेंट में 27 करोड़ रुपए का यह आईपीओ 12 फरवरी को खुलेगा।

फंड का फंडा

इक्विटी सेविंग फंडः कम रिस्क में एफडी से बेहतर रिटर्न

मुंबई| शेयर बाजार के जोखिम से बचकर एफडी से ज्यादा कमाई के लिए 'इक्विटी सेविंग फंड' बेहतर विकल्प है। यह फंड आपके पैसे को शेयर और डेट के साथ 'आर्बिट्राज' में निवेश करता है। आर्बिट्राज यानी नकद और वायदा बाजार की कीमतों के अंतर से सुरक्षित मुनाफा कमाना। अगर आप ज्यादा रिस्क के बिना 1-3 साल पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो यह अच्छा विकल्प है। इसमें शेयर बाजार के मुकाबले कम जोखिम और डेट फंड से बेहतर रिटर्न की संभावना होती है। हालांकि एफडी की तरह फिक्स्ड रिटर्न की गारंटी नहीं होती, बाजार के उतार-चढ़ाव का हल्का जोखिम रहता है, पर लंबी अवधि में यह बेहतर मुनाफा दे सकता है।

3 वर्ष में सालाना 14% तक रिटर्न

इक्विटी सेविंग फंड	रिटर्न
एचएसबीसी	13.66%
एसबीआई	11.59%
मिराए एसेट	11.48%
सुंदरम	11.41%
एडलवाइज	11.29%

निवेश के पांच बड़े फायदे..

1. कम जोखिम में ज्यादा कमाई 2. बेहतरीन टैक्स बचत का लाभ 3. आर्बिट्राज का फायदा 4. पोर्टफोलियो में सटीक संतुलन 5. बैंक एफडी से बेहतर विकल्प।

पर्सनल फाइनेंस

क्रेडिट कार्डः पेमेंट में 30 दिन से ज्यादा देरी न करें

मुंबई| क्रेडिट कार्ड बिल भरने में लापरवाही आपकी वित्तीय साख बिगाड़ सकती है। भुगतान में 30 दिन से ज्यादा देरी होने पर बैंक सिबिल ब्यूरो को रिपोर्ट करते हैं। इससे आपका क्रेडिट स्कोर 50 से 100 अंक तक गिर सकता है। क्रेडिट स्कोर में 35% हिस्सा 'पेमेंट हिस्ट्री' का होता है। एक भी डिफॉल्ट आपकी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर सकता है।

सुविधाः 3 दिन के ग्रेस पीरियड में बच सकती है वित्तीय साख

ड्यू डेट से 1-2 दिन की देरी पर स्कोर खराब नहीं होता। बैंक तीन दिनों का ग्रेस पीरियड देते हैं। इस दौरान पैसा जमा करने पर आप डिफॉल्टर नहीं माने जाते। हालांकि, आपको लेट फीस और भारी ब्याज देना होगा।

बचावः ऑटो डेबिट और बैंक से संपर्क करना है स्मार्ट तरीका

पेमेंट मिस होने पर तुरंत पैसा जमा करें। पहली बार गलती होने पर बैंक से रिपोर्ट न करने का अनुरोध करें। भविष्य में चूक से बचने के लिए 'ऑटो डेबिट' चुनें। स्कोर सुरक्षित रहे इसके लिए 'मिनिमम ड्यू' का भुगतान जरूर करें।

उभरती एसेट क्लास ईवी, डेटा सेंटर और एआई की भूख बढ़ा रहे तांबे की कीमत

सोने-चांदी के बाद कॉपर की रैली!

शुभो मौलिक
फाउंडर और सीईओ
एप्रिसिएट

जब भी हम निवेश की बात करते हैं, तो सोना, चांदी या शेयर की चर्चा सबसे पहले होती है। तांबा (कॉपर) पीछे छूट जाता है। लेकिन यदि आगामी दशक की वैश्विक अर्थव्यवस्था की तस्वीर जूम-इन करके देखें, तो पाएंगे कि भविष्य की दुनिया तांबे के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), एआई डेटा सेंटर्स से लेकर ग्रीन एनर्जी तक सब कुछ इसी पर टिका है। लेकिन तांबे की सप्लाई घट रही है। इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप के मुताबिक, 2026 में वैश्विक बाजार में करीब 1.5 लाख टन तांबे की कमी रहेगी। यह निवेशकों के लिए बड़ा मौका बन सकता है। सप्लाई संकट और औद्योगिक मांग के चलते 2025 के अंत तक कॉपर 10 लाख रुपए प्रति टन का रिकॉर्ड स्तर पार कर गया। अकेले 2025 में दाम 35% से ज्यादा बढ़े हैं।

सप्लाई की चुनौतीः खदान शुरू करने में 10-15 साल लगते हैं?

मौजूदा खदानों से अब शुद्ध धातु निकालना मुश्किल और महंगा होता जा रहा है क्योंकि अयस्क की गुणवत्ता गिर रही है। नई खदान शुरू करने में 10-15 साल लगते हैं। अधिकांश तांबा चिली और पेरू जैसे देशों से आता है, जहां राजनीतिक अस्थिरता और कड़े पर्यावरण नियम उत्पादन बाधित करते हैं।

कम आपूर्ति का असरः कचरे से भी 'खजाना' निकालने लगीं कंपनियां

- तांबे की भारी किल्लत के बीच कंपनियां अब पुरानी खदानों के मलबे और बेकार समझे जाने वाले अयस्कों से तांबा निकाल रही हैं। रियो टिंटो की 'न्यूटोन' तकनीक पारंपरिक खनन से 40% सस्ती है। वहीं, फ्रीपोर्ट-मैकमोरन 'लीचिंग' तकनीक से 2030 तक सालाना 3.63 लाख टन तांबा पैदा करेगी।
- सामान्य खदानें जहां 7,25,000 रुपए प्रति टन भाव पर मुनाफे में आती हैं, वहीं कचरे से तांबा निकालने वाली कंपनियां 3.6 लाख रुपए प्रति टन पर भी मुनाफे में रहती हैं। मौजूदा भाव 11.8 लाख रुपए है।
- बीएचपी के अनुसार 2035 तक मौजूदा खदानों का उत्पादन 15% गिर जाएगा। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि नई तकनीक 2034 तक दुनिया की 5 बड़ी तांबा कंपनियों का उत्पादन सालाना 10 लाख टन बढ़ा सकती है। यह 2030 तक कुल कमी का पांचवां हिस्सा है।

कॉपर की मांग बढ़ाने वाले चार बड़े ग्रोथ इंजन ये हैं...

- **ईवी में 5 गुना कॉपरः** पेट्रोल-डीजल कार के मुकाबले ईवी में 3-5 गुना कॉपर लगता है। 2025 में वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में ईवी की हिस्सेदारी 22% रही, जो 2035 तक 44% हो सकती है।
- **पावर ग्रिड अपग्रेडः** पुरानी बिजली लाइनें हटाकर हाई-वोल्टेज और सुरक्षित ट्रांसमिशन नेटवर्क बिछाया जा रहा है। 2030 तक तांबे की कुल मांग का 60% सिर्फ ग्रिड विस्तार से आएगा।
- **रिन्युएबल एनर्जीः** एक मेगावाट के सोलर या विंड प्लांट में पारंपरिक पावर प्लांट से 4-6 गुना ज्यादा तांबा लगता है।
- **एआई-डेटा सेंटर्सः** एक सामान्य डेटा सेंटर में 15,000 टन तांबे के मुकाबले एआई के लिए बने हाइपरस्केल डेटा सेंटर में 50,000 टन कॉपर खप सकता है।

पोर्टफोलियोः भारत में कॉपर ईटीएफ नहीं, फिर निवेश कैसे करें?

भारत में अभी सिर्फ सोने, चांदी के ईटीएफ हैं। ऐसे में अमेरिका में लिस्टेड ईटीएफ के जरिये तांबे में निवेश किया जा सकता है। यह उनके लिए बेहतर है, जो वैश्विक जोखिम समझते हैं।

- **ग्लोबल एक्स कॉपर माइनर्स ईटीएफः** यह उन कंपनियों में निवेश करता है, जो तांबे का खनन करती हैं। तांबा महंगा होने पर मुनाफा बढ़ेगा।
- **स्प्रॉट कॉपर माइनर्स ईटीएफः** यह प्योर-प्ले कॉपर माइनिंग कंपनियों पर केंद्रित है, जो अधिक फोकस्ड रिटर्न दे सकता है।
- **यूएससीएफ समरहेवन कॉपर इंडेक्स फंडः** यह कॉपर फ्यूचर्स ट्रैक करता है। सीधे कीमतों में उतार-चढ़ाव से लाभ कमाने का जरिया।
- **आईशेयर्स कॉपर एंड मेटल्स माइनिंग ईटीएफः** यह उन कंपनियों का मिश्रण है, जो तांबे के साथ अन्य धातुओं का भी खनन करती हैं।

मार्केट इनसाइट

अमेरिका से डील के बावजूद बड़ी तेजी टिकाऊ नहीं होगी

सुदीप शाह
वाइस प्रेसिडेंट,
एसबीआई
सिक्युरिटीज

पिछला सप्ताह शेयर बाजार के लिए किसी रोलर-कोस्टर से कम नहीं रहा। निफ्टी में जबरदस्त उतार-चढ़ाव रहा। पूरे हफ्ते में यह करीब 1,662 अंकों के दायरे में घूमा। जून 2024 के बाद यह किसी एक हफ्ते में निफ्टी की सबसे बड़ी हलचल है। बजट वाले दिन बाजार में घबराहट दिखी। डेरिवेटिव ट्रेड पर टैक्स बढ़ने से निफ्टी फिसलकर दिन के निचले स्तर 24,571 तक आ गया। लेकिन यह कमजोरी ज्यादा देर नहीं टिकी। अमेरिका से आई एक बड़ी खबर ने बाजार का मूड बदल दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय सामान के आयात पर जवाबी टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने का ऐलान किया। निफ्टी ने 1,770 अंकों की तेज छलांग लगाकर 26,341 का स्तर छू लिया। हालांकि बाजार में यह उत्साह ज्यादा टिक नहीं पाया। अगले ही कारोबारी सत्र के पहले ही मिनट में निफ्टी करीब 600 अंक टूट गया। यह साफ संकेत था कि ऊपरी स्तरों पर निवेशक मुनाफा काटने लगे हैं। वैश्विक संकेत सकारात्मक होने के बावजूद बाजार नए ऊंचे स्तरों पर टिक नहीं सका, जिससे यह बात स्पष्ट हो गई कि निवेशकों का भरोसा अभी भी कमजोर बना हुआ है।

आईटी शेयरों की बिकवाली से बाजार पर बना रहा दबाव

हफ्ते के दूसरे हिस्से में निफ्टी एक सीमित दायरे में घूमता रहा। इसकी बड़ी वजह रही आईटी शेयरों में तेज बिकवाली। एआई से जुड़े हालिया बदलावों को लेकर आईटी सेक्टर के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। इसी डर से निफ्टी आईटी इंडेक्स हफ्ते में करीब 7% गिरा।

इस सप्ताह निफ्टी की चाल धीमी पड़ती नजर आ रही

फिलहाल बाजार की रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है। यानी जब तक कोई बड़ा संकेत नहीं आता, निफ्टी एक दायरे में ऊपर-नीचे हो सकता है। गिरने पर निफ्टी को 25,500–25,550 पर सहारा मिल सकता है। इससे नीचे 25,200 अहम स्तर होगा। बढ़त में 25,850–25,880 तक पहुंच सकता है।

बजट में सपोर्ट के बावजूद डिफेंस शेयरों में तेजी नहीं

बजट में सपोर्ट के बावजूद डिफेंस शेयरों (जैसे एचएएल, मंझगांव डॉक) में कोई खास जान नहीं दिखी। तकनीकी चार्ट्स के मुताबिक, मेटल, ऑयल एंड गैस और सरकारी कंपनियां (पीएसई/सीपीएसई) आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। आईटी, फार्मा और हेल्थकेयर दबाव में रह सकते हैं।

रिस्क-सर्वे 2026

कंपनियों के लिए मुनाफे से बड़ी चुनौती साइबर हमले

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

भारतीय कंपनियों के लिए अब मुनाफा या बाजार हिस्सेदारी नहीं, बल्कि साइबर सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन गई है। उद्योग संगठन फिक्की और प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म ईवाई के रिस्क सर्वे-2026 के मुताबिक, हर दूसरी कंपनी (51%) ने साइबर हमलों और डेटा लीक को बिजनेस के लिए बड़ा जोखिम बताया है। यह खतरा बदलती ग्राहक अपेक्षाओं और वैश्विक भू-राजनैतिक तनाव से भी बड़ा माना गया है। सर्वे के अनुसार, 61% कंपनियां तेज तकनीकी बदलाव और डिजिटल डिसरप्शन को प्रतिस्पर्धा के लिए चुनौती मानती हैं। डेटा चोरी, रैंसमवेयर और अंदरूनी धोखाधड़ी को लेकर भी कंपनियों की चिंता बढ़ी है। करीब 57% ने डेटा लीक को गंभीर जोखिम बताया, जबकि 47% कंपनियों को जटिल साइबर खतरों से निपटने में दिक्कत हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई अपनाने में देरी से कंपनियों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।

कंपनी को जानें ओनिडा के सीएमडी मीरचंदानी शुरुआती निवेशक

फ्रैक्टलः देश का पहला एआई यूनिकॉर्न

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

फ्रैक्टल एनालिटिक्स भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न है। मुंबई और न्यूयॉर्क से चलने वाली यह कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनियों को मशीन लर्निंग, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग और एआई-आधारित निर्णय लेने में मदद करती है। इस हफ्ते आईपीओ के चलते यह कंपनी चर्चा में है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स की स्थापना 28 मार्च 2000 को मुंबई में हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिमिटेड कर दिया गया। ओनिडा समूह के सीएमडी गुलू मीरचंदानी और उनके बेटे साशा मीरचंदानी ने 2001 में फ्रैक्टल में एंजेल निवेशक के रूप में निवेश किया था। इसके मौजूदा ग्रुप सीईओ श्रीकांत वेलामकन्नी और फ्रैक्टल यूएसए के सीईओ प्रणय

अग्रवाल इसके संस्थापकों में शामिल हैं। गणित के शब्द फ्रैक्टल का अर्थ है- टूटा हुआ या खंडित। अपने नाम के अनुरूप ही 26 वर्षों के सफर में यह कंपनी कई बार टूटने से बची है। एक सह-संस्थापक एक साल के भीतर ही कंपनी छोड़कर चले गए। दो सह-संस्थापक 2007 में और एक और 2011 में कंपनी से अलग हो गए, लेकिन यह टूटी नहीं।

फ्रैक्टल एनालिटिक्स की डोमेन विशेषज्ञता कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, रिटेल, टेक्नोलॉजी, मीडिया, टेलीकॉम, हेल्थकेयर, लाइफ साइंसेज और बैंकिंग-फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टरों में फैली है। कंपनी की आय का 90% से ज्यादा हिस्सा विदेश से आता है।

माइक्रोसॉफ्ट, एपल, एनवीडिया, मेटा जैसे 113 दिग्गज क्लाइंट

बीते वित्त वर्ष तक कंपनी 113 वैश्विक ग्राहकों को सेवा दे रही थी। इनमें माइक्रोसॉफ्ट, एपल, एनवीडिया, अल्फाबेट, अमेजन, मेटा, टेस्ला, सिटीबैंक, कोस्टको, नेस्ले, फिलिप्स, मार्स और मोंडेलेज शामिल हैं। टॉप 10 क्लाइंट से करीब 54% कमाई आती है। कंपनी में कुल 5,000 से अधिक कर्मचारी हैं, जिनमें लगभग 4,600 भारत में हैं।

बिजनेस आइडिया

₹7 लाख निवेश से शुरू करें मोबाइल कार वॉश बिजनेस

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

शहरी इलाकों में बढ़ती गाड़ियों, समय की कमी और पानी बचाने की जरूरत ने मोबाइल कार वॉश को तेजी से उभरता बिजनेस बना दिया है। इस मॉडल में ग्राहक को घर या ऑफिस पर ही 30-45 मिनट में कार साफ कराने की सुविधा मिलती है। अपार्टमेंट, ऑफिस कॉम्प्लेक्स में एक साथ कई गाड़ियां मिलने से मुनाफा बढ़ता है।

- **क्या चाहिएः** लोडिंग ऑटो, वाटर टैंक, प्रेशर वॉश मशीन, वैक्यूम क्लीनर और बैटरी-इनवर्टर या जेनरेटर। इन पर 7-8 लाख का शुरुआती निवेश करना होता है।
- **बिजनेस मॉडल ऐसे काम करता हैः** ग्राहक वाट्सएप, फोन या एप के जरिये बुकिंग करता है। टीम तय समय पर पहुंचकर वाहन की सफाई करती है।
- **कमाई का गणितः** एक टीम रोज 10-15 गाड़ियां साफ कर सकती है। प्रति गाड़ी औसतन 400 रु. चार्ज करने पर महीने में 1-1.4 लाख की आय संभव है। खर्च निकालने के बाद 80-90 हजार तक कमाई हो सकती है।

बिजनेस स्ट्रैटजी मेडटेकः प्रोडक्ट की विश्वसनीयता को 23%, सर्विस क्वालिटी को 17% तरजीह, सिर्फ 11% ग्राहक दाम देख रहे

ग्राहकों की संतुष्टि 20% बढ़े तो कंपनियों की आय 32% तक बढ़ सकती है

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

मेडिकल टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री अब सिर्फ हाईटेक मशीनों की दौड़ तक सीमित नहीं है। असली मुकाबला इस बात का हो गया है कि मशीनें बिकने के बाद कंपनी मरीज और अस्पताल के साथ कितनी मजबूती से जुड़ी रहती है। मैकिंजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेडटेक कंपनियों के लिए अगला ग्रोथ इंजन सर्विस और कस्टमर एक्सपीरियंस बनने जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि अगर किसी कंपनी की सर्विस क्वालिटी और ग्राहक संतुष्टि में 10-20% सुधार होता है, तो उसकी आय 32% तक बढ़ सकती है। बेहतर सर्विस का असर सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं रहता। इससे कर्मचारियों का जुड़ाव 20-30% बढ़ता है और सर्विस से जुड़ी लागत में 50% तक कमी आती है। इंजीनियर और सेल्स टीमें खुद को केवल मशीन ठीक करने वाला नहीं, बल्कि मरीज की जान बचाने की प्रक्रिया का हिस्सा मानने लगती हैं। इससे कामकाज का माहौल सुधरता है। मैकिंजी के आंकड़े बताते हैं कि जो कंपनियां सर्विस पर फोकस करती हैं, उनके शेयरहोल्डर्स को सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों की तुलना में चार गुना रिटर्न मिला है। ऐसी कंपनियां कुल आय का 35% हिस्सा इसी सेगमेंट से कमा रही हैं। ग्राहकों की प्राथमिकताएं भी बदल रही हैं। मशीन खरीदते वक्त अस्पताल अब केवल कम कीमत या डिस्काउंट पर ध्यान नहीं देते। ग्राहक प्रोडक्ट की विश्वसनीयता को 23% और सर्विस क्वालिटी को 17% तरजीह देते हैं, जबकि सिर्फ 11% ग्राहकों के लिए कीमत सबसे अहम फैक्टर है। साफ है कि मेडटेक बाजार में अब भरोसेमंद सर्विस की साख, दाम से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है।

सर्विस पर फोकस इसलिए...

फैक्टर	ये हो रहे फायदे
प्रोडक्ट पर भरोसा	23% प्राथमिकता
सर्विस क्वालिटी	17% प्राथमिकता
आय में बढ़ोतरी	32% तक वृद्धि
सर्विस लागत	50% तक बचत
स्पेयर पार्ट्स की बिक्री	37% बढ़ोतरी
दोबारा खरीदारी दर	22% इजाफा

वफादारीः पेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ी लॉयल्टी, पुर्जों की खरीद 37% अधिक

जिन ग्राहकों के पास कंपनियों के पेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हैं, वे ब्रांड के प्रति अधिक वफादार पाए गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि ऐसे ग्राहक मशीनों के स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी उन लोगों के मुकाबले 37% ज्यादा करते हैं, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। साथ ही पुराने प्रोडक्ट को बदलकर उसी कंपनी का नया प्रोडक्ट खरीदने की दर भी इनमें 22% ज्यादा रहती है। यह कॉन्ट्रैक्ट ग्राहकों को मशीनों के लगातार चलते रहने का भरोसा देते हैं, जिससे आपसी रिश्ता मजबूत होता है।

चुनौतीः भारत में अस्पतालों के लिए मशीनें 24 घंटे चालू रहना जरूरी

भारत दुनिया का बड़ा मेडिकल टूरिज्म हब बन रहा है। विदेशी मरीजों के बढ़ते दबाव के बीच अस्पतालों के लिए मशीनों का 'जीरो डाउनटाइम' यानी हर वक्त चालू रहना अनिवार्य हो गया है। अगर कोई एमआरआई या सीटी स्कैन मशीन कुछ घंटों के लिए भी खराब होती है, तो इससे अस्पताल की साख और आय, दोनों पर बुरा असर पड़ता है। यही वजह है कि भारतीय अस्पताल अब ऐसी मेडटेक कंपनियों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो फौरन बेहतरीन सर्विस का भरोसा देती हैं।

भविष्यः डिजिटल टूल्स से सुधरेगा कामकाज... आने वाले समय में कंपनियां जेनरेटिव एआई और ऑटोमेशन का बड़े पैमाने पर सहारा लेंगी। इससे मशीनों में खराबी आने से पहले ही उसका पता लगाना और दूर से मरम्मत करना संभव होगा। कंपनियां अब ग्राहकों को एप और डिजिटल माध्यम से तकनीकी सहायता दे रही हैं। इससे अस्पतालों के संचालन में आने वाली रुकावटें भी कम हो रही हैं। डिजिटल युग में वही कंपनियां सफल होंगी जो ग्राहकों के फीडबैक को आधुनिक तकनीक से जोड़ेंगी।